सूचना और प्रसारण मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट

2006-2007

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित।
क्विक प्रिंट्स, नारायणा फेज-1, नई दिल्ली-110 028 द्वारा टाईप सेट।
मुद्रक :

विषय - सूची

उपलब्धियां

1.	एक नजर	1
2.	प्रशासन	3
3.	सूचना क्षेत्र	12
4.	प्रसारण क्षेत्र	52
5.	फिल्म क्षेत्र	108
6.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	165
7.	योजना एवं गैर-योजना कार्यक्रम	167
8.	नई पहल	179

परिशिष्ट

1.	मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट	184
2.	वर्ष 2006-2007 और 2007-2008 के लिए मीडिया अनुसार बजट	186

वर्ष की उपलब्धियां

- गोआ में राज्य सरकार के सहयोग से 23 नवम्बर से 03 दिसंबर 2006 तक भारत का 37वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किया गया। श्री शशि कपूर उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे।
- इस्राइल, चीन (पेइचिंग और शंघाई), दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम (ब्रसेल्स) और जर्मनी में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों/विशेष उत्सवों के अंतर्गत भारतीय फिल्म समारोह आयोजित किए गए।
- दिसम्बर 2006 तक 18 देशों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के लिए भारतीय फिल्में भेजी गईं।
- पहले साइप्रस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में फिल्म 'राम' को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए पुरस्कार दिए गए।
- फिल्म 'मीनाक्षी - ए टेल आफ थ्री सिटीज' को भी श्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी और श्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन के लिए पुरस्कार दिए गए।
- फिल्म प्रभाग ने अप्रैल से नवम्बर, 2006 तक 60 फिल्मों के साथ 6 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में, 28 फिल्मों के साथ 4 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में और 270 फिल्मों के साथ 21 राज्य स्तरीय समारोहों में हिस्सा लिया।
- फिल्म प्रभाग ने अप्रैल से नवम्बर 2006 के दौरान थिएटर सर्किट्स के लिए 39 फिल्मों के 9791 प्रिंट्स जारी किए।
- अप्रैल से नवम्बर 2006 के दौरान फिल्म प्रभाग ने 188 शैक्षिक और सूचनाप्रद फिल्मों को डिजिटलाइज किया, 480 फिल्में हाई डेफिनेशन टेप्स में डाली गईं और 825 फिल्में इंटरनेशनल ट्रैक्स (डीवीडी) में डाली गईं।
- सूचना और प्रसारण सचिव श्री एस.के. अरोड़ा ने 7 जुलाई 2006 को इंडिया हेबिटाट सेंटर, नई दिल्ली में फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट के डिप्लोमा छात्रों द्वारा तैयार किया गया संग्रह 'मास्टर स्ट्रोक्स' जारी किया।
- गोआ में आयोजित भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारतीय पैनोरमा के लिए पांच डिप्लोमा फिल्में - 'गधा जनम सफल', 'ए रूट काल्ड '13', 'पारसीवाड़ा तारापुर-प्रेजेंट डे,' 'चाबी वाली पाकेट वाच' और 'क्षितिज' - प्रदर्शन के लिए चुनी गईं।
- राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे के सहयोग से 15 मई से 10 जून, 2006 तक 31वां फिल्म एप्रीसिएशन कोर्स आयोजित किया गया। इसमें 75 प्रतिभागी शामिल हुए।
- 29 जुलाई से 20 दिसंबर 2006 तक दूरदर्शन के 52वां टेलीविजन प्रोडक्शन एंड टेक्नीकल कोर्स चलाया गया।
- पत्र सूचना कार्यालय ने इस वित्त वर्ष में दिसंबर 2006 तक देश के विभिन्न हिस्सों में 55 जनसूचना अभियान चलाए। प्रत्येक अभियान पांच दिन का था और प्रत्येक अभियान में 25 स्टाल लगाकर केंद्र सरकार के कार्यक्रमों और इनका लाभ उठाने के तरीकों की जानकारी दी गई।
- पत्र सूचना कार्यालय ने क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, विज्ञापन तथा दृष्य प्रचार निदेशालय और प्रकाशन विभाग की क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय और प्रकाशन विभाग की क्षेत्रीय इकाइयों के सहयोग से फोटो फीचर जारी करने और प्रदर्शनी लगाने जैसे उपायों के जरिए विकास-कार्यों में सफलता की स्थानीय घटनाओं का प्रचार-प्रसार किया।
- पत्र सूचना कार्यालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए 17-18 अप्रैल 2006 को एक सम्मेलन आयोजित किया।
- पत्र सूचना कार्यालय ने जून, 2006 में श्रीनगर में सामाजिक-आर्थिक विकास के बारे में सम्पादकों का सम्मेलन आयोजित किया जिसमें मुख्य फोकस जम्मू-कश्मीर पर था।
- पत्र सूचना कार्यालय ने नई दिल्ली में नवम्बर 2006 में आर्थिक मामलों के सम्पादकों का सम्मेलन भी आयोजित किया।
- पत्र सूचना कार्यालय ने गोआ में आयोजित भारत के 37वें अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह में मीडिया सेंटर स्थापित किया।
- गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग और प्रकाशन विभाग ने 4 जनवरी, 2007 को वार्षिक संदर्भ-ग्रंथ - 'इंडिया - 2007' जारी किया।

- प्रकाशन विभाग ने वार्षिक संदर्भ ग्रंथ 'इंडिया-2007' और इसके हिंदी संस्करण 'भारत-2007' को पीडीएफ ई-बुक फॉर्मेट में अपनी वेबसाइट में डाला। इसके साथ ही प्रकाशन विभाग का यह प्रकाशन इलेक्ट्रॉनिक सुलभ हो गया। अब, भारत के बारे में ताजा जानकारी जन-सामान्य को कंप्यूटर से तत्काल सुलभ हो सकती है।
- प्रकाशन विभाग की मासिक पत्रिका 'आजकल' के बाल साहित्य तथा हिंदी कवयित्री महादेवी वर्मा की जन्मशती पर विशेषांक प्रकाशित हुए।
- गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग की इकाई जन संचार राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र ने वर्ष 2006-07 (दिसंबर 2006 तक) तक जनसंचार के विविध पक्षों के बारे में 38 आलेख जारी किए।
- गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग की प्रशिक्षण इकाई ने इस वर्ष (दिसंबर 2006 तक) मंत्रालय के विभिन्न भागों में कार्यरत भारतीय सूचना सेवा के 82 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया।
- फोटो प्रभाग ने अपनी वेबसाईट तैयार की। सभी डिजिटाइज्ड चित्र वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। प्रभाग ने अपने समाचार सेवा नेटवर्क को बेहतर बनाने का कार्य भी शुरू किया है जिसके वर्तमान वित्त वर्ष में पूरा हो जाने की उम्मीद है।
- फोटो प्रभाग ने अफगानिस्तान की भक्तार न्यूज एजेंसी के कार्मिकों को परंपरागत फोटोग्राफ्स के डिजिटल प्रबंध के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया।
- फोटो प्रभाग ने अगरतला और नई दिल्ली में 'मीडिया संचार और डिजिटल फोटोग्राफी की भूमिका' विषय पर कार्यशालाएं आयोजित कीं।
- विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने समाचारपत्रों के लिए नई विज्ञापन नीति जारी की जो 1 जून 2006 से लागू हो गई है।
- विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने दृश्य-श्रव्य निर्माताओं के पैनल के लिए नीति जारी की। इलेक्ट्रानिक मीडिया चैनलों के पैनल के लिए भी नई नीति जारी की गई।
- भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक ने शीर्षक पुष्टिपत्र अपनी वेबसाइट पर जारी करने शुरू किए। कामकाज में ज्यादा पारदर्शिता आएगी।
- भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक ने उपयोग में नहीं लाए गए शीर्षकों के अपने आप डी-ब्लॉक होने की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली शुरू की जिससे ज्यादा शीर्षक उपलब्ध हो सकेंगे।
- भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक ने पीआरबी अधिनियम, 1876 के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों की लोगों को जानकारी देने और उनकी शिकायतें दूर करने के लिए 'तत्काल समाधान' नाम का विशेष सत्र आयोजित किया। देश के अन्य भागों में भी ऐसे सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव है।
- क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ने पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित 55 सूचना अभियानों में भागीदारी की और 'राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन' के लिए राष्ट्रव्यापी जागरुकता अभियान भी चलाए।
- भारतीय प्रेस परिषद ने अपनी स्थापना के 40 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 16-17 नवंबर 2006 को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर दो दिन का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया।
- सरकार ने दिसंबर 2006 में सामुदायिक रेडियो स्थापित करने की अनुमति देने की नीति का उदारीकरण किया और शैक्षिक संस्थानों के अलावा, सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं आदि अव्यावसायिक संगठनों को भी ऐसी अनुमति के दायरे में शामिल कर लिया ताकि विकास से जुड़े मुद्दों में समाज की ज्यादा भागीदारी हो सके।

1

एक नजर

सूचना और प्रसारण मंत्रालय जनसंचार माध्यमों—रेडियो-टेलीविजन, फिल्मों, समाचार पत्रों और अन्य प्रकाशनों, विज्ञापन और नृत्य तथा नाटक के पारंपरिक तरीकों के द्वारा लोगों को आसानी से सूचना प्रदान करने में प्रभावशाली भूमिका अदा करता है। मंत्रालय विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की मनोरंजन तथा बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, निरक्षरता उन्मूलन तथा महिलाओं और बच्चों समाज के अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित मुद्दों पर जनसाधारण का ध्यान आकर्षित करता है। मंत्रालय चार खंडों में विभाजित है: सूचना खंड, प्रसारण खंड, फिल्म खंड तथा एकीकृत वित्त खंड।

सूचना खंड, संयुक्त सचिव (नीति और प्रशासन) के तहत भारत सरकार के नीतिगत मामले, समाचार पत्रों और प्रकाशनों और प्रचार आवश्यकताओं को देखता है। इस खंड की मीडिया इकाइयों का विवरण नीचे दिया गया है :

प्रसारण खंड संयुक्त सचिव (प्रसारण) की देखरेख में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित मामलों को देखता है। यह क्षेत्र प्रसारण सेवा, केबल टेलीविजन संचालन, प्राइवेट टेलीविजन चैनल, एफ एम

● पत्र सूचना कार्यालय	प्रेस
● फोटो प्रभाग	
● गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग	
● प्रकाशन विभाग	
● विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	प्रचार
● क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	
● गीत और नाटक प्रभाग	
● भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक	प्रेस के सांविधिक कार्य
● भारतीय प्रेस परिषद	
● भारतीय जनसंचार संस्थान	मानव संसाधन विकास

चैनल इत्यादि के लिए नीतियां और नियमों को बना कर उन्हें लागू करता है।

इस खंड के अंतर्गत निम्नलिखित संगठन आते हैं :

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) एक स्वायत्तशासी संस्था है, जिसके अंतर्गत निम्न संस्थान हैं :

- आकाशवाणी
- दूरदर्शन
- ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड
- फिल्म क्षेत्र से संबंधित मामलों को **फिल्म विंग** संयुक्त सचिव (फिल्म) की देखरेख में देखता है। फिल्म विंग फिल्म उद्योग से संबंधित विकास और प्रचार गतिविधियां का समन्वय करता है जिसमें प्रशिक्षण, सार्थक सिनेमा का प्रचार, फिल्म समारोहों का आयोजन और निर्यात नियंत्रण आदि शामिल हैं। इसके अलावा आंतरिक तथा बाहरी प्रचार के लिए वृत्तचित्रों का निर्माण और वितरण भी इसी विंग की जिम्मेदारी है। इसकी निम्नलिखित मीडिया इकाइयां हैं:

● फिल्म प्रभाग	–	वृत्तचित्र निर्माण
● केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	–	फिल्मों का प्रमाणन
● भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	–	फिल्मों का संरक्षण
● राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	–	फिल्मों की वित्त व्यवस्था
● भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे	–	मानव संसाधन विकास
● सत्यजित राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता	–	
● फिल्म समारोह निदेशालय	–	अच्छे सिनेमा को प्रोत्साहन
● बाल फिल्म सोसाइटी, भारत	–	बाल फिल्मों को प्रोत्साहन

एकीकृत वित्त खंड मंत्रालय के वित्तीय मामलों की देखरेख करता है जिसमें बजट बनाना और योजना समन्वयन शामिल है। मंत्रालय की वार्षिक योजना (2006-07) के अंतर्गत कुल व्यय 538.00 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है।

2

प्रशासन

कार्य आबंटन नियमों के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में विस्तृत क्षेत्राधिकार है और उसे मुद्रित ओर इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ-साथ फिल्म संबंधी कार्यों को भी करना होता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्राधिकार

- आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से विदेशों में रह रहे भारतीयों सहित जनता के लिए समाचार सेवाएं
- प्रसारण और दूरदर्शन सेवाओं का विकास
- फिल्मों का आयात-निर्यात
- फिल्म उद्योग का विकास और उसे प्रोत्साहन
- फिल्म समारोहों का आयोजन और फिल्मों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान-प्रदान
- भारत सरकार के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार करना
- भारत सरकार की नीतियों के प्रचार-प्रसार के लिए प्रेस से संपर्क बनाए रखना
- समाचार पत्रों के संदर्भ में प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 का कार्यान्वयन
- राष्ट्रीय महत्व के मामलों में प्रकाशनों तथा मीडिया के माध्यम से भारत के भीतर और देश के बाहर सूचनाओं का प्रचार-प्रसार
- मंत्रालय की मीडिया इकाइयों की मदद के लिए गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण की व्यवस्था
- मंत्रालय की संस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले जाने-माने कलाकारों, संगीतकारों, वाद्य संगीतकारों, नृत्य कलाकारों, नाटककारों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना
- प्रसारण और समाचार सेवाओं के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

मंत्रालय अपने 14 संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, 6 स्वायत्तशाली संगठनों और 2 सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के सहयोग से अपने कार्य संपन्न करता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत क्षेत्रीय संगठन

संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय

1. भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय
2. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय
3. पत्र सूचना कार्यालय
4. प्रकाशन विभाग
5. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय
6. फिल्म समारोह निदेशालय
7. गवेषणा, अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रभाग
8. फिल्म प्रभाग
9. फोटो प्रभाग
10. गीत और नाटक प्रभाग
11. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
12. राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार
13. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केंद्र
14. मुख्य लेखा नियंत्रक

स्वायत्त संगठन और सार्वजनिक उपक्रम

1. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)
2. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे
3. भारतीय जन-संचार संस्थान
4. भारत बाल चलचित्र समिति
5. भारतीय प्रेस परिषद
6. सत्यजित राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता
7. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम
8. ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड

मुख्य सचिवालय

मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के प्रमुख सूचना और प्रसारण सचिव हैं जिनकी सहायता के लिए एक अपर सचिव, एक वित्तीय सलाहकार और अतिरिक्त सचिव, तीन संयुक्त सचिव, एक आर्थिक सलाहकार और एक मुख्य लेखा नियंत्रक होते हैं। मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में निदेशक/उप सचिव स्तर के 15 पद, अवर सचिव स्तर के 21 पद, 58 अन्य राजपत्रित अधिकारियों और 267 गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के पद हैं।

नागरिक अधिकारपत्र

नागरिक अधिकारपत्र तैयार किया गया है और मंत्रालय के अधिकारिक वेबसाइट में प्रदर्शित किया गया है। इसका पता है : (http://www.mib.nic.in)

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

सेवाओं में आरक्षण से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों और आवश्यक दिशानिर्देशों का सभी मीडिया इकाइयों में परिचालित किया जाता है ताकि इन पर कड़ाई से अमल हो सके।

मंत्रालय इस संबंध में सरकार द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों/मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी संगठनों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव

कदम उठा रहा है। मंत्रालय अपने सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों सहित अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी सेवाओं तथा पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के वास्तविक प्रतिनिधित्व और उनके लिए आबंटित आरक्षित पदों के बीच अंतर को दूर करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय से संबद्ध या उसके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों में पदों पर आधारित रोस्टर तैयार किए गए हैं।

मंत्रालय और उसके सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में 1.1.2006 को कर्मचारियों की कुल संख्या में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार थी :

	वर्ग 'ए'	वर्ग 'बी'	वर्ग 'सी'	वर्ग 'डी'	कुल
अनुसूचित जाति	12.66%	15.58%	18.68%	29.78%	20.2%
अनुसूचित जनजाति	6.2%	5.66%	7.86%	11.60%	8.16%
अन्य पिछड़ी जाति	4.90%	4.47%	8.09%	8.16%	7.38%

आरक्षण नीति के कार्यान्वयन और अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.ज. को नियमानुसार देय अन्य लाभ इन लोगों को प्रदान करने के कार्य की निगरानी और समन्वय के लिए निदेशक/उप सचिव स्तर के संपर्क अधिकारी की देखरेख में मंत्रालय और इसके सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त संगठनों व सार्वजनिक उपक्रमों में एक प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है।

राजभाषा के रूप में हिंदी का उपयोग

हिंदी भारत संघ की राजभाषा है। सरकारी कामकाज में हिंदी के इस्तेमाल को उत्तरोत्तर बढ़ाने के बारे में सरकार ने सुचिंतित नीति बनाई है। मंत्रालय भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार हिंदी के उपयोग पर जोर दे रहा है। मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति सचिवालय और इसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के उपयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने के कार्य की निगरानी करती है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं। इस बैठकों में मंत्रालय और इसके विभिन्न संगठनों में राजभाषा नीति पर अमल की स्थिति की समीक्षा की जाती है। बैठकों में सरकारी कामकाज में हिन्दी का इस्तेमाल बढ़ाने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श किया जाता है और इस बात का पता लगाने की कोशिश की जाती है कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्यों को किस तरह प्राप्त किया जाए।

सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग बढ़ाने के लिए 14-28 सितम्बर 2006 तक मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में 'हिंदी पखवाड़े'' का आयोजन किया गया। इस दौरान निबंध लेखन, कविता, टिप्पणी और मसौदा लेखन, भाषण, अनुवाद, हिन्दी स्टेनोग्राफी, वाद-विवाद, क्विज और अंत्याक्षरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें 167 कर्मचारियों ने भाग लिया। इनमें से 72 कर्मचारियों को सूचना और प्रसारण सचिव ने (जिनमें हिंदी भाषी और अहिंदीभाषी, दोनों ही तरह के कर्मचारी शामिल थे) प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किए। इसी तरह के हिन्दी पखवाड़ों और हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में भी किया गया जिनमें विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। माननीय मंत्री जी की ओर से एक अपील भी जारी की गई जिसमें सरकारी कामकाज में हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री और कैबिनेट सचिव द्वारा जारी अपीलों को भी परिचालित किया गया।

मंत्रालय ने 2004-05 के लिए दूसरा इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार जीता। केंद्रीय गृह मंत्री ने 14 सितम्बर 2006 को विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में अतिरिक्त सचिव (सूचना और प्रसारण) को पुरस्कार प्रदान किया।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयनन और इसकी निगरानी तथा अनुवाद के कार्य में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्य सचिवालय में एक निदेशक (राजभाषा), एक सहायक निदेशक (राजभाषा) और चार अनुवादक नियुक्त किए गए हैं।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत सभी कागजात/दस्तावेज द्विभाषिक रूप में जारी करने और हिंदी में प्राप्त तथा हिन्दी में हस्ताक्षर वाले पत्रों के उत्तर का प्रेषण अनिवार्य रूप से हिंदी में ही सुनिश्चित करने के लिए जांच बिंदुओं को ओर सुदृढ़ किया गया। इसके अलावा विभिन्न अनुभागों और मीडिया इकाइयों से प्राप्त हुई त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की गई तथा राजभाषा नीति का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने और कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाये गये तथा आवश्यक सुझाव दिए गए।

माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन के बारे में गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

मंत्रालय और इसके सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने तथा सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग बढ़ाने के तौर-तरीकों के बारे में सुझाव देने के लिए हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार हिंदी में मौलिक टिप्पणियां और प्रारूप लिखने के लिए एक प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 2005-06 में मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) के 10 कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिए गए। मंत्रालय और इसके सभी कार्यालयों के लिए सर्वश्रेष्ठ पत्रिका पुरस्कार नाम की एक योजना चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत सबसे अच्छी पत्रिका को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष में विभिन्न मीडिया एकांशों की पांच बेहतरीन पत्र-पत्रिकाओं को शील्ड देकर सम्मानित किया गया।

राजभाषा के बारे में संसद की दूसरी उप-समिति ने वर्ष के दौरान (31 दिसम्बर 2006 तक) मंत्रालय के अधीन 25 कार्यालयों का निरीक्षण ने किया। इन निरीक्षण बैठकों में एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया। समिति के सुझावों को नोट किया गया और कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाये गए। राजभाषा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय के 15 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और कमियों को दूर करने के लिए सुझाव दिए गए।

मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों के कर्मचारियों द्वारा सरकारी कामकाज में राजभाषा के उपयोग को लगातार बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शन महानिदेशालय, आकाशवाणी महानिदेशालय और मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय द्वारा देश के विभिन्न भागों में राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इस सम्मेलनों के परिणामस्वरूप राजभाषा नीति को लागू करने की दिशा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 2 अप्रेल 2006 को नई दिल्ली में आयोजित 'सिविल सेवा दिवस' प्रदर्शनी देखते हुए; इस अवसर पर कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री सुरेश पचौरी, कैबिनेट सचिव श्री बी.के. चतुर्वेदी और सूचना और प्रसारण सचिव श्री एस.के. अरोड़ा भी उपस्थित थे

संगठन एवं प्रविधि एकांश

व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद अब कार्य मापन अध्ययन कराने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की स्टाफ निरीक्षण इकाई पर आ गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के परामर्श से, जो कि संगठन एवं प्रविधि संबंधी मामलों में केंद्रीय विभाग है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की आंतरिक कार्य अध्ययन इकाई को 24 मई 2006 से संगठन एवं प्रविधि (ओ एंड एम) एकांश नाम दिया गया है।

तब से यह एकांश संगठन और प्रविधि संबंधी अनेक गतिविधियां, जैसे जांच और विलंब आदि विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर अनुपालन की निगरानी की गतिविधियों में लगा है। इसके अलावा यह प्रेषण माध्यम की समीक्षा और मामलों के निस्तारण के लिए समय सीमा के निर्धारण आदि में भी लगा है। इस अवधि के दौरान अभिलेख संरक्षण के मासिक प्रयासों के साथ-साथ दो विशेष अभियान चलाए गए जिससे 21,951 फाइलों को अभिलेखबद्ध किया गया, 24,404 फाइलों की समीक्षा की गई और 9,271 फाइलों की छंटाई की गई। रोजमर्रा के कामकाज में कार्यालयीन प्रक्रिया संबंधी मैनुअल के विभिन्न प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अनुभागों/डेस्कों का निरीक्षण किया गया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इस एकांश को मंत्रालय से संबद्ध और इसके अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण का दायित्व भी सौंपा गया है। इसी के अनुसार इस एकांश ने तिरूअनंतपुरम और चंडीगढ़ में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के तिरुअनंतपुरम स्थित क्षेत्रीय कार्यालय और चंडीगढ़ में गीत और नाटक प्रभाग के क्षेत्रीय केन्द्र के निरीक्षण किए। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व एकांश ने दो या तीन अन्य अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों में इसी तरह के निरीक्षण पूरे करने की योजना बनाई है।

सचिव (सूचना और प्रसारण) द्वारा सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत फार्मों के संशोधन की कार्य योजना के अनुपालन में मंत्रालय में 10 नवम्बर, 2005 को संयुक्त सचिव (पीएंडए) की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया गया था जिसने मंत्रालय और इसकी विभिन्न मीडिया इकाइयों में इस समय इस्तेमाल किए जा रहे सभी फार्मों की समीक्षा की। समीक्षा के बाद कार्य बल ने 35 फार्मों को उनके वर्तमान रूप में ही जारी रखने की सिफारिश की। इसके अलावा 37 फार्मों में परिवर्तन/नये डिजाइन बनाने और 19 फार्मों को समाप्त करने की भी सिफारिश की गई। फार्मों में संशोधन की कार्य योजना के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति के बारे में रिपोर्ट 21 जून 2006 को मंत्रिमंडल सचिव के पास भेजी गई।

संगठन और प्रविधि एकांश केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और आम जनता के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रायोजित विभिन्न लाभप्रद योजनाओं का कार्यान्वयन करने वाली मंत्रालय की केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।

जन शिकायतें

मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में जन शिकायत सेल खोला गया है। संयुक्त सचिव (पी एंड ए) को मंत्रालय ने आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र का प्रमुख बनाया गया है।

सूचना सुविधा केंद्र

प्रशासन को ज्यादा पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने के सरकार के फैसले के अनुरूप मंत्रालय में 4 जुलाई 1997 को सूचना सुविधा केंद्र खोला गया।

महिला सेल

राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मंत्रालय में महिला सेल खोला गया जो महिलाओं की कल्याण योजनाओं की देख-रेख करता है। पिछले दिनों संयुक्त सचिव (पी एंड ए) की अध्यक्षता में महिला सेल का पुनर्गठन किया गया। तीन वरिष्ठ महिला अधिकारियों को इसका सदस्य बनाया गया और वाईडब्ल्यूसीए की सुश्री लीना गोंसाल्वेज को इसका गैर-सरकारी सदस्य बनाया गया। यह सेल माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतों की जांच समिति के रूप में भी काम करेगा। ऐसे मामलों को अब सीएसएस (कंडक्ट) रूल्स, 1964 (नियम 3-सी) में शामिल कर लिया गया है।

भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सरकार और मीडिया के बीच संपर्क सेतु का काम करते हैं। ये अधिकारी सार्वजनिक जनसंचार-कर्मी के रूप में समाचारों के प्रसारण और निजी सम्पर्क के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाने का भी काम करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए इन अधिकारियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय सूचना सेवा के 741 ग्रुप ए और बी अधिकारियों में 134 महिला अधिकारी हैं।

लेखांकन संगठन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख होने के साथ-साथ मुख्य लेखांकन अधिकारी का दायित्व भी निभाते

हैं। सचिव यह कार्य अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से करते हैं।

मुख्य लेखा नियंत्रक लेखांकन संगठन के प्रशासनिक प्रमुख हैं और एक लेखा नियंत्रक, एक उप लेखा नियंत्रक तथा 34 वरिष्ठ लेखा अधिकारियों/लेखा अधिकारियों की मदद से अपने इस कार्य को करते हैं। लेखांकन संगठन के एक प्रधान लेखांकन अधिकारी और 14 वेतन और लेखा अधिकारी हैं। इनमें दिल्ली में पांच, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में दो-दो तथा लखनऊ, नागपुर और गुवाहाटी में एक-एक लेखा अधिकारी हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध में भी लेखा अधिकारी हैं।

लेखांकन संगठन के दायित्व इस प्रकार हैं :

- विनियोग पर व्यय संबंधी नियंत्रण
- प्राप्तियों और व्यय का समय पर लेखांकन
- महानियंत्रक लेखा को भेजने के लिए मंत्रालय के मासिक और वार्षिक लेखों का संकलन और समेकन
- प्राप्ति बजट तैयार करना
- वेतन और भत्तों सहित कार्यालय के आकस्मिक खर्चों, सरकारी, कर्मचारियों के ऋणों और अग्रिमों का तुरंत भुगतान सुनिश्चित करना, राज्य सरकारों के लिए ऋण और अनुदान सहायता को प्राधिकृत करना आदि।
- पेंशन, भविष्य निधि और अन्य दावों को शीघ्रता से निपटान
- मंत्रालय, मीडिया इकाइयों और वेतन व लेखा अधिकारियों का आंतरिक लेखा परीक्षण
- संबंधित अधिकारियों को प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के लिए लेखांकन संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराना।
- फिल्म समारोह निदेशालय, पत्र सूचना कार्यालय, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, प्रशासन विभाग, गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग के आंतरिक वित्तीय सलाहकार की भूमिका।

कंप्यूटरीकरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लेखांकन संगठनों द्वारा 2006-07 में ई-गवर्नेंस संबंधी विशेष पहल इस प्रकार है:

- **अंशदायी पेंशन निधि प्रबंधन:** नई पेंशन योजना संबंधी रिकाई भी अंशदायी पेंशन निधि प्रबंधन साफ्टवेयर के माध्यम से रखा जा रहा है जिसे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत महालेखा नियंत्रक के एनआईसी सेल ने बनाया है। इसका उपयोग 1.1.2004 से लागू नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के पेंशन संबंधी अंशदान को प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से अंशदायी पेंशन लेखांकन अधिकारी को भेजने के लिए किया जा रहा है।
- **लेखों का कंप्यूटरीकरण :** लेखों के कंप्यूटरीकरण का साफ्टवेयर (कॉम्पैक्ट) मल्टी यूजर यानी बहु उपयोक्ता सॉफ्टवेयर का विकास भी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत महालेखा नियंत्रक के एनआईसी सेल ने किया है। इस समय 6 वेतन और लेखा अधिकारी काम्पैक्ट साफ्टवेयर का उपयोग कर वरहे हैं।
- **वेबसाइट का मासिक खर्च :** सूचना और प्रसारण की मासिक प्राप्तियों और खर्च का सारांश मंत्रालय की वेबसाइट पर (न्यू सीसीए शीर्षक के अंतर्गत) प्रदर्शित किया जा रहा है और इसके साथ-साथ पिछले वर्ष के आंकड़े भी दिखाये जाते हैं।
- **ईसीएस के जरिए वेतन का भुगतान :** सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक के स्टाफ के वेतन का भुगतान जुलाई 2005 से इलेक्ट्रॉनिक क्लीरिंग स्कीम (ईसीएस) से किया जा रहा है। अन्य आहरण और संवितरण अधिकारियों को भी चैक/नकद भुगतान की बजाय ईसीएस के जरिए वेतन लेने को प्रेरित किया जा रहा है।

आंतरिक लेखा परीक्षा

लेखा परीक्षा अनावश्यक खर्च पर रोक लगाने और वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए मार्गदर्शन करने का माध्यम है।

सुविधा और किफायत को ध्यान में रखते हुए चार आंचलिक आंतरिक लेखा परीक्षा दल गठित किए गए हैं, जिनके नाम हैं : उत्तर अंचल, दक्षिण अंचल, पश्चिम अंचल और पूर्वी अंचल आंतरिक लेखा परीक्षा दल। ये क्रमश: नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में स्थित हैं। प्रत्येक आंचलिक आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यालय का प्रमुख एक लेखा अधिकारी होता है। मुख्यालय का आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध उत्तरी अंचल का आंतरिक लेखा परीक्षा कराने के साथ-साथ शेष तीन क्षेत्रीय दलों का आंतरिक लेखा परीक्षा कराता है।

2005-06 में 77 इकाइयों की सामान्य लेखा परीक्षा और 2 इकाइयों की विशेष लेखा परीक्षा कराई गई। आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वसूली/विनियमन/संशोधन से संबंधित कुछ ऐसी बड़ी अनियमितताओं

को रोकने में मदद मिली जिनमें काफी बड़ी धनराशि शामिल थी। इसका ब्यौरा इस प्रकार है :

1.	सरकारी देयताओं की वसूली न होना	3381.87 लाख रुपये
2.	अधिक भुगतान	0.71 लाख रुपये
3.	मशीनरी का इस्तेमाल न होना/फालतू सामान	56.72 लाख रुपये
4.	हानि/अनावश्यक खर्च	308.73 लाख रुपये
5.	अनियमित खर्च	78.69 लाख रुपये
6.	अग्रिम राशि का समायोजन न होना	628.04 लाख रुपये
7.	अनियमित खरीद	125.76 लाख रुपये
8.	सरकारी धन बकाया	179.29 लाख रुपये
9.	महंगी भंडार वस्तुओं का हिसाब न रखना	12.13 लाख रुपये
10.	विशेष प्रकार की अन्य वस्तुएं	1262.06 लाख रुपये
	योग	**6034.00 लाख रुपये**

सतर्कता

मंत्रालय का सतर्कता ढांचा सचिव की समग्र निगरानी में कार्य कर रहा है। इस कार्य में मुख्य सतर्कता अधिकारी (संयुक्त सचिव के स्तर पर), निदेशक/उप सचिव (सतर्कता) और अन्य अधीनस्थ अधिकारी उनकी सहायता करते हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्वीकृति से प्रसार भारती के लिए अलग से एक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है जो आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों की सतर्कता संबंधी गतिविधियों का पर्यवेक्षण करता है। मंत्रालय के अन्य संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और पंजीकृत सोसाइटियों में भी अलग से सतर्कता ढांचा विद्यमान है।

भ्रष्टाचार की आशंका को कम से कम करने के लिए प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के समन्वित प्रयास किए गए। संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों पर कड़ी निगाह रखी गई। संवेदनशील पदों पर तैनात स्टाफ के तबादले के भी प्रयास किए गए। नियमों और प्रक्रियाओं का सही-सही अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित और अधिक निरीक्षण किए गए। अप्रैल 2006 से दिसंबर 2006 तक 70 नियमित और 83 औचक निरीक्षण किए गए और 90 लोगों की पहचान निगरानी में रखने के लिए की गई। इसके अलावा मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों में कुल 40 क्षेत्रों को निगरानी के लिए चुना गया। अवधि के दौरान मंत्रालय और उसकी मीडिया इकाइयों के राजपत्रित स्तर के अधिकारियों की 'संदिग्ध निष्ठा' और 'सहमत' श्रेणी की सूचियां तैयार की गई और इन सूचियों की समीक्षा का वार्षिक कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो के परामर्श से किया गया। देश की स्वतंत्रता की 50वीं जयंती पर सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किए गए अभियान को जारी रखते हुए मुख्य सतर्कता अधिकारी को प्रधान मंत्री कार्यालय से अग्रसारित शिकायतों से निपटने के लिए संपर्क अधिकारी नामित किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त शिकायतों पर लगातार निगरानी रखी जाती है और प्रधानमंत्री कार्यालय को आवधिक रिपोर्ट भेजी जाती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों ने सप्ताह पर चलने वाले सतर्कता सप्ताह का भी आयोजना किया।

अप्रैल 2006 से दिसम्बर 2006 तक मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों में विभिन्न स्रोतों से 290 नई शिकायतें प्राप्त हुई। इनकी जांच की गई और 84 मामलों में प्राथमिक जांच के आदेश दिए गए। 42 मामलों में प्राथमिक जांच के आदेश दिए गए। 42 मामलों में प्राथमिक जांच रिपोर्ट भी इसी अवधि के दौरान प्राप्त हो गईं। 34 मामलों में बड़े दंड के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई शुरू की गई और 3 मामलों में छुटपुट दंड की कार्रवाई प्रारंभ की गई। 10 मामलों में बड़ी सजाएं दी गई हैं और 6 मामलों में छुटपुट सजा दी गई। आलोच्य अवधि में 24 कर्मचारियों को निलंबित किया गया और 25 मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई की गई।

अनुशासनात्मक कार्रवाई के लंबित मामलों के बारे में मासिक रिपोर्ट और दंडात्मक कार्रवाई के लिए लंबित स्वीकृति के बारे में पाक्षिक रिपोर्ट सभी मीडिया इकाइयों से नियमित रूप से मंगाई जाती है और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अग्रसारित की जाती है। लंबित सतर्कता मामलों के बारे में विस्तृत सूचना नियमित रूप से केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजी गई। इसके अलावा मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी/सचिव द्वारा समय समय पर समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है जिनमें मंत्रालय तथा उसकी मीडिया इकाइयों में लंबित अनुशासनात्मक मामलों पर चर्चा की जाती है।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

वेतन और भत्तों पर अनावश्यक खर्च

फिल्म प्रभाग ने आठ फालतू कर्मचारियों को मंत्रालय के अन्य कार्यालयों या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के फालतू प्रकोष्ठ को

नहीं भेजा जिससे 1999-2000 और 2004-05 के बीच इन कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर 32.67 लाख रुपये का अनावश्यक खर्च हुआ।

(2006 की रिपोर्ट सं. 2 का पैरा सं. 9.1)
ट्रांजेक्शन लेखा परीक्षा टिप्पणी

एक निर्माता को अनावश्यक लाभ

एक धारावाहिक के प्रोडयूसर को जुलाई 2001 तक अनियमित रूप से मुफ्त में अतिरिक्त एयर टाइम टेकर अनावश्यक रियायत दी गई। प्रसारण की बाद की अवधि मे प्रोडयूसर को रियायती प्रसारण शुल्क और मुफ्त कॉमर्शियल टाइम का उसी तरह से फायदा दिया जाता रहा। इससे प्रोडयूसर को 10.66 करोड़ रुपये का वित्तीय फायदा हुआ।

(2006 की रिर्पोट सं. 3 का पैरा सं. 9.1)
स्वायत्त निकाय

टीवी ट्रांसमिशन प्रणाली और स्टूडियो का चालू न होना

दूरदर्शन मार्च 2001 से सितम्बर 2005 के बीच निर्मित 9 निम्न शक्ति टीवी ट्रांसमिशन प्रणालियों के लिए संचालन तथा अनुरक्षण कर्मचारियों की नियुक्त नहीं कर सका। इसके परिणाम स्वरूप उपकरणों के काम में न आने से ये न केवल बेकार पड़े रहे बल्कि 6.74 करोड़ रुपये का निवेश भी बेकार रहा। यही नहीं, दूरदर्शन मार्च 2001 से मार्च 2005 के दौरान 22.55 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित स्टूडियो को उनके पूरा होने से 12 से 48 महीने के बाद भी चालू नहीं कर पाया।

(2006 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा सं. 9.2)
स्वायत्त निकाय

समयपूर्व खरीद

दूरदर्शन द्वारा समय से पूर्व दो ट्रांसमिटर खरीदे जाने से जुलाई 2005 तक दो से चार साल के लिए 3.82 करोड़ रुपये बेकार रहे। इस दौरान उपरकरणों की गारंटी अवधि भी समाप्त की गई।

(2006 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा सं. 9.3)
स्वायत्त निकाय

धनराशि निरुद्ध किया जाना

दूरदर्शन द्वारा दिल्ली विद्युत बोर्ड से 62.39 लाख रुपये की राशि की वापसी के दावे के बारे में आगे कार्रवाई न किए जाने से यह राशि 5 साल 5 महीने से भी अधिक समय से निरुद्ध रही और इसके परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में 34.53 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

(2006 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा सं. 9.4)
स्वायत्त निकाय

कर्मचारी आवासों पर अदूरदर्शितापूर्ण निवेश

सत्यजित राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कोलकाता ने आवश्यकता का सही तरीके से आंकलन किए बिना 41 कर्मचारी आवासों पर 2.20 करोड़ रुपये का निवेश किया। परिणामस्वरूप कर्मचारियों की ओर से मांग बहुत कम होने के कारण कई स्टाफ क्वार्टर खाली पडे रहे जबकि संस्थान को उनके समान किराया भत्ते पर 27.47 लाख रुपये खर्च करने पड़े।

(2006 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा सं. 9.5)
स्वायत्त निकाय

दूरदर्शन और आकाशवाणी की आमदनी की प्रणाली

दूरदर्शन

दूरदर्शन 2004-05 में 701.34 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य की तुलना में केवल 665.27 करोड़ रुपये की आय अर्जित कर सका। यह अपने नेटवर्क में जबरदस्त विकास का लाभ उठाकर उसी अनुपात में आमदनी में नाकामयाब रहा।

रेट कार्ड में संशोधन करते समय प्रायोजकों को अतिरिक्त मुफ्त वाणिज्यिक समय (एफसीटी) देने से दूरदर्शन को 27.87 लाख रुपये का लाभ हुआ जबकि प्रायोजकों ने 6.55 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया।

सीडीएस नई दिल्ली और डीडीके मुंबई को फीचर फिल्मों के प्रसारण में एफसीटी के उपयोग का ध्यान न रखने में क्रमश: 12.56 करोड़ रुपये और 6.52 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

एफसीटी देने में अनियमितताओं से 100 मामलों में 8.88 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

डीसीएस नई दिल्ली को रेट कार्ड में निर्धारित बढ़ी हुई दरों से प्रसारण शुल्क न लेने से 5.03 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

कार्यक्रमों की विषय वस्तु की प्रसारण अवधि में निगरानी न करने से 4.01 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

दूरदर्शन ने बाहरी प्रोडयूसरों को बिना किसी अनुबंध के अपलिंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जिससे 3.03 करोड़ की वसूली नहीं हो पाई।

दूरदर्शन द्वारा राजस्व वसूली के लिए समय पर कार्रवाई न करने से 513.36 करोड़ रुपये की लेनदारी बकाया पड़ी है।

बिल बनाने, देर से भुगतान होने पर ब्याज न वसूलने और ब्याज वसूल

करने से संबंधित प्रावधानों का सही-सही इस्तेमाल न करने से ब्याज के रूप में 1.17 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

दूरदर्शन केन्द्र तिरुअनंतपुरम में अगस्त 2002 में 2.95 करोड़ रुपये की लागत से एक स्टूडियो बनाया गया लेकिन यह दिसम्बर 2005 तक चालू नहीं हो पाया था।

अभिलेख/रजिस्टरों का रख-रखाव बड़ा दोषपूर्ण था। प्रसार भारती के बनने के बाद से अधिकतर मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं कराई गई है।

आकाशवाणी

2004-05 में आकाशवाणी 251.15 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले केवल 136 करोड़ रुपये की आमदनी कर सकी। यह लक्ष्य आकाशवाणी केन्द्रों को उनके पिछले वर्ष के कार्य निष्पादन की बजाय उनके संभावित बाजार के अनुसार युक्तिसंगत तरीके से समूहबद्ध करने के बाद निर्धारित किया गया था। देश भर में आकाशवाणी के 215 केंद्र हैं जबकि प्राइवेट प्रसारकों के केवल 22 स्टेशन हैं। ऐसे में आकाशवाणी के भारी-भरकम बुनियादी ढांचे के मुकाबले आमदनी में उसकी केवल 49 प्रतिशत की हिस्सेदारी निजी प्रसारकों के मुकाबले बहुत कम है।

2001-02 की तुलना में 2004-05 में चार महानगरों में एफएम चैनलों के राजस्व में भारी गिरावट आई है (मुंबई में 98 प्रतिशत तक)।

आकाशवाणी के पास रेट कार्ड में संशोधन के लिए कोई पूर्वनिर्धारित समय सीमा नहीं है। निजी एफएम चैनलों द्वारा वसूली जाने वाली विज्ञापन दरों को देखते हुए आकाशवाणी के रेट कार्ड में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दरें तय करने की कोई युक्तिसंगत नीति नहीं है। उल्टे दरों को अस्थायी रूप से बढ़ाया गया और कुछ मामलों में तो बढ़ातरी वापस ले ली गई।

औपचारिक समझौता न हो पाने से आकाशवाणी 2004 में वित मंत्रालय द्वारा प्रायोजित विशेष प्रचार अभियान 'इरादा नये भारत का' के लिए 84.12 लाख रुपये के ब्याज सहित 5.19 करोड़ रुपये की राशि वसूल नहीं कर पाया।

आकाशवाणी एजेंसियों/विज्ञापनदाताओं से 18.63 करोड़ रुपये वसूल करने में असफल रही जिसमें से कुछ लेनदारियां तो 199 से भी पहले की थीं। कुछ मामलों में मामला न्यायालय के विचाराधीन था जबकि कुछ अन्य मामलों में एजेंसियों का कोई अता-पता ही नहीं था।

सीएसयू मुंबई ने ऐसी एजेंसियों को जिनकी तरफ लेनदारी बकाया थी, 1.04 करोड़ रुपये के अग्राह्य प्रोत्साहन प्रदान किए।

बिल प्रस्तुत करने और रसीद प्रसार भारती के मुख्य लेखे में जमा कराने में देरी के मामले सामने आए। अकेले सीबीएस पटना में इससे 2001-05 में ब्याज के रूप में 72.76 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

(2006 की रिपोर्ट सं. 19)
निष्पादन लेखा परीक्षा

3

सूचना क्षेत्र

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग का कार्य पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकों आदि की सहायता से मंत्रालय की मीडिया इकाइयों को सामग्री के संग्रह, संकलन और तैयार करने में मदद करना है। प्रभाग मीडिया इकाइयों के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारियों का संकलन करता है और समसामयिक तथा अन्य विषयों पर दिशा-निर्देशों और पृष्ठभूमि सामग्री तैयार करता है। 1945 में गठित गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय और उसके अंतर्गत आने वाली विभिन्न मीडिया इकाइयों के लिए सूचनाएं जुटाने वाली इकाई के रूप में कार्य करता है। प्रभाग जन संचार माध्यमों के क्षेत्र में रुझानों का अध्ययन करता है और जन संचार में संदर्भ तथा प्रलेखन सेवा संचालित करता है। यह मंत्रालय, उसकी मीडिया इकाइयों और जन संचार के क्षेत्र में कार्यरत अन्य संगठनों के उपयोग के लिए पृष्ठभूमि, संदर्भ और अनुसंधान सामग्री उपलब्ध कराता है। प्रभाग भारतीय जन संचार संस्थान के सहयोग से भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण संबंधी पक्ष को भी देखता है।

प्रभाग दो वार्षिक संदर्भ ग्रंथों का संकलन करता है। ये हैं : केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों तथा सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में वर्ष के दौरान हुई प्रगति और विकास के बारे में **भारत : एक संदर्भ ग्रंथ (इंडिया-ए रेफरेंस एनुअल)** और देश में जन संचार के बारे में विस्तृत प्रकाशन: **भारत में जन संचार (मास मीडिया इन इंडिया)**। माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने इस संदर्भ ग्रंथ के 51वें हिन्दी/अंग्रेजी संस्करणों (भारत-2007/इंडिया-2007) का 4 जनवरी 2007 को विमोचन किया।

प्रभाग *डायरी आफ इवेंट्स* नाम से एक नियमित पाक्षिक सेवा भी संचालित करता है। इसमें संदर्भ और प्रलेखन के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय घटनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। प्रभाग विशिष्ट पत्रिकाओं की एक मासिक रिपोर्ट भी तैयार करता है और स्क्रीनिंग के बाद इसे मंत्रालय को प्रेषित करता है। ये ऐसी पत्रिकाएं होती हैं जिनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का हिस्सा होता है और कुछ खास विषयों पर इन्हें भारत में प्रकाशित करने की इजाजत दी जाती है। प्रभाग इस बात की निगरानी करता है कि सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का इन पत्रिकाओं द्वारा कड़ाई से पालन हो रहा या नहीं।

संदर्भ पुस्तकालय

एक सुसज्जित अनुसंधान और संदर्भ के क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी भी संगठन के लिए जीवन रेखा की तरह है। गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों को ऐसी सामग्री का संग्रह और संकलन करने तथा इसे तैयार करने में मदद करता है जिसके लिए अनुसंधान आवश्यक है। प्रभाग का सुसज्जित पुस्तकालय है जिसमें विभिन्न विषयों पर दस्तावेज का विशाल संकलन, कुछ चुनी हुई पत्रिकाओं के जिल्दबंद अंक और मंत्रालय की विभिन्न रिपोर्टें उपलब्ध हैं। यह संकलन पाठकों, समितियों और आयोगों के लिए व्यक्तिगत सहायता के रूप में कार्य करता है। इस संग्रह में पत्रकारिता, जन संपर्क, विज्ञापन और श्रव्य-दृश्य मीडिया पर विशिष्ट पुस्तकें, सभी प्रमुख विश्व कोष पुस्तकमालाएं, वार्षिक ग्रंथ और समसामयिक लेख आदि शामिल हैं। पुस्तकालय के उपयोग की सुविधा भारत और विदेशों के मान्यता प्राप्त पत्रकारों और भारत सरकार के अधिकारियों को भी उपलब्ध है। वर्ष 2006-07 के दौरान (दिसम्बर 2006 तक) पुस्तकालय में 118 नयी पुस्तकें आईं जिनमें से 57 हिन्दी में थीं। बड़ी संख्या में नियमित पाठकों के अलावा पुस्तकालय के करीब 1075 सदस्य भी हैं।

जनसंचार पर राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र

प्रभाग के एक अंग के रूप में अपनी सामयिक पत्रिका सेवा के माध्यम से जनमाध्यमों में हो रही गतिविधियों तथा रुझानों के बारे में सूचनाओं को एकत्र करने, उनका अर्थ निकालने तथा उनके वितरण हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ

समिति की सिफारिशों के मद्देनजर जनसंचार पर राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र (एनडीसीएमसी) का सृजन किया गया था। यह केन्द्र प्रमुख समाचारों, लेखों तथा जनसंचार पर उपलब्ध अन्य सूचना सामग्री का प्रलेखन करता है। केन्द्र का वर्तमान कार्य देश भर में जनसंचार के विकास हेतु सूचनाओं का एकत्रीकरण और प्रलेखन करना तथा उनका वितरण करना है।

एकत्र की गई सूचनाओं को एक स्थान पर रख कर उनका वितरण (प्रसार) विभिन्न सेवाओं के माध्यम से किया जाता है। इनमें चुनिंदा लेखों हेतु की गई टिप्पणी तालिका के लिए **करेंट अवेयरनेस सर्विस,** लेखों की विषय टिप्पणी तालिका हेतु - **बिबलोग्राफी सर्विस,** फिल्म उद्योग की विभिन्न गतिविधियों के निचोड़ हेतु - **बुलेटिन ऑन फिल्म्स,** प्रख्यात मीडिया व्यक्तियों की जीवनियों पर रेफरेंस इनफार्मेशन सर्विस **हू इज हू इन मास मीडिया;** जनसंचार कर्मियों को दिए गए पुरस्कारों के विवरण हेतु, आनर्स कन्फर्ड ऑन मास कम्युनिकेटर्स तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया पहलुओं पर **मीडिया अपडेट** शामिल हैं। केन्द्र द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान (दिसम्बर 2005 तक) ऐसी 38 सेवाएं प्रदान की गईं।

एनडीसीएमसी एक संदर्भ पुस्तक ''मास मीडिया इन इंडिया'' का संकलन और संपादन भी करता है। इस वार्षिक ग्रंथ में जन माध्यमों के विभिन्न पक्षों पर लेख, केन्द्र, राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के मीडिया संगठनों की स्थिति पर सूचना दी जाती है। इसमें प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के बारे में भी सामान्य सूचनाएं शामिल हैं।

प्रशिक्षण

भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग को भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी विशेष रूप से सौंपी गई है। दसवीं योजना अवधि में प्रभाग ने अनेक प्रशिक्षण पाठयक्रमों का आयोजन किया।

वर्ष 2006-07 के दौरान पाठ्यक्रम

- भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली में 17-21 अप्रैल तक क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठयक्रम : यह पाठ्यक्रम वरिष्ठ वेतनमान या इससे ऊपर के स्तर के 12 अधिकारियों के लिए तैयार किया गया था और इसका उद्देश्य उनकी जानकारी में वृद्धि करना और संचार और क्षेत्र में भारी बदलाव के बाद अंतर-वैयक्तिक और ग्रामीण संचार के क्षेत्र में नवीनतम रुझानों व कौशलों से उन्हें अवगत कराना था।

- भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली में 22-26 मई 2006 तक मल्टी मीडिया उपयोग के जरिए प्रेजेंटेशन कौशल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। यह पाठयक्रम 20 क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों के लिए तैयार किया गया था और इसका उद्देश्य संचार, मल्टी मीडिया और सार्वजनिक भाषण के कौशल की जानकारी देना था।

- भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली में 19-23 जून 2006 तक संपादन और प्रकाशन पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम। यह पाठयक्रम प्रकाशन विभाग, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, जन संपर्क निदेशालय (रक्षा), भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय के ग्रुप ए और बी के दस अधिकारियों के लिए था। इसमें उनके संपादन और प्रकाशन कौशल को निखारा गया।

- भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली में 3 से 7 जुलाई 2006 तक पत्र सूचना कार्यालय के अधिकारियों के लिए 'सूचनाओं के प्रसार में नवीनतम प्रवृत्तियां और तकनीकें' विषय पर पुनश्चर्या कार्यक्रम।

- रेडियो और टेलिविजन पत्रकारिता में नवीनतम कौशल और तकनीकों के बारे में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे में 10 से 14 जुलाई 2006 तक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। यह इलेक्ट्रानिक मीडिया के ग्रुप ए और बी के 10 अधिकारियों के लिए तैयार किया गया। इसमें उन्हें अपने कौशल तथा निर्माण, कार्यक्रम और रेडियो व टेलीविजन पत्रकारिता तकनीक में सुधार लाने के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई।

- आईआईएम, लखनऊ द्वारा नई दिल्ली में 4 से 8 सितम्बर तक 2006 तक आयोजित 'मार्केटिंग : विनिंग कान्सेप्ट्स एंड प्रेक्टिसेज' विषय पर पाठ्यक्रम बुनियादी तौर पर दूरदर्शन, आकाशवाणी, प्रकाशन विभाग तथा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के कनिष्ठ प्रशासनिक संवर्ग और उससे ऊपर के 10 अधिकारियों के लिए था। इसका उद्देश्य आम आदमी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मल्टी मीडिया अभियान के बारे में जानकारी देना था।

- भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली में 11 से 24 सितम्बर, 2006 तक ग्रुप बी के अधिकारियों के लिए विशेष

पुनश्चर्या पाठक्रम। यह पाठ्यक्रम ऐसे अधिकारियों के लिए था जिन्हें सेवा में शामिल होते समय कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों के सरकारी कामकाज में बुनियादी कौशलों के विकास और संप्रेषण पर जोर दिया गया।

- भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के अधिकारियों के लिए 18 से 22 दिसम्बर 2006 तक जन सूचना अभियान पाठ्यक्रम। इसे विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और पत्र सूचना कार्यालय के 15 अधिकारियों के लिए तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य इन अधिकारियों को जनता से संबंधित मुद्दों पर मल्टी मीडिया अभियान की जानकारी देना, लोगों को आश्वस्त करने के उनके संप्रेषण कौशल का विकास करना और विभिन्न मीडिया इकाइयों के बीच बेहतर तालमेल कायम करना था।

प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग राष्ट्रीय महत्व के विषयों और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में पुस्तकें, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें और पत्रिकाएं प्रकाशित करता है और उन्हें किफायती दामों पर पाठकों को उपलब्ध कराता है।

विभाग का मुख्यालय सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली में स्थित है और यह अपनी विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों—नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, तिरुअनन्तपुरम स्थित बिक्री केन्द्रों और नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद और बंगलौर स्थित योजना कार्यालयों/बिक्री केन्द्रों के जरिए काम करता है। रोज़गार समाचार और जनरल यूनिट के कार्यालय आर.के. पुरम, नई दिल्ली में स्थित हैं।

पुस्तकें

प्रकाशन विभाग की पुस्तकों के विषय-क्षेत्र में कला, इतिहास, संस्कृति, स्थान और लोग, वनस्पति और जीव-जन्तु, बाल साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, गांधी वांड·मय, विशिष्ट व्यक्तियों की जीवनियों से लेकर भारत-वार्षिक संदर्भ ग्रंथ (इंडिया-ए रेफरेंस एनुअल), प्रेस इन इंडिया और मास मीडिया इन इंडिया जैसे संदर्भ ग्रंथ शामिल हैं। विभाग भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुने हुए भाषणों को भी प्रकाशित करता है।

प्रकाशन विभाग हर वर्ष 120-150 तक पुस्तकें प्रकाशित करता है। अब तक कुल मिलाकर 7700 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। अप्रैल-दिसंबर 2006 की अवधि में अंग्रेजी, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में 75 पुस्तकें प्रकाशित की गईं। इस अवधि में प्रकाशित की गई कुछ प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं—फाइव थाउसेंड इयर्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ए कॅरियर फॉर यू, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उपभोक्ता अधिकार, क्रांतिकारी महिलाएं, संगीत बच्चों के लिए, जलियांवाला बाग, लहरों का कहर, ग्रेट मैन एंड वूमैन ऑफ इंडिया, कल्पना चावला आदि।

पत्रिकाएं

विभाग द्वारा 18 मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं जिनमें हिंदी में बच्चों के लिए पत्रिका 'बाल भारती', हिन्दी और उर्दू में 'आजकल ', हिन्दी एवं अंग्रेजी में 'कुरुक्षेत्र' एवं हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम एवं कन्नड़ में 'योजना' पत्रिकाएं शामिल हैं।

विभाग की पत्रिकाओं की औसत मासिक प्रसार संख्या का तुलनात्मक विश्लेषण सारिणी में दिया गया है। इससे पता चलता है कि पिछले वर्षों में विभाग की सभी पत्रिकाओं की प्रसार संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। इस विवरण से यह भी पता चलता है कि वर्ष 2006-07 की पहली छमाही (सितम्बर 2006 तक) में ही पत्रिकाओं की प्रसार संख्या पिछले वर्ष की प्रसार संख्या को पार कर चुकी है।

बाल भारती

हिन्दी में बच्चों की लोकप्रिय पत्रिका 'बाल भारती' का 1948 से नियमित रूप से प्रकाशन किया जा रहा है। इसका प्रमुख लक्ष्य कहानियों, कविताओं, चित्र-कथाओं एवं सूचनाप्रद लेखों के माध्यम से बाल पाठकों का मनोरंजन करने के साथ ही उनमें मानवीय मूल्यों और वैज्ञानिक सोच का विकास करना है। 'बाल भारती' ने जनवरी 2007 में बच्चों के लिए कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसका प्रयोजन नन्हे-मुन्नों की साहित्यिक प्रतिभा को उजागर करना और उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना लाना था।

आजकल

प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका 'आजकल' हिन्दी और उर्दू में निकलती है। विभाग द्वारा 'आजकल' के ऐसे कई विशेषांक निकाले गए हैं जिनमें भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के विविध स्वरूपों की झांकी दिखती है। 'आजकल (हिंदी)' ने फरवरी 2006 में 'काशी' और जुलाई 2006 में 'भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष' विषय पर विशेषांक प्रकाशित किए। नवंबर 2006 का अंक बाल साहित्य पर केन्द्रित था। हिंदी की

प्रसिद्ध साहित्यकार महादेवी वर्मा की जन्मशती के अवसर पर मार्च 2007 का अंक महादेवी वर्मा विशेषांक के रूप में निकाला जा रहा है। 'आजकल (उर्दू)' ने जनवरी 2007 के अंक में नोबल पुरस्कार विजेताओं और फरवरी 2007 में मिर्जा गालिब की जन्म शती के सिलसिले में विशेषांक निकाले हैं।

योजना

सामाजिक-आर्थिक मुद्दों को समर्पित प्रकाशन विभाग की प्रमुख पत्रिका 'योजना' के प्रकाशन का यह 50वां साल है। तेरह भाषाओं में एक साथ प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के नागरिकों, विशेषकर अर्ध-शहरी/छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों में विभिन्न विकास योजनाओं तथा सामयिक आर्थिक विषयों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष के दौरान प्रकाशित विभिन्न अंकों में किसानों द्वारा आत्महत्याओं के परिप्रेक्ष्य में कृषि संकट और प्रभावित राज्यों के लिए प्रधानमंत्री का राहत पैकेज, प्रधानमंत्री की रूस यात्रा, आठ प्रमुख कार्यक्रम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन, भारत निर्माण और सूचना का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है।

वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 (सितंबर 2006 तक) के दौरान पत्रिकाओं की मासिक औसत प्रसार संख्या (मुद्रित प्रतियां)

क्र.सं.	पत्रिका का नाम (भाषाएं)	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (सितंबर 2006 तक)
1	आजकल (हिंदी)	4518	4480	6667	6622
2	आजकल (उर्दू)	2086	2043	2196	2212
3	बाल भारती (हिंदी)	4747	3762	9121	12058
4	कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी)	13146	15335	17629	18525
5	कुरुक्षेत्र (हिंदी)	20807	24608	30208	30783
6	योजना (अंग्रेजी)	20807	24608	30208	29475
7	योजना (हिंदी)	24029	24440	28977	29475
8	योजना (उड़िया)	729	604	915	975
9	योजना (पंजाबी)	223	221	286	550
10	योजना (उर्दू)	241	322	417	416
11	योजना (असमिया)	500	500	500	500
12	योजना (बांग्ला)	2392	3633	5767	6283
13	योजना (गुजराती)	2850	4758	5119	5101
14	योजना (कन्नड़)	1100	783	1233	1916
15	योजना (मलयालम)	604	600	600	600
16	योजना (मराठी)	2304	2725	3221	3156
17	योजना (तमिल)	15550	15967	16493	17333
18	योजना (तेलुगु)	4000	5314	4998	4770
	कुल योग	112966	124506	151546	159625

जम्मू-कश्मीर सरकार के सहयोग से पत्रिका में एक स्तंभ—**जे एंड के विंडो** शुरू किया गया है ताकि इस राज्य में व्यापार के अवसरों, आर्थिक गतिविधियों की संभावनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। एक अन्य नया स्तंभ—'**बेस्ट प्रैक्टिसेस**' भी प्रारंभ किया गया है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों, व्यक्तियों और अन्य समूहों द्वारा की गई पहल, सफलता की कहानियों के बारे में जानकारी दी जाती है। '**शोधयात्रा**' शृंखला के लिए योजना को 2006 का ज्ञान मीडिया पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस स्तंभ का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा अपनी बेहतरी के लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकियों को प्रचारित करना है। 'योजना' ने हर वर्ष अपना दिसंबर अंक देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र को समर्पित करने का निर्णय किया है। दिसंबर 2006 का अंक पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य मिज़ोरम पर विशेषांक के रूप में निकाला गया। जनवरी 2007 का अंक 'योजना' का स्वर्ण जयंती अंक था। इस विशेषांक में पिछले 50 वर्षों में 'योजना' में प्रकाशित चुने हुए लेखों को शामिल किया गया।

वर्ष के दौरान सरकारी-निजी भागीदारी के अंतर्गत पहले कदम के रूप में योजना और कोमेट टेक्नोलोजीज़ (ई-गवर्नेंस में विशेषज्ञता प्राप्त बंगलौर की एक कंपनी) ने कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के फायदे पहुंचाने पर सहमति व्यक्त की है।

'डू यू नो' यानी 'क्या आप जानते हैं' शीर्षक से एक नई शृंखला शुरू की गई है, जिसमें आर्थिक मुद्दों से संबद्ध बुनियादी तथ्यों को सरल भाषा में विश्लेषित किया जाता है।

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित 'कुरुक्षेत्र' एकमात्र पत्रिका है, जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्यक्रमों, नीतियों और विकास के उपायों के कार्यान्वयन के बारे में विचारों के आदान-प्रदान के मंच के रूप में सेवाएं प्रदान कर रही है। 'कुरुक्षेत्र' प्रकाशन विभाग द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से प्रकाशित की जाती है। इस वर्ष वार्षिक अंक 'भारत निर्माण' पर केन्द्रित था जो गांवों में मूलभूत सुविधाओं के विकास की सरकार की समयबद्ध योजना है।

एम्प्लायमेंट न्यूज (रोजगार समाचार)

विभाग द्वारा अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में रोजगार समाचार/एम्प्लायमेंट न्यूज का प्रकाशन भी किया जाता है जिसमें सरकारी और अर्ध-सरकारी संगठनों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, स्वायत्तशासी निकायों, बैंकों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाती है। इस साप्ताहिक पत्रिका की लगभग 6.5 लाख प्रतियां प्रकाशित होती हैं। देशभर में इसका 350 बिक्री एजेंटों तथा 6000 प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं का नेटवर्क है।

वर्ष 2006-07 की पहली छमाही के दौरान 25.63 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से काफी अधिक है। वर्ष 2004-05 में प्राप्त कुल राजस्व 39.52 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2005-06 के दौरान बढ़कर 41.10 करोड़ रुपये हो गया। प्रति अंक पृष्ठों की औसत संख्या भी वर्ष 2004-05 के 48.06 से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 50.61 हो गई। लागत मूल्य में हुई वृद्धि के बावजूद एम्प्लाइमेंट न्यूज द्वारा अर्जित सकल राजस्व जो वर्ष 2003-04 में 15.46 करोड़ रुपये था, वर्ष 2005-06 में 15.50 करोड़ रुपये हो गया। एम्पलाइमेंट न्यूज का मूल्य पिछले कई वर्षों से 5 रुपये प्रति अंक था, जिसे अब बढ़ाकर 6.50 रुपये प्रति अंक कर दिया गया है।

एम्पलाइमेंट न्यूज की वेबसाइट www.employmentnews.gov.in शुरू की गई। इस वेबसाइट में वर्तमान अंक के अतिरिक्त पिछले अंकों में प्रकाशित रिक्त स्थानों के बारे में दी गई जानकारी के अलावा प्रकाशित लेख तथा अन्य उपयोगी जानकारी भी मिलती है। व्यवसाय के विभिन्न विकल्पों के बारे में युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए वेबसाइट के माध्यम से पाठकों के प्रश्नों के जवाब ऑनलाइन दिए जा रहे हैं। वेबसाइट के जरिए मेल अलर्ट सेवाएं भी शुरू की गई हैं, जिनसे एम्प्लाइमेंट न्यूज में प्रकाशित नौकरियों के बारे में ग्राहकों को ई-मेल के जरिए जानकारी भेजी जाती है। वेबसाइट के जरिए दी जा रही इन निशुल्क सेवाओं का लाभ 20,000 व्यक्ति उठा रहे हैं।

जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के बीच अपनी पैठ बनाने के एक कदम के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र के पुस्तकालयों, शिक्षा संस्थानों तथा सरकारी कार्यालयों में एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार की प्रतियां निशुल्क भेजी जाती हैं।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कार

जनसंचार पर हिन्दी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किए गए 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कार' अब बाल साहित्य तथा महिलाओं की समस्याओं एवं राष्ट्रीय एकता पर मौलिक लेखन के लिए भी दिए जाते हैं।

विपणन

प्रकाशन विभाग नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, तिरुअनंतपुरम, पटना और लखनऊ स्थित अपने बिक्री केंद्रों और करीब 400 एजेंटों के माध्यम से पुस्तकों, पत्रिकाओं, और सीडी आदि की बिक्री करता है। अहमदाबाद, बंगलौर और गुवाहाटी स्थित 'योजना' पत्रिका के कार्यालय बिक्री केंद्र के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त विभाग प्रमुख पुस्तक मेलों, जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला आदि में भी भाग लेता है।

वर्ष 2005-06 के दौरान पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री से 414.16 लाख रुपये राजस्व के रूप में प्राप्त हुए। यह राशि वर्ष 2004-05 में अर्जित राजस्व के मुकाबले 92.92 लाख रुपये अधिक है। चालू वित्त वर्ष के दौरान भी राजस्व में बढ़ोतरी का यह सिलसिला जारी है।

आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण

वर्ष 2006-07 के लिए आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण के वास्ते कोई धन आवंटित नहीं किया गया। फिर भी प्रभाग ने आई-मैक कम्प्यूटर, प्रिंटर्स, स्कैनर्स और अन्य कम्प्यूटर हार्डवेयर खरीदे। 30 प्रयोक्ताओं के लिए कोरल ड्रा, ई-टैक्स, लेन (एल ए एन) फैसेलिटी जैसे साफ्टवेयर भी खरीदे गए। विभाग की वेबसाइट http://publicationsdivision.nic.in है। विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं के विवरण, पुस्तक उद्योग की प्रमुख घटनाओं तथा आगामी पुस्तक प्रदर्शनियों/पुस्तक मेलों के बारे में जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है।

विभाग के दो ई-मेल पते : publicationsdivision@hub.nic.in तथा publicationsdivision@sb.nic.in हैं, जिनका प्रयोग पुस्तकों की खरीद का आदेश देने तथा जरूरी जानकारी हासिल करने के लिए किया जा सकता है।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) केन्द्र सरकार की बहु-माध्यम प्रचार करने वाली केन्द्रीय एजेंसी है। निदेशालय सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और करीब 200 सार्वजनिक उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों की संचार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उन्हें एक ही स्थान से किफायती दामों पर सभी सेवाएं

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी से 19 दिसम्बर, 2006 को नई दिल्ली में वर्ष 2007 के सरकारी कलैंडर की प्रथम प्रति ग्रहण करते हुए; सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी भी इस अवसर पर उपस्थित थे

उपलब्ध कराता है। यह शहरी तथा ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों की जनता को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देता है और जागरूक बनाता है तथा उन्हें विकास संबंधी गतिविधियों में भागीदारी निभाने को प्रेरित करता है।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय विज्ञापनों, मुद्रित सामग्री, दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों, बाह्य प्रचार और प्रदर्शनियों के माध्यम से जनता तक अपनी सेवाएं पहुंचाता है। निदेशालय अपनी विज्ञापन और प्रचार नीति में राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, एड्स जागरूकता, महिला सशक्तीकरण, बालिका उत्थान, अल्प बचत, उपभोक्ता मामले, साक्षरता, रोजगार, आयकर, रक्षा, पर्यावरण, सड़क सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण और हस्तशिल्प आदि पर विशेष ध्यान देता है।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के मुख्यालय के विभिन्न स्कंध इस प्रकार हैं : प्रशासन, बजट और लेखा, अभियान, विज्ञापन, बाह्य प्रचार, मुद्रित प्रचार, प्रदर्शनी, इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग केन्द्र, मास मेलिंग, श्रव्य-दृश्य एकांश और डीटीपी सुविधाओं से युक्त डिजाइन स्टूडियो।

निदेशालय के बंगलौर और गुवाहाटी में दो क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो इन क्षेत्रों में निदेशालय की गतिविधियों में समन्वय करते हैं। इसके अलावा कोलकाता और चेन्नई में इसके दो क्षेत्रीय वितरण केन्द्र हैं जो क्रमश: पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में प्रचार सामग्री के वितरण की देखरेख करते हैं।

निदेशालय का देश भर में फैला 35 क्षेत्रीय प्रदर्शनी इकाइयों का नेटवर्क है। डीएवीपी की क्षेत्रीय प्रदर्शनी इकाइयां सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती हैं। क्षेत्रीय कर्मचारी देश के दूर-दराज के इलाकों में सामाजिक और विकास संबंधी विषयों पर प्रदर्शनियों का आयोजन कर केन्द्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का प्रचार-प्रसार करते हैं।

प्रमुख गतिविधियां

वर्ष के दौरान निम्नलिखित विषयों पर तीन नये नीति-दस्तावेज जारी किये गये :

(1) मुद्रित मीडिया के लिए 1 जून 2006 से लागू नयी विज्ञापन नीति

(2) ऑडियो-वीडियो प्रोड्यूसरों को पैनलबद्ध करने की नीति, 2006

(3) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों को पैनलबद्ध करने की नीति, 2006

डीएवीपी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को डिजिटलाइज कर रहा है। इनमें समाचार पत्रों के विज्ञापनों के लिए इलेक्ट्रानिक क्लीअरेंस योजना (ईसीएस) प्रमुख है। इसके अलावा सजावटी विज्ञापनों के रिलीज ऑर्डर भी अब वेबसाइट पर इलेक्ट्रानिक तरीके से जारी किये जाते हैं ताकि दूर-दराज के अखबार/प्रकाशन भी इन्हें आसानी से ले सकें।

निदेशालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में एक मल्टी मीडिया प्रचार अभियान शुरू किया। मंत्रालय के सहयोग से निदेशालय ने मिशन के बारे में अखबारों के विज्ञापनों के साथ-साथ विस्तृत श्रव्य-दृश्य प्रचार की योजना तैयार कर उस पर अमल किया। नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 'स्वस्थ माता, स्वस्थ शिशु और स्वस्थ राष्ट्र' नाम की प्रदर्शनी आयोजित की गयी। इसे केन्द्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा बनाये गये मंडपों में सर्वश्रेष्ठ मंडप के लिए स्वर्ण पदक मिला। पल्स पोलियो टीकाकरण, एचआईवी/एड्स, तम्बाकू निषेध, बेटी बचाओ, शिशु को स्तनपान, मलेरिया/पाइलेरिया, चिकनगुनिया/डेंगू उन्मूलन, रक्तदान और बाल स्वास्थ्य जैसे विभिन्न विषयों पर प्रचार अखबारों में विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार किया गया। एचआईवी/एड्स जागरूकता और रक्तदान के बारे में भी मल्टी मीडिया प्रचार अभियान के तहत समाचार पत्रों को विज्ञापन जारी किये गए और नाको के लिए फोल्डर, पुस्तिकाएं तथा पोस्टर छपवा कर बांटे गए। डीएवीपी ने देश भर में एचआईवी/एड्स जागरूकता के बारे में 76 प्रदर्शनियां आयोजित कीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में कई विज्ञापन जारी किए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना और सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के बारे में अखिल भारतीय आधार पर सजावटी विज्ञापन जारी किये गये। आकाशवाणी पर हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में दो प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम 'अब मंजिल दूर नहीं' और 'नयी आशाएं, नयी दिशाएं' प्रसारित किए गए। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 'गीत गूंजे गांव गांव' नाम का लोक आधारित प्रायोजित कार्यक्रम तैयार किया गया है।

वर्ष 2006 में गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और शहीद दिवस पर समूचे देश के अखबारों में विज्ञापन जारी किए गए। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने के सिलसिले में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने विभिन्न सामाजिक/आर्थिक क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों पर पुस्तिकाएं प्रकाशित कीं। इसके अलावा सरकार की पहल और

केन्द्रीय योजनाओं में प्रगति के बारे में भी 71 अलग-अलग पुस्तिकाएं प्रकाशित की गईं। भारत निर्माण के बारे में समाचार पत्रों के विज्ञापनों और बाह्य प्रचार के माध्यम से अभियान चलाया गया। ई-गवर्नेंस पर सूचना टेक्नोलॉजी अभियान डीएवीपी के पूर्ण सहयोग से चलाया जा रहा है। सीएएस पर कुछ अखबारों में विज्ञापन जारी किए गए।

वित्त मंत्रालय के विभिन्न संगठनों की ओर से करों की अदायगी, सेवा कर, लघु बचत, आयकर विवरण जमा करने की अंतिम तारीख, पैन कार्ड, ई-फाइलिंग से आयकर विवरण भरने जैसे विषयों पर लगातार प्रचार अभियान चलाया गया और अनेक सजावटी विज्ञापन जारी किए गए। साथ ही इन विषयों पर डीएवीपी ने लगातार श्रव्य-दृश्य अभियान भी चलाया। आयकर निदेशालय (आरएसपी एंड पीआर) की ओर से 'टैक्सेशन आफ सैलेरीड इम्प्लाईज', 'पेंशनर्स एंड सीनियर सिटिजन्स, 'हाउ टू कम्प्यूट योर कैपीटल गेन' और 'फाइलिंग योर टैक्स रिटर्न' नाम की पुस्तिकाएं प्रकाशित की गईं। इसके अलावा अल्प बचत योजनाओं के बारे में जानकारी देने वाला फोल्डर 'नेशनल सेविंग स्कीम्स एट ए ग्लांस' और 'एनएसआई प्लानर' भी प्रकाशित किए गए।

गोवा में आयोजित भारत के 37वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में डीएवीपी ने प्रचार सहायता उपलब्ध कराई। डीएवीपी ने समारोह की विनियम पुस्तिका और विनियम फोल्डर छापे।

वर्ष के दौरान निदेशालय ने आपदा प्रबंधन, बाढ़, चक्रवात और भूकम्प की आशंका वाले राज्यों में इन आपदाओं के बारे में गृह मंत्रालय की ओर से प्रचार अभियान चलाया। यह अभियान तटवर्ती इलाकों के आपदाग्रस्त लोगों, जैसे मछुआरों, किसानों, नाजुक मकानों और निचले इलाकों में रहने वालों के साथ-साथ इस तरह की आपदाओं में सहायता पहुंचाने वाली एजेंसियों जैसे सरकारी संगठनों, स्थानीय निकायों, गैर-सरकारी संगठनों और स्व-सहायता समूहों आदि को लक्ष्य करके बनाया गया था।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जैसे अर्धसैनिक बलों ने अपने-अपने स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी गतिविधियों को उजागर करने वाले विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित किए। गृह मंत्रालय की ओर से भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया जिसमें राष्ट्रीय ध्वज के सही तरीके से उपयोग के बारे में लोगों को जानकारी दी गयी थी।

विज्ञापन

वित्त वर्ष के दौरान (दिसंबर 2006 तक) देश भर में विभिन्न समाचार पत्रों को 16,043 विज्ञापन जारी किये गये। इनमें से 903 सजावटी थे और बाकी वर्गीकृत विज्ञापन थे। इसके अलावा 'पल्स पोलियो दिवस', 'विश्व स्वास्थ्य दिवस', 'सरदार पटेल जयंती', 'डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती', 'इंदिरा गांधी जयंती', 'उपभोक्ता जागरूकता अभियान', 'आयकर', 'विश्व एड्स दिवस', 'नेत्र दान', 'बाल दिवस', 'विकलांग जन', 'विश्व पर्यावरण दिवस', 'स्वतंत्रता दिवस', 'आयोडीन अल्पता निवारण दिवस', 'विश्व खाद्य दिवस', 'मानवाधिकार दिवस', 'राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग निवारण दिवस' आदि पर भी कुछ विज्ञापन जारी किये गये।

निदेशालय ने नयी विज्ञापन नीति तैयार की है जो 1 जून, 2006 से लागू हो गयी है और डीएवीपी की वैबसाइट www.davp.nic.in पर उपलब्ध है।

श्रव्य-दृश्य

डीएवीपी का ऑडियो विजुअल यानी श्रव्य-दृश्य एकांश रेडियो और वीडियो कार्यक्रमों, जिंगल और श्रव्य-दृश्य स्पॉट आदि के जरिए आकाशवाणी, दूरदर्शन, निजी उपग्रह टेलीविजन चैनलों और क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की इकाइयों के जरिए सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर कार्यक्रम प्रायोजित करता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में एक विशेष अभियान शुरू किया गया। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर बनाये गये आडियो-वीडियो स्पॉट्स का रेडियो/दूरदर्शन/ निजी टेलीविजन चैनलों पर प्रसारण किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय के लिए सेवा कर पर एक बड़ा प्रचार अभियान भी शुरू किया गया जिसके अंतर्गत डीएवीपी ने वीडियो स्पॉट्स बनवाये और प्राइवेट टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित किए।

डीएवीपी विकास संबंधी विभिन्न मुद्दों पर अनेक साप्ताहिक प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम तैयार करा रहा है जिनका आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारण किया जाता है। इनमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की कल्याण योजनाओं के बारे में 'संवरती जाएं जीवन की राहें', स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की परिवार कल्याण योजनाओं पर 'खुशियों भरा आंगन', ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न ग्राम विकास योजनाओं के बारे में 'गीत गूंजे गांव-गांव', 'नयी आशाएं, नयी दिशाएं' और 'अब मंजिल दूर नहीं' तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको के लिए एड्स जागरूकता पर 'जीवन है अनमोल' और 'लैट्स टॉक' तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए महिला तथा बाल विकास से संबंधित मुद्दों पर 'आकाश हमारा है' जैसे कार्यक्रम

शामिल हैं। ये कार्यक्रम 15 से 30 मिनट के हैं और हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में रोचक ड्रामा के रूप में तैयार किए गए हैं। आकाशवाणी के मुख्य चैनलों और विविध भारती केंद्रों से देश भर में इनका प्रसारण किया जाता है। कार्यक्रम 'लैट्स टॉक' का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम चैनल से प्रसारण किया जाता है।

डीएवीपी ने पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के लिए साप्ताहिक धारावाहिक वीडियो कार्यक्रम 'खेल-खेल में बदलो दुनिया' की आधे-आधे घंटे की 143 कड़ियां तैयार कीं जिनका दूरदर्शन (नेशनल चैनल) पर हर रविवार को (बुधवार को पुनर्प्रसारण) प्रसारण किया गया। यह कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी रूप में था और इसमें पेट्रोलियम पदार्थों, पानी, बिजली और पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया। देश के विभिन्न भागों के स्कूलों के बच्चों ने इसमें भाग लिया। इन अभियानों के अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम और जन्म-मृत्यु पंजीकरण, आडियो/वीडियो स्पॉट्स/फिल्में तैयार की गईं। गृह मंत्रालय के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पर 30 मिनट की डाक्यूमेंटरी, पशुपालन विभाग के लिए पशुधन बीमा योजना, कृषि मंत्रालय के लिए बसंत सरस मेला और आय कर विभाग के लिए आयकर विवरण भरने पर आडियो/वीडियो स्पॉट्स/फिल्में बनायी गईं। इलेक्ट्रानिक मीडिया में भी अभियान चलाये गए जो इस प्रकार थे - उपभोक्ता मामलों के विभाग के लिए उपभोक्ता जागरूकता पर अभियान, नाको के लिए स्वैच्छिक रक्तदान और एड्स के बारे में जागरूकता पर अभियान, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग के लिए आरोग्य मेलों का आयोजन, खाद्य और पोषाहार बोर्ड के लिए पोषण शिक्षा पर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए अंधता नियंत्रण, पोषण और एनीमिया व विटामिन-ए की कमी से होने वाली बीमारियों, डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम, प्रसव पूर्व गर्भस्थ शिशु के लिंग का पता लगाने की तकनीक के दुरुपयोग को रोकने पर अभियान, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की उपयोगिता पर तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए भारत उदय और गांधी जयंती पर।

ऑडियो-वीडियो प्रोड्यूसरों को पैनलबद्ध करने के लिए नयी नीति 2006 और इलेक्ट्रानिक मीडिया चैनलों को पैनलबद्ध करने की नीति 2006 तैयार की गयीं।

मुद्रित प्रचार स्कंध

मुद्रित प्रचार स्कंध रंगीन पोस्टरों, फोल्डरों, पुस्तिकाओं, कैलेंडर, डायरी, स्टिकर, वाल हैंगर, टेबल कैलेंडर और मुद्रित प्रचार की इसी तरह की विभिन्न प्रकार की सामग्री के बारे में योजना बनाने, निर्माण और मुद्रण संबंधी कार्य की देखरेख करता है। हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा डीएवीपी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, बांग्ला, असमिया, ओड़िया, पंजाबी और उर्दू में मुद्रित प्रचार सामग्री छापता है। चालू साल में जो महत्वपूर्ण मुद्रित सामग्रियां छापी गईं उनमें 'जनता के लिए रिपोर्ट'; 'यूपीए सरकार के दो वर्ष'; 'प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम'; 'सूचना का अधिकार अधिनियम'; 'सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना'; 'यूपीए सरकार की राज्यवार उपलब्धियां'; 'डीएवीपी कैलेंडर 2007' और 'आदि ग्रंथ के चार सौ साल'; 'सामूहिक खुशहाली के लिए सार्क'; 'बेहतर भविष्य का निर्माण'; शामिल हैं। इसके अलावा 'पल्स पोलियो कार्यक्रम'; 'यॉज बीमारी का उन्मूलन'; 'रक्त दान'; 'उपभोक्ता जागरूकता अभियान' आदि पर पोस्टर प्रकाशित किये गये। मुद्रित प्रचार स्कंध ने चालू वित्त वर्ष में (दिसंबर 2006 तक) 139 कार्य हाथ में लिए और 503 सामग्रियों की 92,50,350 प्रतियां प्रकाशित कीं।

बाह्य प्रचार

बाह्य प्रचार स्कंध संदेशों के प्रचार के लिए होर्डिंग, बस पैनल, दीवार चित्र, बैनर, एनीमेशन डिस्प्ले, सड़कों की रेलिंग में सजावट, सिनेमा स्लाइड, मैट्रो रेल के प्रदर्शन बोर्ड, मैट्रो रेल के भीतर पैनलों आदि का सहारा लेता है। 2006-07 में (दिसम्बर 2006 तक) इस स्कंध ने कुल 4,864 डिस्प्ले किए। भारत निर्माण, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बाल विवाह, बालिका शिशु की देखभाल, स्पीड पोस्ट सेवा, एगमार्क, बाल श्रम की रोकथाम, नेत्र दान, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, लोकसभा टीवी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता जैसे अनेक महत्वपूर्ण अभियानों के साथ साथ हिन्दी पखवाड़ा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह आदि के लिए बाह्य प्रचार सामग्री का सहारा लिया गया।

प्रदर्शनी

प्रदर्शनी प्रभाग ने वर्ष 2006-07 में कुल 2168 दिनों की 565 प्रदर्शनियां आयोजित कीं। इसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, गुरुदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर, पं. जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसी हस्तियों के बारे में प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। इसके अलावा 'राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम', 'दांडी यात्रा', 'जम्मू-कश्मीर - एक यात्रा', 'स्वस्थ ग्राम स्वस्थ भारत', 'रिसर्जेंट इंडिया', 'पूर्वोत्तर में विकास', 'जीवन और जल', 'भारत में महिलाएं' ओर 'भारत में संसदीय लोकतंत्र' विषयों पर भी 2006-07 में प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के

लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने के लिए 'स्वस्थ माता, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ राष्ट्र' नाम की प्रदर्शनी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2006 के दौरान प्रगति मैदान में आयोजित की गई। इसे भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा निर्मित मंडपों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मंडप का पुरस्कार मिला।

डीएवीपी देश भर में चलाए जा रहे जन सूचना अभियान में भाग ले रहा है। इसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयां एकसाथ मिलकर कार्य करती हैं। इसका उद्देश्य लोगों को भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जागरूक बनाना है। डीएवीपी ने 'भारत प्रगति की ओर' नाम से एक नयी प्रदर्शनी की योजना बनाई है। दिसम्बर 2006 में रायबरेली में आयोजित जन सूचना अभियान में डीएवीपी की प्रदर्शनी 'भारत उदय' को अपने प्रदर्शन के लिए शील्ड से सम्मानित किया गया।

इसके अलावा डीएवीपी की क्षेत्रीय इकाइयों ने प्रसिद्ध मेलों और उत्सवों के अवसर पर, जैसे केरल में त्रिशूर पूरम उत्सव, मेरठ में नौचंदी मेले, पुरी की रथ यात्रा, चंदौसी के मेले, सोनपुर मेले, गया में पितृपक्ष मेले, प्रगति मैदान में आरोग्य मेले, मैसूर में दशहरा उत्सव और नई दिल्ली के शेख सराय में परफेक्ट हैल्थ मेले में प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

वित्त वर्ष के दौरान प्रदर्शनी प्रभाग ने 'भारत में सिविल सेवाएं : उत्कृष्टता की ओर अग्रसर' और 'स्वस्थ माता, स्वस्थ शिशु और स्वस्थ राष्ट्र' विषयों पर नये प्रदर्शनी सैट बनाए।

लोक सभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी बोलपुर (प. बंगाल) में सितंबर 2006 में डीएवीपी पैवेलियन का अवलोकन करते हुए

मास मेलिंग

डीएवीपी का मास मेलिंग स्कंध का कार्य मुख्य रूप से देश के विभिन्न भागों में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को मुद्रित सामग्री को प्रेषण करना है। देश में यह अपनी तरह का सबसे बड़ा संस्थापन है और इसकी पहुंच ब्लाक स्तर तक है। इसके डाक पते के बैंक में इस समय विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 16.50 लाख पते दर्ज हैं। अप्रैल से नवम्बर 2006 तक विभिन्न विषयों पर मुद्रित सामग्री की 85 लाख प्रतियां वितरित की गईं। इसकी प्रमुख गतिविधियों में यूपीए सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियों, राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम और प्रधानमंत्री के भाषणों की श्रृंखला के अंतर्गत हिन्दी, अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में पुस्तिकाओं के वितरण के अलावा भारत सरकार के कैलेंडरों और डायरियों का वितरण भी शामिल है।

योजना कार्यक्रमों के लिए आवंटन

योजना कार्यक्रमों के लिए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित राशि सहित) आवंटन इस प्रकार है :

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान 200-07	संशोधित अनुमान 2006-07
1	2	3	4
1.	विकासमूलक प्रचार कार्यक्रम *(संकल्पना और क्रियान्वयन)*	259.00	2315.00

वार्षिक बजट (2006-07) में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए स्वीकृत परिव्यय इस प्रकार है :

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	योजना का नाम	परिव्यय
	विकासमूलक प्रचार कार्यक्रम : संकल्पना तथा क्रियान्वयन	
	(क) बाह्य प्रचार	6.50
	(ख) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए सूचनाओं का संप्रेषण	8.50
	(ग) सजावटी तथा वर्गीकृत विज्ञापन	10.00
	(घ) मुद्रित प्रचार	1.00
	कुल योग	**26.00**

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (आरएनआई)

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (आरएनआई) सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, जिसे विभिन्न सांविधिक और गैर-सांविधिक कार्य सौंपे गए हैं। इस कार्यालय द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के शीर्षकों का सत्यापन और स्वीकृति, पंजीकरण तथा उनके प्रसार दावों की जांच की जाती है। अपने गैर-सांविधिक कार्यों के अंतर्गत आरएनआई पंजीकृत प्रकाशकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए अखबारी कागज के आयात के लिए पात्रता प्रमाण पत्र, मुद्रण मशीनरी के आयात के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र आदि जारी करता है। यह देश में मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया की स्थिति को उजागर करने के लिए हर वर्ष 'प्रेस इन इंडिया' का भी प्रकाशन करता है।

शीर्षकों की सत्यापन और पंजीकरण

अप्रैल से नवंबर 2006 की अवधि में आरएनआई ने शीर्षकों के सत्यापन के लिए 12912 आवेदनों के दावों की जांच की और 10684 शीर्षकों को स्वीकृति दी गई। इसी अवधि में 1925 समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को पंजीकरण प्रमाण पत्र (1475 नए + 450 संशोधित) जारी किए गए।

शीर्षकों को मुक्त किया जाना (डी-ब्लॉकिंग)

ऐसे शीर्षकों को मुक्त करने की कार्रवाई की गई जिन्हें आरएनआई द्वारा सत्यापित कर दिया गया था किन्तु प्रकाशकों द्वारा कतिपय औपचारिकताएं पूरी नहीं किए जाने के कारण दो वर्ष के भीतर पंजीकरण नहीं किया जा सका। 2004 में सत्यापित किए गए 5772 शीर्षकों को वर्ष 2006-07 के दौरान मुक्त कर दिया गया।

अखबारी कागज (न्यूज प्रिंट)

आरएनआई अखबारी कागज (ग्लेज्ड और स्टैंडर्ड न्यूज प्रिंट) के आयात के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी करता है। अप्रैल से नवंबर 2006 की अवधि में आरएनआई द्वारा पंजीकृत समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के प्रकाशकों को अखबारी कागज के आयात के लिए 603 पात्रता प्रमाणपत्र जारी किए गए।

प्रिंटिंग मशीनरी

प्रिंटिंग मशीनरी और इससे संबद्ध उपकरणों के आयात के लिए आरएनआई संस्तुति करता है। अप्रैल से नवंबर 2006 की अवधि में 4 समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के लिए प्रिंटिंग मशीनरी और संबद्ध उपकरणों के आयात की संस्तुति की गई। इसके अतिरिक्त विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्राप्त करने के सिलसिले में तीन पत्र भी जारी किए गए।

राजभाषा

हिंदी पखवाड़े का आयोजन 14 से 28 सितंबर 2006 के दौरान किया गया। सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस अवधि में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

कंप्यूटरीकरण

आरएनआई ने शीर्षक सत्यापन संबंधी पत्र वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था की है। अब आवेदक नई दिल्ली स्थित आरएनआई कार्यालय आने की बजाए अपने सत्यापन पत्र कहीं से भी किसी भी समय वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और घोषणा दर्ज करके प्रकाशन आरंभ कर सकते हैं। इससे अनावश्यक विलम्ब से बचने तथा अधिक पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। साथ ही आवेदकों के समय और धन की बचत होगी।

आरएनआई ने स्वत: शीर्षक मुक्त करने की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली भी शुरू की है। अब निर्धारित अवधि में पंजीकृत न कराए गए शीर्षक स्वत: मुक्त हो जाते हैं। इससे शीर्षक आसानी से उपलब्ध कराने में मदद मिलती है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

परिचय

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की स्थापना 1953 में हुई। उस समय इसे पंचवर्षीय योजना प्रचार संगठन कहा जाता था। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता था। इसका एकमात्र उद्देश्य पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रचार करना था। दिसम्बर 1959 में इसका नाम बदला गया और इसे क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी) के नाम से पुनर्गठित करते हुए इसका दायरा बढ़ाया गया।

संगठन

निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है और देश भर में इसके 22 प्रादेशिक कार्यालय तथा 207 क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां हैं।

समाज के निचले स्तर पर प्रचार संगठन के रूप में यह निदेशालय सभी वर्गों के लोगों को राष्ट्र-निर्माण की गतिविधियों में शामिल करके महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। प्रचार अभियान चलाने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों और अन्य आवश्यक साधनों से सुसज्जित क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों का इस्तेमाल करती है, जिनमें समूह वार्ताएं, जनसभाएं, सेमिनार, संगोष्ठियां और प्रतियोगिताएं शामिल हैं। संदेश पहुंचाने के लिए फिल्मों और जीवन्त मनोरंजन माध्यमों का भी इस्तेमाल किया जाता है। निदेशालय सरकार और लोगों के बीच दो-तरफा माध्यम के रूप में काम करता है। निदेशालय के काम का एक महत्वपूर्ण घटक फीडबैक है। क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों तथा ग्राम स्तर पर उनके क्रियान्वयन के बारे में सफलता की कहानियां और जन प्रतिक्रियाएं एकत्र करती हैं, जिन्हें समेकित फीडबैक रिपोर्ट के रूप में सरकार और कार्यान्वयन अधिकारियों को भेजा जाता है, ताकि सुधार के उपाय और अन्य समुचित कार्रवाइयां की जा सकें।

योजना गतिविधियां

योजना आयोग ने 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान निदेशालय के लिए 11.00 करोड़ रुपये के व्यय की मंजूरी दी। 10वीं पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना 2006-07 के लिए क्षेत्रवार ब्योरा निम्नलिखित है :

क्षेत्र	10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 का परिव्यय	2005-2006 का परिव्यय
	11.00 करोड़	**1.10 करोड़**

योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की भौतिक और वित्तीय उपलब्धियां

वर्ष 2006-07 के दौरान डीएफपी के योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की भौतिक और वित्तीय उपलब्धियां इस प्रकार रहीं-

योजना के अंतर्गत दो कार्यक्रम हैं-(1) **राजस्व :** फिल्म/कैसेटों/सीडी आदि की खरीद-तंबाकू निषेध के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की तीन फिल्मों की डबिंग और डुप्लिकेशन के लिए 10.00 लाख रुपये डीएवीपी को हस्तांतरित किए गए, और (2) **पूंजी :** आधुनिकीकरण और पूंजीगत माल का उन्नयन-विभिन्न उपकरणों और कम्प्यूटरों की खरीद के लिए अब तक 66.20 लाख रुपये इस्तेमाल किए जा चुके हैं। इस राशि में 43,849 रुपये की राशि के आवक दावे का निबटारा भी शामिल है, जो वर्ष 2003-04 के दौरान वाहनों की खरीद पर खर्च की गयी थी। इसके

अतिरिक्त 90,000 रुपये की लागत से वायरलैस पीए प्रणालियां, 50,05,182 रुपये की लागत से 41 मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर खरीदे गए और उनमें से 6 मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर, जिनका मूल्य 7,32,468 रुपये है, पूर्वोत्तर क्षेत्र को भेजे गए। कम्प्यूटरों की खरीद के संदर्भ में 6,31,321 रुपये के आवक दावों का निपटारा किया गया, जिसमें से 68,949 रुपये के दावे पूर्वोत्तर से संबद्ध थे। इसके अलावा वर्ष 2005-06 की बकाया मदों पर 8,08,392 रुपये खर्च किए गए जिसमें 40 वायरलैस पी ए प्रणालियों के 5% बकाया के 18,000 रुपये, 40 मल्टी मीडिया प्रोजेक्टरों की खरीद के 16 प्रतिशत बकाया के 7,81,297 रुपये और अखबारों में विज्ञापनों के 9,095 रुपये थे। प्रादेशिक कार्यालय बंगलूर ने क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण पर 41,500 रुपये खर्च किए।

वित्त वर्ष के शेष महीनों में किया जाने वाला खर्च

5 लाख रुपये मूल्य के 40 वायरलैस पीए सिस्टम्स खरीदने के लिए आर्डर दिए गए हैं और 41 डीवीडी प्लेयर की खरीद संबंधी टेंडर खोलने के बाद उनके मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया गया है, जल्दी ही इनके लिए आर्डर दिया जाएगा। कम्प्यूटरों की खरीद के संदर्भ में बकाया 4,02,914 रुपये और 4 कम्प्यूटर प्रशिक्षणों के लिए बकाया 2,08,500 रुपये का भुगतान किया जाना है।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लागू किए जा रहे कार्यक्रम

डीएफपी ने दोनों योजनाओं के अंतर्गत 110 लाख रुपये के वर्ष 2006-07 के कुल वार्षिक परिव्यय में से 14.00 लाख रुपये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित किए हैं। ''फिल्मों/कैसेटों की खरीद'' योजना के तहत स्वीकृत 10 लाख रुपये के कुल परिव्यय में से 1 लाख रुपये पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 2.27 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। 2006-07 के संशोधित अनुमानों में इस मद के लिए और प्रावधान किया जा रहा है। ''पूंजीगत स्टाक के आधुनिकीकरण और उन्नयन'' की योजना के अंतर्गत कुल 100 लाख रुपये के परिव्यय में से 13 लाख रुपये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित किए गए, जिसमें से 8.64 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

कार्यक्रम गतिविधियां

वर्ष 2006-07 के लिए क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की इकाइयों का वार्षिक निष्पादन

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ने भारत सरकार के ग्राहक मंत्रालयों की ओर से अनेक विशेष प्रचार अभियान चलाए। सभी क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों ने अपने नियमित प्रचार अभियानों के हिस्से के रूप में जन सूचना अभियान, भारत निर्माण और उसके अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रमों,

क्र.स.	कार्यक्रम	वास्तविक उपलब्धियां (31.10.2006 तक)	प्रत्याशित उपलब्धियां (01.11.2006 से 31.03.2007 तक)
1	फिल्म शो	22,018	24,815
2	गीत और नाटक	1,633	1,098
3	विशेष कार्यक्रम (भाषण/निबंध/प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता/ग्रामीण खेल/चित्रकारी प्रतियोगिता/रैली/बेबी शो आदि सहित)	3,985	3,105
4	मौखिक वार्ताएं (समूह वार्तालाप, सेमिनार और संगोष्ठियों सहित)	33,128	27,170
5	फोटो प्रदर्शनियां	18,436	13,870
6	जन प्रतिक्रिया बैठकें।	5,060	3,105

मां और शिशु के स्वास्थ्य, परिवार नियोजन सहित प्रजनन बाल स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, सूचना का अधिकार, रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम, प्रसव पूर्व निदानात्मक तकनीक (पीएनडीटी) अधिनियम, स्त्री-पुरुष के बीच भेदभाव से जुड़े मुद्दे, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम-एनआईडीडीसीपी, एड्स जागरूकता, बाल विवाह जैसे मुद्दों का प्रचार किया।

अप्रैल-अक्टूबर 2006 की अवधि के दौरान डीएफपी के कार्यक्रमों और गतिविधियों तथा नवंबर 2006-मार्च 2007 की अवधि में प्रत्याशित निष्पादन का ब्योरा पिछले पृष्ठ पर दिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह पर डीएफपी ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को राष्ट्रव्यापी प्रचार का प्रमुख मुद्दा बनाया। लोगों को जानकारी देने के लिए परस्पर वार्तालाप, फिल्म शो, समूह वार्तालाप, सार्वजनिक सभाओं जैसे विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंत्रालय ने इस मिशन के विभिन्न पहलुओं को रेखांकित किया और डीएफपी ने उनके बारे में व्यापक अभियान चलाया। यह अभियान समूचे देश में पूरे जोरों पर है। डीएफपी 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और सामाजिक क्षेत्र' के बारे में प्रचार के लिए पूरे देश को कवर कर रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र से संबद्ध अन्य मुद्दों के प्रचार-प्रसार की गहन जानकारी देने के लिए क्षेत्र प्रचारकों, स्वास्थ्यकर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को अभियान में शामिल किया गया।

पल्स पोलियो टीकाकरण

डीएफपी ने देश को पोलियो से मुक्त बनाने के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अभियान को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रचार किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनेक राज्यों में कई बार उप-राष्ट्रीय टीकाकरण दिवसों का आयोजन किया। डीएफपी की क्षेत्रीय इकाइयों ने इन राज्यों में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान को प्रचार के जरिए सहयोग दिया। इन इकाइयों ने लोगों को प्रेरित किया कि वे पांच वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए पोलियो बूथ पर ले जायें। उ.प्र., बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, म.प्र. और उत्तराखंड जैसे अधिक जोखिम वाले राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया। सभी क्षेत्रीय इकाइयों ने अनेक बार आयोजित उप-राष्ट्रीय और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवसों के अवसर पर दो-दो सप्ताह के विशेष अभियान चलाए ताकि जन जागरूकता पैदा की जा सके और लोगों को पांच वर्ष तक के सभी बच्चों को दवा पिलाने के लिए एकजुट किया जा सके। इसी प्रकार उप-राष्ट्रीय टीकाकरण दिवसों के लिए भी विशेष प्रचार अभियान आयोजित किए गए।

राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकास नियंत्रण कार्यक्रम - (एनआईडीडीसीपी)

आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों की रोकथाम और लोगों को केवल आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए प्रेरित करने वाले राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय सहयोग दे रहा है। यह विशेष अभियान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एनआईडीडीसीपी अभियान के लिए 32 लाख रुपये से ज्यादा प्रदान किए।

एड्स जागरूकता

निदेशालय की क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां एचआईवी/एड्स के बारे में नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं। इस काम के लिए फिल्म शो, विद्यार्थियों और आम लोगों में समूह वार्तालाप, विचार गोष्ठियों, निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। समाज में एड्स का बढ़ता हुआ संकट निदेशालय के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। डीएफपी ने एक्वायर्ड इम्युनो-डेफिसिएंसी सिंड्रोम (एड्स) के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रचार जारी रखा है और वह लोगों को एड्स से संक्रमित व्यक्तियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने के लिए प्रेरित करता रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एड्स अभियान के लिए करीब 40 लाख रुपये प्रदान किए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एक ऐसा वरीयता क्षेत्र है, जिसके लिए निदेशालय दूरदराज में रहने वाले लोगों को जानकारी प्रदान करने का भरसक प्रयास कर रहा है। क्षेत्रीय इकाई ने अपने नियमित क्षेत्र कार्यक्रमों के जरिए लोगों को अनेक मसलों जैसे जनसंख्या नियंत्रण, आहार, गर्भ धारण के समय सावधानी, नवजात शिशु की देखभाल, अस्पताल में प्रसव कराने के फायदे, विवाह की आयु आदि के बारे में जानकारी दिलाने का प्रयास किया। क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अंतर्गत विभिन्न मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए। इस विषय पर फिल्म शो और समूह वार्ताओं का आयोजन किया गया।

मलेरिया उन्मूलन

जून माह को मलेरिया विरोधी माह के रूप में मनाया गया। माह

के दौरान क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों ने मलेरिया के उन्मूलन के लिए रोकथाम उपायों और बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला।

इस काम में फिल्म प्रदर्शन, मौखिक संचार और पोस्टर प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।

विश्व तंबाकू-निषेध दिवस

31 मई, 2006 को विश्व तंबाकू- निषेध दिवस के अवसर पर प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनका उद्देश्य धूम्रपान और तंबाकू खाने के दुष्प्रभावों को उजागर करना था। अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर लगे प्रतिबंधों के बारे में जागरूकता पैदा करने और परोक्ष धूम्रपान के हानिकर प्रभावों पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

जनवरी-मार्च 2007 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम/गतिविधियां

एनआईडीडीसीपी, एड्स/एचआईवी, रोग प्रतिरक्षण टीकाकरण के बारे में प्रचार गतिविधियां जारी रखी जाएंगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गयी विशेष धनराशि से एड्स जागरूकता और आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में विशेष प्रचार अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव है।

जन-जागरुकता अभियान

निदेशालय सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में पत्र सूचना कार्यालय के नेतृत्व में देश के विभिन्न भागों में चलाए जाने वाले जन-जागरूकता अभियानों के लिए जोरदार प्रचार सहायता प्रदान करता है। जन-जागरूकता अभियान के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में प्रचार गतिविधियों का आयोजन किया गया। निदेशालय ने संबद्ध मुद्दों के बारे में महत्वपूर्ण स्थलों पर विशेष स्टाल लगाए और इन कार्यक्रमों के बारे में सूचना का संप्रेषण किया। क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों ने सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में कार्यक्रम आयोजित किए।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम

सरकार द्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम स्वीकार किए जाने के अनुरूप सभी क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों ने समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाने के वास्ते तैयार किए गए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का प्रचार किया। प्रचार कार्यक्रमों में न्यूनतम साझा कार्यक्रम के सभी छह बुनियादी सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इनमें सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना, 7-8 प्रतिशत विकास दर का आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करना, रोजगार मुहैया कराना, किसान और मजदूरों के कल्याण को बढ़ावा देना, महिलाओं का संपूर्ण सशक्तिकरण, समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसर प्रदान करना शामिल है। आम जनता के स्तर पर काम करने वाला संगठन होने के नाते क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के प्रचार अभियानों का केंद्र निर्धन लोगों के लिए कार्यक्रम व योजनाएं रहीं। प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वोत्तर एवं जम्मू-कश्मीर में संचार माध्यमों की पहुंच पर बल देना भी सीमावर्ती क्षेत्रों में गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा।

दांडी यात्रा की प्लेटिनम जयंती समारोह में योगदान करते हुए निदेशालय ने अनेक प्रचार कार्यक्रम चलाए, जिससे 1930 की इस ऐतिहासिक यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके, और युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों के बलिदान के बारे में बताया जा सके। यह अभियान अप्रैल 2006 तक जारी रहा।

केरोसिन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से निदेशालय ने विभिन्न राज्यों के लगभग 500 चुने हुए खंडों में केरोसिन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रचार अभियान चलाया।

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय ने क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कार्यक्रमों/गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान की। नोडल मंत्रालय को उसके सभी प्रकार के उपकरणों के वांछित प्रदर्शन के लिए क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों का इस्तेमाल प्रदर्शन केंद्रों के रूप में करने की सुविधा प्रदान की गई।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से निदेशालय ने विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए विशेष जागरुकता अभियान चलाया, जिसमें उनके कल्याण के लिए लागू किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और प्रदान की जा रही सुविधाओं की जानकारी दी गयी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए डीएफपी ने कार्यक्रम शृंखलाओं का आयोजन किया, जिनमें इन समुदायों के लिए प्रदत्त वरीयताओं और सुविधाओं पर प्रकाश डाला गया। वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल, उनके संरक्षण और कल्याण के लिए किए गए उपायों के प्रचार को भी निदेशालय ने वरीयता प्रदान की और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति समाज का नजरिया बदलने पर ध्यान केन्द्रित किया।

राष्ट्रीय विधिक सेवा कार्यक्रम

निदेशालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से समाज के कमजोर और असहाय वर्गों के लिए कानूनी साक्षरता व नि:शुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करने के अभियान आयोजित किए। राज्यों के विधिक सेवा प्राधिकरणों की सक्रिय भागीदारी के साथ देश भर की क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों ने 9 नवंबर, 2006 को राष्ट्रीय विधिक सहायता दिवस के रूप में मनाया और शेष माह में गहन जानकारी प्रदान करने के कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को निशुल्क कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना और निहित स्वार्थी व्यक्तियों की गलत सलाह से बचने के प्रति आगाह करना था।

इसके अलावा राष्ट्रीय और साम्प्रदायिक सद्भाव, सर्वशिक्षा अभियान, अस्पृश्यता और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषय क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के नियमित प्रचार कार्यक्रमों का हिस्सा बने रहे।

पाक्षिक समाचार डाइजेस्ट

प्रचार गतिविधियों के अलावा सरकार को उसके कार्यक्रमों और नीतियों पर जनसाधारण की राय से अवगत कराना भी डीएफपी की एक महत्वपूर्ण सेवा है। निदेशालय निरंतर यह सेवा सरकार को प्रदान कर रहा है। 'पाक्षिक समाचार डाइजेस्ट' लोगों और समाज की बुनियादी परिस्थितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जो नीति निर्माताओं और प्रशासकों को राष्ट्रीय महत्व के अनेक मसलों पर सरकारी नीतियां तय करने और कार्यक्रम बनाने तथा उन पर अमल करने के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करता है।

सूचना सुविधा केन्द्र

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 लागू होने और दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्र निवासियों को सरकार के बारे में जानकारी हासिल करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सभी क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां सूचना सुविधा केन्द्रों के तौर पर काम करने लगी हैं। सभी क्षेत्रीय प्रमुख अधिकारियों को जन सूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी मनोनीत कर दिया गया है।

मल्टी मीडिया अभियान

राष्ट्रीय महत्व के मसलों को व्यापक पैमाने पर अन्य मीडिया इकाइयों के साथ मल्टी मीडिया अभियानों के द्वारा प्रचारित करना निदेशालय का एक प्रमुख कार्य है। ऐसे कार्यक्रमों के पीछे अवधारणा यह है कि सभी सरकारी मीडिया इकाइयों के एक मंच पर आकर किसी विषय पर गहन अभियान, लक्षित जन समुदाय पर दूरगामी प्रभाव डालता है। निदेशालय द्वारा जून 2006 से देश के विभिन्न भागों में मल्टी मीडिया अभियान आयोजित करने की नीति अपनाने के बाद से सभी क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा इस तरह के जन-जागरूकता अभियानों पर बल दिया गया।

महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों/दिवसों/सप्ताहों और विषयों को मनाना

क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों द्वारा प्रादेशिक प्रमुखों के मार्गदर्शन में निम्नलिखित उपयुक्त प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए गए : 1-7 अप्रैल 2006 तक नेत्रहीनता निवारण सप्ताह, 7 अप्रैल 2006 को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 अप्रैल 2006 को विश्व पृथ्वी दिवस, 1 मई 2006 को राष्ट्रीय श्रम दिवस, 8 मई 2006 को विश्व रेडक्रास दिवस, 11 मई 2006 को प्रौद्योगिकी दिवस, 21 मई 2006 को आतंकवाद-विरोध दिवस, 31 मई 2006 को विश्व तंबाकू-निषेध दिवस, 5 जून 2006 को विश्व पर्यावरण दिवस, 11 जुलाई 2006 को विश्व जनसंख्या दिवस, 1 से 7 अगस्त 2006 तक विश्व स्तनपान सप्ताह, 15 अगस्त 2006 को स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त से 5 सितंबर 2006 तक सद्भावना दिवस एवं साम्प्रदायिक सद्भाव पखवाड़ा, 1 से 7 सितम्बर 2006 तक राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह, 5 सितंबर 2006 को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर 2006 को अंतराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 से 28 सितंबर 2006 तक हिंदी पखवाड़ा, 28 सितंबर 2006 को विश्व पर्यटन दिवस, 1 अक्टूबर 2006 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 से 8 अक्टूबर 2006 तक महात्मा गांधी जयंती और अस्पृश्यता निवारण सप्ताह, 11 से 25 अक्टूबर 2006 तक परिवार कल्याण पखवाड़ा, 21 अक्टूबर 2006 को विश्व आयोडीन अल्पता विकार रोकथाम दिवस, 9 से 14 नवम्बर 2006 तक अंतराष्ट्रीय विज्ञान एवं शांति सप्ताह, 14 नवंबर 2006 बाल दिवस, 19 से 25 नवम्बर 2006 तक कौमी एकता सप्ताह, 19 नवंबर 2006 को राष्ट्रीय एकता दिवस, 20 नवम्बर 2006 को अल्पसंख्यक कल्याण दिवस, 20 नवम्बर 2006 को कमजोर वर्ग दिवस, 23 नवम्बर 2006 को सांस्कृतिक एकता दिवस, 24 नवम्बर 2006 को महिला दिवस, 25 नवम्बर 2006 को संरक्षण दिवस, 1 दिसंबर 2006 को विश्व एड्स निवारण दिवस, 2 दिसंबर 2006 को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 8 दिसम्बर 2006 को बालिका दिवस, 10 दिसम्बर 2006 को मानवाधिकार दिवस तथा 14 दिसम्बर, 2006 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस।

जनवरी से मार्च 2007 के महीनों के दौरान निदेशालय का 5 से 11 जनवरी, 2007 तक सड़क सुरक्षा सप्ताह, 12 जनवरी 2007 को राष्ट्रीय युवा दिवस, 26 जनवरी 2007 को गणतंत्र दिवस, 30

जनवरी 2007 को कुष्ठ निवारण दिवस, 1 से 14 फरवरी 2007 तक तेल संरक्षण पखवाड़ा, 28 फरवरी 2007 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 1 से 7 मार्च 2007 तक अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह, 8 मार्च 2007 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 14 मार्च 2007 को उपभोक्ता अधिकार दिवस आयोजित करने का कार्यक्रम है।

मेले और उत्सव

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ने देश के विभिन्न भागों में आयोजित अनेक मेलों और उत्सवों में भाग लिया। कुछ महत्वपूर्ण मेले और उत्सव इस प्रकार हैं :

1. आंध्र प्रदेश में आयोजित गोदावरी नदी का कुंभ मेला
2. आंध्र प्रदेश में कृष्णा पुष्करम (कृष्णा नदी का कुंभ मेला)
3. पुरी में लोक मेला
4. नई दिल्ली में परफेक्ट हेल्थ मेला-2006
5. श्रावणमास महोत्सव मेला, खुर्जा, उत्तर प्रदेश
6. रायबरेली में स्वास्थ्य मेला
7. उड़ीसा में पुरी, बारिपदा और कोरापुट में भगवान जगन्नाथ का रथयात्रा महोत्सव
8. नई दिल्ली में भारत का अंतराष्ट्रीय व्यापार मेला
9. गोवा में भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव-2006
10. इलाहाबाद में अर्धकुंभ मेला

वर्ष के दौरान सतर्कता गतिविधियां

निदेशालय रोजमर्रा के कार्यकलापों में अनुशासनहीनता और अनियमितताओं को रोकने के लिए सतर्कता गतिविधियों पर सर्वाधिक ध्यान देता है। निदेशालय स्तर पर सतर्कता कार्रवाइयों के लिए महानिदेशक सक्षम अधिकारी हैं और क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्र निदेशक। कार्यप्रणाली को मुस्तैद बनाने के लिए समय-समय पर निवारक, निगरानी और गुप्तचरी की जाती है। वर्ष के दौरान अनियमितताओं की 6 शिकायतों की जांच की गई और प्रारंभिक जांच-पड़ताल आयोजित की गई। 6 मामलों में पी ई रिपोर्ट पेश कर दी गई है। पहले की तरह क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों ने नवंबर 2006 में सतर्कता सप्ताह मनाया। इस सप्ताह के दौरान देश के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना की आवश्यकता पर प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए गए।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग में प्रगति

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ने राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा (संघ के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में निहित सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के निर्देशों को लागू करने के लिए निम्न कदम उठाए:

(i) राजभाषा नियम (संघ के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 के नियम के अंतर्गत अधिसूचना

इस निदेशालय को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत 2 जनवरी 1979 को अधिसूचित किया गया। इसके अतिरिक्त क और ख क्षेत्रों में कार्यरत इसके 131 कार्यालयों को अधिसूचित किया जा चुका है। समय-समय पर आदेश जारी करके हिंदी में दक्ष अधिकारियों और कर्मचारियों से राजभाषा में काम करने को कहा गया। सख्ती से अनुपालन के लिए इस बारे में हर वर्ष अनुदेश दोहराए जाते हैं।

(ii) हिंदी दिवस/पखवाड़े का आयोजन

राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से और कर्मचारियों में राजभाषा की नीति के बारे में जानकारी बढ़ाने तथा हिंदी में सरकारी कामकाज के प्रयोग के लिए अनेक प्रोत्साहन कार्यक्रमों के मद्देनजर 14-28 सितंबर 2006 के दौरान 'हिंदी पखवाड़ा' मनाया गया। इस अवसर पर माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री से प्राप्त संदेश डीएफपी मुख्यालय और उसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रसारित किया गया। ऐसा करने के पीछे दो उद्देश्य थे (क) विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार करना और (ख) हिंदी में अधिकतम काम को बढ़ावा देना। 'हिंदी पखवाड़ा' के दौरान हिंदी निबंध प्रतियोगिता, टंकण प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, अंताक्षरी प्रतियोगिता और हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिताओं का आयोजन डीएफपी मुख्यालय में किया गया।

(iii) राजभाषा से संबंधित आदेशों को लागू करने के बारे में जांच बिंदु

मुख्यालय और प्रादेशिक कार्यालयों के प्रत्येक अनुभाग से तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंगवाई जाती है, ताकि कार्यान्वयन के जांच बिंदुओं की प्रभावकारिता पर निगरानी रखी जा सके।

हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के जवाब अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाने की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए समय-समय पर आदेश जारी किए। रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निदेशालय के सभी अनुभागों को अंग्रेजी-हिंदी कोष

प्रदान किए गए हैं। जरूरत के आधार पर अधिकारियों को अनुवाद सहायता उपलब्ध कराई गई।

राजभाषा से संबद्ध संसदीय समिति ने हैदराबाद क्षेत्र के अंतर्गत विशाखापट्टनम के क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय का निरीक्षण 7 फरवरी 2006 को और क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के नई दिल्ली मुख्यालय का निरीक्षण 7 जुलाई 2006 को किया। इसका उद्देश्य राजभाषा नीति के अनुपालन की जांच करना था। इसके अतिरिक्त डीएफपी मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किए गए। 25 जनवरी 2006 को उपनिदेशक (प्रशासन) द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर का निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार 10 मार्च 2006 को पुणे स्थित प्रादेशिक कार्यालय का निरीक्षण डीएफपी मुख्यालय के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी द्वारा किया गया।

डीएफपी मुख्यालय में कंप्यूटरों की समुचित व्यवस्था की गई है ताकि हिंदी में काम करने में सुविधा रहे।

इस निदेशालय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए गए कि वे अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी/हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण देने की समयबद्ध योजना तैयार करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। इसी प्रकार हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण के पात्र कर्मचारियों को क्रमश: हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। इस दिशा में हुई प्रगति पर डीएफपी मुख्यालय द्वारा नियमित आधार पर निगरानी रखी गयी और भविष्य में भी इस पर अमल जारी रहेगा।

डीएफपी मुख्यालय में 19-20 सितंबर 2006 को हिंदी कार्यशाला आयोजित की गयी जिसमें 24 अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान निम्न विषयों पर व्याख्यान दिए गए: (1) राजभाषा नीति, नियम एवं अधिनियम और (2) हिंदी भाषा में काम करने के लिए प्रोत्साहन। कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य कर्मचारियों को प्रेरित करना था ताकि वे हिंदी में काम करते हुए संकोच अनुभव न करें। राज्य स्तर पर प्रादेशिक कार्यालयों द्वारा भी समय-समय पर हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

गीत और नाटक प्रभाग

गीत और नाटक प्रभाग का गठन 1954 में आकाशवाणी की एक इकाई के रूप में हुआ था। वर्ष 1956 में इसे विकास संचार के प्रयोजन से स्वतंत्र मीडिया इकाई का दर्जा दिया गया। यह देश का सबसे बड़ा संगठन है, जो संचार के माध्यम के रूप में अभिनय कलाओं का प्रयोग करता है। यह प्रभाग कला के विभिन्न रूपों जैसे नाटक, बैले, ओपेरा, नृत्य-नाटक, लोक और पारंपरिक शैली के गीतों और कठपुतली कला का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त यह प्रभाग राष्ट्रीय हित के विषयों जैसे साम्प्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक विरासत के संवर्द्धन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा आदि विषयों पर ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रमों के माध्यम से थियेटर शो भी आयोजित करता है।

संगठनात्मक स्वरूप

प्रभाग का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अतिरिक्त इसके निम्नलिखित क्षेत्रीय कार्यालय हैं :

(क) **12 क्षेत्रीय कार्यालय :** बंगलौर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, रायपुर और रांची;

(ख) **7 सीमावर्ती केंद्र :** इम्फाल, जम्मू, शिमला, नैनीताल, दरभंगा, जोधपुर और गुवाहाटी;

(ग) **6 नाटक मंडलियां :** भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद, पटना, पुणे और श्रीनगर;

(घ) सशस्त्र सेना मनोरंजन इकाई की दिल्ली और चेन्नई में नौ मंडलियां;

(ड़) इलाहाबाद, बंगलौर और दिल्ली में तीन ध्वनि-प्रकाश इकाइयां; और

(च) रांची में जनजातीय प्रायोगिक परियोजना।

प्रभाग ने 515 विभागीय कलाकारों, करीब 800 पंजीकृत मंडलियों और लगभग 1200 सूचीबद्ध कलाकारों की मदद से वर्ष 2005-06 में 52,000 और वर्ष 2006-07 (नवंबर, 2006 तक) के दौरान 25,150 कार्यक्रम आयोजित किए।

जनवरी से मार्च 2006 की अवधि में इस प्रभाग ने सभी क्षेत्रीय इकाइयों के जरिए 21,000 कार्यक्रमों का आयोजन किया। इनमें एड्स से बचाव के लिए विशेष अभियान, आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल, न्यूनतम साझा कार्यक्रम और चुने हुए जिलों में विकास गतिविधियों तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबद्ध विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम प्रमुख थे। इस अवधि में 57 ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन किए गए। स्वतंत्रता दिवस समारोह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस, दांडी मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस और होली के सिलसिले में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सशस्त्र सेना मनोरंजन इकाई ने दिल्ली में एक विशेष समारोह का आयोजन

किया, जिसमें भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई केन्द्रीय मंत्री पधारे।

सशस्त्र सेना मनोरंजन इकाई

यह प्रभाग दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों तथा कठिन परिस्थितियों में रहने वाले सैन्य बलों की मनोरंजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। सशस्त्र सेना मनोरंजन इकाई की मंडलियां देश की सांस्कृतिक एकरूपता को दर्शाने वाले सभी राज्यों के लोकनृत्यों को उनके मौलिक और आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने के लिए बहुत सराही जाती हैं। इन मंडलियों में लेह, लद्दाख, चुमाथांग, थोयास, परतापुर, मोकोकचुंग, लुंग तलाई, आलोन समधु, पंग तथा पोर्टब्लेयर और अन्य द्वीपों में अप्रैल से दिसंबर 2006 की अवधि में 160 कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

जनजातीय क्षेत्रों में प्रचार

वर्ष 1980 में रांची जनजातीय केंद्र की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य विकास प्रक्रिया में जनजातीय कलाकारों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करके जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में मंडलियों ने 311 कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन कार्यक्रमों के जरिए वर्ष 2006-07 में जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई।

सीमावर्ती क्षेत्रों की प्रचार-प्रसार मंडलियां

सीमावर्ती प्रचार मंडलियां इम्फाल, गुवाहाटी, दरभंगा, नैनीताल, शिमला, जम्मू और जोधपुर में कार्यरत विभागीय मंडलियां हैं। इन मंडलियों ने अपने कार्यक्रमों के जरिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को जानकारी प्रदान की और सीमा पार से फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का निराकरण किया। ये कार्यक्रम एसएसबी, बीएसएफ और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ पूरे तालमेल से आयोजित किए गए।

विभागीय नाट्य मंडलियां

वर्ष के दौरान पुणे, पटना, हैदराबाद, भुवनेश्वर, जम्मू और दिल्ली स्थित विभागीय नाट्य मंडलियों ने विभिन्न विषयों पर नाटक प्रस्तुत किए। इनमें परिवार कल्याण, एड्स, नशाखोरी से बचाव, राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव और पर्यावरण आदि विभिन्न विषय शामिल थे। इन नाटक मंडलियों ने खास तौर से स्थानीय मेलों और उत्सवों तथा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2006 के दौरान नाटकों का मंचन किया। ऐसे अवसरों पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं।

योजनागत कार्यक्रम

योजनागत कार्यक्रमों के तहत प्रभाग ने पर्वतीय/जनजातीय/रेगिस्तानी संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों में सूचना संचार और तकनीक से संबद्ध (आईसीटी) गतिविधियां संचालित कीं और प्रभाव मूल्यांकन तथा 'गीत और नाटक प्रभाग के आधुनिकीकरण' संबंधी कार्यक्रम चलाए।

वर्ष 2006-07 के दौरान प्रभाग के स्वीकृत योजना कार्यक्रम के विशेष घटक निम्नांकित हैं :

(क) पर्वतीय/जनजातीय/रेगिस्तानी/संवेदनशील व सीमावर्ती क्षेत्रों में सूचना, संचार व तकनीक से संबद्ध गतिविधियां।

(ख) चुने हुए 56 जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन।

(ग) 12 प्रादेशिक केंद्रों में न्यूनतम साझा कार्यक्रम का प्रचार।

(घ) जम्मू-कश्मीर व पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम।

(ड़) राष्ट्रीय/सामाजिक विषयों पर नाटकों का मंचन।

(च) गीत व नाटक प्रभाग का आधुनिकीकरण।

पर्वतीय/जनजातीय, रेगिस्तानी/संवेदनशील व सीमावर्ती क्षेत्रों में आईसीटी गतिविधियां

यह प्रभाग दूर-दराज के जनजातीय, पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में कार्यक्रम चलाता है ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को उनके कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के प्रति जागरूक किया जा सके। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य इन क्षेत्रों के लोगों में देश के प्रति अपनेपन की भावना मजबूत करना और उन्हें समझ में आने वाले कार्यक्रमों के जरिए विकास कार्यों में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। इसके लिए स्थानीय लोगों की ही मंडलियां तैयार की जाती हैं जो स्थानीय बोलियों और शैलियों में कार्यक्रम तैयार करती हैं। इस योजना के तहत जनवरी से मार्च 2006 की अवधि में 1930 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

चुने हुए 56 क्षेत्रों में कार्यक्रम

योजना-कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2006-07 में इस प्रभाग ने संपूर्ण भारत में चुने हुए 56 जिलों में राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव, आतंकवाद के विरोध तथा देशभक्ति के भावों को प्रदर्शित करने वाले

कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जनवरी से मार्च 2006 की अवधि में इस तरह के 836 कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम का प्रसार

न्यूनतम साझा कार्यक्रम के प्रसार की योजना के तहत इस प्रभाग ने जनवरी-मार्च 2006 के दौरान 9940 कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया। इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों को न्यूनतम साझा कार्यक्रम के विभिन्न पक्षों की जानकारी दी गई।

जम्मू कश्मीर व पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम

वर्ष 2005-06 के दौरान इस प्रभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू-कश्मीर के और अन्य चुने हुए जिलों में विशेष कवरेज के लिए 3000 कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस विशेष घटक के अंतर्गत 2006-07 के दौरान 1,500 कार्यक्रम प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय हित के विषयों पर नाटकों का प्रस्तुतिकरण

आम जनता को राष्ट्रीय हित के मुद्दों के प्रति जागरूक करने, विशेषकर युवा वर्ग को देश की समृद्ध सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत की जानकारी मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रभाग की ध्वनि व प्रकाश इकाई देश के विभिन्न भागों में ध्वनि व प्रकाश कार्यक्रम आयोजित करती है। प्रभाग ने नई दिल्ली और सासाराम (बिहार) में **समर यात्रा,** शिमला में **कविता में कृष्ण,** कोलकाता और झांसी में **शतरूपा** शीर्षक से कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बंगलौर इकाई ने मैसूर और बंगलौर में **कर्नाटक वैभव,** कर्नाटक में हम्पी में **विजय नगर वैभव** और बंगलौर में **नेनेयो आ दनरूवा** नामक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वर्ष 2006-07 के दौरान प्रभाग ने (दिसंबर 2006 तक) 56 कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण

प्रभाग ने दिसंबर 2005-06 के दौरान देश भर में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से विभिन्न विषयों पर करीब 8100 कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वर्ष 2006-07 के दौरान इस तरह के 8,000 कार्यक्रम प्रदर्शित करने की योजना है। प्रभाग की क्षेत्रीय इकाइयों ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न भागों में विश्व जनसंख्या दिवस सहित विविध अवसरों पर आयोजित सभी स्वास्थ्य मेलों में विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए। दिल्ली में आयोजित परफेक्ट स्वास्थ्य मेले को विशेष प्रचार मिला। नवंबर 2006 में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर आयोजित प्रचार कार्यक्रम प्रभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। वर्ष 2005-06 के दौरान पल्स पोलियो टीकाकरण पर 2100 और आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग पर 448 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

एड्स रोकथाम के लिए विशेष अभियान

सभी क्षेत्रीय इकाइयों ने एड्स से बचाव पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन कार्यक्रमों से पहले भागीदार मंडलियों को महिलाओं और बालकों की देखभाल, बालिकाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों, एच.आई.वी. और एड्स जैसे विषयों की जानकारी दी गई। बंगलौर इकाई ने कर्नाटक राज्य एड्स इकाई के साथ मिलकर एड्स से बचाव के बारे में कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वर्ष 2005-06 के दौरान देश के चुने हुए जिलों में कुल मिलाकर 1200 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वन संरक्षण अभियान

प्रभाग ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के सहयोग से वन संरक्षण और सामाजिक वानिकी के विकास के बारे में अभियान चलाया। अभियान शुरू करने से पहले, प्रभाग की ओर से उसमें हिस्सा लेने वाले प्रशिक्षकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इन प्रशिक्षकों ने भागीदार कलाकारों के समूहों को जानकारी देने के लिए ऐसी ही कार्यशालाओं का आयोजन किया। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश में रतलाम, राजस्थान में जयपुर, बिहार में कटिहार, महाराष्ट्र में नागपुर, उत्तर प्रदेश में रायबरेली और तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जिलों को वन संरक्षण अभियान के लिए चुना गया था। वर्ष 2006-07 के दौरान इन चुने हुए जिलों में 253 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

भारत निर्माण—जन सूचना अभियान

वर्ष 2006-07 के दौरान प्रभाग ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित सभी जन सूचना अभियानों में हिस्सा लिया। इन अभियानों के दौरान सभी प्रचार इकाइयों ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, सभी स्कूलों में दोपहर के भोजन का कार्यक्रम, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन, सूचना का अधिकार अधिनियम आदि विषयों को प्रचारित करने में उल्लेखनीय भूमिका अदा की। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत विकास योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रभाग ने अभियान स्थलों पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अभियान से 5 दिन पहले और अभियान के बाद भी आसपास के गांवों में प्रचार कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 2006-07 के दौरान प्रभाग ने राजस्थान में उदयपुर और करौली, मध्यप्रदेश में झाबुआ और खंडवा, बिहार में दानापुर और पटना, मणिपुर में बिशनुपुर, उड़ीसा में क्योंझर, छत्तीसगढ़ में धमतारी, पश्चिम बंगाल में वीरभूम जिला, केरल में तिरुवनंतपुरम और वायनाड, आंध्रप्रदेश

में नलगौंडा और विजयवाड़ा, कर्नाटक में येलाहंका, हिमाचल प्रदेश में सिरमौर, त्रिपुरा में अगरतला, अमल में मिर्ज़ा और कामरूप, तमिलनाडु में कांचीपुरम, कड्डालूर, नागपट्टनम, डिंडीगुल और मदुरई, पुदुचेरी में कराइकल और अन्य कई स्थानों पर आयोजित जन सूचना अभियानों में भरपूर प्रचार किया।

मेले और पर्व

गीत एवं नाटक प्रभाग ने विशेष महत्व के दिवस मनाने के अलावा देश के विभिन्न भागों में स्थानीय मेलों और त्योहारों के अवसर पर भी प्रचार अभियानों में हिस्सा लिया।

अन्य प्रमुख गतिविधियां

प्रभाग ने देश भर में न्यूनतम साझा कार्यक्रम का विशेष प्रचार किया। पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाए गए। प्रभाग ने वर्ष के दौरान आतंकवाद-प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवाद-विरोधी विशेष कार्यक्रम चलाए। वर्ष 2006-07 के दौरान प्रभाग ने अम्बेडकर जयंती, पुरी रथ यात्रा महोत्सव, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, स्वतंत्रता दिवस, सद्भावना दिवस, गांधी जयंती, जम्मू-कश्मीर और देश के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में बहु-प्रचार माध्यम अभियान, कौमी एकता सप्ताह, बाल दिवस और अन्य सभी प्रमुख गतिविधियों और स्थानीय मेलों, त्यौहारों और वर्षगांठ समारोहों के दौरान व्यापक प्रचार किया।

वर्ष की शेष अवधि में प्रभाग की सभी महत्वपूर्ण अवसरों पर विशेष कवरेज प्रदान करने की योजना है।

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, प्रयासों और उपलब्धियों की जानकारी पत्र-पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों को संप्रेषित करने वाली केन्द्रीय एजेंसी है। प्रचार माध्यमों और सरकार के बीच माध्यम की भूमिका निभाने के अलावा पीआईबी पत्र-पत्रिकाओं में व्यक्त जनता की राय से सरकार को अवगत भी कराता है। पत्र सूचना कार्यालय अपने आठ क्षेत्रीय कार्यालयों और 34 शाखा कार्यालयों तथा सूचना केंद्रों के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, विशेष लेखों, पृष्ठभूमि, प्रेस विवरण, फोटोग्राफ, संवाददाता सम्मेलन, साक्षात्कार, पीआईबी के वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा बेस, प्रेस टूर, ए.वी. क्लिपिंग्स आदि के जरिए सूचनाओं का प्रचार करता है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं सहित 8400 अखबारों एवं मीडिया संगठनों के जरिए जानकारी प्रकाशित की जाती है।

ब्यूरो के मुख्यालय में विभागीय प्रचार अधिकारी हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ जुड़े हुए हैं। ये अधिकारी प्रेस विज्ञप्तियों और संवाददाता सम्मेलनों आदि के जरिए प्रचार माध्यमों को जानकारी संप्रेषित करने में विभाग की सहायता करते हैं और प्रचार गतिविधियों संबंधी सभी मामलों में सलाह देते हैं। वे संबद्ध मंत्रालयों और विभागों को मीडिया में उनके बारे में व्यक्त की गई लोगों की प्रतिक्रियाओं की जानकारी फीडबैक के रूप में देते हैं। विशेष सेवाओं के हिस्से के रूप में पीआईबी का फीडबैक सेल राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दैनिक पत्रों तथा पत्रिकाओं में प्रकाशित समाचारों और संपादकीयों के आधार पर दैनिक डाइजेस्ट (सार-संग्रह) और विशेष डाइजेस्ट तैयार करता है। ब्यूरो की विशेष सेवाओं का फीचर एकांश संदर्भ सामग्री, अद्यतन जानकारी, विशेष लेख और आरेख प्रदान करता है। यह सामग्री राष्ट्रीय नेटवर्क पर संप्रेषित की जाती है और इसे क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों को भी भेजा जाता है ताकि उसे अनुदित करके स्थानीय प्रेस को उपलब्ध कराया जा सके। प्रेस कतरन यूनिट द्वारा दिसंबर, 2006 तक करीब 5,15,600 ई-क्लिपिंग तैयार की गयीं।

फीचर एकांश सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए विशेष लेख जारी करता है। वर्ष के दौरान महिला अधिकारिता, बाल मजदूरी, पेयजल, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य (एड्स), लघु उद्योग और अन्य समसामयिक विषयों पर तैयार कराए गए विशेष लेख उल्लेखनीय हैं। यह यूनिट हर वर्ष औसतन 250 विशेष लेख प्रकाशित करती है, इनमें फोटो फीचर और संदर्भ सामग्री संबंधी लेख भी शामिल है।

पीआईबी ने वर्षभर विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की फोटो कवरेज की व्यवस्था की, और दैनिक पत्रों तथा पत्रिकाओं को फोटोग्राफ्स की आपूर्ति की। 1 अप्रैल-2006 से दिसंबर 2006 के बीच पीआईबी के फोटो प्रचार एकांश ने 936 कार्यक्रमों को कवर किया, और 2930 फोटो जारी किए। फोटो एकांश ने इस वर्ष फोटो पुस्तकालय (संग्रहालय) के डिजिटाइजेशन का काम शुरू किया। इस पुस्तकालय में करीब 8 लाख दुर्लभ फोटोग्राफ हैं, जिन्हें शीर्षक सहित संभाल कर रखा गया है। अभी तक एक लाख फोटोग्राफ का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। वर्ष के दौरान पीआईबी ने 59,393 प्रेस विज्ञप्तियां और 3773 विशेष लेख जारी किए और 1053 संवाददाता सम्मेलनों का आयोजन किया। ब्यूरो ने हाल ही में गोवा में हुए भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई)-2006 का शानदार प्रचार किया।

पत्र सूचना कार्यालय विदेशी मीडिया सहित प्रेस संवाददाताओं को प्रत्यायित (मान्यता) करता है। इससे संवाददाताओं को सरकारी स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। करीब 1194

संवाददाताओं और 331 कैमरामैन/फोटोग्राफरों को प्रत्यायित किया गया। इसके अतिरिक्त 140 तकनीशियनों और करीब 70 संपादकों तथा मीडिया समीक्षकों का भी प्रत्यायन किया गया।

पीआईबी का फीडबैक प्रकोष्ठ पत्र-पत्रिकाओं में छपी समाचार सामग्री और संपादकीय टिप्पणियों के आधार पर समाचारों और विचारों की दैनिक डायरी (डेली डाइजेस्ट) तैयार करता है। यह डाइजेस्ट सभी कार्य दिवसों में तैयार की जाती है और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति कार्यालयों, प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, मंत्रालयों और सभी सचिवालयों तथा सरकार में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को नियमित रूप से भेजी जाती है। इसके अतिरिक्त यह प्रकोष्ठ साप्ताहिक आधार पर 'आर्थिक मुद्दों के बारे में मीडिया रिपोर्ट' भी तैयार करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रेस में ध्यान आकृष्ट करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में भी समय-समय पर विशेष डाइजेस्ट और विशेष रिपोर्ट तैयार की जाती है। जनवरी-मार्च 2007 की अवधि में प्रकोष्ठ आर्थिक मुद्दों के बारे में दैनिक डाइजेस्ट और मीडिया रिपोर्ट तैयार करने के अलावा सामाजिक क्षेत्र के मुद्दों से संबंधित सम्मेलन, आर्थिक सर्वेक्षण, रेल बजट और आम बजट के बारे में भी विशेष डाइजेस्ट तैयार करेगा।

पीआईबी की वेबसाइट (http://pib.nic.in) भारत के छोटे और मझोले समाचार पत्रों के लिए सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी कार्य प्रणाली की समीक्षा की गई और इसे पत्रकारों एवं अन्य प्रयोक्ताओं के अनुकूल बनाया गया। मीडिया से प्राप्त फीडबैक के आधार पर सुझाए गए परिवर्तनों से पीआईबी वेबसाइट के होमपेज को नया स्वरूप मिला है और इसे गतिशील बनाने में मदद मिली है।

एक नई पहल करते हुए पीआईबी ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से श्रव्य-दृश्य सामग्री तैयार करने और उसे संप्रेषित करने के लिए विभागीय श्रव्य-दृश्य एकांश की स्थापना की है। इस सेवा का उदघाटन सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने 25 सितंबर, 2006 को किया। इस आडियो-विजुअल एकांश में दो हाई-एंड वीडियो कैमरे और नोन-लीनियर एडिटिंग सूट्स की व्यवस्था की गई है ताकि कैमरामैनों द्वारा एकत्र की गई वीडियो सामग्री का संपादन किया जा सके। सितंबर से दिसंबर 2006 की अवधि में 80 क्लिपिंग जारी की गईं। पीआईबी की वेबसाइट पर दृश्य-श्रव्य सामग्री प्रदर्शित करने के लिए एक नया सेक्शन कायम किया गया है, जिसे ऑनलाइन देखा जा सकता है और उसकी आनलाइन हाई रिजोल्यूशन कॉपी डाउनलोड की जा सकती है। यह नई सेवा विशिष्ट श्रव्य/दृश्य सामग्री उपलब्ध कराती है, जो समाचार चैनलों को नियमित कवरेज के जरिए उपलब्ध नहीं हो पाती। इसका इस्तेमाल तात्कालिकता के क्षणों में किसी मुद्दे पर अविलंब सरकार का दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए भी किया जा सकता है।

यूपीए सरकार के प्रमुख निर्णयों और उपलब्धियों को 69 पुस्तिकाओं में संकलित किया गया और पीआईबी द्वारा-'यूपीए सरकार के प्रमुख कार्यक्रम : राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में दो वर्ष की उपलब्धियां' (मेजर प्रोग्राम्स आफ यूपीए गवर्नमेंट : टू इयर्स आफ एचीवमेंट्स इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़) शीर्षक के अंतर्गत अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया। प्रधानमंत्री ने 'रिपोर्ट टू द पीपल' नामक पुस्तिका और यूपीए अध्यक्ष ने राज्यवार 69 पुस्तिकाएं 22 मई, 2006 को प्रधानमंत्री निवास पर हुए एक समारोह में जारी कीं। इन सभी प्रकाशनों का पीआईबी के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के जरिए देश भर में संप्रेषण किया गया। यह सामग्री ब्यूरो की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की गई।

प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधन, श्रीनगर में दूसरी राउंड टेबल कांफ्रेंस, हैदराबाद में एशियाई विकास बैंक की 39वीं आम बैठक, आंतरिक सुरक्षा के बारे में मुख्य सचिवों, मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधन, मुंबई विस्फोटों के बाद राष्ट्र को संबोधन, सूचना का अधिकार अधिनियम के एक वर्ष पूरा होने पर राष्ट्रीय सम्मेलन, योजना आयोग की पूर्ण बैठक और राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की बैठक में भाषण को विशेष कवरेज प्रदान की गयी।

मुंबई विस्फोटों, डॉक्टरों की हड़ताल, आंध्र प्रदेश, मुंबई और गुजरात में बाढ़ जैसे विभिन्न संकटों के अवसर पर सरकार द्वारा किए गए उपायों का प्रचार किया गया।

पीआईबी ने प्रधानमंत्री की जर्मनी और उज्बेकिस्तान यात्राओं, सेंट पीटर्सबर्ग में जी-8 सम्मेलन, हेलसिंकी में यूरोपीय संघ सम्मेलन और हवाना में सार्क सम्मेलन में भागीदारी, 'सत्याग्रह' के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की यात्रा, ब्रिटेन यात्रा और जापान यात्रा की कवरेज के लिए विशेष व्यवस्था की।

वर्ष के दौरान सर्वोच्च स्तर पर कैबिनेट और विभिन्न कैबिनेट समितियों द्वारा अभूतपूर्व तेजी के साथ रिकार्ड संख्या में निर्णय लिए गए। कैबिनेट और कैबिनेट समितियों के ये निर्णय तेजी के साथ मीडिया को संप्रेषित किए गए। इसके लिए संबद्ध मंत्रालयों द्वारा रिकार्ड संख्या में संवाददाता सम्मेलनों का आयोजन किया गया और बाद में ये निर्णय पीआईबी की वेबसाइट में शामिल किए गए।

मीडिया कर्मियों को दैनिक आधार पर जानकारी प्रदान करने के लिए मीडिया रूम में संस्थागत व्यवस्था भी की गयी है। गृह मंत्री/

गृह सचिव के साथ प्रेस दौरों का भी आयोजन किया गया। इनमें अमृतसर-लाहौर बस सेवा के सिलसिले में गृह सचिव के साथ वाघा सीमा का दौरा, गृह मंत्री के साथ भारत-बंगलादेश सीमा, अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा के लिए गृह सचिव के साथ जम्मू-कश्मीर दौरा, श्रीनगर में संपादकों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए गृह सचिव के साथ श्रीनगर का दौरा, बीएसएफ अकादमी में पासिंग आउट परेड के अवसर पर टेकनपुर में सीआरपीएफ के आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखने संबंधी समारोह में हिस्सा लेने के लिए लातूर का दौरा शामिल है।

विभिन्न आयोगों और समितियों, जैसे व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति, आर्थिक सलाहकार परिषद, ऊर्जा समन्वय समिति, कृषि समन्वय समिति को प्रचार सहायता प्रदान की गयी। इसी प्रकार ज्ञान आयोग, बुनियादी ढांचा समिति, ग्रामीण ढांचा समिति, जैसी समितियों में प्रधानमंत्री की पहल की जानकारी मीडिया को दी गई।

भारत-अमरीका परमाणु समझौते के बारे में राज्यसभा में दिए गए प्रधानमंत्री के जवाब को संचार माध्यमों में प्रचारित किया गया। पीआईबी ने इसे हिंदी और उर्दू में अनुवाद कराया और उसकी प्रतियां प्रधानमंत्री कार्यालय तथा डीएवीपी को पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करने के लिए उपलब्ध कराईं। देश भर में संप्रेषित करने के लिए प्रधानमंत्री के भाषण की एक सौ सीडी तैयार की गईं। राज्यसभा और लोकसभा में इस मुद्दे पर दिए गए प्रधानमंत्री के भाषणों को पीआईबी की वेबसाइट पर श्रव्य-दृश्य फार्मेट में उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमत्री के परमाणु वैज्ञानिकों के साथ हुए विचार-विमर्श के व्यापक प्रचार की व्यवस्था की गयी।

वर्ष के दौरान प्रचारित प्रमुख मुद्दों में निम्नांकित शामिल हैं :

(1) मुंबई और मालेगांव बम विस्फोटों और वडोदरा में हुई हिंसा से निपटने के लिए सरकार के प्रयास, (2) दांतेवाड़ा में बड़े नक्सली हमले को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को दी गई सहायता, (3) जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित राज्यों की स्थिति, (4) बाढ़ प्रभावित राज्यों को दी गई सहायता, (5) आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के बारे में सचिवों एवं पुलिस महानिदेशकों की बैठक (6) नक्सलवाद के बारे में मुख्यमंत्रियों की स्थायी समिति की बैठक, (7) असम में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार और पीपुल्स कन्सल्टेटिव ग्रुप (पीसीजी) के बीच वार्ता, (8) भारत द्वारा पाकिस्तान के असैनिक कैदियों और मछुआरों की रिहाई, (9) आपदा जोखिम प्रबंधन के बारे में दक्षिण एशियाई नीति वार्ता, (10) भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश तथा भारत और म्यांमार के बीच गृह सचिव स्तर की वार्ताएं, (11) नक्सलवाद और आंतरिक सुरक्षा के बारे में मुख्यमंत्रियों की बैठक, (12) मोहम्मद अफज़ल के मामले में दया याचिका, (13) पुलिस अधिनियम 1861 को बदलने के प्रयासों सहित पुलिस सुधार, (14) नेताजी के बारे में मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट।

आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के 31 जिलों के किसानों के लिए ऋण राहत के रूप में घोषित पुनर्वास पैकेज के व्यापक प्रचार की व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बीज नीति, और राष्ट्रीय बांस मिशन आदि योजनाओं के प्रारंभ का संचार माध्यमों में प्रचार किया गया।

एपीएमसी अधिनियम के संशोधन के जरिए कृषि विपणन को बढ़ावा देने और टर्मिनल बाजारों की स्थापना की तैयारी जैसे विषयों को समुचित मीडिया कवरेज दिलाई गई।

प्रचार माध्यमों में फसल पैदावार के अग्रिम अनुमान, रबी अभियान, और कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा भी प्रमुखता से प्रचारित की गई।

वर्ष के प्रारंभ में एवियन एन्फ्लुएंजा फैलने से पैदा हुई स्थिति से निपटने में समुचित प्रचार सहायता प्रदान की गई। इसके लिए पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दैनिक संवाददाता सम्मेलनों के आयोजन की व्यवस्था की गई।

प्रधानमंत्री द्वारा अधिक संख्या में सर्वेक्षण परमिट जारी किए जाने और अधिक विदेशी निवेश आमंत्रित करने के प्रयास को समुचित रूप से प्रचारित किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन (एनएलसी), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल), नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको), भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) और मिनरल एक्स्प्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल) की उपलब्धियों को नियमित रूप से प्रचारित किया गया।

ढाबों, रेस्तराओं, दुकानों आदि में बच्चों को घरेलू नौकर के रूप में रखने पर प्रतिबंध, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किए गए कानून के मसौदे, 5 वर्ष में 10 लाख लोगों और उसके बाद हर वर्ष 10 लाख लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए कौशल विकास के उपायों संबंधी योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा लाभार्थी श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की चिकित्सा खर्च सुविधाओं में बढ़ोतरी जैसे विषय व्यापक रूप में प्रचारित किए गए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा ईपीएफ संबंधी कार्यों के कम्प्यूटरीकरण और ईपीएफ ग्राहकों को विशिष्ट राष्ट्रीय सामाजिक

सुरक्षा संख्या जारी करने के लिए 6 स्थानों पर प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई परियोजना 'री-इनवेंटिंग ईपीएफ इंडिया' के शुभारंभ को समुचित कवरेज दी गई।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा, 10वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा, मोहाली में नए विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह, सर्व शिक्षा अभियान, दोपहर के भोजन की योजना, लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यूजीसी-सीईसी एडुसैट नेटवर्क, अल्पसंख्यक शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय निगरानी समिति, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन, भारत में साक्षरता के प्रसार में सहायता के रूप में ओपन स्कूलिंग जैसी खबरों को प्रेस विज्ञप्तियों, संदर्भ सामग्री, विशेष लेख आदि के जरिए व्यापक रूप से प्रचारित किया गया।

राष्ट्रपति डा. ए पी जे अब्दुल कलाम द्वारा निशुल्क शैक्षिक पोर्टल 'साक्षात' का शुभारंभ और जर्मनी के फ्रेंकफर्ट में मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह द्वारा 58वें फ्रेंकफर्ट पुस्तक मेले के उद्घाटन को भी प्रचारित किया गया। फ्रेंकफर्ट पुस्तक मेला दुनियाभर के प्रकाशन व्यवसायियों के लिए सबसे बड़ा आयोजन था। इससे प्रकाशन उद्योग को अद्यतन गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने, नई धारणाओं और विचारों के आदान प्रदान और पुस्तकों की खरीद-फरोख्त का महत्वपूर्ण अवसर मिला। भारत को 2006 के फ्रेंकफर्ट पुस्तक मेले में विशेष रूप से सम्मानित किया गया। पीआईबी ने ''फ्रेंकफर्ट पुस्तक मेला'' शीर्षक से एक विशेष लेख जारी किया।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग तथा उपभोक्ता मामलों के विभाग की विकास गतिविधियों को उजागर करने के लिए प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उपभोक्ता मामलों संबंधी नीतिगत निर्णयों को प्रचारित करने के लिए मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिल्ली और अन्य शहरों में कई अवसरों पर संवाददाता सम्मेलनों का आयोजन किया गया और विषयगत पर्चे बांटे गए।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोतरी रोकने के लिए सम्बद्ध मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए नियमित रूप से पर्चे वितरित किए गए। गेहूं और दालों के आयात की स्थिति की जानकारी भी समय-समय पर प्रेस को उपलब्ध कराई गई। उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने और उपभोक्ता आंदोलन में स्कूली बच्चों और युवाओं को शामिल करने के लिए प्रचार अभियान चलाया गया। बड़ी संख्या में पर्चे वितरित करके जरूरी वस्तुओं के वायदा सौदों और राष्ट्रीय स्तर पर इन वस्तुओं के आदान-प्रदान का पर्याप्त कवरेज किया गया।

'गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और विकास का अधिकार' विषय पर राष्ट्रीय विधि प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय विचार गोष्ठी और दिल्ली विधि प्राधिकरण की रजत जयंती समारोह के सिलसिले में दिल्ली में आयोजित समारोहों संबंधी खबरों का व्यापक प्रचार किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। आर्थिक सम्पादकों के सम्मेलन में इस्पात, उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय ने हिस्सा लिया और मंत्री श्री रामविलास पासवान ने संपादकों को संबोधित किया। पीआईबी ने 'उर्वरक और भारत में खेती को बेहतरी' विषय पर फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित विचारगोष्ठी का व्यापक प्रचार किया, जिसमें श्री रामविलास पासवान मुख्य अतिथि थे।

गोवा में 37वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई)

आईएफएफआई में मीडिया सेंटर, पीआईबी ने भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए गोवा की राजधानी पणजी में मीडिया सेंटर स्थापित किया। गोवा में आईएफएफआई-2006 की कवरेज के लिए देश के विभिन्न भागों से संचारकर्मियों को 408 प्रत्यायन कार्ड वितरित किए गए। इनमें से 296 संचारकर्मी मुद्रित माध्यम और 112 इलेक्ट्रोनिक माध्यम से सम्बद्ध थे। समारोह के दौरान 51 संवाददाता सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इनकी शुरुआत 22 नवंबर 2006 को संक्षिप्त परिचर्यात्मक संवाददाता सम्मेलन से हुई। इन संवाददाता सम्मेलनों को फिल्म समारोह निदेशालय के निदेशक और गोवा के मुख्य सचिव ने संबोधित किया।

प्रेस विज्ञप्तियां : 'फिल्म समारोह' के समाचार देने के लिए अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू और मराठी में 407 प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं। इन विज्ञप्तियों में 42 फिल्मों का परिचय शामिल था। पीआईबी ने आईएनओएक्स और कला अकादमी पुरस्कार दिए जाने के कार्यक्रमों में मीडिया को जुटाने और उसकी व्यवस्था में सहायता की।

फोटो प्रचार : 'फोटो एकांश ने आईएफएफआई-06 के 157 फोटोग्राफ मीडिया सेंटर में जारी किए। ये फोटोग्राफ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से सम्बद्ध थे, जैसे-उद्घाटन समारोह, भारतीय पेनोरमा, मुक्त मंच, आईएनओएक्स और कला अकादमी के प्रस्तुतिकरण, संवाददाता सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समापन समारोह। इन्हें पीआईबी वेबसाइट और आईएफएफआई-2006 की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया। मीडिया सेंटर में स्थापित सूचना डेस्क ने 37वें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई) के बारे में संचारकर्मियों को सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई। इस डेस्क ने 20 नवंबर से 3 दिसंबर 2006 तक काम किया और

प्रदर्शन कार्यक्रम, संवाददाता सम्मेलनों के आयोजन, पुस्तिकाएं, पर्चे और समारोह के न्यूजलेटर आदि जारी किए।

आर्थिक संपादकों का सम्मेलन, 2006

आर्थिक संपादकों के वार्षिक सम्मेलन-2006 का उद्घाटन वित्त मंत्री ने किया। दो दिन के इस सम्मेलन में देशभर से आये करीब 300 संपादकों और वित्तीय विषयों से संबद्ध लेखकों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में आर्थिक और बुनियादी ढांचे से संबद्ध 11 महत्वपूर्ण मंत्रालयों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन से सरकार को आर्थिक संपादकों से फीडबैक हासिल करने में मदद मिली। सम्मेलन से संबंधित खबरों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और पत्र-पत्रिकाओं में व्यापक स्थान मिला।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के पूर्णाधिकारियों का सम्मेलन

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के पूर्णाधिकारियों का सम्मेलन 6 से 24 नवंबर 2006 के बीच तुर्की में अंटाल्या में आयोजित किया गया। इस बारे में परिचयात्मक (कर्टेन रेजर) स्तर से लेकर सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया। सम्मेलन के दौरान भारत के काउंसिल के लिए फिर से चुने जाने और चुनाव के माध्यम से भारतीय प्रतिनिधि के रेडियो रेगुलेशन्स बोर्ड (आरआरबी) के लिए चुने जाने को व्यापक कवरेज दिलाई गई। ब्रूनई दारुसलाम के संचार मंत्री श्री पेहिन अबू बाकर अपोंग और मिस्र के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर तारिक केमल के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद के साथ बैठक को संचार माध्यमों में यथेष्ट स्थान दिलाया गया। 'इन' डोमेन रजिस्ट्रेंट्स के दो लाख की संख्या को पार कर जाने पर प्रेस विज्ञप्ति के जरिए व्यापक प्रचार किया गया।

हार्वर्ड और वार्टन बिजनेस स्कूल के विद्यार्थियों की रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव के साथ नई दिल्ली में बैठक

हार्वर्ड और वार्टन बिजनेस स्कूल के 137 विद्यार्थियों ने नई दिल्ली में रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव से भेंट की। पीआईबी ने एक अभिनव उपाय करते हुए रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव की हार्वर्ड तथा वार्टन बिजनेस स्कूल के विद्यार्थियों के साथ 27 दिसंबर 2006 को हुई बैठक की श्रव्य-दृश्य क्लिप जारी की। इस बैठक से संबंधित यह एकमात्र रिकार्ड था, जिसका इस्तेमाल मुद्रित और इलेक्ट्रोनिक दोनों ही प्रचार माध्यमों द्वारा संबंधित समाचार देने के लिए किया गया। इस घटना की कवरेज के लिए एकमात्र इलेक्ट्रोनिक माध्यम का काम पीआईबी के ए.वी. सेल ने किया। विद्यार्थियों के साथ दिलचस्प वार्तालाप के दौरान मंत्री ने उन्हें रेलवे के विभिन्न पहलुओं के बारे में तथ्य और आंकड़े पेश करते हुए भारतीय रेल सेवाओं के कायापलट की जानकारी दी। विद्यार्थियों को दी गई उनकी इस सलाह को पीआईबी ने उपयुक्त ढंग से प्रचारित किया कि किसी भी संगठन के प्रबंधन में जमीनी वास्तविकताओं का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वार्तालाप सत्र के तत्काल बाद एक संवाददाता सम्मेलन भी आयोजित किया गया।

'इंडिया टेलिकॉम 2006'-तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन

दूरसंचार विभाग के तत्त्वाधान में फिक्की और टेलिकॉम इक्विपमेंट मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन (टेमा) के सहयोग से इंडिया टेलिकॉम 2006 शीर्षक से तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पहली बार दुनिया की बड़ी दूरसंचार कंपनियां एक मंच पर दिखाई दीं। सम्मेलन और प्रदर्शन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने किया। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री दयानिधि मारन ने इंडिया टेलिकॉम 2006 के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की राउंड टेबल बैठक में दस सूत्रीय चार्टर की घोषणा की। पीआईबी ने चार्टर और तीन दिन के इस आयोजन से संबंधित समाचारों को संचार माध्यमों में व्यापक कवरेज दिलाई।

स्वतंत्रता दिवस समारोह

स्वतंत्रता दिवस से संबंधित प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के भाषणों की मीडिया कवरेज की व्यापक व्यवस्था की गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण को संप्रेषित करने के व्यापक प्रबंध किए गए। प्रधानमंत्री का भाषण पीआईबी की वेबसाइट पर प्रसारित (वेबकास्ट) किया गया। प्रधानमंत्री के भाषण का समूचा पाठ और तत्संबंधी विशेष बातें संचारकर्मियों की सुविधा के लिए जारी की गईं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के भाषण के संप्रेषण के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति का भाषण भी वेबसाइट पर वेबकास्ट किया गया।

क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा प्रचार

पीआईबी जालंधर ने राष्ट्रपति डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की लुधियाना और अमृतसर यात्राओं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 पर फ्लाई ओवर के निर्माण कार्य के उद्घाटन के लिए जहाजरानी, भूतल परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री श्री के.एच. मुनियप्पा की फगवाड़ा यात्रा, उद्योग राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार (तीन यात्राएं), पंचायती राज, युवा मामलों और खेल मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर, अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री विलास मुत्तेमवार, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष

डॉक्टर गिरिजा व्यास, गृह सचिव श्री वी.के. दुग्गल की यात्राओं का व्यापक प्रचार किया।

पीआईबी राजकोट ने यूनिसेफ के सहयोग से दो क्षेत्रीय मीडिया कार्यशालाओं का आयोजन किया।

पीआईबी नांदेड ने दूरदर्शन, आकाशवाणी और क्षेत्रीय प्रचार एकांश सहित मंत्रालय की अन्य प्रचार माध्यम इकाइयों को सेवाएं प्रदान कीं। इन एकांशों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के प्रचार की व्यवस्था की गई। इन कार्यक्रमों में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी द्वारा एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और एड्स जागरूकता अभियान प्रमुख थे।

पीआईबी जयपुर ने दो प्रचार माध्यम कार्यशालाओं का आयोजन किया। पहली कार्यशाला विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के लिए आयोजित की गई, जिसमें उत्तरी क्षेत्र की सभी क्षेत्रीय प्रदर्शनी इकाइयों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारियों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, एड्स और लेखा प्रक्रिया संबंधी मामलों की जानकारी प्रदान करना था। दूसरी कार्यशाला नेहरू युवा केंद्र के लिए आयोजित की गई, जिसमें नेहरू युवा केंद्र के क्षेत्रीय और जिला समन्वयकों ने हिस्सा लिया। पीआईबी जयपुर ने भारतीय सेना द्वारा आयोजित 'सद्भावना यात्रा' की कवरेज की भी विशेष व्यवस्था की। इस यात्रा के दौरान जम्मू-कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों ने राजस्थान की संस्कृति, कला, शिक्षा और इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य के विभिन्न शहरों का दौरा किया।

पीआईबी श्रीनगर ने जून 2006 में सामाजिक ढांचे के बारे में संपादकों के सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें जम्मू-कश्मीर पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह और मुख्यमंत्री श्री गुलाम नबी आजाद ने संयुक्त रूप से किया। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय, जम्मू-कश्मीर के उप मुख्यमंत्री श्री मुजफ्फर हुसैन बेग, केंद्रीय गृह सचिव श्री वी.के. दुग्गल तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों ने सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में 150 से अधिक संवाददाताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें 37 राज्य से बाहर के थे। पत्रकारों को कश्मीर घाटी के विभिन्न पर्यटक स्थलों और अन्य पवित्र स्थलों पर ले जाया गया।

पीआईबी गंगटोक ने उपराष्ट्रपति श्री भैरोसिंह शेखावत और तत्कालीन पंचायती राज मंत्री, शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की सिक्किम यात्राओं को कवरेज प्रदान की। नाथुला दर्रे के जरिए सीमा व्यापार पुन: खोलने की ऐतिहासिक घटना को क्षेत्र एवं समूचे देश में व्यापक रूप से प्रचारित किया गया।

पीआईबी चेन्नई ने इस क्षेत्र में प्रेस जगत को सुविधा पहुंचाने के लिए स्वयं की द्विभाषी वेबसाइट: www.- pibchennai.gov.in का संचालन जारी रखा। हाल ही में वेबसाइट के डिजाइन को नया रूप दिया गया और इसमें समाचारों, विशेष लेखों और फोटो जैसी परम्परागत सुविधाओं के अतिरिक्त कुछ नई विशेषताएं भी जोड़ी गईं। पीआईबी चेन्नई ने सूचना अधिकार अधिनियम कार्यशाला, हिंदी कार्यशाला जैसी विभिन्न मीडिया कार्यशालाओं का आयोजन किया।

पीआईबी कोच्चि ने महिलाओं की अधिकारिता, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, आयकर विभाग के संदर्भ में स्थायी लेखा संख्या यानी पैन के महत्व, कचरा प्रबंधन, अपरम्परागत ऊर्जा संवर्द्धन और पीएमएस द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने जैसे सरकार के उपायों पर प्रकाश डालने वाले विशेष लेख प्रचारित किए।

पीआईबी हैदराबाद ने हैदराबाद में 7 से 9 जनवरी 2006 की अवधि में आयोजित चौथे प्रवासी भारतीय दिवस के प्रचार की पुख्ता व्यवस्था की। इसका आयोजन अप्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। पीआईबी ने इस कार्यक्रम से संबद्ध कवरेज में सहायता के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पर मीडिया सेंटर की स्थापना की और करीब 390 संचारकर्मियों को विशेष प्रत्यायन कार्ड जारी किए। इनमें स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रचार माध्यमों से संबद्ध संचारकर्मी शामिल थे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन एवं समापन समारोहों के अलावा पीआईबी ने तीन दिन तक चले इस समारोह में विभिन्न सत्रों और संवाददाता सम्मेलनों, आप्रवासी भारतीय कार्य मंत्री द्वारा प्रेस को दी गई जानकारी आदि के लिए प्रचार की व्यवस्था की। इस कार्यालय द्वारा एड्स की रोकथाम, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन और ग्रामीण विकास आदि के बारे में भी विशेष प्रचार अभियान आयोजित किए गए, जिनमें इन गतिविधियों से संबद्ध प्रेस विज्ञप्ति, विशेष लेख, फोटोग्राफ आदि जारी करना शामिल था। इससे मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही प्रचार माध्यमों के जरिए आम लोगों में जागरूकता पैदा करने में मदद मिली।

पीआईबी अगरतला ने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सर्व शिक्षा अभियान, सभी स्कूलों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था, सूचना का अधिकार अधिनियम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दों के व्यापक प्रचार का प्रबंध किया।

पीआईबी बंगलौर ने मीडिया टेलीफोन डायरेक्टरी-2006 प्रकाशित की। डायरेक्टरी का विमोचन केन्द्रीय जहाजरानी, भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री के.एच. मुनिअप्पा ने पीआईबी द्वारा आयोजित एक समारोह में किया। डायरेक्टरी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इसकी प्रचार माध्यम इकाइयों, पीआईबी एवं राज्य सूचना विभाग द्वारा कर्नाटक से प्रत्यायित पत्रकारों, आदि से संबंधित जानकारी दी गई है। इस कार्यालय ने एक दिन की राज्य स्तरीय मीडिया जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। इसका विषय था 'तंबाकू के दुष्प्रभाव'। यह कार्यशाला केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित की गई थी। कार्यशाला का उद्घाटन राज्यसभा के उपसभापति श्री के. रहमान खान ने किया। पीआईबी बंगलौर ने 'सूचना का अधिकार' के बारे में कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिसिएटिव (सीएचआरआई) के साथ मिलकर केनरा बैंक, विजया बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, सिंडिकेट बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक की मदद से एक मीडिया कार्यशाला, *इन्फो मीट* का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय योजना राज्य मंत्री श्री एम. वी. राजशेखरन द्वारा किया गया।

मुख्यालय से प्राप्त यूपीए सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों से संबद्ध पुस्तिका 'यूपीए गवर्मेंट-टू इयर्स ऑफ अचीवमेंट्स (कर्नाटक)' के अंग्रेजी संस्करण का कन्नड़ में अनुवाद कराया गया और उसे पीआईबी मुख्यालयों को भेजा गया। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के महत्वपूर्ण विषयों जैसे महिला अधिकारिता और जल प्रबंधन से संबंधित एक विशेष लेख जारी किया गया और स्थानीय प्रेस तथा जिला स्तरीय अखबारों को भेजा गया। यूपीए सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियों के बारे में उर्दू में कई लेख उर्दू के अखबारों को जारी किए गए। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में अनेक प्रेस विज्ञप्तियां भी जारी की गईं।

मौजूदा प्रचार माध्यम नीति के पूरक के रूप में पीआईबी ने नई प्रचार माध्यम संपर्क रणनीति (मीडिया आउटरीच स्ट्रेटजी) तैयार की। प्रचार माध्यम संपर्क कार्यक्रम ने सरकार और प्रचार माध्यमों के बीच अब तक एक माध्यम की भूमिका तक सीमित रहे पीआईबी की गतिविधियों में एक नया आयाम जोड़ दिया है। प्रचार माध्यम संपर्क घटक के अंतर्गत एक अभिनव नीति अपनाई जाती है, जिसमें सूचना संप्रेषण को लाभार्थियों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों के द्वार तक सेवाओं के वितरण के साथ जोड़ा गया है। प्रचार माध्यम संपर्क नीति को सूचना संप्रेषण के एक समग्र साधन के रूप में तैयार किया गया है। इसमें 'आम आदमी' के साथ सीधे संपर्क कायम करने और सामान्य-जन खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को निम्नांकित प्रमुख कार्यक्रमों के जरिए जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है ताकि वे अपने जीवन की गुणवत्ता सुधारने में इन कार्यक्रमों का लाभ उठा सके।

क) भारत निर्माण ग्रामीण ढांचे के विकास के लिए पैकेज।

ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम।

ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।

घ) सर्व शिक्षा अभियान।

ड़) दोपहर के भोजन का कार्यक्रम।

च) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन।

छ) सूचना का अधिकार अधिनियम।

ज) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम।

झ) समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम।

योजना के घटक

इस योजना के चार घटक हैं :

(क) जन सूचना अभियान

(ख) प्रचार माध्यम परस्पर संपर्क सत्रों का आयोजन

(ग) सफलता की कहानियों का संप्रेषण

(घ) प्रेस टूर (संचारकर्मियों की यात्राओं का आयोजन)

(क) जन सूचना अभियान

अभिनव संपर्क नीति के हिस्से के रूप में पीआईबी ने जन सूचना अभियानों की धारणा का विकास किया है, जो देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। इन अभियानों का उद्देश्य यूपीए सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए लक्षित लाभार्थियों तक जानकारी संप्रेषित करना है। इस नीति के अंतर्गत लाभार्थियों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके द्वार पर सेवाओं के वितरण के साथ सूचना संप्रेषण को जोड़ा गया है।

प्रत्येक जन सूचना अभियान पांच दिन की अवधि का होता है और उसमें करीब 25 स्टॉल लगाये जाते हैं, जो केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इन स्टॉलों पर उदाहरण के साथ यह बताया जाता है कि सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यक्रमों से कैसे लाभ उठाया जाए। प्रमुख बैंकों, बीमा कंपनियों, नाबार्ड, फारवर्ड मार्केटिंग कमीशन (अग्रिम विपणन आयोग) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान

और स्थानीय स्वैच्छिक संगठन, युवा संगठन आदि भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्रचार इकाइयों, पीआईबी, डीएफपी, डीएवीपी, गीत और नाटक प्रभाग के साथ इन अभियानों में हिस्सा लेते हैं। आस-पास के जिलों से संचार प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है, जिससे इस सूचना संप्रेषण अभियान को अधिक प्रभावकारी बनाने में मदद मिलती है। महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों जैसे सूचना का अधिकार, एड्स जागरूकता, कृषि की उत्कृष्ट पद्धतियां, एनआरईजीपी, कन्या भ्रूण हत्या के सामाजिक-आर्थिक और जन-सांख्यिकीय प्रभाव और अन्य प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में विचार-गोष्ठियां भी आयोजित की जाती हैं, जिनमें विशेषज्ञों, संसद सदस्यों, विधायकों, पंचायती राज प्रतिनिधियों और स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल किया जाता है।

बहु-प्रचार माध्यम नीति अपनाते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्रचार माध्यम इकाइयों को शामिल करने से यूपीए सरकार के प्रमुख कायक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा की गई। अभियान के दौरान क्षेत्रीय अधिकारियों ने संप्रेषण के लिए संबद्ध राज्य और जिले के बारे में विशेष जानकारी हासिल की।

अभियान के दौरान स्थानीय स्तर (डीएफपी की क्षेत्रीय इकाइयों के जरिए) पर एकत्र की गई सफलता की कहानियों को फोटोग्राफ और डीएवीपी की प्रदर्शनियों के जरिए उजागर किया गया। ये फोटोग्राफ आगे संप्रेषण के लिए पीआईबी मुख्यालय को भी भेजे गए।

अभियानों के दौरान लोगों की राय और प्रतिक्रियाएं भी एकत्र की गयीं।

पीआईबी के क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों ने दिसंबर 2006 के अंत तक देश भर में 55 जन सूचना अभियान (सूची संलग्न) आयोजित किए। इन अभियानों में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अनुमान है कि देश के विभिन्न भागों में आयोजित इन अभियानों में से प्रत्येक में औसतन करीब 75000 लोगों ने हिस्सा लिया। स्थानीय अखबारों ने इन अभियानों को व्यापक कवरेज प्रदान की और इस बारे में हजारों प्रेस क्लिपिंग एकत्र की। अभियानों में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने शिरकत की। इनमें केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकारों के मंत्री, जनप्रतिनिधि (सांसद, विधायक, विधान परिषद के सदस्य), पंचायती राज प्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। अभियानों में हिस्सा लेने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सूची संलग्न है।

(ख) संचार माध्यम परस्पर संपर्क सत्र :

संचार माध्यम संपर्क कार्यक्रम का दूसरा घटक संचार माध्यम परस्पर संपर्क शृंखलाओं का आयोजन था, जो चुनी हुई राज्यों की राजधानियों में आयोजित किए गए। इन सत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा, विकास योजनाओं आदि मुद्दों पर चर्चा हुई। इस उपाय के अंतर्गत संबद्ध मंत्रालयों के महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया गया ताकि वे पूर्वोत्तर जैसे देश के पिछड़े क्षेत्रों और आतंकवाद से पीड़ित जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपायों पर प्रकाश डालने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय प्रचार माध्यमों से रू-ब-रू हो सकें। इन प्रचार शृंखलाओं का आयोजन दो-तीन दिन तक जारी रहा और उनमें देश के विभिन्न भागों से पत्रकारों को आमंत्रित किया गया ताकि वे सामाजिक-आर्थिक और ढांचागत विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे विकास के विभिन्न उपायों का विश्लेषण करें और उनके बारे में लिखें। परस्पर संपर्क की इन प्रचार शृंखलाओं का आयोजन अभी तक चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, गुवाहाटी में किया गया है। (विवरण संलग्न है)

(ग) सफलता की कहानियों का संप्रेषण :

संचार माध्यम परस्पर संपर्क कार्यक्रम का तीसरा महत्वपूर्ण घटक देश के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में सफलता की कहानियों, लोगों के प्रयासों को संकलित करना और उन्हें संप्रेषित करना है। जन सूचना अभियान आयोजित करते हुए पीआईबी ने लघु ऋण, ऊर्जा संरक्षण, स्वच्छता, पेयजल की व्यवस्था, रोजगार के अवसर पैदा करने आदि विकासात्मक कार्यक्रमों में लोगों का नेतृत्व करने में अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्तियों/संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों/सरकारी एजेंसियों की पहचान की। इस तरह की सफलता की कहानियों को संकलित किया गया और स्थानीय भाषाओं में अनुदित करके स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर संप्रेषित किया गया। इस काम में एएनआई, आईएएनएस और यूएनआई जैसी समाचार एजेंसियों की सेवाओं का इस्तेमाल करते हुए प्रेस विज्ञप्तियां/ विशेष लेख भी तैयार किए गए। ये विशेष लेख प्रचार माध्यमों को जारी किए गए ताकि मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए उनका उचित प्रचार-प्रसार किया जा सके।

(घ) प्रेस टूर :

देश के दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में सफल हुए जन-कार्यक्रमों की पहचान की गई और उन्हें दर्शाने के लिए राष्ट्रीय तथा स्थानीय संचारकर्मियों को विकासात्मक परियोजनाओं पर ले जाया गया। इसके अंतर्गत दूरदराज के वे गांव भी शामिल थे, जहां व्यक्तियों, संगठनों और सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया जा सका।

परस्पर संपर्क संचार सत्र/संपादक सम्मेलन
पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान

उत्तरी क्षेत्र पर विशेष ध्यान
चंडीगढ़ सम्मेलन : (17-18 अप्रैल, 2006)

- केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री द्वारा संबोधन।
- शहरी विकास और आप्रवासी भारतीय कार्य मंत्री द्वारा संबोधन।
- चंडीगढ़ और पंजाब से 70 पत्रकारों ने हिस्सा लिया।

जम्मू-कश्मीर क्षेत्र पर विशेष ध्यान
श्रीनगर सम्मेलन : (22-24 जून, 2006)

- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटन।
- ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा संबोधन।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, रेलवे, गृह मंत्री द्वारा संबोधन।
- जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ वार्तालाप।
- करीब 157 पत्रकारों ने हिस्सा लिया (23 राष्ट्रीय स्तर के, 11 दिल्ली से, 10 जम्मू से, 110 श्रीनगर से)।

(दाचीगाम अभयारण्य, फूलों की खेती, बागवानी और पर्यटक स्थलों की यात्राएं की गईं)

वर्ष 2006-2007 के लिए सतर्कता गतिविधियां

1) मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता व्यवस्था

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अगले आदेश तक के लिए श्री टी.एस. आरसू, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) को पीआईबी का सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया। पीआईबी ने नियमित सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी की मंजूरी की जानकारी देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को तीन अधिकारियों की एक सूची भी भेजी। समन्वय अनुभाग सतर्कता मामलों की देख-रेख करता है। यह अनुभाग एक अनुभाग अधिकारी और शाखा अधिकारी की निगरानी में कार्य करता है। पीआईबी के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के संदर्भ में सतर्कता मामलों की देख-रेख के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुखों को प्राधिकार और दायित्व सौंपे गए हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों में ऐसे मामलों से निपटने में क्षेत्रीय प्रमुखों की सहायता के लिए प्रशासनिक अधिकारी के एक पद की व्यवस्था की गई है। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सलाह मांगे जाने पर समय-समय पर उन्हें दिशा-निर्देश और अनुदेश भेजे जाते हैं।

वर्ष 2006 की प्रमुख गतिविधियां

वर्ष 2006 के दौरान पीआईबी की प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार रहीं :

1. श्रव्य-दृश्य एकांश :

- 6 सितंबर से श्रव्य-दृश्य व्यवस्था चालू की गई और पीआईबी की वेबसाइट से श्रव्य-दृश्य विषयवस्तु प्रदान की गई।
- प्रचार माध्यमों को विशिष्ट सामग्री प्रदान की गई, जो समाचार चैनलों के पास सामान्य कवरेज के जरिए उपलब्ध नहीं थी।
- इस तरह की करीब 80 श्रव्य-दृश्य कवरेज वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गईं।
- प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण भाषणों के व्यापक श्रव्य-दृश्य अभिलेखीकरण की व्यवस्था की गई।

अनुलग्नक

जन सूचना अभियानों में हिस्सा लेने वाले कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सूची

क्र. सं.	अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम	जन सूचना अभियान का नाम, जिसमें भाग लिया।	तारीख
1.	श्री टी आर बालू, केंद्रीय जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री।	नागपट्टिनम कांचीपुरम	2-6 जुलाई 3-7 सितंबर
2.	श्री तरुण गोगोई, मुख्यमंत्री, असम	उपारहली, गुवाहाटी	8-12 अगस्त
3.	श्री संतोष मोहन देव, केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री	उपारहली, गुवाहाटी	8-12 अगस्त
4.	श्री गुलाम नबी आजाद, मुख्यमंत्री, जम्मू और कश्मीर	किश्तवाड़	29 अगस्त-2 सितंबर
5.	श्री मंगतराम शर्मा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जम्मू और कश्मीर	लेह	21-25 सितंबर
6.	श्री त्सेरिंग दोरजी, (अध्यक्ष, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (लेह) एचडीसी	लेह	21-25 सितंबर
7.	श्री मणिशंकर अय्यर, केंद्रीय युवा एवं खेल और पंचायती राज मंत्री	कराइकल	21-24 अगस्त
8.	श्री जयराम रमेश, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री	आइजोल	22 अगस्त-1 सितंबर
9.	श्री वायलार रवि, केंद्रीय आप्रवासी भारतीय कार्य मंत्री	तिरुअनंतपुरम	17-21 सितंबर
10.	श्री वीरभद्र सिंह, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	18-22 सितंबर
11.	श्री सोमनाथ चटर्जी, लोकसभा अध्यक्ष	बीरभूम	16-20 सितंबर
12.	श्रीमती सूर्यकांता पाटिल, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री	हिंगोली	4-8 अक्टूबर
13.	श्री अजित जोगी, सांसद	धमातरी (रायपुर)	9-13 अक्टूबर
14.	श्री के वैंकटपति, गृह राज्य मंत्री	नागपट्टिनम	2-6 जुलाई
15.	श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीसन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री	नागपट्टिनम	2-6 जुलाई
16.	श्री आर. वेलू, रेल राज्य मंत्री	मदुरई	16-20 जुलाई
17.	श्री के एच मुनियप्पा, जहाजरानी, भूतल परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री	येलाहंका (बंगलौर)	1-5 सितंबर
18.	सुश्री गिरिजा व्यास, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग	केजार (राजस्थान)	7-11 सितंबर
19.	श्री पृथ्वीराज चौहान, राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय	कराड़	26-30 दिसंबर
20.	श्री नारायण दत्त तिवारी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड	हरिद्वार	30 अक्टूबर-3 नवंबर
21.	श्री प्रणव मुखर्जी, केंद्रीय रक्षा मंत्री	मुर्शिदाबाद	30 अक्टूबर-3 नवंबर
22.	श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री	वैशाली	20-24 नवंबर
23.	श्री वी रामाराव, राज्यपाल, सिक्किम	गंगटोक	24-28 नवंबर
24.	लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त), एमएम लखेड़ा, प्रशासक अंडमान निकोबार	पोर्ट ब्लेयर	3-7 दिसंबर
25.	श्री चंद्रशेखर साहू, केंद्रीय मंत्री	बहरामपुर	8-12 दिसंबर
26.	श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, हरियाणा के जन स्वास्थ्य, परिवहन मंत्री	सिरसा	18-22 दिसंबर
27.	श्री शंकरसिन वाघेला, केंद्रीय कपड़ा मंत्री	साबरकांठा	23-27 दिसंबर

जून से दिसंबर 2006 के दौरान आयोजित 55 जन सूचना अभियानों का ब्योरा

महीना तथा अभियानों की संख्या	तारीख	जिला/स्थान	राज्य
जून (1)	12-16 जून	तरनतारण/अमृतसर	पंजाब
जुलाई (5)	2-6 अगस्त	नागपट्टिनम	तमिलनाडु
	3-7	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
	9-13	डिंडीगुल	तमिलनाडु
	16-20	मदुरई	तमिलनाडु
	24-28	साहनीवाल/लुधियाना	पंजाब
अगस्त (11)	31 जुलाई-4 अगस्त	उस्मानाबाद	महाराष्ट्र
	2-6	अगरतला	त्रिपुरा
	4-8	बेल्कुड़ी/पुरुलिया ब्लॉक	पश्चिम बंगाल
	8-12	उपारहली/मिर्ज़ा/गुवाहाटी	असम
	20-24	कराइकल/पुदुचेरी	पुदुचेरी
	21-25	बजवाड़ा/होशियारपुर	पंजाब
	22-23, 28-29, सितंबर-1	आइज़ोल	मिज़ोरम
	27-31	कड्डालूर	तमिलनाडू
	28 अगस्त-1 सितंबर	राहुड़ी/अहमदनगर	महाराष्ट्र
	29 अगस्त-3 सितंबर	किश्तवाड़/डोडा	जम्मू और कश्मीर
	29 अगस्त-02 सितंबर	नलगोंडा	आंध्र प्रदेश
सितंबर (14)	1-5 सितंबर	येलाहंका/बंगलौर	कर्नाटक
	3-7	कांचीपुरम/बृहत् चेन्नई	तमिलनाडु
	7-11	केजार/उदयपुर	राजस्थान
	12-16	यूमियाम/शिलांग	मेघालय
	16-20	वीरभूम	पश्चिम बंगाल
	17-21	तिरुअनंतपुरम	केरल
	18-22	नाहन/सिरमौर	हिमाचल प्रदेश
	18-22	पणजी	गोवा

महीना तथा अभियानों की संख्या	तारीख	जिला/स्थान	राज्य
	18–22	दानापुर/पटना	बिहार
	18–22	क्योंझर	उड़ीसा
	21–25	लेह	जम्मू और कश्मीर
	27 सितंबर–1 अक्टूबर	वुय्यूनु मंडल कृष्णा जिला	आंध्र प्रदेश
	26–30	इंफाल	मणिपुर
	30 सितंबर–4 अक्टूबर	थांडला/झाबुआ	मध्य प्रदेश
अक्टूबर (8)	4–8 अक्टूबर	हिंगोली	महाराष्ट्र
	6–10	झाल्थी/पूर्वी निमार	मध्य प्रदेश
	9–13	धर्मतारी/रायपुर	छत्तीसगढ़
	10–14	गोलपाड़ा	असम
	15–19	वयानाड़ जिला	केरल
	26–30	करोली/जयपुर	राजस्थान
	30 अक्टूबर–3 नवंबर	हरिद्वार	उत्तराखंड
	30 अक्टूबर–3 नवंबर	मिर्जापुर/मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल
नवंबर (9)	4–8 नवंबर	झालड़ापाटन/झालावाड़	राजस्थान
	12–16	मुल्ताई/बेतुल	मध्य प्रदेश
	12–16	पाल्लकाड जिला	केरल
	13–17	कामरेड्डी/निजामाबाद	आंध्र प्रदेश
	14–18	जौनपुर	उत्तर प्रदेश
	14–18	लांगतलई	मिजोरम
	20–24	वैशाली	बिहार
	24–28	गंगटोक	सिक्किम
	27 नवंबर–1 दिसंबर	खुंती/रांची	झारखंड
दिसंबर (07)	3–7 अक्टूबर	विम्बरलीगंज	अंडमान और निकोबार
	3–7	तिरूवलूर	तमिलनाडु
	8–12	बहरामपुर/गंजम	उड़ीसा
	9–13	गुलबर्ग	कर्नाटक
	18–22	सिरसा	हरियाणा
	19–23	रायबरेली	उत्तर प्रदेश
	23–27	हिम्मतनगर/साबरकांठा	गुजरात

2. जन सूचना अभियान :

- पीआईबी द्वारा नई प्रचार माध्यम संपर्क नीति विकसित की गई, जिसमें सूचना संप्रेषण को सेवाओं के वितरण के साथ जोड़ा गया।
- देश के विभिन्न भागों में दिसंबर 2006 तक 55 से अधिक जनसूचना अभियान आयोजित किए गए।
- प्रत्येक जनसूचना अभियान की अवधि 5 दिन की थी और उसमें करीब 25 स्टॉल लगाए गए, जिनके माध्यम से केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और उनका लाभ उठाने के तरीकों की जानकारी दी गई।
- भारत निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.), सर्वशिक्षा अभियान, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन, सूचना का अधिकार अधिनियम आदि सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में अतिरिक्त जागरूकता पैदा करने के लिए बहु-प्रचार माध्यम नीति अपनाई गई, जिसमें मंत्रालय की प्रचार माध्यम इकाइयों को शामिल किया गया।
- पीआईबी ने डीएफपी की क्षेत्रीय इकाइयों के जरिए स्थानीय सफलता की कहानियों को उजागर करने में प्रमुख भूमिका निभाई। इसके लिए विशेष फोटो लेख जारी किए गए और डीएवीपी द्वारा प्रदर्शनियां लगाई गईं।

3. संचार माध्यम परस्पर संपर्क श्रृंखलाएं :

- सामाजिक-आर्थिक, बुनियादी ढांचा, सामाजिक क्षेत्र संबंधी मुद्दों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के लिए चुने हुए राज्यों की राजधानियों में संचार माध्यम संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर आदि पिछड़े क्षत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपायों की जानकारी राष्ट्रीय और स्थानीय प्रचार माध्यमों तक पहुंचाने के लिए संबद्ध मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को परस्पर संपर्क कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया।

4. महत्वपूर्ण सम्मेलन :

- उत्तरी क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने संबंधी सम्मेलन, 17-18 अप्रैल, चंडीगढ़।
- जम्मू-कश्मीर पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए सामाजिक-आर्थिक विकास के बारे में संपादकों का सम्मेलन, जून 2006, श्रीनगर।
- आर्थिक संपादकों का सम्मेलन-नवंबर 2006, दिल्ली।
- ग्रामीण विकास के बारे में संपादकों का सम्मेलन, फरवरी 2007, दिल्ली।
- ये श्रृंखलाएं 2-3 दिन तक आयोजित की गईं, जिनमें देश के विभिन्न भागों के वरिष्ठ पत्रकारों/संपादकों ने विकास संबंधी विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण किया और उनके बारे में लिखा।

5. विशेष प्रचार के उपाय :

- पीआईबी ने गोवा में 37वें आईएफएफआई में मीडिया सेंटर स्थापित किया। करीब 408 मीडिया प्रत्यायन कार्ड जारी किए गए। 57 संवाददाता सम्मेलन आयोजित किए गए और करीब 157 फोटो जारी किए गए।
- पीआईबी द्वारा 7-9 जनवरी 2007 के दौरान नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस पर मीडिया सेंटर की स्थापना की गई।

कुछ आंकड़े

(अप्रैल 2006 से दिसंबर 2006)

1.	मुख्यालय द्वारा कवर किए गए कार्यक्रमों की संख्या	936
2.	पीआईबी द्वारा जारी किए गए फोटोग्राफों की संख्या	2930
3.	जारी प्रेस विज्ञप्तियों की संख्या	59,393
4.	जारी विशेष लेखों की संख्या	3773
5.	आयोजित संवाददाता सम्मेलनों की संख्या	1053

पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	शाखा कार्यालय	कार्यालय एवं सूचना केंद्र	सूचना केंद्र	शिविर कार्यालय	कुल
1. उत्तरी क्षेत्र चंडीगढ़	1. जम्मू 2. शिमला 3. देहरादून	1. श्रीनगर 2. जालंधर			6
2. मध्य क्षेत्र भोपाल	1. जयपुर 2. इंदौर 3. कोटा 4. जोधपुर 5. रायपुर				6
3. पूर्व-मध्य क्षेत्र लखनऊ	1. वाराणसी 2. कानपुर 3. पटना 4. रांची				5
4. पूर्वी क्षेत्र कोलकाता	1. कटक 2. अगरतला 3. भुवनेश्वर	गंगटोक	पोर्ट ब्लेयर		6
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी	1. शिलांग	1. कोहिमा 2. इंफाल	आइज़ोल		5
6. दक्षिण मध्य क्षेत्र हैदराबाद	1. विजयवाड़ा 2. बंगलौर				3
7. दक्षिणी क्षेत्र चेन्नई	1. मदुरई 2. कोच्चि 3. तिरुअनंतपुरम				4
8. पश्चिमी क्षेत्र मुंबई	1. नागपुर 2. पुणे 3. पणजी 4. राजकोट 5. नांदेड़ 6. अहमदाबाद				7
कुल क्षेत्रीय कार्यालय = 8	शाखा कार्यालय = 27	5	2		42

फोटो प्रभाग

फोटो प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन फोटो उपलब्ध कराने वाली मीडिया इकाई है। यह प्रभाग भारत सरकार की ओर से आंतरिक (देश में) तथा बाह्य (विदेश में) प्रचार के लिए श्वेत-श्याम तथा रंगीन चित्र और दृश्य प्रलेख फोटो डोक्यूमेंटेशन उपलब्ध कराने का दायित्व संभालता है।

प्रभाग का प्रमुख कार्य देश में हुए विकास तथा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों को चित्रों के माध्यम से एक स्थान पर संग्रह करना है। साथ ही, फोटो प्रभाग का कार्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा अन्य केंद्रीय एवं राज्य सरकारों, मंत्रालयों/विभागों जिनमें राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय की प्रचार माध्यम इकाइयों के साथ ही विदेश मंत्रालय के बाह्य (विदेश) प्रचार विभाग (और इसके माध्यम से विदेश स्थित भारतीय मिशनों को) महत्वपूर्ण घटनाओं के चित्र (स्टिल) उपलब्ध कराना है।

यह प्रभाग गैर-प्रचार संगठनों तथा जन सामान्य को भी अपनी मूल्य योजना के अंतर्गत भुगतान आधार पर श्वेत-श्याम और रंगीन चित्र उपलब्ध कराता है।

10वीं पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम

प्रौद्योगिकी में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रभाग ने 10वीं योजना अवधि के दौरान अपने योजना कार्यक्रम को नया रूप दिया, जिसके अंतर्गत प्रभाग की प्रयोगशालाओं और इसके संग्रहालय में उपलब्ध चित्रों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने पर जोर दिया गया है। योजना अवधि के तीसरे वर्ष में प्रभाग ने अपने पास उपलब्ध सभी चित्रों का अभिलेखीकरण, वर्गीकरण (कैटलॉग बनाना) तथा डिजिटीकरण करने के साथ ही चरणबद्ध तरीके से अपनी प्रयोगशालाओं को डिजिटल बना दिया है और समाचार फोटो प्रणाली (न्यूज फोटो नेटवर्क) को अध्यतन कर दिया है। चालू वर्ष के दौरान दिसंबर 2006 तक) प्रभाग ने चित्रों के वर्गीकरण तथा डिजिटीकरण के हिस्से के रूप में करीब तीन लाख चित्रों को क्यूमुलस प्रणाली के रूप में बदल दिया।

प्रभाग ने अपनी वेबसाइट तैयार की है। सभी डिजिटल फोटोग्राफ वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। समाचार फोटो नेटवर्क के जरिए प्रभाग देश के विभिन्न भागों से चित्र प्राप्त करने में सक्षम होगा ताकि उन्हें नवनिर्मित वेबसाइट और पीआईबी नेट पर अपलोड किया जा सके।

महत्वपूर्ण गतिविधियां

प्रभाग ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भक्तार न्यूज एजेंसी में परम्परागत चित्रों के डिजिटल प्रबंधन के बारे में अफगान अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण पाठयक्रम आयोजित किया। प्रभाग ने त्रिपुरा सरकार के सूचना, संस्कृति और पर्यटन विभाग तथा पीआईबी अगरतला के सहयोग से अगरतला में 'मीडिया संचार और डिजिटल फोटोग्राफी की भूमिका' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।

प्रभाग ने उपराष्ट्रपति की गयाना और ट्रिनिडाड एवं टोबेगो की यात्रा तथा देश में विभिन्न स्थानों पर की गई यात्राओं के दौरान व्यापक फोटो कवरेज प्रदान की।

प्रभाग ने क्यूबा में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन, हेलसिंकी (फिनलैंड) में भारत-यूरोपीय संघ सम्मेलन और ब्राजील में तीन देशों के सम्मेलन से संबंधित प्रधानमंत्री के भाषणों और उनकी विभिन्न देशों की यात्राओं के लिए व्यापक फोटो कवरेज प्रदान की।

प्रभाग ने कन्याकुमारी में कृषि और मछली उद्योग, अमरनाथ यात्रा, दिल्ली में रमजान और ईद समारोह, मुगलकालीन स्वतंत्रता आंदोलनों और दिल्ली में क्रिसमस समारोह जैसे विषयों पर अनूठे फीचर तैयार किए हैं।

फोटो प्रभाग ने 'जीवन और जल' विषय पर 18वीं राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

प्रभाग ने कोलकाता में 'भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि' विषय पर एक प्रदर्शनी आयोजित की। प्रभाग ने विभिन्न जन सूचना अभियानों के दौरान डीएवीपी/ पीआईबी को भी फोटोग्राफ उपलब्ध कराए।

योजना कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटन इस प्रकार है :

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान 2006-07	संशोधित अनुमान 2006-07
1	2	3	4
1.	फोटो प्रभाग का आधुनिकीकरण	125.00	155.00

भारतीय जन संचार संस्थान

पृष्ठभूमि

भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, जिसे संचार शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र के 'उत्कृष्ट केंद्र' के रूप में जाना जाता है। संस्थान की स्थापना 17 अगस्त, 1965 को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक विभाग के रूप में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के संपूर्ण विकास की नीति के तहत संचार के साधनों के बेहतर इस्तेमाल के तौर-तरीके विकसित करना था। संस्थान को 22 जनवरी, 1966 को समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21वां अधिनियम) के तहत स्वायत्त संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया। इसे आवर्ती एवं अनावर्ती खर्च के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार से अनुदान के रूप में धन प्राप्त होता है। संस्थान प्रिंट, फोटोग्राफी, रेडियो और टेलीविज़न, विकास संचार, संचार अनुसंधान, विज्ञापन और जन संपर्क सहित विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने के साथ-साथ संगोष्ठियों, प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं आदि के संचालन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को सहयोग भी प्रदान करता है। यह संस्थान उद्योग, सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त शोध परियोजनाओं और अल्पावधि पाठ्यक्रमों का संचालन भी करता है।

वर्तमान गतिविधियां

वर्ष 2006-07 के दौरान भारतीय जन संचार संस्थान ने निम्नलिखित दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए :

1. भारतीय सूचना सेवा (ग्रुप 'ए') के अधिकारियों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम;
2. नई दिल्ली और ढेंकनाल (उड़ीसा) में पत्रकारिता (अंग्रेजी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम;
3. पत्रकारिता (हिंदी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम;
4. विज्ञापन और जन संपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम;
5. रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम;
6. उड़िया पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम; और
7. विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

इसके अलावा, संस्थान भारतीय सूचना सेवा के मध्यम स्तर तथा वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों तथा विभिन्न मीडिया इकाइयों के कार्मिकों के लिए अल्पावधि शैक्षिक पाठ्यक्रम भी संचालित करता है।

संस्थान द्वारा संचालित वर्तमान पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, विज्ञापन, जन संपर्क, प्रसारण और मुद्रण क्षेत्र के प्रशिक्षकों और व्यावसायियों/विशेषज्ञों के बीच व्यापक विचार-विमर्श किया गया। उद्योग से मिली जानकारी के आधार पर पाठ्यक्रमों को नया रूप दिया जा रहा है ताकि उनमें अधिक व्यावहारिक पहलुओं और ज्ञान का समावेश किया जा सके।

विचारगोष्ठियां और सम्मेलन

भारत और अन्य विकासशील देशों के संदर्भ में संचार को बेहतर तरीके से समझने के लिए संस्थान विभिन्न विषयों पर सेमिनार, संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन करता है।

परामर्श

संस्थान केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनुरोध पर उन्हें सलाहकार सेवा उपलब्ध कराता है और विकासात्मक जन-संचार से संबंधित अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने और उनके आयोजन में मदद करता है।

शैक्षिक सत्र

देश के विभिन्न भागों में आठ केंद्रों (नई दिल्ली सहित) में 20 मई 2006 को हुई लिखित प्रवेश परीक्षा के आधार पर 40 विद्यार्थियों ने पत्रकारिता (हिंदी) और 43 विद्यार्थियों ने पत्रकारिता (अंग्रेजी) पाठ्यक्रम में नई दिल्ली में तथा 39 विद्यार्थियों ने ढेंकनाल (उड़ीसा) में दाखिला लिया। इसी प्रकार 50 विद्यार्थियों ने विज्ञापन और जन संपर्क, 34 विद्यार्थियों ने रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता तथा 15 विद्यार्थियों ने ढेंकनाल में उड़िया पत्रकारिता पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। इनमें 12 प्रवासी भारतीय विद्यार्थी भी शामिल हैं, जिन्होंने विज्ञापन एवं जन संपर्क, रेडियो तथा टी वी पत्रकारिता और अंग्रेजी पत्रकारिता पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया। सभी स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम 1 अगस्त, 2006 को प्रारंभ हुए।

अल्पावधि पाठ्यक्रम

वर्ष के दौरान संस्थान ने निम्नांकित अल्पावधि पाठ्यक्रम आयोजित किए–

क्रम सं.	अल्पावधि पाठ्यक्रम/कार्यशाला/सेमिनार	भागीदार	स्थान
1	जेसीओ/एनसीओ के लिए वीडियोग्राफी पाठ्यक्रम, 3 से 28 अप्रैल, 2006	26	नई दिल्ली
2	प्रभाव संचार और प्रलेखन के बारे में कार्यशाला का आयोजन, 10 से 12 अप्रैल, 2006	19	नई दिल्ली
3	दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों का जन संपर्क कौशल बढ़ाने के लिए कार्यशाला का आयोजन,17 से 21 अप्रैल, 2006	10	नई दिल्ली
4	डीएफपी अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, 17 से 21 अप्रैल, 2006	11	नई दिल्ली
5	वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के लिए जन संचार पाठ्यक्रम, 8 से 19 मई, 2006	14	नई दिल्ली
6	डीएफपी अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, 22 से 26 मई, 2006	20	नई दिल्ली
7	बिहार सरकार के जन संपर्क अधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन, 12 से 23 जून, 2006	15	नई दिल्ली
8	आईआईएस अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, 19 से 23 जून, 2006	06	नई दिल्ली
9	पीआईबी अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, 3 से 7 जुलाई, 2006	09	नई दिल्ली
10	सेना के मध्यम स्तरीय अधिकारियों के लिए मीडिया संचार पाठ्यक्रम, 10 से 21 जुलाई 2006	24	नई दिल्ली
11	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के आईईसी (सूचना शिक्षा संचार) अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 24 से 28 जुलाई, 2006	30	नई दिल्ली
12	रक्षा लेखा अधिकारियों के लिए संचार कौशल के बारे में कार्यशाला, 24 और 25 अगस्त, 2006	19	नई दिल्ली
13	आईआईएस अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, 11 से 24 सितम्बर, 2006	06	नई दिल्ली
14	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुभाग अधिकारियों के लिए जन संचार में ऐडवान्स्ड पाठ्यक्रम, 25 सितम्बर से 07 अक्टूबर, 2006	21	नई दिल्ली
15	सशस्त्र सेनाओं के चुने हुए अधिकारियों के लिए ऐडवान्स्ड मीडिया संचार पाठ्यक्रम, 18 सितंबर से 13 अक्टूबर, 2006	21	नई दिल्ली
16	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों के लिए मीडिया मुद्दे और मीडिया प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पाठ्यक्रम, 25 सितंबर से 7 अक्टूबर 2006	20	नई दिल्ली
17	एसएसबी अधिकारियों के लिए ऐडवान्स्ड मीडिया कोर्स, 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2006	12	नई दिल्ली
18	राष्ट्रमंडल सचिवालय, लंदन (ब्रिटेन) के सहयोग से स्वास्थ्य मीडिया के बारे में सीएमडीएफ कार्यशाला : एचआईवी/एड्स, मलेरिया और एवियन फ्लू पर रिपोर्टिंग, 30 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2006	15	नई दिल्ली
19	ईएसआईसी के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए पांच दिन का जन संपर्क पाठ्यक्रम, 6 से 10 नवंबर, 2006	31	नई दिल्ली
20	हरियाणा सरकार के अधिकारियों और सूचना अधिकारियों के लिए पांच दिन का जन संपर्क पाठ्यक्रम, 6 से 10 नवंबर, 2006	10	नई दिल्ली
21	वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के लिए मीडिया संचार पाठ्यक्रम, 20 नवंबर से 01 दिसम्बर, 2006	15	नई दिल्ली

विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

विकासशील देशों में पत्रकारिता कौशल में सुधार के प्रयासों की गुट-निरपेक्ष आंदोलन की परंपरा जारी रखते हुए और साथ ही विकासशील देशों का अपना दृष्टिकोण विकसित करने के लिए संस्थान विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी संचालित करता है। हर वर्ष 4-4 महीने की अवधि के ऐसे दो पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस शृंखला का 47वां पाठ्यक्रम (अगस्त-नवंबर) 3 अगस्त, 2006 को प्रारंभ हुआ।

शिक्षण और अनुसंधान कार्मिक

भारतीय जन संचार संस्थान के शिक्षण और अनुसंधान कार्मिकों में शिक्षाविद्, अनुसंधानकर्ता और मीडिया से जुड़े ऐसे विशेषज्ञ शामिल हैं, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया हो। इसके अतिरिक्त प्रमुख समाचार पत्रों और अन्य मीडिया संगठनों से भी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है।

शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए तीन स्तरीय शिक्षण प्रणाली अपनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत नियमित शिक्षकों के अलावा, उद्योग क्षेत्र और मीडिया के वरिष्ठ विशेषज्ञ समय-समय पर बुलाए जाते हैं, ताकि उनके जन संचार के अनुभवों से प्रशिक्षार्थियों/विद्यार्थियों की जानकारी बढ़ाई जा सके।

जन संचार का आधार व्यापक बनाना

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जन संचार के क्षेत्र में बेहतर शिक्षा की बढ़ती मांग पूरी करने और दूरदराज के क्षेत्रों में जन-संचार शिक्षा का विकास करने के लिए, भारतीय जन संचार संस्थान के कई केंद्रों की स्थापना की गई। इनमें आईआईएमसी, ढेंकनाल (उड़ीसा), दीमापुर (नागालैंड), कोट्टायम (केरल) और झाबुआ (मध्य प्रदेश) शामिल हैं।

ढेंकनाल स्थित आईआईएमसी की शाखा अगस्त 1993 से पूरी तरह काम कर रही है और बड़ी संख्या में पूर्वोत्तर क्षेत्र से विद्यार्थियों को आकर्षित कर रही है। इस शाखा में सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं, और यहाँ पत्रकारिता (अंग्रेजी और उड़िया) में दो स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

वित्त व्यवस्था

(लाख रुपये)

	योजना			गैर-योजना		
वर्ष	सकल योग	राजस्व प्राप्तियां	विशुद्ध अनुदान/व्यय	सकल योग	राजस्व प्राप्तियां	विशुद्ध अनुदान/व्यय
2005-06						
एसबीजी	**240.80**	**—**	**240.80**	**521.00**	**160.00**	**361.00**
संशोधित अनुमान/ अंतिम अनुदान	**103.50**	**—**	**103.50**	**549.00**	**161.00**	**388.00**
व्यय	**98.08**	**—**	**98.08**	**549.00**	**173.64**	**375.16**
2006-07						
बजट अनुमान	**158.50**	**—**	**158.50**	**570.00**	**170.00**	**400.00**
संशोधित अनुमान/ (प्रस्तावित)	**210.00**	**—**	**210.00**	**597.74**	**200.00**	**397.74**

नागालैंड विश्वविद्यालय के साथ सहयोग

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहल और योजना कार्यक्रम 'क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्रों के साथ सहयोग' के अंतर्गत भारतीय जन संचार संस्थान ने पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए नागालैंड विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत 14 विद्यार्थियों के लिए पहला पाठ्यक्रम 20 जनवरी, 2005 को प्रारंभ हुआ।

अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ भी इस तरह के सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

वार्षिक योजना 2006-07

भारतीय जन संचार संस्थान ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए निम्नांकित चार कार्यक्रमों पर अमल किया :-

(i) भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के लिए भवन और आवास परियोजना;

(ii) इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट पत्रकारिता के लिए सुविधाओं का आधुनिकीकरण एवं विस्तार;

(iii) क्षेत्रीय अध्ययन केंद्रों के साथ सहयोग; और

(iv) अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन

भारतीय प्रेस परिषद

परिचय

भारतीय प्रेस परिषद संसद द्वारा गठित अर्द्ध-न्यायिक सांविधिक प्राधिकरण है। इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण करना और भारत में समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्तर में सुधार करना है। यह एक स्वायत्त संगठन है जिसे प्राधिकारियों और पत्रकारों पर एक समान अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकार प्राप्त हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए परिषद में एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। परम्परा से ही प्रेस परिषद का अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाया जाता है। इसके 28 सदस्यों में से 20 प्रेस के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि शेष 8 संसद के दोनों सदनों तथा देश की प्रमुख साहित्यिक एवं कानूनी संस्थाओं, अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार काउंसिल आफ इंडिया और साहित्य अकादमी के प्रतिनिधि होते हैं। प्रेस परिषद का वित्त पोषण मुख्य रूप से केन्द्र सरकार द्वारा हर साल आबंटित की जाने वाली अनुदान राशि से होता है। प्रेस परिषद समाचार पत्रों से शुल्क भी लेती है।

वर्ष 2006-07 के वित्त वर्ष में प्रेस परिषद का कुल स्वीकृत बजट 2.69 करोड़ रुपये था जिसमें से 231.53 लाख रुपये केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित कुल अनुदान राशि के रूप में मिला हैं।

प्रेस परिषद, प्रेस द्वारा पत्रकारिता संबंधी आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों या प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन की शिकायतों पर अपने न्यायिक निर्णयों के माध्यम से अपना कार्य करता है। जहां प्रेस परिषद जांच के बाद इस बात को लेकर आश्वस्त होती है कि किसी समाचार पत्र या समाचार एजेंसी ने पत्रकारिता की आचार संहिता या लोकरुचि के मानदंडों को तोड़ा है या किसी संपादक या श्रमजीवी पत्रकार ने कोई व्यावसायिक कदाचार किया है वहां प्रेस परिषद उन्हें चेतावनी दे सकती है या उनकी भतर्सना अथवा निंदा कर सकती है या उनके आचरण को गलत ठहरा सकती है। प्रेस परिषद को प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने संबंधी किसी कार्रवाई के लिए सरकार सहित किसी प्राधिकारी के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी करने का भी अधिकार प्राप्त है जो वह उचित समझती है। प्रेस परिषद के निर्णय अंतिम होते हैं और उन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

1 अप्रैल, 2006 से 25 जनवरी, 2007 के दौरान भारतीय प्रेस परिषद को 600 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 164 प्रेस ने दर्ज करायी थीं और 436 प्रेस के खिलाफ दर्ज करायी गयी थीं। 760 मामले पहले से लंबित पड़े थे। इनमें से परिषद ने 122 मामलों में अपना न्यायिक निर्णय सुनाया जबकि 282 मामलों को मौखिक छानबीन के बिना ही बंद कर दिया गया। इस तरह परिषद ने 1 अप्रैल, 2006 से 25 जनवरी, 2007 के दौरान 404 मामले निपटाये। 2006-07 के दौरान कुल 654 मामलों के निपटा लिये जाने की संभावना है।

परिषद ने विश्व के विभिन्न भागों में प्रेस/मीडिया और इसी तरह के संगठनों से परामर्श/संवाद की प्रक्रिया प्रारंभ की ताकि प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा तथा इसके मानदंडों और नैतिकता दुनिया भर में खुल कर बढ़ावा दिया जा सके।

जून 8-12, 2006 के बीच भारतीय प्रेस परिषद् ने तुर्की के शहर इस्तांबूल में विश्व के देशों की प्रेस परिषदों के समन्वयकारी संगठन

वर्ल्ड एसोसिएशन और प्रेस काउंसिल्स (डब्ल्यूएपीसी) की कार्यकारी परिषद/आम सभा की बैठक में भाग लिया। डब्ल्युएपीसी के अध्यक्ष तुर्की के प्रो. ओताये एक्सी के साथ वह इस संगठन के उपाध्यक्ष बने। इस बैठक में डब्ल्यूएपीसी ने अपने बदलते रहने वाले मुख्यालय के स्थान पर अपना स्थायी मुख्यालय वर्तमान अध्यक्ष सहित तुर्की में स्थापित करने का फैसला किया।

भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष ने लोकसभा सचिवालय के निमंत्रण पर भारत यात्रा पर आये इथोपिया के संसदीय शिष्टमंडल को भी संबोधित किया।

मीडिया संबंधी मामलों पर बहस को बढ़ावा देने के प्रयासों में प्रेस परिषद ने देश के विभिन्न भागों में आयोजित बहसों में भी हिस्सा लिया।

इस वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर भारतीय प्रेस परिषद ने फोटो पत्रकारिता पर एक प्रदर्शनी और मीडिया संबंधी मामलों पर 16-17 नवम्बर 2006 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दो दिन की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की। संगोष्ठी में ''वैश्वीकरण के युग में पत्रकारिता, नैतिकता और समाज'' के संदर्भ में ''मीडिया में स्व-विनियामक संगठनों की भूमिका'' और ''मीडिया में नैतिकता'' जैसे विषयों पर विशेष रूप से चर्चा हुई। भारत के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी और दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीया शीला दीक्षित की उपस्थिति में समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जारी एक स्मारिका में इन विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण लेख दिए गए थे। ग्यारह देशों के प्रतिनिधियों ने संगोष्ठी के विचार-विमर्श में हिस्सा लिया जबकि कई अन्य ने लिखित पर्चे प्रस्तुत किए जिससे यह बहस बड़ी जीवन्त हो गयी। संगोष्ठी के निष्कर्षों और संस्तुतियों को संगोष्ठी दस्तावेज के रूप में संकलित किया गया और इन्हें आगे की कार्रवाई के लिए व्यापक रूप से परिचालित किया जा रहा है।

प्रदर्शनी में कल के इतिहास की गाथा के रूप में फोटो पत्रकारिता की भूमिका को स्वीकार करते हुए इसे विशेष रूप से उजागर करने का प्रयास किया गया। 15 नवम्बर, 2006 को नई दिल्ली के रफी मार्ग स्थित आइफैक्स हॉल में आयोजित इस प्रदर्शनी में अंतराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त फोटोग्राफरों के फोटो प्रदर्शित किए गए थे। भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद उसी दिन अपने विचार इस प्रकार अंकित किये : *''ये फोटोग्राफ आगे बढ़ रहे भारत का बड़ा अच्छा दृश्य अभिलेख प्रस्तुत करते हैं। मुझे आशा है कि इससे हमारे फोटोग्राफरों और पत्रकारों को अपने व्यवसाय में और ऊंचे मानदंड कायम करने की प्रेरणा मिलेगी।''* उसी दिन उद्घाटन समारोह में विशेष अतिथि लोकसभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी ने **'सेल्फ-रेग्यूलेटरी मैकेनिज्म फार द मीडिया'** नाम का एक संकलन भी जारी किया। इसमें दुनिया भर में मीडिया को विनियमित करने वाले संगठनों के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी गयी है।

वर्ष भर के दौरान प्रेस के खिलाफ दर्ज शिकायतों पर जांच की प्रक्रिया को आसान तथा उपयोग करने वालों के अनुकूल बनाया गया। इसके अलावा प्रेस द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए खतरे के बारे में दर्ज मामलों के विनियमन की प्रक्रिया तय की गयी और राजपत्र में प्रकाशित की गई।

प्रेस परिषद के वैबसाइट में परिषद के नवीनतम फैसलों और अन्य घटनाक्रमों को शामिल कर और अधिक समृद्ध बनाया गया। समाचारपत्रों से लिए जाने वाले शुल्क के जरिए अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए चूक करने वाले समाचारों पत्रों की सूची आम जानकारी और सूचना के लिए वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई। अपनी हार्डवेयर क्षमता बढ़ाने का भी प्रेस परिषद को लाभ हो रहा है।

संसद ने भारतीय प्रेस परिषद को प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 8-सी के तहत अपीलीय प्राधिकरण की अतिरिक्त भूमिका भी सौंपी है। अपील बोर्ड को मिलने वाली अपीलों की सुनवाई के लिए परिषद के अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य वाले इस अपीलीय बोर्ड की नियमित रूप से बैठकें आयोजित की गईं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भारतीय प्रेस परिषद ने अपने तीन अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया है।

4

प्रसारण क्षेत्र

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)

प्रसार भारती बोर्ड का मौजूदा संघटन इस प्रकार है :

1.	श्री एम.वी. कामथ	अध्यक्ष
2.	श्री बी.एस. लाली	कार्यकारी सदस्य
3.	श्री ए.के. जैन	सदस्य (वित्त)
4.	श्री प्रदीप सिंह अतिरिक्त सचिव	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि
5.	सुश्री चित्रा मुद्गल	अंशकालिक सदस्य
6.	श्री एम.एल. मेहता	अंशकालिक सदस्य
7.	श्री आर.एन. बिसारिया	अंशकालिक सदस्य
8.	ब्रिजेश्वर सिंह महानिदेशक आकाशवाणी	पदेन सदस्य

1 अप्रैल 2006 से 31 जनवरी 2007 तक प्रसार भारती बोर्ड की पांच बैठकें आयोजित की गईं और संस्थान के उद्देश्यों के अनुरूप अनेक नीतिगत निर्णय लिए गए। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

i) सिविल निर्माण स्कंध की इंजीनियरिंग इकाई की संवर्ग समीक्षा।

ii) दूरदर्शन की स्थलीय सेवा के डिजिटलीकरण को सैद्धांतिक मंजूरी।

iii) दूरदर्शन से प्रसारण के लिए तैयार स्ववित्तपोषित कार्यक्रमों पर विचार करने, संसाधन और स्वीकृति के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन।

iv) स्थलीय डिजिटल रेडियो प्रसारण शुरू करने के लिए सैद्धान्तिक मंजूरी।

v) दूरदर्शन चैनलों के प्रसारण के लिए कार्यक्रम तैयार करने के बारे में विचार करने, संसाधन और स्वीकृति प्रदान करने के मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन।

vi) आकाशवाणी की विदेश प्रसारण प्रभाग को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी।

vii) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आकाशवाणी के हार्डवेयर विकास के संभावित क्षेत्रों/उद्देश्यों को सैद्धान्तक मंजूरी।

दूरदर्शन

सार्वजनिक प्रसारणकर्ता दूरदर्शन विश्व में सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करने वाला संस्थान है। इसकी शुरुआत 15 सितम्बर 1959 को दिल्ली में शैक्षिक एवं विकास संबंधी आधे घंटे के कार्यक्रम का प्रसारण करने के लिए प्रयोग के आधार पर की गई थी। दूसरा टेलीविजन केन्द्र 1972 में मुंबई में शुरू हुआ था और बाद में दूरदर्शन की टेलीविजन सेवा का अन्य भागों में विस्तार हुआ। दूरदर्शन का 1984 में तेजी से विकास किया गया और इसी वर्ष देश में लगभग प्रतिदिन एक ट्रांसमीटर स्थापित किया गया और आज दूरदर्शन 25 चैनलों का संचालन करता है जिनमें 5 राष्ट्रीय चैनल, 11 क्षेत्रीय भाषा के सेटेलाइट चैनल, राज्यों के 8 चैनल और एक अन्तर्राष्ट्रीय चैनल शामिल है। इसके अलावा दूरदर्शन ने हाल ही में लोगों के घरों तक 'डायरेक्ट टू होम' (डीटीएच) की शुरुआत की है जिसे डीडी डायरेक्ट प्लस कहा जाता है। इससे देश के शत-प्रतिशत क्षेत्रफल की जनसंख्या तक प्रसारण सुनिश्चित हो सका है।

दूरदर्शन का अपना व्यापक नेटवर्क है जिसमें 64 दूरदर्शन केन्द्र/स्टूडियो केंद्र और विभिन्न शक्तियों के कुल 1397 ट्रांसमीटर स्थापित हैं। (संलग्नक-1) स्थलीय प्रकार के ट्रांसमीटर से देश के कुल 79 प्रतिशत क्षेत्र और 91 प्रतिशत जनसंख्या तक टेलीविजन कवरेज होती है। इसके डीटीएच संकेत छोटे आकार की डिश रिसीवर इकाई की सहायता से (अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर) देशभर में कहीं भी प्राप्त किए जा सकते हैं। दूरदर्शन का एक महानिदेशक होता है, कार्यक्रम प्रभाग में उन्हें सहायता देने के लिए उपमहानिदेशक होते हैं। इंजीनियरिंग प्रभाग का प्रमुख इंजीनियर-

MAP DOORDARSHAN

इन-चीफ होता है जबकि प्रशासन और वित्त प्रभाग का एक अतिरिक्त महानिदेशक होता है तथा समाचार प्रभाग के लिए एक अलग अतिरिक्त महानिदेशक होता है।

2006-07 के दौरान महत्वपूर्ण पहल और उपलब्धियां

इंजीनियरिंग

नया चैनल

डी डी उर्दू के नाम से एक नए चैनल की शुरुआत की गई है इस चैनल के कार्यक्रम को दिल्ली से अपलिंक किया जाता है और इनसेट-3ए उपग्रह के माध्यम से इनका प्रसारण होता है। डीडी उर्दू चैनल के कार्यक्रम दूरदर्शन के डीटीएच (केयू बैण्ड) के प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होता है।

स्टूडियो केंद्र

रांची में एक अतिरिक्त स्टूडियो (दूरदर्शन केंद्र डीडीके रांची का दूसरा स्टूडियो) की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है। गोरखपुर में स्थाई स्टूडियो स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। भवन निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। विभागीय अधिष्ठापन का कार्य चल रहा है। गोरखपुर में स्थाई स्टूडियो के 2006-07 के अंत तक पूरी तरह तैयार हो जाने की संभावना है।

डी.टी.एच. सेवा का विस्तार

दूरदर्शन ने फ्री टू एअर डी.टी.एच. सेवा ''डी डी डायरेक्ट प्लस'' की शुरुआत दिसंबर 2004 में 33 टी.वी. चैनलों के साथ की थी। डी.टी.एच. भू-केंद्र की क्षमता बढ़ाकर 50 टी.वी. चैनल कर दी गई है। इस समय डी.टी.एच. प्लेटफार्म पर 35 टी.वी. चैनल काम कर रहे हैं और चरणबद्ध ढंग में अतिरिक्त चैनल भी जोड़े जा रहे हैं।

डिजिटलीकरण

चालू पंचवर्षीय योजना (2002-07) में दूरदर्शन का डिजिटलीकरण एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। 2006-07 के दौरान दूरदर्शन के 6 प्रमुख स्टूडियो केंद्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। ये तिरुअनंतपुरम, भुवनेश्वर, भोपाल, जालन्धर, श्रीनगर और लखनऊ में स्थित है। इन 6 स्टूडियो केंद्रों के डिजीटलीकरण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। इनके अलावा 19 छोटे स्टूडियो केंद्रों का आंशिक डिजीटलीकरण किया जा रहा है। ये केंद्र शिलांग, तूरा, कोहिमा, ईटानगर, इंफाल, सिलचर, डिब्रूगढ़, आइजोल, पुणे, विजयवाड़ा, अगरतला, संबलपुर, शिमला, मऊ, जलपाईगुड़ी, इलाहाबाद, राजकोट, इंदौर और गुवाहाटी में स्थित है। शिमला, विजयवाड़ा और गुआहाटी के स्टूडियो केंद्रों के आंशिक डिजिटलीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। शेष 16 अन्य स्टूडियो केंद्रों के डिजिटलीकरण का कार्य विभिन्न चरणों में है। इनके 2006-07 के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

भू-भागीय कवरेज

भू-भागीय कवरेज के विस्तार के लिए 2006-07 के दौरान निम्नलिखित ट्रांसमीटर परियोजना शुरू की गई है:

प्रत्येक एल.टी.पी. केंद्र में प्रचुर क्षमता वाले 500 वाट के दो सॉलिट स्टेट ट्रांसमीटर लगाए गए हैं। 41 अतिरिक्त ऑटोमोड एल.टी.पी. के उपकरणों की आपूर्ति हो चुकी है और इन्हें लगाने का कार्य शुरू हो गया है। इन 41 आटो मोड एल.टी.पी. स्थापित करने का कार्य चरणबद्ध ढंग से 2006-07 के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है।

राज्यों में नेटवर्किंग

आइजोल दूरदर्शन केंद्र डी.डी.के. में तैयार कार्यक्रम मिजोरम तथा त्रिपुरा में विभिन्न एचपीटी और एलपीटी से रिले किए जा रहे हैं। इसी तरह डी.डी.के. देहरादून द्वारा तैयार कायक्रमों को दूर उत्तराखण्ड में सभी टी.वी. ट्रांसमीटरों (एच पी टी, एल पी टी और वी एल पी टी) से रिले किया जाने लगा है। अब 11 राज्यों में नेटवर्क हो गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में वी.एल.पी.टी. दिल्ली के कार्यक्रमों को समग्र रूप से रिले करते थे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के अनुसंधान और विकास इकाई की ओर से विकसित आटो स्विचिंग सुविधा के उपलब्ध होने से इन्हें वी.एल.पी.टी. में लगाया गया है। इससे डी.डी.के. जयपुर, डी.डी.के. रांची और डी.डी.के. शिमला जैसे राजधानी केंद्रों से 'टाइमस्लॉट' पर क्षेत्रीय सेवा के कार्यक्रमों को रिले करना संभव हो गया है।

नई पहल

मोबाइल टीवी

दूरदर्शन ने दिल्ली में मौजूदा डिजिटल भू-भागीय ट्रांसमीटर का उपयोग करते हुए डीवीबी-एच ट्रांसमिशन की एक परियोजना शुरू की है। आवश्यक उपकरणों के लिए आदेश दिए जा चुके हैं। डीवीबी-एच ट्रांसमिशन के चालू वर्ष के अंत तक शुरू हो जाने की आशा है। इस ट्रांसमिशन के शुरू हो जाने पर ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र में मोबाइल फोन पर टीवी के सिगनल्स प्राप्त होने लगेंगे।

एच.डी.टी.वी. (उच्च स्पष्टता प्रसारण)

एचडीटीवी, एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसके माध्यम से टेलीविजन

के बड़े स्क्रीन पर बेहतरीन गुणवत्ता के चित्र अधिक स्पष्ट रूप में प्राप्त होते हैं। चौड़े स्क्रीन के चित्रों को देखने का अलग ही अनुभव है। परंपरागत टी.वी. पिक्चर की तुलना में एच.डी.टी.वी. की पिक्चर पांच गुना अधिक साफ होती है। एच.डी.टी.वी. के लिए दूरदर्शन की परियोजना को हाल ही में मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के तहत एच.डी.टी.वी. की क्षेत्रीय निर्माण सुविधा दिल्ली में 2007-08 तक स्थापित हो जाएगी।

समाचार संकलन

समाचार संकलन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए देशभर में 70 स्थानों पर वी-सेट नेटवर्क स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई है। इस नेटवर्क स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई है। इस नेटवर्क का केन्द्रीय-स्थल दिल्ली होगा। वी-सेट प्राप्त करने के लिए कार्यवाही शुरू हो गई है। उपरोक्त वी-सेट की स्थापना के बाद देश में 70 स्थानों के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार एकांशों में

एच.पी.टी.

करनाल	डीडी-I
धरमपुरी (अंतरिम)	डीडी-I
श्रीनगर	डीडी न्यूज
(1 किलोवाट से 10 किलोवाट क्षमता की गई)	
श्रीनगर	डीडी कशीर
(1 किलोवाट से 10 किलोवाट क्षमता की गई)	
साम्बा (स्थाई ढांचा)	डीडी-1
श्रीनगर (बदलाव)	डीडी-1
कुर्सियांग (बदलाव)	डीडी-1

इसके अलावा निम्नलिखित ट्रांसमीटरों की स्थापना का कार्य चल रहा है और इनके 2006-07 के अंत तक पूरे हो जाने की संभावना है।

एच.पी.टी.

तिरुनेलवेली (डीडी-1)	धर्मशाला (डीडी-1)
हिसार (डीडी-1)	धरमापुरी (डीडी-1 स्थायी ढांचा)
हिसार (डीडी न्यूज)	भटिंडा (डीडी न्यूज)
राघनपुर (डीडी-1)	कार्सियांग (डीडी न्यूज)
सागर (डीडी-1)	पुढुचेरी (डीडी-1 स्थायी ढांचा)
राघनपुर (डीडी-1)	कर्सियांग (डीडी न्यूज)
सागर (डीडी-1)	पुदुचेरी (डीडी-1 स्थायी ढांचा)
भटिंडा (डीडी-1 बदलना)	
जलगांव (डीडी-1 स्थायी ढांचा)	

एल.पी.टी. हरिद्वार (डीडी न्यूज)

एल.टी.पी. आटोमेशन

चालू वर्ष में दूरदर्शन ने पुराने एलटीपी हटाकर 14 आटोमोड एलटीपी लगाए। ये ट्रांसमीटर निम्नलिखित जगहों पर लगे हैं -

गुन्टकल	गया
फोरबेसगंज	नौगांव
सासाराम	गिरिडीह
जामुई	दुमका
खगड़िया	घाटसिला
मधेपुरा	कायमकुलम

उपग्रह के माध्यम से समाचार भेजना सुलभ हो जाएगा। यह नेटवर्क वी-सेट टर्मिनल्स लगे स्थानों के बीच आवाज/आंकड़ों का संचार भी संभव होगा।

वाणिज्यिक विज्ञापनों की बुकिंग

भुगतान के आधार पर वाणिज्यिक विज्ञापनों की बुकिंग शुरू में 10 एल.पी.टी. केंद्रों से आरंभ की गई जिसे बाद में 12 एच.पी.टी., केन्द्रों तक बढ़ा दिया गया। अब 494 अतिरिक्त ट्रांसमीटरों से वाणिज्यिक विज्ञापनों का प्रसारण शुरू करने का प्रस्ताव है। स्क्रोलिंग के लिए आवश्यक उपकरण खरीदे जा चुके हैं। इन्हें प्रेषक केन्द्रों पर स्थापित किया जा रहा है। करीब 400 ट्रांसमीटरों पर उपकरणों को लगाने का कार्य पूरा हो चुका है।

पूर्वोत्तर राज्यों और द्वीप समूह क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज

भारत सरकार की ओर से पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए मई 2006 में 256.85 करोड़ (134.43 करोड़ हार्डवेयर और 122.55 करोड़ साफ्टवेयर हेतु) रुपये का विशेष पैकेज मंजूर किया गया। इस पैकेज के अन्तर्गत शामिल योजनाएं इस प्रकार हैं:

पूर्वोत्तर राज्य

i. पूर्वोत्तर में दो चैनल शुरू करना

ii. कोकराझार में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना

iii. असम्मिलित क्षेत्रों में डी.टी.एच. इकाईयां स्थापित करने और टी.वी. सेट (संख्या 25000) वितरित करने का प्रावधान

iv. पूर्वोत्तर क्षेत्रों के दूरदर्शन केंद्रों पर निर्माण के बाद की सुविधाएं तथा ओ.बी. सुविधाओं का संवर्धन।

v. डी.एस.एन.जी. की इकाईयों की संख्या - 6

vi. पासी घाट और अगरतला में दो रखरखाव केन्द्रों की स्थापना

अण्डमान निकोबार द्वीप समूह

i. पोर्टब्लेयर में दो एच.पी.टी. (डी.डी. 1 और डी.डी. न्यूज) की स्थापना

ii. 16 नए वीएलपीटी (डीडी1-10, डीडी न्यूज-6) की स्थापना

iii. मौजूदा 6 वीएलपीटी का उन्नतिकरण

iv. कार-निकोबार में डीडी न्यूज एलपीटी की स्थापना

v. पोर्टब्लेयर स्टूडियो का संवर्धन, पोर्टब्लेयर के लिए डीएसएनजी.

vi. अण्डमान निकोबार के लिए सभी सी-बैण्ड डी.टी.एच.

vii. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में 1000 डी.टी.एच. रिसीवर इकाईयां और टी.वी. सेट का प्रावधान

viii. पोर्टब्लेयर में एक रख-रखाव केन्द्र की स्थापना

लक्षद्वीप समूह

i. 6 वी.एल.पी.टी. की स्थापना (डी.डी. न्यूज)

ii. मौजूदा 9 वी.एल.पी.टी. का संवर्धन

उपरोक्त स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। इन योजनाओं को चरणबद्ध ढंग से 2008-09 तक लागू कर दिया जाएगा।

डी.डी.-1 (राष्ट्रीय चैनल)

दूरदर्शन का डी.डी.-1 चैनल विश्व में सबसे बड़े भू-भाग पर प्रसारित होता है। इस समय देश की 91 प्रतिशत आबादी इसका प्रसारण देख सकती है। एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता होने के नाते दूरदर्शन मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक बदलाव, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए प्रेरित करने, ज्ञान का प्रसार करने, शैक्षिणिक कार्यक्रमों, जन-जागरण, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, परिवार कल्याण संबंधी सन्देश, पर्यावरण सुरक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन, महिला कल्याण, बच्चों और कमजोर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस चैनल ने देश में खेलों, कलाओं और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में भी योगदान दिया है।

सार्वजनिक प्रसारणकर्ता होने के अलावा यह मनोरंजक कार्यक्रमों का प्रसारण भी करता है जिनमें सामाजिक महत्व के प्रायोजित/ववित्त पोषित/अधिकृत धारावाहिक और फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न दूरदर्शन केंद्रों पर तैयार किये गये कार्यक्रम भी इस चैनल से प्रसारित होते हैं। वर्ष के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रसारण किया गया है :

- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम, गणतंत्र दिवस परेड, स्वाधीनता दिवस, एन.सी.सी. रैली, बीटिंग रिट्रीट आदि।

- कुछ राज्य विधान सभाओं के चुनाव
- खेलों के आयोजन : राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं
- वर्षगांठ, त्यौहार और राष्ट्रीय घटनाएं
- संसद सत्र
- केंद्रीय बजट, रेल बजट तथा लोगों की प्रतिक्रियाएं।
- संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति का अभिभाषण
- प्रवासी भारतीय दिवस

इनके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी विभागों के विकास कार्यक्रमों और सामाजिक महत्व के विशेष कार्यक्रमों को भी कवरेज दी गई है इनमें पल्स पोलियो अभियान, कैंसर रोधी, कुष्ठरोग, तपेदिक, डेंगू और स्वास्थ्य से जुड़े अन्य मुद्दे, सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, एड्स, आईआरडीए, उपभोक्ता शिक्षा, सड़क सुरक्षा तथा कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त कानूनी सहायता के विशेष अभियान शामिल हैं।

इसके अलावा विभिन्न भाषाओं के क्षेत्रीय केन्द्रों ने विकास संबंधी प्रसारण क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार और करेंट अफेयर्स कार्यक्रमों तथा क्षेत्रीय भाषा के मनोरंजन कार्यक्रमों के प्रसारण भी करते हैं।

राष्ट्रीय चैनल सेवा के कार्यक्रम टेरेस्ट्रियल मोड और सेटेलाइट मोड पर सुबह साढ़े पांच वजे से आधी रात तक और उसके बाद सेटेलाइट मोड पर अगले दिन सुबह साढ़े पांच बजे तक उपलब्ध रहते हैं।

क्षेत्रीय भाषा की उपग्रह सेवा और क्षेत्रीय नेटवर्क

क्षेत्रीय भाषा की उपग्रह सेवा और क्षेत्रीय नेटवर्क अपनी भाषा में जनता से संपर्क करने के लिए विकास से जुड़ी खबरों, धारावाहिकों, वृतचित्रों, समाचारों और समसामयिक कार्यक्रमों का बड़े पैमाने पर प्रसारण करते हैं। अन्य प्रमुख कार्यक्रमों के रूप में सामान्य सूचना से जुड़े कार्यक्रमों, सामाजिक कार्यक्रमों और फिल्मी कार्यक्रमों का भी प्रसारण किया जाता है।

इन चैनलों के कार्यक्रम प्रतिदिन दोपहर तीन बजे से शाम 8 बजे तक डी.डी.-1 के क्षेत्रीय ट्रांसमीटरों से रिले किया जाता है। क्षेत्रीय उपग्रह चैनल इस प्रकार हैं :

डीडी-मलयालम	— डीडी-सप्तगिरि (तेलुगु)
डीडी-बांग्ला	— डीडी-चन्दना (कन्नड़)
डीडी-उड़िया	— डीडी-सहयाद्रि (मराठी)
डीडी-गुजराती	— डीडी-कशीर (कश्मीरी)
डीडी-पंजाबी	— डीडी-पूर्वोत्तर
डीडी-मोधीगई (तमिल)	

राज्यों के क्षेत्रीय नेटवर्क उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के हिन्दीभाषी क्षेत्रों के रहनेवाले लोगों के लिए कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इस सेवा के कार्यक्रम संबंधित राज्यों के राजधानी केन्द्रों से तैयार कर प्रसारित किए जाते हैं। जिसे राज्य की सभी भू-भागीय ट्रांसमीटर रिले करते हैं।

डीडी न्यूज चैनल

एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के लिए समाचार और करेंट अफेयर्स कार्यक्रम के अभिन्न अंग होते हैं। दूरदर्शन का न्यूज चैनल अपनी शुरुआत 3 नवंबर 2003 से लेकर अब तक पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने उत्तरदायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन करता रहा है। 24 घंटे प्रसारित होने वाला यह न्यूज चैनल उत्तेजना और स्पर्धा से दूर रहते हुए परिशुद्धता के साथ त्वरित गति से समाचार और करेंट अफेयर्स के कार्यक्रम पेश करने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहा है। यह चैनल सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों, सूचना और खबरों को प्रसारित करते हुए शासन और विकास के उद्देश्यों को उजागर करता रहा है।

हिंदी और अंग्रेजी में यह द्विभाषी चैनल अपने दर्शकों को रोजमर्रा की घटनाओं और विकास गतिविधियों के बारे में संतुलित और उद्देश्यपूर्ण कवरेज करता रहा है। इनमें राजनीति, व्यापार, खेल, अन्तराष्ट्रीय घटनाएं, संसद की कार्यवाही, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि मुद्दे शामिल हैं।

डीडी न्यूज को एकमात्र जमीनी तथा उपग्रह समाचार चैनल की अनोखी विशिष्ठता प्राप्त है। यह एकमात्र चैनल है, जिसकी केबल-विहीन और उपग्रह सुविधा के रहित घरों तक भी पहुंच है। इसमें देश की अधिकांश आबादी शामिल है। यह देश में सबसे व्यापक कवरेज क्षेत्र वाला न्यूज चैनल है, और घर-घर तक पहुंचने वाला अग्रणी चैनल बना हुआ है।

इसकी ख्याति और विश्वसनीयता की परख बी.बी.सी. और रायटर के साथ शोध कंपनी ग्लोब स्कैन की ओर से किए गए सर्वेक्षण के परिणामों से की जा सकती है। इस सर्वेक्षण में दूरदर्शन को सबसे अधिक विश्वसनीय और विशिष्ट समाचार स्रोत का दर्जा दिया गया है। ग्लोब स्कैन द्वारा ब्रिटेन, अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, भारत,

इन्डोनेशिया, नाइजीरिया, रूस और दक्षिण कोरिया में मार्च और अप्रैल 2006 में 10,230 व्यस्क लोगों से पूछे गए प्रश्नों के आधार पर हुए सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष सामने आया है। 24 घंटे का यह न्यूज चैनल औसतन सप्ताह के एक दिन में हिंदी और अंग्रेजी में कुल 16 घंटे समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है। बुलेटिनों की संख्या की दृष्टि से यह कुल 32 समाचार बुलेटिन लाइव प्रसारित करता है जिनमें 17 हिंदी में और 13 अंग्रेजी में होते हैं। डीडी राष्ट्रीय चैनल के लिए हिंदी और अंग्रेजी में 15 मिनट की अवधि के दो बुलेटिन सुबह और शाम दिल्ली समाचार कक्ष द्वारा तैयार किए जाते हैं।

उर्दू बोलने वाली जनसंख्या तक अपनी पहुंच बनाने के प्रयास में इस चैनल ने प्रतिदिन सुबह 30 मिनट की अवधि का बुलेटिन- 'उर्दू खबरें' शुरू किया है। दिल्ली समाचार कक्ष द्वारा 30 मिनट की अवधि का एक और उर्दू बुलेटिन शाम के समय शुरू किया गया है जिसे डीडी उर्दू चैनल से प्रसारित किया जाता है। 5 मिनट का एक संस्कृत बुलेटिन भी हर रोज सुबह प्रसारित किया जाता है जबकि बधिरों के लिए समाचार प्रत्येक रविवार को दिखाये जाते हैं।

सप्ताह में एक दिन विभाग द्वारा तैयार एक घंटे का करेंट अफेयर्स कार्यक्रम इस चैनल से प्रमुख समय के दौरान प्रसारित किया जाता है। दिन के प्रमुख विषय, सामाजिक मुद्दों और सरकार की महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणाओं के बारे में 'चर्चा में' और 'आमने-सामने' जैसे कार्यक्रमों में जाने-माने अतिथि विशेषज्ञों के साथ चर्चा होती है। सप्ताह के अन्त में करेंट अफेयर्स कार्यक्रम की अवधि बढ़ जाती है क्योंकि इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित कार्यक्रम 'प्राइम मेरिडियन' और 'जायजा' तथा 'सिनेमा इस हफ्ते' हफ्ता आदि शामिल हैं। प्रत्येक रविवार को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने वाला एक घंटे का वार्तालाप आधारित कार्यक्रम पेश किया जाता है। 'टोटल हैल्थ' नाम के इस कार्यक्रम में डॉक्टर दर्शकों को स्वास्थ्य संबंधी सुझाव देते हैं। करेंट अफेयर्स कार्यक्रम में साम्प्रदायिक सद्भाव, रक्षा और सुरक्षा संबंधी मुद्दे, ग्रामीण विकास और सूचना का अधिकार जैसे मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम शामिल होते हैं।

विश्व समाचार में व्यापार और आर्थिक घटनाओं की सुर्खियों के बारे में यह चैनल 30 मिनट की अवधि के दो बुलेटिन प्रसारित करता है जिनमें अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य की ताजा खबर होती हैं। दोपहर का व्यापार बुलेटिन देश की व्यापारिक राजधानी मुंबई से जबकि शाम को व्यापार-समीक्षा दिल्ली स्थित व्यापार ब्यूरो द्वारा तैयार की जाती है। सर्राफा बाजार में निवेशकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए, शेयर बाजार, धातु और वस्तुओं के सूचकांक को पूरे दिन बॉटम स्क्रौल पर दिखाया जाता है जिसके लिए एन.एस.ई. बी.एम.ई., एम.सी.एक्स. और एन.सी.डी.ई.एक्स. की ताजा जानकारी स्वत: उपलब्ध होती रहती है। सप्ताह के अंत में 'व्यापार इस हफ्ते' कार्यक्रम में फोन पर दर्शकों को शेयर बाजार में निवेश के बारे में जानकारी दी जाती है।

खेल गतिविधियां भी दूरदर्शन न्यूज चैनल का महत्वपूर्ण अंग हैं। प्रतिदिन खेलों को 30 मिनट की अवधि के तीन प्रसारण होते हैं। क्रिकेट-शृंखला जैसी खेल घटनाओं के लिए विशेष कार्यक्रम भी तैयार किये जाते हैं जिनमें खेल जगत की जानी-मानी हस्तियां और विशेषज्ञ विश्लेषण में भाग लेते हैं। हिंदी शब्दों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से ''आज का शब्द'' शीर्षक कार्यक्रम के तहत हर घंटे में एक बार अंग्रेजी अर्थ सहित हिंदी के शब्द स्क्रोल पर दिखाए जाते हैं।

राज्यों की राजधानियों में 24 क्षेत्रीय समाचार एकांश न्यूज चैनल तथा दिनभर की घटनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज कवरेज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। डीडी न्यूज चैनल, क्षेत्रीय समाचार एकांशों से प्राप्त दृश्य कवरेज तथा संवाददाताओं से प्राप्त सजीव खबरों और न्यूज कैप्सूल का भरपूर उपयोग करता है। दूरदर्शन न्यूज चैनल पर 'मैट्रो स्कैन' और 'समाचार राज्यों से' क्षेत्रीय समाचार एकांशों के लिए निर्धारित कार्यक्रम जिनमें राज्यों की विकास गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाता है। 'स्टेट स्कैन' से तिरुअनंतपुरम हाल ही में जुड़ा है जबकि राज्यों से समाचार कार्यक्रम में भोपाल, चण्डीगढ़ और शिमला शामिल हैं।

देश भर में कुल 24 क्षेत्रीय समाचार एकांश प्रतिदिन 19 भाषाओं में 85 बुलेटिन प्रसारित करते हैं। इस वर्ष इंफाल से मणिपुरी भाषा में 5 मिनट का समाचार बुलेटिन शुरू किया गया है। अगरतला से प्रसारित होने वाले बंगाली और कोकबोरोक भाषा के स्थानीय बुलेटिनों की अवधि 5 मिनट से बढ़ाकर 7 मिनट 30 सेकेण्ड की गई है।

माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन को केवल डीडी न्यूज चैनल से ही प्रसारित किया जाता है। संसद के सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही पर हिंदी और अंग्रेजी में विशेष बुलेटिन भी प्रसारित होते हैं। इस चैनल ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की विदेश दौरों की भी कवरेज की और अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश और अन्य विदेशी नेताओं की भारत यात्रा के बारे में प्रमुखता से समाचार दिए। विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों को भी कवरेज दिया गया तथा चुनाव प्रचार और मतगणना के दिन विशेष समाचार बुलेटिन और कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

दिन-रात प्रसारित होने वाले डीडी न्यूज चैनल में विज्ञापनों, प्रचार

कार्यक्रमों को भी प्रसारित किया जाता है। चैनल ने विभागीय स्तर पर ग्राफिक जरूरतों की पूर्ति की क्षमता हासिल कर ली है तथा शुरुआती दौर से समयबद्ध नवीकरण होता रहा है।

डीएसएनजी की सुविधा उपलब्ध कराने से देशभर के समाचार संकलन और विभिन्न स्थानों से समाचार फुटेज की अपलिंकिंग की क्षमता में वृद्धि हुई है। भारत में महत्वपूर्ण कवरेज के समय अंतरराष्ट्रीय प्रसारण एजेंसियों को इंजीनियरिंग सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गईं। अक्तूबर 2005 से अब तक विदेशी प्रसारण संस्थाओं को 100 से अधिक फीड्स और स्टूडियो सुविधाएं उपलब्ध करा कर करीब 50 हजार अमेरिकी डालर की राशि अर्जित की गई।

दूरदर्शन न्यूज का अपना एक समाचार वेबसाइट ddinews.gov.in भी है जहां से ताजा समाचारों की जानकारी ली जा सकती है। इस वेबसाइट के माध्यम से इंटरनेट पर दूरदर्शन के लाइव समाचार बुलेटिन भी उपलब्ध होते हैं। इसे देश और विदेश में काफी पसन्द किया गया है।

डीडी स्पोर्टस

डीडी स्पोर्टस चैनल देश का एकमात्र फ्री टू एयर खेल चैनल है। इस वर्ष जिन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

- कॉमनवेल्थ खेल - मेलबोर्न, मार्च-2006, कामनवेल्थ खेलों की कवरेज, कार्यक्रम निर्माण और उनके प्रसारण के लिए दूरदर्शन का एक बड़ा दल भेजा गया। उद्घाटन समारोह, समापन समारोह और प्रतिदिन कम से कम चार घंटे का कार्यक्रम डीडी स्पोर्टस से प्रसारित करने के अलावा इन्हें दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल से भी दिखाया गया। कामनवेल्थ खेलों को डीडी स्पोर्टस चैनल से दिन-रात सीधा प्रसारित किया गया और सीधे प्रसारण के रिकार्ड किये गए अंशों का प्रसारण भी किया गया।
- कतर (दोहा में 1-15 दिसंबर तक पंद्रहवें एशियाई खेल, 2 से 15 दिसंबर 2006 तक इन खेलों का चौबीसों घंटे डीडी स्पोर्टस चैनल से प्रसारण किया गया और डीडी-1 पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए गए।
- हापमैंस एशिया कप, हैदराबाद में नवंबर-2006
- नवंबर 2006 में दिल्ली और चण्डीगढ़ में भारत-पाकिस्तान टेनिस टूर्नामेंट।
- अप्रैल 2006 में भारत और पाकिस्तान के बीच डेविस कप मुकाबला।
- कोलकाता में 9-10 अप्रैल 06 तक आयोजित 111वें बेटन कप मध्य हाकी टुर्नामेंट का प्रसारण।
- अप्रैल 06 में चिकमंगलूर में आयोजित ए.टी.पी. चैलेंजर टेनिस का सीधा प्रसारण।
- पुणे में मई 2006 में आयोजित एशियन एथलिटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का सीधा प्रसारण।
- सिंगापुर में जून 06 में आयोजित आई.बी.एफ. बैडमिन्टन प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण।
- जून 06 में चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से नेशनल फेडरेशन कप जूनियर एथलिटिक्स चैम्पियनशिप का सीधा प्रसारण।
- 20 से 24 नवंबर 2006 तक दिल्ली के डॉ. आम्बेडकर स्टेडियम में आयोजित 119वें एशियन डूरण्ड कप का सीधा प्रसारण।

डीडी स्पोर्टस पर आगामी खेल आयोजन

- 33वें राष्ट्रीय खेल, गुवाहाटी में 9 फरवरी 2007 तक
- विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता, मार्च-अप्रैल 2007

डीडी भारती

प्रसार भारती ने 26 जनवरी 2002 को सेटेलाइट मोड में इस चैनल की शुरुआत की। यह चैनल भारतीय जीवनशैली पर विशेष जोर देते हुए संगीत, नृत्य, विरासत, स्वास्थ्य और बच्चों पर कार्यक्रम प्रसारित करता है। यह अपने प्रसारण में योग और ध्यान, औषधि की वैकल्पिक चिकित्सा, एयरोबिक्स तथा स्वास्थ्य के अन्य पहलुओं पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित करता है। बाल और युवा प्रसारण में यह चैनल रोज युवाओं के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करता है जिनमें कार्टून, प्रतिभा, खोज कार्यक्रम, वन्य प्राणी फिल्में, विज्ञान-फिल्में और परामर्श कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा इस चैनल से पर्यटन और साहित्य के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं।

इस चैनल के कार्यक्रम मिश्रित होते हैं जिनमें स्वत: निर्मित, प्रायोजित और अर्जित और रायल्टी श्रेणी के कार्यक्रम शामिल हैं। इस चैनल से संगीत के सीधे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में ग्वालियर का तानसेन संगीत सम्मेलन, मुक्तेश्वर नृत्य समारोह, भुवनेश्वर, पुणे समारोह-2006, गिधोर समारोह बिहार (जमई जिला) और तूरा का ढोल उत्सव शामिल है। संगीत और नृत्य समारोहों के अलावा इस चैनल से संसद के उद्घाटन सत्र, राजीव गांधी

राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार और नोबल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर डगलस डी शौफ के भाषण को सीधे प्रसारित किया।

उभरते हुए युवा संगीतकारों को प्रोत्साहित करने के लिए 'स्वर्णांजलि' कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका प्रसारण अब भी जारी है।

समीक्षा अवधि के दौरान इस चैनल से वे ही कार्यक्रम प्रसारित किए गए जो डीडी भारती के बनाए हुए थे। इस समय तीन प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला पर रिपोर्ट प्रायोजित श्रेणी में और दूरदर्शन द्वारा अर्जित कार्यक्रम प्रसारित हुए। डीडी भारती कवि सम्मेलनों और मुशायरों का भी प्रसारण करता है। जिनमें राज्यों के भी कवि शामिल होते हैं। डीडी भारती ने अन्य सरकारी एजेंसियों के भी कार्यक्रम प्रसारित किये हैं, जिनमें सीईसी, इंदिरा गांधी कला केंद्र, शामिल है। इसने हाल में एन.सी.सी.ई.आर.टी. के साथ एक करार पत्र पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहत फरवरी 2007 से सप्ताह में तीन बार बच्चों के लिए कार्यक्रम टेलीकास्ट होगा।

चैनल ने कला संस्कृति, संगीत और भारत के समारोह विषयों पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम तैयार करने तथा महीने में एक बार संगीत समारोह प्रस्तुत करने की योजना बनाई है।

डीडी उर्दू

डीडी उर्दू चैनल 15 अगस्त 2006 को प्रारम्भ हुआ। यह चैनल प्रतिदिन सुबह, दोपहर बाद और शाम को तीन अलग-अलग ट्रांसमिशन में कुल मिलाकर 11 घंटे 30 मिनट का प्रसारण करता है।

इस प्रसारण में आवृत्ति, गैर-आवृत्ति अर्जित और विभागीय रूप से तैयार मिश्रित कार्यक्रम होते हैं जिनमें दर्शकों की अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए विरासत, संस्कृति, साहित्य, सूचना, शिक्षा और सामाजिक मुद्दे शामिल होते हैं। इस चैनल के लिए निर्माताओं से विशेष रूप से कार्यक्रम नहीं बनवाए गए हैं बल्कि उनके पास पहले से उपलब्ध कार्यक्रमों को लिया गया है। 12 प्रतिशत कार्यक्रम विभागीय स्तर पर तैयार होते हैं जिनमें करेंट अफेयर्स, फिल्म और रोजमर्रा की कवरेज और दूरदर्शन के राज्य और केन्द्रीय अभिलेखागारों से मिलने वाले कार्यक्रम शामिल हैं। प्रसारण में जिन विषयों को महत्व दिया जाता है उनमें लक्षित दर्शकों के शैक्षिक और सामाजिक दृष्टिकोण के आधुनिक बनाना, पड़ोस के दक्षिण-एशियाई देशों के तुलनात्मक सामाजिक अध्ययय को लोकतांत्रिक और गैर-लोकतांत्रिक सामाजिक ढांचे की पहचान के लिए पेश करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रचार, विज्ञान का रहस्योद्घाटन तथा उर्दू से जुड़े साहित्य और सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण शामिल है।

यह चैनल इस समय रोजाना 4 घंटे का ताजा कार्यक्रम दिखाता है। विभागीय तौर पर और माउंटसोर्जिंग के जरिए कार्यक्रम तैयार करने का प्रयास जारी है। इससे कार्यक्रमों में विविधता व्यापक और चमकदार होगी।

डीडी इंडिया

दूरदर्शन ने 14 मार्च 1995 को अंतरराष्ट्रीय चैनल शुरू किया। आरंभ में इस चैनल को डीडी वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था लेकिन 2002 में इसका नाम बदलकर डीडी इंडिया कर दिया गया। इस चैनल के कार्यक्रमों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को भारत की सामाजिक सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक गतिविधियों की नवीनतम जानकारी दी जाती है। डी.डी. इंडिया विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ संपर्क सेतु कायम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य असली भारत की तस्वीर, उसकी संस्कृति, विरासत, मूल्य, आधुनिकता, विविधता, एकता, संघर्ष उल्लास की झलक पूरी दुनिया के सामने बेहतरीन कार्यक्रमों के माध्यम से पेश करना है ताकि सार्वजनिक प्रसारणकर्ता की सर्वोच्च परम्पराओं के अनुरूप लोगों को सूचित, शिक्षित करते हुए मनोरंजन भी उपलब्ध कराया जा सके।

डीडी इंडिया से समाचार बुलेटिन, समसामयिक घटनाों पर फीचर, मनोरंजन कार्यक्रम, फीचर फिल्में, संगीत और नृत्य, बाल कार्यक्रम, घटनाएं और पर्यटन से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा उर्दू, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, गुजराती और मराठी के कार्यक्रम इस अंतरर्राष्ट्रीय चैनल से प्रसारित होते हैं।

डीडी इंडिया चौबीसों घंटे चलने वाला चैनल है। यह नई दिल्ली से अपलिंकिंग से जुड़ा हुआ है। पीएएस और पीएएम उपग्रहों के माध्यम से यह चैनल दुनिया के 146 देशों में देखा जा सकता है।

डीडी इंडिया के कार्यक्रम दूरदर्शन के अन्य चैनलों के कार्यक्रमों से हासिल किए जाते हैं। जैसे हिंदी के मनोरंजक धारावाहिक डीडी-1 से लिए जाते हैं। शास्त्रीय संगीत और नृत्य के कार्यक्रम डीडी भारती से और समाचार बुलेटिन डीडी न्यूज तथा क्षेत्रीय भाषा`क समाचारों और कार्यक्रमों से क्षेत्रीय भाषी सेटेलाइट चैनलों के जरिए प्राप्त होते हैं। चूंकि डीडी इंडिया के लक्षित दर्शक विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं, इसलिए इन कार्यक्रमों के सम्मिश्रण से इनकी रूचि और जरूरतों की पूर्ति की आशा की जाती है।

विदेशों में चैनल का वितरण

(i) चैनल का कनाडा में वितरण मैसर्स एस.एस. टीवी कनाडा द्वारा किया जाता है जिसके साथ 4 वर्ष के एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे प्रसार भारती को 2 लाख 50 हजार कनेडियन डालर की आमदनी होगी।

(ii) अमेरिका में डीडी इंडिया चैनल के कार्यक्रमों के वितरण के लिए डॉ. हेमंत पटेल के साथ 27-2-2006 को 5 वर्ष की अवधि के करार पर हस्ताक्षर किए गए। डा. हेमंत पटेल इस अवधि के दौरान प्रसार भारती को 31 लाख 65 हजार अमेरिकी डालर का भुगतान करेंगे।

(iii) ब्रिटेन के डी.डी. इंडिया और डी.डी. न्यूज के वितरण के लिए मैसर्स श्यात ग्रुप के साथ करार पर हस्ताक्षर होने वाले हैं।

इस चैनल के कार्यक्रमों के बारे में विदेशों से प्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों की प्रतिक्रियाएं और विचार पत्रों और ई-मेल के द्वारा नियमित रूप से प्राप्त होते हैं।

डीडी इंडिया दूरदर्शन के सेटेलाइट डीटीएच सेवा, डीडी डायरेक्ट प्लस पर भी उपलब्ध रहता है। डीडी डायरेक्ट प्लस भारत की पहली और एकमात्र फ्री-टू-एयर सेवा है।

निम्नलिखित देशों में डीडी इंडिया के कार्यक्रम देखे जा सकते हैं। पड़ोसी देश और दक्षिण-पूर्व एशिया:

अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, ब्रूनेई, चीन (आंशिक), कंबोडिया, हांगकांग, इंडोनेशिया, इस्राइल, कोरिया (उत्तर व दक्षिण) मालदीव, मलेशिया, माइक्रोनेशिया, मंगोलिया म्यांमार, जापान, लाओस, नेपाल, पालाउ, पापुआ, न्यू-गिनी, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान, थाइलैंड और विएतनाम।

सी.आई.एस.

अल्बेनिया, आर्मेनिया, बेलारूस, क्रोएशिया, जार्जिया, इस्तोनिया, कजाखिस्तान, किर्गिस्तान, लात्विया, मेकेडोनिया, मोल्दोवा, चेक गणराज्य, रोमानिया, रूसी संघ, स्लोवाक्मिया, स्लोवेनिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उक्रेन, यूगोस्लाविया।

पश्चिम एशिया

बहरीन, ईरान, इराक, इस्राइल, जोर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, फिलीस्तीन, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, यू.ए.ई. यमन।

अफ्रीका

अंगोला, अल्जीरिया, बेनिन बुर्किना फासो, बुरूण्डी, बोत्सवाना, कैमरून, मध्य अफ्रीका गणराज्य, चाड, कांगो, आइवरी कोस्ट, ज़िबूती, मिस्र, इरिट्रिया, इथोपिया, गेबोन, घाना, गिनी, गिनी बिसाउ फीनिया, लेसोथो, लाइबेरिया, लीबिया, मेडागास्कर, मालावी, माली, मोरक्को, मारिशस, मारिटेनिया, मोज़ाम्बिक, नामीबिया, नाइजर, खांडा गणराज्य, सेनेगल सेशेल्स, सिएरा लिओन, सोमानिया, दक्षिण अफ्रीका, स्वाज़ीलैंड, सूडान, तंजानिया, टोगेलो गणराज्य, ट्यूनीशिया, यूगाण्डा, ज़ायर, जांबिया, जिम्बाब्वे।

यूरोप तथा अमेरिका

आस्ट्रिया, बेलिज्यम, साइप्रस, डेनमार्क, फिनलैंड, यूनान, जर्मनी, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लिस्टेंसीन, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विटरजरलैंड, ब्रिटेन।

आस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको।

वाणिज्यिक सेवा

डीडी कमर्शियल सर्विस विभिन्न चैनलों के लिए सामान और सेवाओं के विज्ञापनों की बुकिंग करता है। विज्ञापनों की बुकिंग प्रत्यायित और पंजीकृत एजेंसियों के जरिए की जाती है। अग्रिम भुगतान मिलने पर बिना एजेंसी कमीशन के सीधे भी बुकिंग की जाती है।

वर्ष 2006-07 के दौरान नवंबर 2006 तक दूरदर्शन ने 474.95 करोड़ रुपये की वाणिज्यिक आय अर्जित की।

विकास संचार मंडल

विकास संचार मण्डल की स्थापना मार्च 2002 में सरकार के मंत्रालयों, विभागों और संगठनों की संचार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई थी। यहां कार्यक्रम तैयार करने, दूरदर्शन के एयर टाइम का विपणन, परामर्श, मीडिया नियोजन और कार्यान्वयन आदि सभी कार्यक्रम किए जाते हैं।

यह क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम तैयार करने के अलावा ग्राहक को मूलभूत जानकारी तथा शोध सर्वे भी उपलब्ध कराता है। 2005-06 वित्त वर्ष के दौरान विकास संचार मंडल ने 62 कंपनियों से 191 करोड़ रुपये अर्जित किए। इस तरह 5 वर्षों में इसकी आमदनी में 825 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वर्ष मंडल ने 2004-05 के अपने। राजस्व में 26 प्रतिशत वृद्धि हासिल करते हुए 150 करोड़ रुपए कमाए।

मंडल की इस सफलता में निम्नलिखित का योगदान रहा -

1. केंद्र और राज्य सरकारों के सभी राजस्व स्रोतों पर पकड़ बनाए रखना।

2. विपणन में व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ समय से अभियान शुरू कर समय पर समाप्त करना।

3. विपणन, निर्माण टेलीकास्ट, बिल बनाना, प्राप्ति और ग्राहक सेवा की सुविधाएं एक ही स्थान पर सुलभ कराना।

4. विभागीय कार्यक्रम निर्माण में अप्रत्याशित सुधार और शोध आधारित और प्रभावीन्मुख संघटन अपनाना।

5 सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बकाया खातों का समाधान।

प्रगति के पथ पर सार्वजनिक सेवा

विकास संचार मंडल निजी निर्माताओं से कड़ी स्पर्धा करते हुए सरकार के मंत्रालयों और विभागों से धन प्राप्त करता है। इसके विभागीय तौर पर बनने वाले कार्यक्रमों में अप्रत्याशित बदलाव आया है। मंडल द्वारा तैयार किए कार्यक्रमों के अनेक समसामयिक सामाजिक मुद्दों पर लोगों के बीच जागरुकता पैदा करने में असीम योगदान दिया है।

यह सब इसकी सकारात्मक सोच, सतर्क आयोजना, अनवरत प्रयास और अनेक अभिनव परिवर्तनों से संभव हो सका है। 2002 से लगातार चलने वाला सबसे लम्बा स्वास्थ्य संचार अभियान 'कल्याणी' ऐसे कार्यक्रम का ज्वलंत उदाहरण है। इससे एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता की शक्ति और दक्षता का पता चलता है। विभागीय स्तर पर तैयार किए गए कार्यक्रम 'कल्याणी' को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें यू.एन. एड्स सिविल सोसायटी पुरस्कार-2006 में विश्व एड्स दिवस पर प्राप्त हुआ।

'कल्याणी' कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए तैयार किया गया है और सप्ताह में एक दिन देश के 9 राज्यों में टेलीकास्ट होता है।

'कल्याणी' तथा डीसीडी द्वारा एचआईवी एड्स जागरूकता पर तैयार एक और कार्यक्रम - कैनो - बीसीसी-एनएकेसी की साझेदारी से बना जासूसी धारावाहिक 'जासूस विजय' जनवरी 2004 में विश्व मीडिया एड्स कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर संयुक्त राष्ट्र सचिव को पेश किए गए थे। जनवरी 2005 में एच आई वी एड्स पर आयोजित राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन में प्रधान मंत्री के समक्ष किए गए।

विकास संचार मंडल के जरिए दूरदर्शन की यूनीसेफ, एआईबीडी, हीरोज परियोजना और एमटीवी के साथ एड्स पर विभिन्न अभियानों के लिए साझेदारी है। इन प्रचार अभियानों के लिए दूरदर्शन को अनेक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं और राजस्व भी प्राप्त हुआ है।

क्षमता निर्माण

नीति निर्माताओं, सेवाकर्ताओं तथा ग्रामीण स्तर तक के कर्मियों के बीच नियमित रूप से संपर्क के लिए सहयोग की रूपरेखा तैयार की गई है। इससे सेवा सुधार के लिए सुझाव मिलने तथा संदेश तैयार करने में मदद मिलेगी। कल्याणी क्लबों की स्थापना की पहल से यह स्पष्ट हुआ कि टेलीविजन किस प्रकार समुदायों को प्रेरित कर सकता है। संचार मंडल अपने समृद्ध अनुभव को दूरदर्शन को प्रदान करता है। इससे दूरदर्शन टीम की कार्यकुशलता बढाने, तथा मुख्यालय और क्षेत्रीय स्तर पर इसके विभिन्नि अनुभागों - कार्यक्रम, इंजीनियरिंग, प्रशासन और अनुसंधान के बीच समन्वय मजबूत करने में मदद मिलती है। ऐसे प्रयासों से ढांचागत सुविधाओं में सुधार, कार्यप्रणाली को सरल बनाने, क्षमता निर्माण तथा मौजूदा संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायता मिली है।

नैरोकास्टिंग

कृषि के बारे में क्षेत्रीय महत्व की सूचनाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दूरदर्शन ने 2002 में एक अग्रगामी परियोजना शुरू कर देश के 18 राज्यों में 11 ट्रांसमीटरों पर लागू किया। 'नैरोकास्टिंग' की इस अवधारणा को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद देश के अन्य भागों में इसके प्रसार की मांग उठी। इसे देखते हुए नियमानुसार कृषि मंत्रालय के माध्यम से योजना आयोग को एक प्रस्ताव भेजा गया था। केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजना कृषि विस्तार में दूरदर्शन मीडिया को स्वीकृति मिली और इसे जनवरी 2004 में लागू कर दिया गया। इसका उदघाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किया। यह परियोजना अब 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत तीन चरणों में 225 करोड़ रुपए के बजट से लागू की जा रही है।

1. राष्ट्रीय चैनल पर पूरे देश के लिए कृषि कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। ये कार्यक्रम सप्ताह के 6 दिन (सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन सुबह साढ़े छ बजे) प्रसारित होते हैं।

2. 18 क्षेत्रीय चैनलों पर राज्य विशेष के कृषि कार्यक्रम टेलीकास्ट होते हैं। ये कार्यक्रम सप्ताह में 5 दिन (सोमवार-शुक्रवार) प्रतिदिन शाम को आधे घंटे के लिए प्रसारित होते हैं। इन्हीं कार्यक्रमों को दूसरे दिन सुबह सम्बन्धित क्षेत्रीय भाषा के सेटेलाइट चैनल से फिर प्रसारित किया जाता है।

3. 'नैरोकास्टिंग मोड' में क्षेत्रीय महत्व की सूचनाएं टेलीकास्ट होती हैं। इनका प्रसारण सप्ताह में 5 दिन (सोमवार-शुक्रवार) शाम के समय 180 ट्रांसमीटरों से होता है। इससे देश के 140 जिलों के किसानों को क्षेत्र विशेष की सूचनाएं प्राप्त होती हैं।

इन कार्यक्रमों की निगरानी और मार्गदर्शन तीन समितियां करती हैं;

(क) कृषि मंत्री की अध्यक्षता में सर्वोच्च समिति – इनमें कृषि सचिव, सीईओ-प्रसार भारती और महानिदेशक और (दूरदर्शन) सदस्य होते हैं।

(ख) राज्य-स्तरीय समिति – इनमें संबंधित राज्य के कृषि सचिव अध्यक्ष होते है तथा कृषि, मत्स्यकी, पशुपालन, और बागवानी विभागों के निदेशक तथा दूरदर्शन और आकाशवाणी के निदेशक आदि सदस्य होते हैं।

(ग) जिलास्तरीय समिति के अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होते हैं तथा कृषि, मत्स्यकी, पशु चिकित्सा और बागवानी विभागों के जिला-स्तरीय अधिकारी सदस्य होते हैं।

कृषि बागवानी, पशु चिकित्सा, मत्स्यकी के विशेषज्ञ इन विषयों के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम तैयार करते हैं। जिनमें फसलों की विभिन्न प्रौद्योगिकियों, विभिन्न योजनाओं, विकास-कार्यों की सफलता के प्रसंगों, मौसम और बाजार-भाव आदि विषयों को प्रमुखता दी जाती है। मुख्य कार्यक्रमों के अलावा कुछ महत्वपूर्ण और विशिष्ट कार्यक्रम इस प्रकार हैं –

(i) गांव-चौपाल की चर्चा जैसी संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं जिनमें 300-400 किसान मौजूद होते हैं। इनमें 12-15 विशेषज्ञ मौके पर ही किसानों के सवालों का जवाब देते हैं। सवाल-जवाब सत्र का संबंधित राज्य के दूरदर्शन नेटवर्क से सीधा प्रसारण होता है। हर वर्ष खरीफ और रबी फसल के दौरान कम-से-कम एक ऐसा कार्यक्रम प्रसारित होता है। इस धारणा का महत्वपूर्ण असर देखने को मिला है। संबंधित राज्यों से ऐसी ही संगोष्ठियां बार-बार आयोजित करने की मांग बढ़ी है।

(ii) किसानों के साथ साप्ताहिक फोन-इन कार्यक्रम संबंधित राज्यों के 'नैरोकास्टिंग जोन' से प्रसारित होता है। इसमें किसानों द्वारा फोन पर प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका विशेषज्ञ तुरंत समाधान करते हैं।

(iii) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पुणे का कृषि मौसम विभाग प्रत्येक केंद्र वेबसाइट के जरिए मौसम की ताजा जानकारी उपलब्ध कराता है, जिसे क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्र डाउनलोड कर, मौसम की जानकारियों के साथ प्रत्येक सप्ताह प्रसारित करते हैं।

(iv) राष्ट्रीय चैनल, 18 राज्यों के सभी 18 क्षेत्रीय केंद्रों और संबद्ध राज्यों के सभी 18 नैरोकास्टिंग केंद्रों से सप्ताह में (सोमवार-शुक्रवार) 5 दिन एक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाता है जिनमें नई खोजों, नीति, निर्यात और मौसम आदि की जानकारी होती है।

(v) राष्ट्रीय चैनल तथा 18 राज्यों के 'नैरोकास्टिंग' केंद्रों से सप्ताह में (सोमवार-शुक्रवार) 5 दिन विभिन्न मंडियों में चीजों की कीमतों के बारे में बुलेटिन प्रसारित किया जाता है।

55 निर्माण केंद्रों में तैयार कार्यक्रमों की तिथिवार निर्धारित सूची विशेष वेबसाइट (www.daenet.nic.in/csms) पर अपलोड किया जाता है, ताकि क्षेत्रीय कार्यकर्ता, योजनाकार, शिक्षित किसान भविष्य में प्रसारित कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी हासिल कर सकें।

कार्यक्रम निर्माताओं के हुनर और ज्ञान को नवीनता प्रदान करने के और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए इन्हें खेती, बिक्री आदि के बारे में विभिन्न कृषि-संस्थानों में प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

केंद्रीय कमीशनिंग यूनिट

दूरदर्शन ने भारतीय गौरव ग्रंथ शीर्षक से अभिलेखीय महत्व के साहित्यिक कार्यक्रमों के निर्माण की परियोजना शुरू की है। इस योजना के तहत दूरदर्शन ने अपने 23 केंद्रों से 15 भाषाओं में 30 मिनट अवधि की करीब 700 एपिसोड का निर्माण किया है। अडूर गोपालाकृष्णन, गिरीश कर्नाड, अमोल पालेकर, मुजफ्फर अली और गौतम घोष जैसे जाने-माने निर्माताओं ने गौरवग्रंथ के ये कार्यक्रम तैयार किए हैं।

भारतीय गौरव ग्रन्थ कार्यक्रम 'कथासरिता' 14 मई 2006 से प्रत्येक रविवार को दिन के 11 बजे प्रसारित होता है। क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम क्षेत्रीय केंद्रों से अक्टूबर 2006 से प्रसारित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम को भारी लोकप्रियता हासिल हुई है। यह भारी संख्या में दर्शकों को अपनी ओर खींचने में सफल हुआ है। विज्ञापनों से आमदनी भी हुई है। भारतीय गौरव ग्रन्थ कार्यक्रम के लिए सॉफ्टवेयर का सहयोग डीडी-1, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और क्षेत्रीय सेवाओं से प्राप्त होता है।

केंद्रीय कमीशनिंग यूनिट की महत्वपूर्ण कार्य और उपलब्धियां इस प्रकार हैं –

1. पूर्व प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री पर टेलीफिल्म का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है।

2. सीसीयू बाजार के अनुकूल कार्यक्रम तैयार करने के लिए पीएसबीटी के साथ कार्य जारी रखे हुए है।

3. 'प्रगतिशील भारत' शीर्षक से लघु फीचर कार्यक्रम को चालू वित्त वर्ष में बढ़ा कर 10 कड़ियों का कर दिया गया है। यह यूपीए सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर आधारित है।

4. 'गीतांजलि' शीर्षक से गुरुदेव रवीद्रनाथ ठाकुर को समर्पित 10 कड़ियों का कार्यक्रम बनाने का कार्य कोलकाता के मैसर्स साउनविंग को सौंपा गया है।

स्व वित्तपोषित कमीशनिंग (एसएफसी)

'सेल्फ फाइनेंसिंग कमीशनिंग' एक नई योजना है। इसके अन्तर्गत एक बाहरी निर्माता अपने साधन और खर्च से कार्यक्रम तैयार करता है। दूरदर्शन द्वारा इसका चयन होने पर डीडी इसे प्रसारित करता है और बाजार उपलब्ध कराता है तथा भुगतान करता है। इसमें एक निश्चित समय लगता है। यह योजना प्रायोजित कार्यक्रम व्यवस्था को समाप्त करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना जून 2005 में शुरू की गई। उस समय चल रहे प्रायोजित कार्यक्रम – ये हवाएं, करन जासूस, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, आपबीती, मैं बनूंगी मिस इंडिया और हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, को बदल कर एसएफसी कार्यक्रम में तब्दील कर दिया गया।

यह योजना निम्नलिखित कारणों से बहुत ही उत्साहवर्द्धक साबित हुई है:

1. गुणवत्ता और विविधता की दृष्टि से ये कार्यक्रम दूरदर्शन के कायक्रमों के पूरक साबित हुए हैं।

2. इस योजना के तहत निर्मित कार्यक्रम दूरदर्शन की संपत्ति होते हैं। दूरदर्शन अपनी इच्छानुसार इन कार्यक्रमों का उपयोग कर सकता है और इसे अपने किसी भी चैनल पर दिखा सकता है। प्रायोजित कार्यक्रमों में दूरदर्शन के पास यह अधिकार नहीं होता था। इस प्रकार एक बार खर्च से ही बार-बार उपयोग की सुविधा इस योजना की विशेषता है।

3. कार्यक्रम के निर्माण के प्रत्येक स्तर पर डीडी का गुणवत्ता नियंत्रण पर अधिकार होता है। इस उद्देश्य के लिए कार्यक्रम अनुश्रोता नियुक्त किए जाते हैं। प्रायोजित कार्यक्रमों के मामले में डीडी के पास यह व्यवस्था नहीं थी।

4. सॉफ्टवेयर के स्थाई अधिकारों के चलते, सीडी/वीसीडी और ब्राड बैण्ड आदि प्रौद्योगिकी का व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है।

5. एसएफसी कार्यक्रमों का विपणन दूरदर्शन के विपणन स्कंध द्वारा किया जाता है। प्रायोजित कार्यक्रम व्यवस्था की तुलना में आमदनी तीन गुना बढ़ गई है। राजस्व वृद्धि के अलावा डीडी को आज विपणन संस्थाओं/प्रायोजकों के साथ लेनदेन के बकायों से निजात मिल गई है क्योंकि दूरदर्शन अब ग्राहक से सीधे जुड़ा हुआ है। इसमें अदालती मामलों/ मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है।

6. उत्कृष्ट कार्यक्रम आकृष्ट करने के लिए दूरदर्शन के पास निर्माताओं को प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान है। इसके लिए निर्माता की टीआरपी एक निश्चति स्तर से अधिक होना चाहिए। अन्यथा उनकी देय राशि में कटौती की जा सकती है। यह फार्मूला बहुत कारगर साबित हुआ है। इससे डीडी उच्च स्तर के कार्यक्रम और पर्याप्त राजस्व, दोनों हासिल कर रहा है।

7. प्रति एपीसोड (किस्म, विषय, समय व टीआरपी के अनुसार) के अनुसार प्रति स्लॉट राजस्व प्राप्ति 6 लाख से 27 लाख रुपये के बीच होती है। औसतन प्रति एपीसोड 11 लाख रुपये की आय होती है।

8 एनएफसी की लोकप्रियता के चलते, डीडी के कुछ कमजोर स्लॉट और कार्यक्रम भी पैकेज कारोबार में बेहतर दर से बेचे जाते हैं।

9. इस समय (2-1-2007 को) 23 एसएफसी कार्यक्रम (20 प्राइम टाइम, 3 मिड प्राइम टाइम) प्रसारित हो रहे हैं।

10. कुल मिला कर एसएफसी बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। इस बात की अच्छी संभावना है कि दूरदर्शन बाहर के निर्माताओं से और अधिक उच्चस्तरीय कार्यक्रम हासिल कर बड़े पैमाने पर दर्शकों को अपने से जोड़ते हुए और अधिक राजस्व अर्जित करे।

दूरदर्शन अभिलेखागार - दूरदर्शन के केंद्रीय अभिलेखागार में 70,000 घण्टे के कार्यक्रम एनालोग वीडियो टेपों में है। इसके स्थान पर अब दूरदर्शन ने अपने सभी कार्यक्रमों डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की विस्तृत योजना तैयार की है।

अब तक 1400 घंटे के कायक्रमों को डिजिटल रूप में सुरक्षित कर लिया गया है। भावी कार्यक्रम में शामिल योजनाएं इस प्रकार हैं -

- डिजिटल माइग्रेशन ब्राडबैंड अभिसरण को सुसाध्य बनाना।
- कार्यक्रमों का वाणिज्यिक उपयोग
- डीवीडी/सीडी/वीसीडी का मुद्रण ताकि ग्राहक उन्हें आसानी से देख-सुन सके।

- युवाओं और साधकों में भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि जगाई जा सके।
- प्रवासी भारतीयों को यह सांस्कृतिक निधि उपलब्ध कराना।
- भारत और विदेशों में सांस्कृतिक संस्थाओं को महान भारतीय कलाकारों के प्रदर्शन उपलब्ध कराना।

डीडी अभिलेखागार ने अब तक बाजार में 51 शीर्षक जारी किए हैं।

डीडी एमटीएनएल ब्रॉडबैंड परियोजना के लिए 600 घंटे के कार्यक्रमों की पहचान की जा चुकी है। इनमें सांस्कृतिक यात्रा, व्यक्तियों, ऐतिहासिक स्थानों, स्वस्थ शरीर और जीवन शैली तथा हस्तशिल्प शामिल हैं।

मीडिया पहल - दूरदर्शन का जनसंपर्क प्रभाग मीडिया और प्रचार गतिविधियों को देखता है। सभी तरह के संचार साधनों, विज्ञापन, सीधा संपर्क, विज्ञप्तियों, प्रदर्शनियों आदि के जरिए दूरदर्शन के कार्यक्रमों और गतिविधियों का प्रचार किया जाता है। इस वर्ष के दौरान जनसंपर्क प्रभाग ने स्ववित्त पोषित कमीशनिंग योजना (एसएससी) के तहत गौरव ग्रंथ (कथा सरिता) कार्यक्रम के बारे में पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया।

दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली लोकप्रिय फिल्मों के बारे में विशेष विज्ञापन अभियान चलाए गए। मुख्यालय की तर्ज पर क्षेत्रीय दूरदर्शन केंद्रों पर भी जन संपर्क प्रभाग स्थापित किए गए हैं।

दूरदर्शन पुरस्कार

दूरदर्शन के प्रतिभाशाली कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2000 से दूरदर्शन वार्षिक पुरस्कार शुरू किए गए। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष सर्वोत्तम कार्यक्रमों को प्रदान किए जाते हैं। इस योजना में कुल 34 वर्गों के पुरस्कार हैं जिनमें 26 कार्यक्रम वर्ग, 5 इंजीनियरी वर्ग दो व्यक्तिगत पुरस्कार और एक सर्वोत्तम केंद्र के लिए है। यह पुरस्कार योजना प्रति पुरस्कार 25000 रुपये की राशि के साथ शुरू की गई थी। पुरस्कार राशि वितरण का अनुपात 60 : 40 प्रतिशत है यानी 60 प्रतिशत निर्माता के लिए और 40 प्रतिशत सहकर्मियों के लिए है।

वर्ष 2006 में सर्वोत्तम प्रायोजित कार्यक्रम वर्ग को सर्वोत्तम एसएफसी कार्यक्रम में बदल दिया गया। इस वर्ष दूरदर्शन ने अपना छठा वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह दूरदर्शन केंद्र जालंधर में आयोजित किया। कुल 44 वर्गों में पुरस्कार प्रदान किए गए। दूरदर्शन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 10 महानिदेशक की ओर से विशेष पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इस वर्ष पुरस्कार समारोह के टेलीकास्ट से 1.12 लाख की आमदनी हुई जबकि खर्च केवल 25 लाख रुपये हुए।

श्रोता अनुसंधान - दूरदर्शन का श्रोता अनुसंधान एकांश की देशभर के क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों में 19 क्षेत्रीय इकाई है। यह 4076 से प्रसारण के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करने में संलग्न है।

इसकी क्षेत्रीय इकाइयां, रांची, जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, नागपुर, चेन्नई, बैंगलौर, लखनऊ, हैदराबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, मुंबई, जालंधर, तिरुअनंतपुरम और श्रीनगर में हैं। इन इकाइयों का संचालन पेशेवर अनुसंधानकर्ताओं द्वारा होता है लेकिन तकनीकी दृष्टि से इसका नियंत्रण निदेशालय में श्रोता अनुसंधान निदेशक के हाथ में होता है।

वर्ष 2006-07 के दौरान श्रोता अनुसंधान इकाई ने निम्निलिखित कार्य जारी रखा है -

- डीएआरटी का डायरी के आधार पर मूल्यांकन
- कृषि विकास को मास मीडिया सहयोग के प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि कार्यक्रमों के बारे में नियमित जानकारी उपलब्ध कराना।
- साप्ताहिक आधार पर टीएएम रेटिंग के बारे में विश्लेषण और जानकारी देना।

इसके अलावा इकाई के अन्य योगदान इस प्रकार हैं:

- प्रसार भारती और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 2005-06 की वार्षिक रिपोर्ट के लिए मसौदा सामग्री तैयार करना
- दूरदर्शन की वार्षिक रिपोर्ट 2005-06 तैयार करना (प्रकाशित हो रही है)
- टेलीविजन क्रिकेट कमेंट्री पर टेलीफोन सर्वेक्षण।
- सितम्बर 2006 में तिरुअनंतपुरम में विभिन्न माध्यमों के जरिए संयुक्त प्रचार के प्रभाव का अध्ययन।
- जम्मू-कश्मीर में सीमा पार के टीवी के प्रभाव पर रिपोर्ट तैयार की गई।

यह इकाई दूरदर्शन की डीटीएच सेवा डीडी डायरेक्ट प्लस की वर्ष की आखिरी तिमाही के बारे में दर्शकों की राय जानने के लिए सर्वेक्षण की योजना बना रही है।

संलग्नक

दूरदर्शन ट्रांसमीटर (1-12-2006 को)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	स्टूडियो	राष्ट्रीय चैनल					न्यूज चैनल			
		एचपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	टीआरपी	कुल	एचपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	कुल
आंध्र प्रदेश	3	9	75	10	1	95	4	6	0	10
अरुणाचल प्रदेश	1	1	3	40	1	45	1	0	0	1
असम	4	3	21	1	1	26	2	1	0	3
बिहार	2	3	33	2	0	38	2	2	0	4
छत्तीसगढ़	2	3	16	8	0	27	1	0	0	1
गोवा	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1
गुजरात	2	6	54	3	0	63	4	3	0	7
हरियाणा	1	1	14	0	0	15	0	8	0	8
हिमाचल प्रदेश	1	2	8	39	2	51	2	1	0	3
जम्मू-कश्मीर	3	14	16	86	1	117	5	3	0	8
झारखंड	2	3	17	2	0	22	2	2	1	5
कर्नाटक	2	8	47	7	0	62	4	2	0	6
केरल	2	4	20	4	0	28	3	2	0	5
मध्य प्रदेश	3	6	63	5	0	74	4	0	0	4
महाराष्ट्र	3	8	79	20	0	107	5	10	0	15
मणिपुर	1	2	1	4	0	7	1	0	0	1
मेघालय	2	2	3	2	1	8	2	0	0	2
मिजोरम	1	2	1	2	1	6	1	1	0	2
नागालैंड	1	2	2	6	2	12	1	1	0	2
उड़ीसा	3	5	62	16	1	84	2	7	2	11
पंजाब	2	4	5	0	1	10	2	0	0	2
राजस्थान	1	6	66	17	2	91	4	4	0	8
सिक्किम	1	1	0	6	0	7	1	0	0	1
तमिलनाडु	3	6	45	7	1	59	2	9	0	11
त्रिपुरा	1	1	5	1	1	8	1	1	0	2
उत्तर प्रदेश	7	11	52	3	0	66	7	10	1	18
उत्तराखंड	1	1	15	33	2	51	1	1	0	2
पश्चिम बंगाल	3	9	19	1	0	29	3	2	0	5
अंडमान, निकोबार द्वीप समूह	1	0	2	11	0	13	0	1	0	1
चंडीगढ़	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
दादरा और नगर हवेली	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
दमन एवं दीव	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
दिल्ली	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
लक्षद्वीप	0	0	1	8	0	9	0	0	1	1
पुदुचेरी	1	1	2	2	0	5	0	1	0	1
कुल	**64**	**126**	**751**	**346**	**18**	**1241**	**69**	**78**	**5**	**152**

नोट - 1. ऊपर दर्शाए गए डीडी-1 ट्रांसमीटर (1241) में 108 ट्रांसमीटर प्रसारण के दौरान क्षेत्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करते हैं।

2 इनके अतिरिक्त 4 डिजिटल ट्रांसमीटर (एचपीटी) 4 महानगरों में चालू हालत में हैं।

कुल ट्रांसमीटर : 1397 (1241+ 152+ 4)

दूरदर्शन नेटवर्क

1-12-2006

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	प्राथमिक चैनल (डी डी 1) ट्रांसमीटर						न्यूज चैनल ट्रांसमीटर				क्षेत्रीय चैनल ट्रांसमीटर			
		स्टूडियो	एचपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	टीआरपी	कुल	एचपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	कुल	एचपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	3	9	75	0	1	85	4	6	0	10	0	0	10	10
2	अरुणांचल प्रदेश	1	1	3	40	1	45	1	0	0	1	0	0	0	0
3	असम	4	3	20	1	1	25	2	1	0	3	0	0	0	0
4	बिहार	2	3	33	2	0	38	2	2	0	4	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	2	3	16	8	0	27	1	0	0	1	0	0	0	0
6	गोवा	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
7	गुजरात	2	6	54	0	0	60	4	3	0	7	0	0	3	3
8	हरियाणा	1	0	14	0	0	15	0	8	0	8	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	1	2	8	39	2	51	2	1	0	3	0	0	0	0
10	जम्मू-कश्मीर	3	10	8	72	1	87	5	3	0	8	4	9	17	30
11	झारखंड	2	3	17	2	0	22	2	2	1	5	0	0	0	0
12	कर्नाटक	2	8	47	0	0	55	4	2	0	6	0	0	7	7
13	केरल	2	4	20	0	0	24	3	2	0	5	0	0	4	4
14	मध्य प्रदेश	3	6	63	5	0	74	4	0	0	4	0	0	0	0
16	महाराष्ट्र	3	8	79	0		87	5	10	0	15	0	0	20	20
17	मणिपुर	1	2	1	4	0	7	1	0	0	1	0	0	0	0
15	मेघालय	2	2	3	2	1	8	2	0	0	2	0	0	0	0
18	मिजोरम	1	2	1	2	1	6	1	1	0	2	0	0	0	0
19	नागालैंड	1	2	2	6	2	12	1	1	0	2	0	0	0	0
20	उड़ीसा	3	5	62		1	68	2	7	2	11	0	0	16	16
21	पंजाब	2	4	5	0	1	10	2	0	0	2	0	0	0	0
22	राजस्थान	1	6	67	17	2	92	4	4	0	8	0	0	0	0
23	सिक्किम	1	1	0	6	0	7	1	0	0	1	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	3	4	46	0	1	51	2	9	0	11	1	0	7	8
25	त्रिपुरा	1	1	5	1	1	8	1	1	0	2	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	7	11	52	3	0	66	7	11	1	19	0	0	0	0
27	उत्तराखण्ड	1	1	15	33	2	51	1	1	0	2	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	3	8	19	0	0	27	3	2	0	5	1	0	1	2
29	अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	1	0	2	11	0	13	0	1	0	1	0	0	0	0
30	चंडीगढ	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
31	दादरा और नागर हवेली	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दमन द्वीव	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	8	8
35	पुदुचेरी	1	1	2	1	0	4	0	1	0	1	0	0	1	1
	कुल	64	120	742	253	18	1133	69	78	5	152	6	9	93	108

टिप्पणी : इनके अलावा 4 महानगरों में 4 डिजिटल ट्रांसमीटर (एच पी टी) काम कर रहे हैं।

कुल ट्रांसमीटरों की संख्या : 1397

आकाशवाणी

संगठनात्मक ढांचा

आकाशवाणी के महानिदेशक प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) के अंतर्गत काम करते हैं। महानिदेशक को 'विभागाध्यक्ष' घोषित किया गया है। महानिदेशक समूचे आकाशवाणी नेटवर्क के समग्र प्रशासन और देख-रेख के लिए जिम्मेदार है। दायित्वों और कार्यों के निर्वाह में महानिदेशक की सहायता के लिए निम्नांकित अधिकारी हैं:-

कार्यक्रम स्कंध

महानिदेशक की सहायता के लिए मुख्यालय में उप-महानिदेशक होते हैं। इसी प्रकार क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न केन्द्रों की देख-रेख उप-महानिदेशकों द्वारा की जाती है। क्षेत्रीय उप महानिदेशकों के मुख्यालय कोलकाता (पूर्वी क्षेत्र), मुंबई (पश्चिमी क्षेत्र-1), लखनऊ (मध्य क्षेत्र-1), भोपाल (मध्य क्षेत्र-2), और गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र), चेन्नई (दक्षिणी क्षेत्र-1), बंगलौर (दक्षिणी क्षेत्र-2), दिल्ली (उत्तर क्षेत्र-1) और चंडीगढ़ (उत्तरी क्षेत्र-2) में हैं। एक नये उप महानिदेशक का कार्यालय अहमदाबाद (पश्चिमी क्षेत्र-2) में स्थापित किया जा रहा है।

इंजीनियरी स्कंध

आकाशवाणी के तकनीकी मामलों में महानिदेशक की सहायता के लिए मुख्यालयों में इंजीनियर-इन-चीफ और चीफ इंजीनियरों की नियुक्ति की गई है। इसी प्रकार आंचलिक स्तर पर जोनल चीफ इंजीनियर तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी के विकास योजना कार्यक्रमों के संदर्भ में महानिदेशक की सहायता सिविल निर्माण स्कंध द्वारा की जाती है जिसका प्रमुख एक चीफ इंजीनियर होता है। सिविल निर्माण स्कंध दूरदर्शन की जरूरतें भी पूरी करता है।

प्रशासनिक स्कंध

सभी प्रशासनिक मामलों में महानिदेशक की सहायता के लिए एक उप महानिदेशक (प्रशासन) और एक उप महानिदेशक (कार्यक्रम) होते हैं। आकाशवाणी के इंजीनियरी प्रशासन की देख-रेख निदेशक द्वारा की जाती है, जबकि प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में महानिदेशक की सहायता के लिए एक अन्य निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) होता है।

सुरक्षा स्कंध

आकाशवाणी प्रतिष्ठानों, ट्रांसमीटरों, स्टूडियो, कार्यालयों आदि की सुरक्षा और बचाव से संबद्ध सभी मामलों में महानिदेशक की सहायता के लिए उप महानिदेशक (सुरक्षा), सहायक महानिदेशक (सुरक्षा) और उप निदेशक (सुरक्षा) की व्यवस्था की गई है। दूरदर्शन की सुरक्षा जरूरतें भी इन्हीं अधिकारियों द्वारा पूरी की जाती हैं।

श्रोता अनुसंधान स्कंध

आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के बारे में श्रोता अनुसंधान सर्वेक्षण कराने में महानिदेशक की सहायता निदेशक (श्रोता अनुसंधान) द्वारा की जाती है।

आकाशवाणी के अधीनस्थ कार्यालयों की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण

आकाशवाणी के कई अधीनस्थ कार्यालय हैं, जो विशिष्ट कार्यों, व्यापक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

समाचार सेवा प्रभाग

समाचार सेवा प्रभाग दिन-रात काम करता है और घरेलू एवं विदेशी सेवाओं के अंतर्गत हर रोज बुलेटिन प्रसारित करता है। ये समाचार बुलेटिन भारतीय और विदेशी भाषाओं में होते हैं। प्रभाग के प्रमुख महानिदेशक (समाचार) हैं। नई दिल्ली मुख्यालय तथा 44 अन्य क्षेत्रीय समाचार एकांश हैं। समाचारों की जरूरत के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न तरह के बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं।

विदेश सेवा प्रभाग

आकाशवाणी का विदेश सेवा प्रभाग 27 भाषाओं में प्रसारण करता है। इनमें 16 विदेशी और 11 भारतीय भाषाएं हैं। ये सेवाएं कुल मिलाकर हर रोज 72 घंटे की अवधि का प्रसारण करती है और 100 से अधिक देशों में यह प्रसारण सुना जाता है।

लिप्यंतरण और कार्यक्रम विनिमय सेवा

यह सेवा आकाशवाणी केन्द्रों के बीच कार्यक्रमों का आदान-प्रदान और ध्वनि अभिलेखागार का रखरखाव करती है। प्रतिष्ठित संगीतकारों की रिकार्डिंग वाणिज्यिक आधार पर जारी करने का काम भी इस सेवा को सौंपा गया है।

अनुसंधान विभाग

अनुसंधान विभाग के कार्यों के अंतर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए अपेक्षित उपकरणों का अनुसंधान और विकास, आकाशवाणी और दूरदर्शन संबंधी अन्वेषण और अध्ययन, आकाशवाणी और

AIR MAP

दूरदर्शन के नेटवर्क में सीमित इस्तेमाल के लिए क्षेत्र परीक्षणों के वास्ते अनुसंधान एवं विकास उपकरणों के प्रोटोटाइप मॉडल विकसित करना शामिल है।

केन्द्रीय स्टोर कार्यालय

केन्द्रीय स्टोर कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह आकाशवाणी केन्द्रों में तकनीकी उपकरणों के रखरखाव के लिए इंजीनियरी सामान की खरीद, उसके भण्डारण और वितरण के लिए जिम्मेदार है।

कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम)

निदेशालय के साथ 1948 में स्थापित कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम) की फिलहाल दो प्रमुख शाखाएं हैं, जो किंग्सवे कैम्प, दिल्ली और भुवनेश्वर में कार्यरत हैं। ये शाखाएं कार्यक्रम कार्मिकों और प्रशासनिक कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देती हैं और नए कर्मचारियों के लिए प्रवेश पाठ्यक्रमों के अलावा अल्पावधि के पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का संचालन करती है। प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन भी संस्थान द्वारा किया जाता है।

इसके अतिरिक्त 5 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद, शिलांग, लखनऊ, अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम में कार्यरत हैं।

कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी)

कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) 1985 से निदेशालय का हिस्सा है। यह किंग्सवे कैम्प दिल्ली में कार्यरत है। संस्थान आकाशवाणी और दूरदर्शन के इंजीनियरी कर्मचारियों के लिए तकनीशियन के लेकर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर स्तर तक के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है। यह विभागीय क्वालिफाइंग और प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है। एक क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) भुवनेश्वर में स्थित है।

वाणिज्यिक प्रसारण सेवा केन्द्र और विविध भारती

आकाशवाणी के अंतर्गत 39 विविध भारती एवं वाणिज्यिक प्रसारण सेवा (सीबीएस) केन्द्र हैं। इनमें तीन विशेष विविध भारती केंद्र शामिल हैं। सीबीएस संबंधी कार्य दो अनुभागों यानी बिक्री और कार्यक्रम-निर्माण के अंतर्गत पूरे किए जाते हैं। केंद्रीय बिक्री एकांश नाम से एक स्वतंत्र कार्यालय विपणन और प्रसारण समय की देख-रेख करता है, जिसके अंतर्गत 15 मुख्य सीबीएस केंद्र हैं। वाराणसी और कोच्चि में दो और विविध भारती केन्द्र हैं, जो अभी वाणिज्यिक प्रसारण नहीं कर रहे हैं।

आकाशवाणी केन्द्र

फिलहाल 222 आकाशवाणी केंद्र हैं। ये सभी केन्द्र आकाशवाणी के अधीनस्थ कार्यालयों के रूप में काम करते हैं।

उक्त शक्ति ट्रांसमीटर

उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों के अंतर्गत शॉर्ट वेब/मीडियम वेब ट्रांसमीटर शामिल हैं, जो आठ व्यापक एरियल प्रणालियों के जरिए आकाशवाणी की विदेश, घरेलू और समाचार सेवाओं का प्रसारण करते हैं। इन केन्द्र का मुख्य कार्य निकटवर्ती स्टूडियो और दिल्ली स्टूडियो से निर्मित कार्यक्रमों को ट्रांसमिट करना है।

समाचार सेवा प्रभाग

आकाशवाणी के समाचार स्कंध, समाचार सेवा प्रभाग ने लोगों की सूचना आवश्यकताएं पूरी करने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यह समाज और देश को प्रभावित करने वाले मुद्दों/समस्याओं को उजागर करते हुए लोगों में जागरूकता पैदा करके सामाजिक परिवर्तन के एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में काम करता है।

समाचार और समाचार कार्यक्रम

समाचार सेवा प्रभाग के काम-काज को मोटे तौर पर समाचार बुलेटिनों और समसामयिक कार्यक्रमों में विभाजित किया जा सकता है। प्रभाग हर रोज 82 भाषाओं/बोलियों (भारतीय और विदेशी) में 509 समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है। कुल मिलाकर 52 घंटे का यह प्रसारण नई दिल्ली मुख्यालय और देश भर में फैली 44 क्षेत्रीय समाचार इकाइयों से किया जाता है। समाचार प्रसारण के अंतर्गत अन्य भाषाओं/बोलियों के अतिरिक्त भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं और 15 विदेशी भाषाओं में बुलेटिन शामिल हैं। क्षेत्रीय समाचार इकाइयां हर रोज 66 भाषाओं/बोलियों में 355 बुलेटिन प्रसारित करती है। विदेश सेवा के अंतर्गत आकाशवाणी 26 भाषाओं (भारतीय और विदेशी) में 65 समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है, जिनकी कुल अवधि करीब 9 घंटे होती है। समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के प्राइमरी, एफएम और डीटीएच चैनलों से प्रसारित किए जाते हैं। हर घंटे समाचार बुलेटिनों का प्रसारण एफएम गोल्ड से होता है। इसके अंतर्गत आकाशवाणी के 22 केंद्रों से एफएम रेनबो पर मुख्य समाचारों का प्रसारण भी शामिल है।

समाचार सेवा प्रभाग और इसकी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों द्वारा समाचार बुलेटिनों के अतिरिक्त सामयिक विषयों पर अनेक दैनिक और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम विविध

रूपों जैसे बातचीत, साक्षात्कार, वार्ताएं, समाचार पत्रिका, विश्लेषण और आंखों देखा हाल के रूप में प्रसारित होते हैं। समाचारकर्मियों, विशेषज्ञों और आम लोगों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से संबद्ध मुद्दों का विश्लेषण किया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। इनमें चर्चा का विषय है, सामयिकी, स्पॉट लाइट, मार्केट मंत्र (व्यापार पत्रिका), स्पोर्ट्स स्कैन (खेल-पत्रिका), वाद-संवाद, कंट्रीवाइड, मनी टॉक और सुर्खियों से परे जैसे कुछ कार्यक्रम अत्यन्त लोकप्रिय हैं।

फोन पर समाचार (एनओपी)

आकाशवाणी के समाचार फोन पर भी उपलब्ध हैं। विशिष्ट नंबरों पर मात्र एक फोन कॉल करके कोई भी व्यक्ति ताजा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय समाचार या क्षेत्रीय समाचार सुन सकता है। इस सेवा का विस्तार 2006 में चार और शहरों-जयपुर, अहमदाबाद, बंगलौर और तिरुवनंतपुरम में किया गया। इन्हें मिलाकर अब यह सेवा दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और पटना सहित 9 शहरों में उपलब्ध है। आने वाले महीनों में इस सेवा का विस्तार गुवाहाटी, इंफाल, लखनऊ, रायपुर और शिमला में करने की योजना है।

इंटरनेट पर समाचार और इंट्रा-एनएसडी

समाचार प्रेमी अब समाचार सेवा प्रभाग की आधिकारिक वेबसाइड-www.newsonair.com पर अद्यतन समाचार देख सकते हैं और बुलेटिन सुन सकते हैं। वेबसाइट को अक्टूबर 2006 में नया रूप दिया गया और उसमें अतिरिक्त विशेषताएं जोड़ी गईं।

अब समाचार आधारित साप्ताहिक और दैनिक कार्यक्रम ऑडियो यानी श्रव्य रूप में वेबसाइट पर उपलब्ध है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा विशेष घटनाओं और महत्वपूर्ण दिवस मनाने के सिलसिले में तैयार किए गए विशेष कार्यक्रम भी श्रव्य रूप में वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

आकाशवाणी समाचार के उत्सुक श्रोता चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हों, वे समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट पर क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों सहित सभी समाचार बुलेटिन सुन सकते हैं। 1 नवंबर 2006 से तीन और भाषाओं यानी असमिया, मलयालम और उड़िया वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए। वेबसाइट पर उपलब्ध अन्य क्षेत्रीय बुलेटिनों में बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, गुजराती और (शिलांग से) अंग्रेजी बुलेटिन शामिल हैं। उर्दू प्रेमियों के लिए भी नई दिल्ली से प्रसारित आकाशवाणी की उर्दू खबरें वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इससे क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों की पहुंच विश्वव्यापी बना दी गई है।

समाचार सेवा प्रभाग और उसकी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों तथा गैर क्षेत्रीय समाचार इकाइयों के लिए इंट्रा-नेटवर्क कायम किया गया है। 'इंट्रा-एनएसडी' की स्थापना से प्रभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय इकाइयों के बीच सरकार और सूचना का मुक्त और तीव्र प्रवाह बनाने में मदद मिलेगी। 'इंट्रा-एनएसडी' के जरिए ऑडियो फाइल का हस्तांतरण भी संभव है। इससे संवाददाताओं को इंटरनेट के जरिए अपनी आवाज में डिस्पैच भेजने में मदद मिलेगी। 'इंट्रा-एनएसडी' का उद्घाटन नवंबर 2006 में किया गया।

विस्तार के तरीके

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने अगस्त माह में देश के 19 और आकाशवाणी केंद्रों से एफएम मुख्य समाचार प्रारंभ करके एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने और देश में आकाशवाणी नेटवर्क पर समाचारों के परिचालन को व्यापक बनाने में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। 4 अगस्त 2006 को 7 क्षेत्रीय समाचार इकाइयों-कोलकाता, कटक, हैदराबाद, चेन्नई, त्रिची, पणजी और मुंबई तथा 29 अगस्त 2006 को 12 क्षेत्रीय समाचार इकाइयों-जयपुर, अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर, शिमला, पटना, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, पुणे, कालीकट, चंडीगढ़ और धारवाड़ से मुख्य समाचार बुलेटिनों का प्रसारण शुरू हुआ। इन्हें मिलाकर अब दिल्ली, लखनऊ और बंगलौर सहित 22 आकाशवाणी केंद्रो/क्षेत्रीय समाचार इकाइयों से एफएम समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं। अधिकाधिक एफएम केंद्रों और आकाशवाणी के विविध भारती केंद्रों से भी हर घंटे समाचार बुलेटिन शुरू करने के उपाय किए जा रहे हैं।

नया स्वरूप

श्रोताओं की रुचि और बदलते समय के साथ गति बनाए रखने के लिए समाचार सेवा प्रभाग ने अपने कुछ बुलेटिनों और कुछ कार्यक्रमों को नया रूप दिया है। नई विशेषताएं शामिल करके समाचारों का स्वरूप अधिक जनोन्मुखी बनाया गया है। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से आकाशवाणी के दोपहर के प्रमुख समाचार बुलेटिनों में सप्ताह के सभी दिनों 6-8 मिनट की अवधि का एक विशेष फीचर शामिल किया गया है। ये फीचर विकास प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, चिकित्सा और नशीले पदार्थों के सेवन, शिक्षा, महिला और बाल विकास, वरिष्ठ नागरिक,अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों, कला-संस्कृति और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में श्रोताओं की विशेष रूचि का ध्यान रखते हैं। बुलेटिन में फीचर शामिल किए जाने पर उत्साहजनक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। इसे देखते हुए अब एफएम गोल्ड पर तीन प्रमुख समाचार बुलेटिनों में ये फीचर प्रसारित किए जाने लगे हैं।

'मेट्रो रिपोर्ट' नाम से एक अन्य साप्ताहिक समाचार कार्यक्रम एफएम समाचार प्रसारण में शुरू किया गया है, जिसमें चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, और चेन्नई के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि श्रोताओं को उनकी तात्कालिक रुचि की खबरें मिल सकें।

लाखों बेरोजगार युवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समाचार सेवा प्रभाग ने एफएफ गोल्ड पर दोपहर के प्रमुख समाचार बुलेटिनों में 'रोजगार के अवसरों' के बारे में एक साप्ताहिक कैप्सूल शामिल किया है।

स्थानीय खबरों को अधिक संख्या में दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत करने के प्रयास के अंतर्गत 'जिले की चिट्ठी' अथवा 'डिस्ट्रिक्ट न्यूज लैटर' जैसे समाचार आधारित कार्यक्रमों को नया रूप दिया गया और 2006 में गांधी जयंती से इनका प्रसारण पुन: प्रारंभ किया गया। आकाशवाणी समाचारों के प्रसारण को आकर्षक बनाने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों और सम-सामयिक कार्यक्रमों के साथ नई 'सिग्नेचर ट्यून्स' यानी 'संकेत-धुनें' जोड़ी गईं।

संवाददाताओं के नेटवर्क का विस्तार

किसी भी अन्य समाचार संगठन के पास समाचार कार्यालयों, संवाददाताओं और संपादकों का इतना विश्वसनीय नेटवर्क नहीं है, जितना समाचार सेवा प्रभाग का है। देश भर में प्रभाग की 44 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां हैं, जिनमें 110 पूर्णकालिक संवाददाता/संपादक काम कर रहे हैं। इन क्षेत्रीय समाचार इकाइयों के अलावा देश में 13 महत्वपूर्ण समाचार केंद्रों पर आकाशवाणी संवाददाता तैनात किए गए हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन की जरूरतें पूरी करने के लिए विश्वभर में महत्वपूर्ण समाचार केंद्रों पर स्ट्रिंगर्स यानी अंशकालिक संवाददाता नियुक्त करने का प्रस्ताव है। स्थानीय समाचारों/समाज के निचले स्तर से संबद्ध खबरों के महत्व को पहचानते हुए समाचर सेवा प्रभाग देश में प्रत्येक जिला मुख्यालय में अंशकालिक संवाददाता की नियुक्ति कर रहा है। फिलहाल 425 अंशकालिक संवाददाता आकाशवाणी के लिए काम कर रहे हैं। ये अंशकालिक संवाददाता दूरदर्शन समाचारों की जरूरतें भी पूरी करते हैं।

कौशल में सुधार

समाचार सेवा प्रभाग मानव संसाधनों-संपादकों और संवाददाताओं के कौशल में सुधार पर विशेष बल दे रहा है। संवाददाताओं के भाषिक कौशल के महत्व को समझते हुए प्रभाग ने ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से भाषिक कौशल के बारे में 30 घंटे की दो कार्यशालाओं का आयोजन किया। पहली कार्यशाला अप्रैल 2006 में और दूसरी मई 2006 में समाचार सेवा प्रभाग के मुख्यालय में आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं का प्रयोजन समाचार कार्मिकों के उच्चारण और भाषिक क्षमता में सुधार लाना था।

अंशकालिक संवाददाता आकाशवाणी के लिए निचले स्तर पर समाचारों के स्रोत के रूप में काम करते हैं। उनसे बेहतर परिणाम हासिल करने के वास्ते उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता अरसे से महसूस की जा रही थी। इसे देखते हुए प्रभाग ने पहली प्रशिक्षण कार्यशाला आकाशवाणी रांची में 24 से 26 जुलाई 2006 के दौरान आयोजित की। इसमें झारखंड से 20 अंशकालिक संवाददाताओं ने हिस्सा लिया, जिन्हें विभाग और बाहर के विशेषज्ञों द्वारा प्रसारण पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। इसी प्रकार की अन्य कार्यशालाएं मुंबई (18 से 20 अगस्त), लखनऊ (31 अगस्त से 2 सितम्बर), गुवाहाटी (10 से 12 अक्टूबर), शिलांग (11 से 13 अक्टूबर) और तिरुवनंतपुरम (17 से 19 अक्टूबर, 2006) में आयोजित की गईं।

क्षेत्रीय समाचारों को बेहतर बनाना

समाचार सेवा प्रभाग ने, व्यावसायिक और ढांचागत, दोनों की तरह की सहायता प्रदान करके क्षेत्रीय समाचार नेटवर्क को सुदृढ़ करने की कोशिश की है। क्षेत्रीय बुलेटिनों के फोरमेट को नया रूप दिया गया। क्षेत्रीय बुलेटिनों को सुदृढ़ बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए और उन पर अमल सुनिश्चित किया गया ताकि समाचारों को अधिक रोचक बनाया जा सके। बुलेटिनों के लिए एक समान संकेत धुन तैयार की गई और अब सभी इकाइयों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वर्ष सभी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों को कम्प्यूटर, प्रिंटर जैसी बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान की गईं। कठिन और तनावपूर्ण परिस्थितियों के अंतर्गत काम करने में अधिकारियों को प्रेरित करने के लिए इस वर्ष संवाददाताओं को दिए जाने वाले मौजूदा पुरस्कारों के अतिरिक्त दो नए पुरस्कार—'आरएनयू आफ द ईयर' और 'बेस्ट न्यूज एडिटर' यानी 'वर्ष की सर्वोत्तम क्षेत्रीय समाचार इकाई' और 'सर्वोत्तम समाचार संपादक' शुरू किए गए।

क्षेत्रीय सम्मेलन

पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की क्षेत्रीय समाचार इकाइयों के प्रमुखों का एक सम्मेलन 19 और 20 नवंबर 2006 को पुरी, उड़ीसा में आयोजित किया गया। सम्मेलन में 16 क्षेत्रीय समाचार इकाइयों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। इसमें क्षेत्रीय बुलेटिनों की विषयवस्तु और गुणवत्ता, समाचार एकत्र करने संबंधी नेटवर्क, प्रौद्योगिकी और नवीनता, विस्तार योजनाएं, कार्यालय सहायता प्रणाली आदि मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त रेडियो समाचारों की भावी दिशा पर भी चर्चा हुई।

समाचार कवरेज

इस वर्ष प्रभाग की कवरेज का केंद्रबिंदु आम आदमी रहा। प्रभाग ने आम आदमी को प्रभावित करने वाले मुद्दों और अनुसूचित जातियों/जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, किसानों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों सहित केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी को व्यापक कवरेज की गई। सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, भारत निर्माण और सर्व शिक्षा अभियान आदि को विशेष कवरेज दी गई।

वर्ष 2006 के दौरान समाचार सेवा प्रभाग ने सभी प्रमुख घटनाओं पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए। इनमें केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पांडिचेरी, में विधानसभा चुनाव, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम (1857) की 150वीं वर्षगांठ, राष्ट्रीय गीत-वंदे मातरम् के शताब्दी समारोहों और शहीद भगत सिंह की जन्मशताब्दी समारोह जैसी घटनाएं शामिल थीं। इसके अतिरिक्त भारत और चीन के बीच 44 वर्ष बाद नाथू ला दर्रे से सीमा व्यापार बहाल होने, पूंछ और पाकिस्तान के कब्जे वाले रावलकोट के बीच बस सेवा के उद्घाटन को विशेष कवरेज प्रदान की गई।

सूचना का अधिकार अधिनियम को समाचार बुलेटिनों और कार्यक्रमों में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। विश्व व्यापार संगठन वार्ता, मूल्य वृद्धि रोकने के सरकार के प्रयास और किसानों को राहत पैकेज जैसे आर्थिक मुद्दों तथा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम और उसके कार्यान्वयन पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए गए। भारत-पाकिस्तान संबंधों, विशेष रूप से सीमा पार से आतंकवाद रोकने और मुंबई तथा मालेगांव में बम बिस्फोटों के सिलसिले में समाचार आधारित कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

समाचार सेवा प्रभाग ने प्रधानमंत्री की जर्मनी, ब्राजील, उज्बेकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, जापान, लैटिन अमरीकी देशों और यूरोप की यात्राओं को व्यापक कवरेज प्रदान की। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, जैसे हवाना में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, सेंट पीटर्सबर्ग में जी-8 शिखर सम्मेलन, विभिन्न स्तरों पर सार्क की बैठकों आदि को व्यापक कवरेज प्रदान करने के लिए आकाशवाणी संवाददाता नियुक्त किए गए। अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू. बुश, चीन के राष्ट्रपति हू चिन ताओ और फ्रांस के राष्ट्रपति यॉक शिराक सहित महत्वपूर्ण विदेशी नेताओं तथा उनके साथ हस्ताक्षर किए गए महत्वपूर्ण समझौतों को विस्तृत करवेज की गई। कोलंबो, काठमांडू, ढाका और काबुल स्थित आकाशवाणी के विशेष संवाददाताओं ने संबद्ध देशों की राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी घटनाओं के बारे में व्यापक समाचार दिए। भारतीय संदर्भ में वैश्विक घटनाओं की कवरेज बढ़ाने के लिए चुने हुए समाचार केंद्रों पर स्ट्रिंगर तैनात करने का प्रस्ताव है।

खेल जगत इस वर्ष की कवरेज में विशेष रूप से लोकप्रिय रहा। मार्च 2006 में मेलबार्न में हुए राष्ट्रमंडल खेल, सिंतबर, 2006 में कोलम्बो में दक्षिण एशियाई खेल, अक्टूबर से भारत में खेली गई आईसीसी चैम्पियन्स ट्राफी प्रतियोगिता, सितम्बर में क्वालालम्पुर में तीन देशों की क्रिकेट श्रृंखला, जर्मनी में विश्व कप फुटबाल प्रतियोगिता, जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं ने वर्ष भर खेलों की कवरेज को बुलंदी पर रखा। दोहा में आकाशवाणी के दुबई संवाददाता की सेवाओं का लाभ उठाते हुए 15वें एशियाई खेलों को व्यापक कवरेज प्रदान की गई।

संसदीय कवरेज

संसद के सत्र के दौरान हिंदी में 'संसद समीक्षा' और अंग्रेजी में 'टुडे इन पार्लियामेंट' का प्रसारण किया गया, जिसमें संसद के दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाही की समीक्षा की गई। इसी प्रकार राज्य विधान मंडलों के सत्र के समय प्रभाग की संबद्ध क्षेत्रीय समाचार इकाइयों द्वारा सदन की कार्यवाही की दैनिक समीक्षा प्रसारित की गई।

विदेश सेवा प्रभाग

आकाशवाणी ने 1 अक्टूबर, 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कुछ ही समय बाद विदेश प्रसारण के क्षेत्र में कदम रखा, जब देश के तत्कालीन उत्तर-पश्चिमी सीमावर्ती श्रोताओं के लिए पश्तो में सेवा शुरू की गई। इस सेवा का उद्देश्य अफगानिस्तान, ईरान और अरब देशों के लिए रेडियो जर्मनी द्वारा किए जाने वाले प्रोपेगंडा का सामना करना था। युद्ध समाप्त होने के बाद ऐसी सेवाओं को जारी रखने की आवश्यकता का मूल्यांकन किया गया, और अनेक सेवाओं को पुन: व्यवस्थित किया गया। आकाशवाणी का विदेश सेवा प्रभाग भारत और शेष विश्व के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क के रूप में काम कर रहा है। विशेषकर उन देशों के साथ संपर्क बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जहां बड़ी संख्या में भारतीयों के बसे होने से राष्ट्र से हित जुड़े हुए हैं। बेहतर जीवन की तलाश में दशकों पहले स्वदेश छोड़कर जाने वाले भारतीय आज विश्व के कोने-कोने में बसे हुए हैं और अब भी अपने 'मूल राष्ट्र' के बारे में जानने के इच्छुक रहते हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि विदेश सेवा प्रभाग अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है।

आकाशवाणी का विदेश सेवा प्रभाग पहुंच और जानकारी के दायरे दोनों ही दृष्टियों से दुनिया के चोटी के विदेश नेटवर्कों में से एक

है। यह 27 भाषाओं में करीब 100 देशों के लिए कार्यक्रम प्रसारित करता है। इनमें 16 विदेशी और 11 भारतीय भाषाएं हैं। हर रोज 70 घंटे 30 मिनट की अवधि के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम विदेश में स्थित श्रोताओं को भारतीय लोकाचार और भारतीय मूल्यों से जोड़ते हैं। इन प्रसारणों में भारत के विचारों और एक मुक्त समाज के रूप में उसकी उपलब्धियों को व्यक्त किया जाता है।

विदेशी भाषाएं : आकाशवाणी से निम्नांकित विदेशी भाषाओं में प्रसारण होता है : अरबी (3 घंटे 15 मिनट), बलूची (1 घंटा), चीनी (1 घंटा 30 मिनट), दरी (1 घंटा 45 मिनट), फ्रेंच (45 मिनट), इंडोनेशियाई (1 घंटा), नेपाली (3 घंटे), फारसी (1 घंटा 45 मिनट), पश्तो (2 घंटे), रूसी (1 घंटा), सिंहली (2 घंटे 30 मिनट), स्वाहिली (1 घंटा), थाई (45 मिनट), तिब्बती (1 घंटा 15 मिनट) और अंग्रेजी (जी ओ एस) (8 घंटे 15 मिनट)।

भारतीय भाषाएं: विदेश सेवा के अंतर्गत निम्नाकित भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं : हिंदी (5 घंटे 15 मिनट), पंजाबी (2 घंटे), सिंधी (3 घंटे 30 मिनट), उर्दू (12 घंटे 15 मिनट), सराइकी (30 मिनट), मलयालम (1 घंटा) और कन्नड़ (1 घंटा)।

विदेश सेवा के अंतर्गत निम्नांकित भारतीय भाषाओं के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं : हिंदी (5 घंटे 15 मिनट), तमिल (5 घंटे 30 मिनट), तेलुगु (30 मिनट), बांग्ला (6 घंटे 30 मिनट), गुजराती (30 मिनट), पंजाबी (2 घंटे), सिंधी (3 घंटे 30 मिनट), उर्दू (12 घंटे 15 मिनट), सराईकी (30 मिनट) मलयालम (1 घंटा), और कन्नड़ (1 घंटा)।

प्रसारण के अंतर्गत समाचार बुलेटिन, समीक्षाएं, समसामयिक घटनाएं और भारतीय समाचार पत्रों की समीक्षा शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूज रील, खेल और साहित्य पत्रिका कार्यक्रम, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विषयों पर वार्ताएं और बातचीत भी प्रसारित की जाती है। विकासात्मक गतिविधियों, महत्वपूर्ण घटनाओं और संस्थानों के बारे में फीचर, भारत के विविध क्षेत्रों के शास्त्रीय, लोक और आधुनिक संगीत को भी समग्र कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया जाता है।

विदेश सेवा प्रभाग के कार्यक्रमों का प्रमुख लक्ष्य एक सुदृढ़, सशक्त, प्रगतिशील और तेजी से आर्थिक, औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी विषयक प्रगति करने वाले लोकतंत्र के रूप में भारत की छवि को प्रस्तुत करना है। भारत की विस्तृत तकनीकी कार्मिक शक्ति, उसकी उपलब्धियों तथा पारिस्थितिकी संतुलन जैसे तथ्यों को सहज और सरल ढंग से कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचारित किया गया।

इसी प्रकार अहिंसा में भारत की आस्था, मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रति उसकी वचनबद्धता और नई आर्थिक विश्व व्यवस्था के निर्माण में उसके योगदान के बारे में बार-बार बताया गया।

विदेश सेवा प्रभाग के प्रसारण के दायरे में पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया, पश्चिम, उत्तर-पश्चिम, और पूर्वी अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, यूरोप और समूचा भारतीय उपमहाद्वीप शामिल हैं। विदेशी भाषाओं के अतिरिक्त विदेश सेवा प्रभाग विश्व के विभिन्न भागों में बसे प्रवासी भारतीयों के लिए भारतीय भाषाओं में भी प्रसारण करता है। विदेश स्थित भारतीयों के लिए हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मलयालम, और कन्नड़ में कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है इसी प्रकार उपमहाद्वीप और सीमावर्ती देशों के श्रोताओं के लिए उर्दू, बांग्ला, पंजाबी, और सिंधी में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, ताकि लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सह-अस्तित्व के सिद्धांतों के प्रति समर्पित और आधुनिक प्रगतिशील एवं उन्नत भारत की छवि प्रस्तुत की जा सके।

मौजूदा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत विदेश सेवा प्रभाग ने संगीत, भाषिक और मिश्रित कार्यक्रमों की रिकार्डिंग करीब 23 विदेशी प्रसारण संगठनों को देना जारी रखा।

मूल रूप से घरेलू सेवा के लिए अंग्रेजी में तैयार किए गए रात 9.00 बजे के राष्ट्रीय बुलेटिन का प्रसारण सार्क देशों, पश्चिम एशिया, खाड़ी और दक्षिणी-पूर्व एशियाई देशों मे भी किया जाता रहा। विदेश सेवा प्रभाग ने समसामयिक और संबद्ध मुद्दों पर टिप्पणियों और अखबारों की समीक्षा का वैश्विक प्रसारण जारी रखा।

महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण

भारत आने वाले विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों और अन्य महत्वपूर्ण विदेशी व्यक्तियों की यात्राओं को व्यापक कवरेज प्रदान किया गया। इनमें सउदी शाह अब्दुल्ला, फ्रांस के राष्ट्रपति याक शिराक, अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू. बुश, रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन, फिनलैंड के प्रधानमंत्री, डब्ल्यूटीओ अध्यक्ष पास्कल लैमी, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, कुवैत के अमीर, स्पेन के प्रधानमंत्री जोसे कैप्टेरो, और चीन के राष्ट्रपति हू चिन ताओ, श्रीलंका के राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षे शामिल थे।

राष्ट्रपति डा० एपीजे अब्दुल कलाम की विभिन्न देशों, जैसे फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, म्यांमार और मॉरिशस की यात्राओं को समुचित

कवरेज दी गई। प्रधानमंत्री डा० मनमोहन सिंह की अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, ताशकंद, ब्रासिलिया और दक्षिण अफ्रीका की विदेश यात्राओं पर विदेश प्रसारण सेवा ने पर्याप्त ध्यान दिया और इनकी कवरेज में राजनीतिक एवं आर्थिक महत्व के मुद्दों को उजागर किया।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को विदेश प्रसारण सेवा से संबद्ध विभिन्न भाषाओं के प्रसारणों में व्यापक कवरेज प्रदान की गई। इनमें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, विश्व पुस्तक मला, राष्ट्रमंडल प्रसारण संघ, विश्व नेताओं का जी-8 शिखर सम्मेलन, हवाना में 14वां गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रमुख रूप से शामिल थे।

इंटरनेट का इस्तेमाल

वर्तमान में अमरीका, कनाडा आदि देशों को लक्ष्य बनाकर विदेश सेवा प्रभाग के प्रसारण नहीं किए जा रहे हैं, हालांकि वहां इन कार्यक्रमों के श्रोता कम नहीं हैं। इसे देखते हुए अमरीका और कनाडा में श्रोताओं के लाभ के लिए इंटरनेट पर फीड करने के वास्ते 12 घंटे के कार्यक्रम (अंग्रेजी और हिंदी) तैयार करने की योजना है। परंतु, यह प्रस्ताव धन की उपलब्धता और इस प्रयोजन के लिए अलग प्रकोष्ठ कायम करने पर निर्भर है।

सीडी के जरिए ट्रांसमिशन

विदेश सेवा प्रभाग की एक अन्य उपलब्धि इस वर्ष यह रही कि उसने नए प्रसारण भवन में स्थापित नई व्यवस्था से डिजिटल ट्रांसमिशन प्रारंभ किया। अधिकाधिक श्रोताओं को आकर्षित करने के लिए सभी आधुनिक प्रणालियों और उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। आकाशवाणी से इंटरनेट प्रसारण शुरू हाने के बाद अमरीका, कनाडा, पश्चिम और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के श्रोताओं के लिए यह संभव हो गया है कि वे इंटरनेट पर 24 घंटे उपलब्ध आकाशवाणी की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। विदेश प्रसारण सेवा की उर्दू सेवा भी 30 जून 2006 से डीटीएच के माध्यम से प्रसारित की जा रही है।

नए प्रसारण भवन परिसर में प्रसारण की सर्वाधिक आधुनिक पद्धति अपनाई जा रही है। टेप प्ले करने की परंपरागत पद्धति के स्थान पर कम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

'राष्ट्र की आवाज' के रूप में आकाशवाणी का विदेश सेवा प्रभाग भारत के बारे में जानने के लिए 'विश्व के लिए प्रामाणिक माध्यम' साबित हुआ है। विश्व में भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को देखते हुए आने वाले समय में विदेश प्रसारण सेवा का महत्व भी बढ़ेगा।

वाणिज्यिक स्कंध

आकाशवाणी के लिए राजस्व जुटाना इसकी वाणिज्यिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन के बावजूद, आकाशवाणी का वाणिज्यिक स्कंध मुंबई स्थित केन्द्रीय बिक्री एकांश, देश के विभिन्न भागों में स्थित 15 मुख्य वाणिज्यिक प्रसारण सेवा केंद्र, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी स्थित 8 विपणन प्रभागों के जरिए हर वर्ष अपने समग्र वाणिज्यिक राजस्व में बढ़ोतरी करने में सफल रहा है। साथ ही उसने लोक सेवा प्रसारणकर्ता के रूप में अपनी मूल पहचान भी निरंतर बनाए रखी है।

आकाशवाणी के कार्यक्रमों और वाणिज्यिक प्रसारणों पर एक आचार संहिता लागू होती है। प्रसारण और वाणिज्यिक संहिताओं का सख्ती से पालन करते हुए और वाणिज्यिक प्रसारण केंद्रों/विविध भारती केंद्रों/एफएम चैनलों सहित आकाशवाणी के लगभग सभी स्टेशनों पर बजट और स्टाफ संबंधी कठिनाइयों के बावजूद, वाणिज्यिक स्कंध प्रमुख कार्पोरेट ग्राहकों/विज्ञापन दाताओं तथा सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से व्यापार जुटाने में सक्षम रहा है। कुछ प्रमुख निजी कार्पोरेट ग्राहकों में हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, डाबर (इंडिया) लिमिटेड, हीरो होंडा और रिलायंस ग्रुप शामिल हैं। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख ग्राहकों में ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, प्रौढ़ शिक्षा विभाग, इंयिन आयल, बीएसएनएल, एमटीएनएल, नाको, एनएचएआई, एसबीआई, पीएनबी और आईआरडीए शामिल हैं।

निजी प्रसारणकर्ताओं के प्रवेश के कारण बाजार में निरंतर बढ़ती जा रही प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए वाणिज्यिक स्कंध अपनी शुल्क दरों में संशोधन करने की प्रक्रिया में है, ताकि उन्हें ग्राहकोन्मुखी और प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके। एफएम चैनलों के लिए विशेष पैकेज दरें और एफएम इंडिया के लिए संयुक्त पैकेज दरें तय की जा रही हैं और जल्दी ही इन्हें लागू किया जाएगा।

वाणिज्यिक स्कंध में सभी प्राथमिक चैनलों, स्थानीय रेडियो केंद्रों, एफएम और विविध भारती केंद्रों पर स्पॉट-खरीद बुकिंग के लिए 1 : 1 बोनस योजना जारी रखी। बाजार केंद्रित योजनाओं पर ध्यान देने के साथ साथ वाणिज्यिक स्कंध ग्राहकों/विज्ञापनदातओं से सभी स्तरों पर निरंतर संपर्क कायम रखता है। ताकि उन्हें इस बात के लिए राजी किया जा सके कि वे अपने निवेश का बड़ा हिस्सा समूचे देश को कवर करने वाले एकमात्र माध्यम आकाशवाणी पर विज्ञापन देने में खर्च करें।

आकाशवाणी का वाणिज्यिक स्कंध इस संगठन के अन्य कार्यकारी अनुभागों को सहायता/नीतिगत फीडबैक प्रदान करने में भी अपनी भागीदारी निभाता है, ताकि मौजूदा प्रतिस्पर्धात्मक मीडिया माहौल में रेडियो कार्यक्रमों को अधिक प्रभावकारी बनाया जा सके। संगठन के लिए राजस्व जुटाने का पूरा दायित्व वाणिज्यिक स्कंध का है और निश्चय ही उसने पिछले कुछ वर्षों में आकाशवाणी के समग्र राजस्व को बढ़ाने के लिए बेहतर परिणाम हासिल किए हैं।

पिछले 4 वर्षों के दौरान आकाशवाणी द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा इस प्रकार है:

2002-03	रु. 132.25 करोड़
2003-04	रु. 141.04 करोड़
2004-05	रु. 156.67 करोड़
2005-06	रु. 268.83 करोड़

आकाशवाणी का समग्र राजस्व चालू वित्त वर्ष (2006-07) के दौरान अक्टूबर, 2006 तक 153.67 करोड़ रुपये (लगभग) था। इसमें लगातार उत्साहजनक वृद्धि हुई है।

विपणन प्रभाग

हाल के वर्षों में लोक सेवा प्रसारणकर्ता के अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए प्रसार भारती अपना राजस्व बढ़ाने के लिए ही ठोस प्रयास करता रहा है। इसके लिए विभागीय कार्यक्रमों के उचित एवं आक्रामक विपणन की नीति अपनाने के साथ-साथ ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक कार्यक्रमों का निर्माण भी किया गया। मुंबई, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में विपणन प्रभाग की स्थापना इसी दिशा में एक कदम है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों के लिए एक ही स्थान पर सुविधाएं मुहैया कराते हुए विपणन प्रभाग विज्ञापन की सभी जरूरतें पूरी कर रहा है। विपणन प्रभाग के महत्वपूर्ण कार्यों में ग्राहकों तक पहुंच कायम करना, उनके बजट और जरूरत के अनुसार प्रचार माध्यम योजनाएं तैयार करना, उनके प्रचार अभियानों को अमल में लाना और आवश्यकता पड़ने पर स्पॉट्स/जिंगल्स और प्रायोजित कार्यक्रम तैयार करना शामिल है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विस्तृत नेटवर्क और उनकी व्यापक पहुंच को देखते हुए प्रसार भारती का विपणन प्रभाग ग्राहकों को देश के कोने-कोने में पहुंचा देता है और वह भी एक ही स्थान पर बैठे हुए।

हमारे कुछ प्रमुख ग्राहकों में ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सड़क और भूतल परिवहन मंत्रालय, एनएएलएसस, सूचना का अधिकार से संबद्ध राष्ट्रमंडल मानवाधिकार संगठन, डाक और तार विभाग, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, बीएसएनएल और प्राइवेट ग्राहकों में एलजी, पेप्सी, कैस्ट्रोल, डाबर, रिलायंस, हिंदुस्तान लीवर और हीरा होंडा आदि शामिल हैं।

इन प्रभागों के सतत और ठोस प्रयासों की बदौलत आकाशवाणी के वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान 268.83 करोड़ रुपये का सकल राजस्व अर्जित करके पिछले सभी रिकार्ड तोड़ दिए।

भाषिक कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों में मुख्य रूप से वार्षिक स्मारक व्याख्यान और वार्ताएं, भेटवार्ता/बातचीत, चर्चाएं/गोष्ठी, रेडियो पत्रिका, कविता पाठ और लघु कथा वाचन जैसे साहित्यक कार्यक्रम और रूपक/डाक्यूमेंटरीज शामिल हैं। 2006 में आयोजित और प्रसारित/2007 के पहले तीन महीनों में प्रसारित किए जाने वाले कुछ महतवपूर्ण कार्यक्रमों का ब्योरा इस प्रकार है:-

1. सरदार पटेल समारक व्याख्यान इस वर्ष 26 अक्टूबर 2006 को चेन्नई में आयोजित किया गया। जाने-माने पत्रकार श्री एन. राम ने अंग्रेजी में यह व्याख्यान दिया। इसका विषय था, 'मीडिया एंड सोसायटी इन इंडिया : फ्रीडम, रोल एंड रिस्पोंसिबिलिटीज'। इसकी रिकार्डिंग सरकार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर, 2006 को प्रसारित की गई।

2. इस वर्ष डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान का आयोजन 17 नवंबर, 2006 को पटना में किया गया। इसका विषय था, 'शिक्षा, समानता और भारत की संप्रभुता' यह व्याख्यान प्रोफेसर अनिल सद्गोपाल ने हिंदी में दिया। इसकी रिकार्डिंग 3 दिसंबर, 2006 को डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर प्रसारित की गई।

3. राष्ट्रीय कवि गोष्ठी (सर्व भाषा कवि सम्मेलन) का आयोजन 1956 से किया जा रहा है। फिलहाल इसके अंतर्गत संस्कृत सहित 22 भारतीय भाषाओं मे कविताएं शामिल की जाती हैं और सभी भाषाओं में उनका अनुवाद कराया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुजराती में प्रस्तुत की गई किसी कविता का अनुवाद हिंदी, उर्दू, सिंधी, असमियां, बांग्ला, बोड़ो, उड़िया, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, मराठी, कोंकणी, पंजाबी, कश्मीरी और डोगरी में किया जाता है। इन कविताओं के माध्यम से राष्ट्र

की रचनात्मक प्रतिभा और विवेक भावना को उदात्त सौन्दर्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम आमतौर पर जनवरी के महीने में आयोजित किया जाता है और इसकी रिकार्डिंग हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित की जाती है।

4. 1997 से आकाशवाणी पांच मासिक राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये हैं : साहित्य भारती, संस्कृति भारती, चित्र भारती, विज्ञान भारती और युवा भारती। ये सभी कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होते हैं और क्रमशः साहित्य, संस्कृति, फिल्म, विज्ञान, और युवाओं से संबद्ध होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि हर हफ्ते तीस मिनट की होती है। इन कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी के विभिन्न केंद्र योगदान करते हैं, जिससे उनमें राष्ट्रीय रंगत आ जाती है।

लिप्यंतरण एवं कार्यक्रम आदान-प्रदान सेवा

लिप्यंतरण सेवा 3 अप्रैल 1954 को शुरू की गई थी, इसे सभी विशिष्ट व्यक्तियों के भाषणों के लिप्यंतरण का काम सौंपा गया था। इसके अंतर्गत देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भाषणों का लिप्यंतरण प्रमुख था। यह एकांश भावी प्रसारण के लिए रिकार्डिंग के परिरक्षण के वास्ते 'एआईआर-टीएस रिकार्ड्स' लेबल वाले वाइन्यल डिस्क प्रोसेस करने का दायित्व भी निभा रहा था। इसे देखते हुए 1 अप्रैल, 1959 को सेवा का नया नामकरण 'लिप्यंतरण एवं कार्यक्रम आदान-प्रदान सेवा' के रूप में किया गया और इस एक 'निदेशक' के स्वतंत्र प्रभार के अंतर्गत रखा गया। अंततः प्रोसेस किए जाने वाले रिकार्ड महंगे साबित हुए, जिसे देखते हुए प्रोसेसिंग कार्य जून 1967 में बंद करना पड़ा, और परिरक्षण के नए तरीके अपनाए गए। इनमें एनालॉग मैग्नेटिक टेप आदि शामिल थे। देश में अनौपचारिक अभिलेखीकरण किया जा रहा था परंतु एक संगठित गतिविधि के रूप में यह कार्य बाद में इस एकांश को सौंपा गया।

संगठनात्मक संरचना

इस कार्यालय के अंतर्गत निम्नांकित कार्य इकाइयां आती हैं:-

क. केन्द्रीय अभिलेखागार

ख. कार्यक्रम विनिमय एकांश (घरेलू और विदेशी)

ग. राष्ट्रपति/प्रधनामंत्री के भाषणों का लिप्यंतरण

घ. आकाशवाणी नेटवर्क के लिए केन्द्रीय टेप बैंक

ड. परिमार्जन एकांश (रिफर्बिशिंग यूनिट)।

आकाशवाणी अभिलेखागार से जारी 'आकाशवाणी संगीत' और विपणन

आकाशवाणी का केन्द्रीय अभिलेखागार 2002 से 'आकाशवाणी संगीत' नाम से संगीत एल्बम जारी करता है। अभी तक 35 एल्बम जारी किए जा चुके हैं। 2006-07 के दौरान बेगम अख्तर, एम.एल. वसंतकुमारी, पंडित भीमसेन जोशी के दो-दो और कर्नाटक संगीत के जाने-माने कलाकार चेम्बई बैद्यनाथ भागवतार का एक एल्बम जारी किया गया। आने वाले महीनों में उस्तार बड़े गुलाम अली खान के तीन, बड़ी मोतीबाई और रसूलनबाई, महाराजापुरम संतनाम, टी.आर. महालिंगम, डी.के. राय, उस्ताद अमीर खान और रामचरित मानस का एक-एक एल्बम जारी किए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त पहले जारी किए गए एल्बमों के नए संस्करण भी जारी किए गए। आकाशवाणी के करीब 50 केंद्रों में बिक्री काउंटर खोले गए हैं। इसी प्रकार कई दूरदर्शन केंद्रों में भी बिक्री की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दिल्ली में खुदरा संगीत दुकानों पर भी ये एल्बम उपलब्ध कराए गए। आने वाले महीनों में अन्य शहरों में भी यह व्यवस्था की जाएगी। इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को एकमुश्त आर्डर के लिए आकर्षित किया जाए। इन प्रयासों के अनुकूल नतीजे भी मिलने लगे हैं।

9 नवंबर, 2006 तक रु. 16,73,116/- का राजस्व अर्जित किया गया।

ध्वनि अभिलेखागार

आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार को देश का राष्ट्रीय श्रव्य अभिलेखागार भी कहा जाता है इसमें 15000 घंटे से अधिक अवधि की संगीत और भाषिक कार्यक्रमों की विभिन्न श्रेणियों की बहुमूल्य रिकार्डिंग का खजाना है। यह भारतीय संगीत की रिकार्डिंग का सबसे बड़ा संग्रह है और इसमें हिंदुस्तानी, कर्नाटक और विभिन्न लोक संगीत परंपराओं के 12000 से अधिक टेप मौजूद हैं।

इस संग्रह में 11 मई, 1947 को कोलकाता में प्रार्थना सभा में दिए गए महात्मा गांधी के भाषण से लेकर 29 जनवरी, 1948 को बिरला हाउस, दिल्ली में अंतिम प्रार्थना सभा में दिए गए भाषण तक, सभी वे भाषण मौजूद हैं, जो विभिन्न प्रार्थना सभाओं में इस अवधि में दिए गए। आकाशवाणी से राष्ट्रपिता का एकमात्र प्रसारण 12 नवंबर, 1947 को हुआ था, जिसे संरक्षित रखा गया है। आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार में 3000 एनालॉग टेपों में पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण संरक्षित हैं।

अन्य महत्वपूर्ण ध्वनि रिकार्डिंगों में रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस, डॉ० भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू आदि

हस्तियों के भाषण भी संरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा पुरस्कार विजेता रेडियो नाटक, फीचर, डाक्यूमेंटरी आदि और स्मारक व्याख्यान भी उपलब्ध हैं। भारत के सभी राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के भाषणों की रिकार्डिंग भी रखी गई हैं।

रेडियो आत्मकथा

रेडियो आत्मकथा श्रेणी के अंतर्गत जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संबद्ध विशिष्ट व्यक्तियों की 129 रिकार्डिंग मौजूद थीं, जिनमें इस वर्ष इजाफा हुआ और यह संख्या 137 पर पहुंच गई। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों के मार्गदर्शन से प्रभावशाली लोगों की पहचान की जाती है। अभिलेखागार ने 9 नवंबर 2006 तक अभिलेखीय रिकार्डिंगों के संप्रेषण से 1,39,200 रु. अर्जित किए। इस एकांश को वर्ष के दौरान 240 नई श्रृव्य रिकार्डिंग प्राप्त हुई, और 630 रिकार्डिंग श्रेणीबद्ध की गईं।

अभिलेखागार का डिजिटल संग्रहालय

सभी अभिलेखीय रिकार्डिंगों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने की एक विशेष परियोजना 2001 में शुरु हुई, जिसे 2005 में पूरा किया गया। आकाशवाणी अब प्रसारण नेटवर्क में उन संगठनों में शामिल हो गया है, जिनके पास बड़े डिजिटल संग्रहालय हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय रूप में स्वीकार्य मानदंड के अनुसार आधुनिक टेप संख्या प्रणाली अपनाई गई हैं। करीब 15900 घंटे के कार्यक्रमों को डिजिटल माध्यम में हस्तांतरित किया जा चुका है। डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित रिकार्डिंगों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

राष्ट्रपति के भाषण	3200 घंटे
प्रधानमंत्री के भाषण	1150 घंटे
महात्मा गांधी के भाषण	280 घंटे
सरदार पटेल के भाषण	35 घंटे
गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर और संबंधित रिकार्डिंग	175 घंटे
रेडियो जीवनियां	525 घंटे
हिंदुस्तानी संगीत	3000 घंटे
कर्नाटक संगीत	1400 घंटे
सुगम संगीत	1000 घंटे
लोक संगीत	500 घंटे

नई डिजिटल लाइब्रेरी को बेहतर बनाने का काम पूरा कर लिया गया है। डिजिटलीकरण का दूसरा चरण आने वाले दिनों में शुरू होने की संभावना है। अभी करीब 10000 ऐनालॉग टेप हैं, जिन्हें परिवर्तित किया जाना है।

कार्यक्रम विनिमय एकांश

इस एकांश का मुख्य प्रयोजन विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों के बीच उनकी जरूरतों के अनुसार अच्छी क्वालिटी के कार्यक्रमों का आदान-प्रदान है। संगीत और भाषिक कार्यक्रमों से संबद्ध 8000 टेप इस प्रयोजन के लिए संरक्षित किए गए हैं।

विभिन्न भारतीय भाषाओं में संगीत और भाषिक दोनों तरह के कार्यक्रमों का संग्रह करने के अलावा कार्यक्रम विनिमय एकांश में बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, संस्कृत, तमिल और तेलुगू में भाषा पाठ भी संरक्षित हैं।

लिप्यंतरण और कार्यक्रम विनिमय सेवा के लिए 11.00 बजे से 12.00 बजे के बीच आर एन चैनल के जरिए आकाशवाणी केंद्रों को कार्यक्रम ट्रांसमिट किए जाते हैं। इसके अंतर्गत भेजे जाने वाले कार्यक्रमों में ध्वनि अभिलेखागार, कार्यक्रम विनिमय लाइब्रेरी, रेडियो धारावाहिकों, भाषा पाठों, और आकाशवाणी महानिदेशालय के समूह-गानों विभिन्न केंद्रों द्वारा मांगे गए विशिष्ट कार्यक्रमों तथा केंद्रों द्वारा लाइब्रेरी को भेजे गए कार्यक्रम शामिल होते हैं।

कार्यक्रम विनिमय लाइब्रेरी चुने हुए आकाशवाणी केंद्रों से रेडियो धारावाहिक भी प्रसारित करता है। ये रेडियो धारावाहिक आकाशवाणी महानिदेशालय की पीपी एंड डी यूनिट की साफ्टवेयर विकास परियोजना के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी महानिदेशालय के केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किए गए मासिक श्रृंखला नाटक भी नियमित आरएन चैनल चंक के जरिए फीड किए जाने के बाद चुने हुए रेडियो केंद्रों को भेजे जाते हैं।

लिप्यंतरण एकांश

इस सेवा के मुख्य कार्यों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भाषणों की रिकार्डिंग को लिपिबद्ध करना और कालक्रमानुसार उन्हें परिरक्षित करना भी है।

आकाशवाणी केंद्रों का यह दायित्व है कि वे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा जनसभाओं में दिए गए सभी भाषणों को रिकार्ड करें। विभिन्न संबद्ध आकाशवाणी केंद्रों से भाषणों की रिकार्डिंग के टेप और उनकी लिप्यंतरित प्रतिलिपि टी एंड पीईएस अनुभाग द्वारा प्राप्त की जाती है। लिप्यंतरित प्रतियों के जिल्द बनाये जाते हैं और उन्हें अभिलेखागार में रखा जाता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सभी भाषण विस्तृत डाटा एंट्री के साथ सीडी में संरक्षित किए जाते हैं।

केन्द्रीय टेप बैंक

यह एकांश विभिन्न केंद्रों को कार्यक्रम सामग्री की उनकी मांग पर खाली टेप आपूर्ति करने वाले बैंकर के रूप में काम करता है। कार्यक्रमों के विनिमय के प्रयोजन के लिए सभी आकाशवाणी केंद्रों के बीच 75 हजार टेप प्रचलन में हैं। यह बैंक नए केंद्रों के चालू होने के समय उन्हें खाली टेपों की आपूर्ति करता है।

विदेशी कार्यक्रम एकांश

टी एंड पीईएस का विदेशी कार्यक्रम एकांश विश्वभर के प्रसारण संगठनों से प्राप्त कार्यक्रमों के आदान-प्रदान में समन्वय करता है। ये कार्यक्रम व्यापक विषय-क्षेत्रों जैसे विज्ञान, सम-सामयिक घटनाएं, पाश्चात्य सुगम संगीत, पॉप और रॉक संगीत से लेकर महिलाओं और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों से संबद्ध होते हैं। यह एकांश भारत में सार्क श्रव्य-दृश्य विनिमय (एसएवीई) कार्यक्रमों के प्रसारण में भी समन्वय करता है। इन कार्यक्रमों के श्रोताओं की रूचि के सभी प्रकार के विषय शामिल किए जाते हैं।

दिल्ली केंद्र

1 अप्रैल, 2006 से 31 दिसंबर 2006 की अवधि में विभिन्न गतिविधियां (प्रचार, विभिन्न रूपों में तैयार किए गए कार्यक्रम, कवरेज, रिले आदि)

क) कार्य योजना पर अमल

(1) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम

रोजगार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालिका, खाद्य और पोषण, अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए कल्याण योजनाएं, सामाजिक सद्भाव, अल्पसंख्यकों का कल्याण, बुनियादी ढांचा, जल-संसाधन, क्षेत्रीय विकास, केंद्र-राज्य संबंध, पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर, प्रशासनिक सुधार, उद्योग, श्रम, सार्वजनिक क्षेत्र, वित्तीय नीति, पूंजी बाजार, आर्थिक सुधार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राजभाषा।

(2) यूपीए सरकार की उपलब्धियां

सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे भारत निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, दोपहर का भोजन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन, सूचना का अधिकार अधिनियम और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करना।

(3) संसद के अधिवेशनों का कवरेज

(4) अप्रैल/मई 2006 में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव/चुनाव परिणामों के सिलसिले में विशेष कार्यक्रम

(5) दिवस/सप्ताह/पखवाड़े

नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह, दांडी मार्च की वर्षगांठ, विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वतंत्रता दिवस, अस्पृश्यता. निवारण दिवस, बाल दिवस, प्रसार भारती स्थापना दिवस, सद्भावना दिवस आदि सभी महत्वपूर्ण अवसर।

(6) जयंती/पुण्यतिथि

महात्मा गांधी, डॉ. अंबेडकर, राजीव गांधी, पं. नेहरू, रवींद्रनाथ ठाकुर, इंदिरा गांधी, बेगम अख्तर आदि महत्वपूर्ण राजनेताओं, साहित्यकारों-कलाकारों की जयंतियों/पुण्यतिथियों पर विशेष कार्यक्रम।

(7) उत्सव

विभिन्न धर्मों-समुदायों के पावन-पर्वों पर विशेष प्रसारण।

खेल कवरेज

(क) क्रिकेट

(i) आबु धाबी (अप्रैल) में भारत-पाकिस्तान के बीच खेला गया एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच

(ii) वेस्टइंडीज (मई-जून) में भारत-वेस्टइंडीज शृंखला-2006

(iii) क्वालालम्पुर, मलेशिया (सिंतबर) में भारत-आस्ट्रेलिया-वेस्टइंडीज के बीच एक दिवसीय मैचों की त्रिकोणीय शृंखला

(iv) भारत (अक्टूबर-नवंबर) में खेली गई आईसीसी चैम्पियनशिप क्रिकेट ट्राफी-2006

(ख) फुटबॉल

(i) फीफा विश्व कप-2006 (जून-जुलाई) : 19 मैचों के बारे में दैनिक रिपोर्ट और आंखों देखा हाल

(ii) कोलकाता में अगस्त में खेली गई एएफसी एशियाई कप 2006 प्रतियोगिता

(iii) बंगलौर में अक्टूबर में खेली गई एएफसी क्वालीफाइंग फुटबाल प्रतियोगिता-2006

(iv) गुड़गांव में अक्टूबर में खेली गई संतोष ट्राफी-2006 प्रतियोगिता।

(v) कोलकाता में नवंबर में खेली गई एएफसी युवा प्रतियोगिता-भारत-2006

(ग) टेनिस

(i) मुंबई में अप्रैल में भारत और पाकिस्तान के बीच डेविस कप क्वालीफायर।

(ii) कोलकाता में सितंबर में हुई सन्फीस्ट टेनिस ओपन प्रतियोगिता-2006

(iii) नई दिल्ली में अक्टूबर में हुई डीएससीएल नेशनल ओपन टेनिस प्रतियोगिता-2006

(iv) चंडीगढ़ में नवंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच टेनिस मैच-2006

(v) विम्बलडन टेनिस चैम्पियनशिप-2006 के बारे में वॉयसकास्ट (जून-जुलाई)

(vi) अमरीकी ओपन टेनिस चैम्पियनशिप-2006 के बारे में वॉयसकास्ट (अगस्त-सितम्बर)

(घ) हॉकी

(i) 111वीं अखिल भारतीय बेटन कप हॉकी प्रतियोगिता (अप्रैल)

(ii) अखिल भारतीय मुंबई गोल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता (अप्रैल)

(iii) विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता-2006, जर्मनी (सितंबर)

(iv) 62वीं राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता-2006, जालंधर (नवंबर)

(v) 23वीं सुरजीत सिंह हॉकी प्रतियोगिता-2006, जालंधर (नवंबर)

(ड) जिमनास्टिक

(i) सूरत में तीसरी सीनियर एशियन जिमनास्टिक प्रतियोगिता-2006 (अगस्त)

(च) मैराथन

(i) दिल्ली हाफ मैराथन-2006 (अक्टूबर)

(छ) पुरस्कार वितरण समारोह

राष्ट्रपति भवन में अगस्त 2006 में आयोजित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार वितरण समारोह

(ज) दोहा (कतर) में 1 से 16 दिसंबर 2006 की अवधि में आयोजित एशियाई खेल

9. आकाशवाणी संगीत सम्मेलन 2006

10. लोक सेवा प्रसारण दिवस (12 नवंबर)

(ख) आगे दिए गए चुने हुए विषयों के लिए मीडिया प्रचार सहायता उपलब्ध कराई गई, जिसके बारे में मासिक रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई :

(i) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम

(ii) यूपीए सरकार की उपलब्धियां

(iii) आर्थिक और सामाजिक सुधार

(iv) सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी

(v) व्यापार और वाणिज्य, उद्योग, कृषि

(vi) शिक्षा

(vii) स्वास्थ्य

(viii) अंतर्राष्ट्रीय संबंध

(ix) नशीले पदार्थों के सेवन और उनके अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस

(x) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

(xi) किशोर, युवा, महिलाएं, बालिका, बाल मजदूरी

(xii) अनैतिक व्यापार (निवारण) संशोधन विधेयक-2006

(xiii) विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों आदि में महिलाओं के लिए विकास के अवसर

(xiv) राष्ट्रीय सुरक्षा

(xv) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न के बारे में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के प्रति जागरूकता

(xvi) वरिष्ठ नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस समारोह

(vxii) शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

(xviii) अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह

(xix) किरायेदारों और पुरानी कार, स्कूटर/मोटरबाइक आदि खरीदने वालों के पूर्व-वृत्तांत की जांच

(xx) नकली, जाली, अप्रमाणिक और वर्जित उत्पादों के खिलाफ कार्य-दल।

(xxi) महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह आंदोलन

(xxii) महात्मा गांधी की जयंती

(xxiii) भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

(xxiv) गोवा की राजधानी पणजी में 37वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह।

(xxv) स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम का राष्ट्र के नाम संदेश

(xxvi) स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से ध्वजारोहण समारोह और प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह के राष्ट्र के नाम संदेश का सीधा प्रसारण

(xxvii) समेकित नीति कार्यान्वयन

(xxviii) पर्यावरण संरक्षण

(xxix) सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान (अक्टूबर 2006)

(xxx) वर्ष 2003 के ज्ञानपीठ पुरस्कारों का वितरण

(xxxi) श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर संगीत कार्यक्रम

(xxxii) प्रौद्योगिकी दिवस पर राष्ट्रपति का संदेश

(xxxiii) विज्ञान भवन, नई दिल्ली में भगवान बुद्ध के महा-परिनिर्वाण की 2550वीं वर्षगांठ मनाने के सिलसिले में आयोजित समारोह का उद्घाटन

(xxxiv) विश्व खाद्य दिवस पर कृषि, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री शरद पवार का संदेश।

(xxxv) हिंदी दिवस के अवसर पर गृह मंत्री श्री शिवराज वी. पाटिल का संदेश

(xxxvi) राष्ट्रपति डॉ० एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण

(xxxvii) डॉ० राजेन्द्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान (दिसंबर 2006)

(ग) अल्पसंख्यक कल्याण संबंधी कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रम

(i) सद्भावना दिवस का प्रमुख संदेश सभी के प्रति सद्भावना और हिंसा से दूर रहना। इस संदेश को प्रोत्साहित करने के लिए 20 अगस्त से 5 सितंबर 2006 के बीच की अवधि को साम्प्रदायिक सद्भाव पखवाड़े के रूप में मनाया गया।

(ii) कौमी एकता सप्ताह।

(iii) संविधान दिवस।

(iv) मानवाधिकार दिवस।

(v) मिलाद-उल-नबी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, बैसाखी, ईस्टर संडे, बुद्ध पूर्णिमा, हजरत अली का जन्मदिवस, महावीर निर्वाण, ईद-उल-फितर, गुरु नानक जयंती, गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस, क्रिसमस, हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत अमीर खुसरो के 702वें वार्षिक उर्स समारोह, जैसे उत्सवों के मौके पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए गए/विशेष कवरेज प्रदान की गई।

(vi) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में वर्णित विषय, जैसे सामाजिक सद्भाव, अल्पसंख्यकों का कल्याण, क्षेत्रीय विकास, प्रशासनिक सुधार, राजभाषा।

(vii) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम।

(घ) महत्वपूर्ण नीति निर्णय/कानून/उपलब्धियां/घटनाएं

(i) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लिए प्रचार

(ii) यूपीए सरकार की उपलब्धियां को उजागर करना

(iii) 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ मनाना

(iv) दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ मनाना

(v) पल्स पोलियो टीकाकरण

(vi) डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में व्याप्त भय दूर करने तथा तत्संबंधी अफवाहों पर विराम लगाने के लिए व्यापक प्रचार/उपयुक्त कार्यक्रम

(vii) किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति

(viii) किशोरों, युवाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम

(ix) सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे भारत निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, दोपहर का भोजन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, सूचना का अधिकार अधिनियम, और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करना

(x) वरिष्ठ नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस-वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दी गई सेवाओं की पहचान और वृद्ध व्यक्तियों की

समस्याओं और जरूरतों के बारे में समाज को जागरूक बनाना

(xi) आम लोगों को कृषि की पैदावार की सही जानकारी देना ताकि आने वाले महीनों में कृषि उत्पादन की कमी आने संबंधी आम लोगों और बाजार की आशंकाओं का निराकरण किया जा सके और साथ ही खेती की ऊंची उत्पादकता का भरोसा दिलाने के लिए पर्याप्त वर्षा, खेती के अनुकूल मिट्टी, नमी की स्थिति, जलाशयों में पर्याप्त पानी होने और तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी होने से बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार से उन्हें अवगत कराया जा सके

(xii) बच्चों के लिए हेल्पलाइन-जरूरतमंद, विपत्ति में फंसे और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 24 घंटे काम करने वाली आपातकालीन हेल्पलाइन की जानकारी देना। चाइल्ड हेल्पलाइन बच्चों को आपात सहायता प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत चिकित्सा सहायता, आश्रय, राहत और बचाव के उपाय शामिल हैं। इस आपातकालीन हेल्पलाइन के लिए 1098 नंबर पर निशुल्क काल की जा सकती है

(xiii) किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

(xiv) 6 से 10 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाना।

(xv) शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान के निधन पर 21 अगस्त को राष्ट्रीय शोक मनाया गया

(ड) विभिन्न सलाहकार बोर्डों/परिषदों की गतिविधियां, जिनकी वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखी जाती हैं-

(i) पल्स पोलियो अभियान में राष्ट्रीय टीकाकरण के दौर।

(ii) देश में उचित 'शहरी परिवहन' प्रणाली सुनिश्चित करने और इस बारे में बेहतर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ''शहरी परिवहन'' विषय पर शहरी विकास से संबद्ध स्थायी संसदीय समिति द्वारा लोगों की राय मांगा जाना।

(iii) एशियाई विकास बैंक के बारे में विचार गोष्ठी/बैंक की गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट।

(iv) किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा।

(v) सागर विकास मंत्रालय की स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष। सागर क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं यानी अनुसंधान, प्रौद्यौगिकी विकास, मानचित्र सर्वेक्षण, समुद्री पर्यावरण का परिरक्षण, संरक्षण और बचाव, समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में कार्यक्रमों का प्रसारण।

(vi) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा 8 सितंबर, 2006 को अंतर्राष्ट्रीय दिवस।

(vii) गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2006 में प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह के भाषण सहित विशेष कार्यक्रम।

(viii) वरिष्ठ नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस।

(ix) चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक परियोजना।

(x) कृषि उत्पादन के अनुमान के बारे में आम लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम।

(xi) सूचना का अधिकार अधिनियम-2006।

(xii) लाभ के पद से संबंधित संवैधानिक और कानूनी स्थिति के विवेचन के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन संबंधी लोकसभा सचिवालय की प्रेस विज्ञप्ति।

(xiii) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के बारे में उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश।

(xiv) डेंगू और चिकनगुनिया बुखार के बारे में जन जागरूकता।

(xv) 6 से 10 नवंबर 2006 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने संबंधी केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देश।

(xvi) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी प्रेस विज्ञप्ति— जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों के बारे में आम लोगों से सुझाव मांगे गए।

(xvii) विदेश मंत्रालय (पूर्वी एशिया प्रभाग)-कैलाश मानसरोवर यात्रा-2006 के बारे में जानकारी।

(xviii) पर्यावरण मंत्रालय-पर्यावरण के बारे में संदेश।

(xix) मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय समिति द्वारा 'अनैतिक व्यापार (रोकथाम) संशोधन विधेयक-2006' के बारे में मांगे गए सुझाव।

(xx) विदेश मंत्रालय (विशेष कुवैत प्रकोष्ठ)-1990-91 के इराक-कुवैत युद्ध के दौरान नुकसान झेलने वाले अज्ञात दावेदारों के

लिए क्षतिपूर्ति के बारे में संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग, जिनेवा से संबंधित प्रसारण।

(xxi) पर्यावरण संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश।

(xxii) ढाबों, पटरियों पर चल रहे भोजनालयों, रेस्तराओं, होटलों, मोटलों, चाय की दुकानों, रिजार्ट्स, स्पार्स या अन्य मनोरंजन केंद्रों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घरेलू नौकर के रूप में रखे जाने पर रोक लगाने संबंधी श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना। 10 अक्टूबर 2006 से लागू इस अधिसूचना में जुर्माना या कारागार अथवा दोनों दंड देने का प्रावधान है।

(xxiii) 'अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार और उनसे संबद्ध सामाजिक अपराधों की प्रवृत्ति के बारे में चौथी रिपोर्ट (14वीं लोकसभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई' के बारे में गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जानजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी 14वीं रिपोर्ट जारी।

(च) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण और विकास

अनुसूचित जाति/जाति के लोगों उत्थान के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों, सरकारों की विभिन्न योजनाओं, संवैधानिक अधिकारी, कानूनी अधिकारों के बारे में व्यापक प्रचार किया गया।

(छ) आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण

(i) अंतर्राष्ट्रीय मानकों से होड़ करते हुए नए प्रसारण भवन में पूरी तरह डिजिटल ट्रांसमिशन की व्यवस्था, ट्रांसमिशन स्टूडियो में अद्यतन प्रौद्योगिकी से युक्त उपकरणों की स्थापना।

(ii) मीडियम वेव (एम डब्ल्यू), फ्रीक्वेंसी माड्यूलेशन (एफएम) और उपग्रह सेवा (डीटीएच) के जरिए कार्यक्रमों का ट्रांसमिशन।

(iii) डिजिटल रिकार्डिंग, संपादन और डबिंग।

(iv) अद्यतन इलेक्ट्रोनिक उपकरणों और उपग्रह सेवाओं के साथ ओबी कवरेज, सीधे रिले आदि तकनीक काम में लाई गईं।

(ज) एकांशों/स्कन्धों की योजना और विशेष पैकेज तथा विषय:

(i) हर महीने होने वाली आईएमपीसीसी की बैठक में विचार विमर्श और निर्णय लिए जाने के बाद मासिक विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित किए गए। अप्रैल से नवंबर की अवधि में कवर किए गए विषयों में जल संरक्षण और जल-जनित बीमारियां, जल और ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषण और मौसम का बदलता मिजाज, राष्ट्रीय एकता, साक्षरता, प्रदूषण, बच्चों से संबंधित विभिन्न विषय जैसे कार्यक्रम शामिल थे।

(i) 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ।

(i) दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के प्रथम सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ।

1 जनवरी, 2007 से 31 मार्च, 2007 की अवधि में आयोजित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

नववर्ष दिवस, पशु कल्याण पखवाड़ा, सेना दिवस, गणतंत्र दिवस, बीटिंग रीट्रीट समारोह, शहीद दिवस, तेल संरक्षण दिवस, नेत्रहीन कल्याण सप्ताह, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, विश्व वानिकी दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व रंगमंच दिवस, गुरु गोविंद सिंह और गुरु रविदास की जयंतियां, महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुण्यतिथियां।

उत्सव : ईद-उल-जुहा (बकरीद), लोहड़ी, मकर संक्रांति/पोंगल, बसंत पंचमी, मुहर्रम, महाशिवरात्रि, होली।

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का राष्ट्र के नाम संदेश।

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सर्वभाषा कवि सम्मेलन 2007

गणतंत्र दिवस पर राजपथ से सलामी मंच और परेड तथा सांस्कृतिक समारोह का सीधा प्रसारण।

बजट सत्र (रेल और केन्द्रीय बजट के सीधे प्रसारण सहित)

मार्च 2007 में वेस्टइंडीज में होने वाली विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता का प्रसारण।

एआईआर रिसोर्सेज

''एआईआर रिसोर्सेज'' एक स्वतंत्र केंद्र है जिसकी स्थापना मई 2001 में की गई थी। यह आकाशवाणी और दूरदर्शन के विस्तृत हार्डवेयर ढांचे से राजस्व अर्जित करता है। यह आकाशवाणी का एक वाणिज्यिक अंग है, जो इंजीनियरी स्कन्ध की पहल पर प्रसारण

के क्षेत्र में परामर्श और टर्नकी समाधान प्रदान करता है। इसकी मौजूदा गतिविधियों में निम्नांकित शामिल हैं:

यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को देश में 40 स्थानों पर ज्ञानवाणी केंद्रों के लिए एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना में टर्नकी आधार पर समाधान प्रदान कर रहा है। 25 ज्ञानवाणी केंद्र पहले ही चालू हो चुके हैं, और चालू वर्ष के दौरान चार और ऐसे केंद्रों के चालू हो जाने की संभावना है। इस प्रकार वित्त वर्ष के अंत तक 25 ज्ञानवाणी केंद्र काम करने लगेंगे। यह अभी तक चालू किए सभी ज्ञानवाणी केंद्रों के परिचालन और रखरखाव का काम भी देखता है।

'एआईआर रिसोर्सेज' ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्राइवेट एफएम प्रसारण योजना के प्रथम चरण में प्राइवेट प्रसारणकर्ताओं को प्रसार भारती का मूलभूत सुविधाएं जैसे भूमि, भवन और टावर आदि किराये पर दिए। चार स्थानों पर 10 प्राइवेट एफएम प्रसारणकर्ता प्रसार भारती के बुनियादी ढांचे यानी भूमि और टावर का इस्तेमाल लाइसेंस फीस/किराया आधार कर रह रहे हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नीति के अनुसार प्राइवेट एफएम चरण-2 कार्यक्रम के अंतर्गत सभी 91 शहरों के लिए 'एआईआर रिसोर्सेज' ने प्रसार भारती की ओर से आकाशवाणी और दूरदर्शन के बुनियादी ढांचे (भूमि, भवन और टावर आदि) में साझेदारी के बारे में सभी प्राइवेट एफएम प्रसारणकर्ताओं के साथ करार किए हैं। इससे सभी 245 आवंटित एफएम चैनलों के लिए साझा ट्रांसमिशन ढांचा (सीटीआई) कायम किया जा सकेगा। एआईआर रिसोर्सेज 6 शहरों (हैदराबाद, चेन्नई, बंगलौर, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता) में सीटीआई कायम होने तक अंतरिम व्यवस्था कायम करने के लिए 9 प्राइवेट एफएम प्रसारणकर्ताओं के साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन को मूलभूत सुविधाओं (भूमि, भवन और टावर आदि) में हिस्सेदारी कर रहा है।

'एआईआर रिसोर्सेज' विभिन्न मोबाइल आपरेटरों को प्रसार भारती का ढांचा यानी भूमि, भवन और टावर आदि किराये के आधार पर उपलब्ध करा रहा है। इसके अंतर्गत उन्हें मोबाइल सेवाएं परिचालित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर जीएसएम/सीडीएमए/डब्ल्यूएलएल एंटीना एफएम/टीवी/एसटीएल के लिए आकाशवाणी/दूरदर्शन के टावरों और भूमि में हिस्सेदारी की अनुमति दी जाती है। वर्ष के दौरान 'एआईआर रिसोर्सेज' ने 5 सेवा प्रदाताओं के साथ 25 स्थानों पर टावरों में हिस्सेदारी की। एआईआर रिसोर्सेज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय उसके ज्ञानवाणी स्टूडियो तैयार होने तक विभिन्न स्थानों पर स्टूडियो सुविधाएं मुहैया करा रहा है और अपना मूलभूत ढांचा भी विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा रहा है।

'एआईआर रिसोर्सेज' ने नवंबर 2006 तक करीब 28.85 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया और यह अभी तक कुल 126.87 करोड रुपये का राजस्व अर्जित कर चुका है।

प्रचार अभियान

1. राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के निम्नांकित घटकों का नियमित प्रचार जारी है : 1. रोजगार के अवसर, 2. कृषि विकास, 3. शिक्षा, 4. स्वास्थ्य, 5. महिला महिला और बाल विकास, 6. खाद्य और पोषण, 7. पंचायती राज, 8. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, 9. सामाजिक सद्भाव और अल्पसंख्यकों का कल्याण, 10. उद्योग, 11 बुनियादी ढांचा विकास, 12. जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पूर्व और सीमावर्ती राज्यों का विकास। इसके अतिरिक्त ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अनैतिक व्यापार रोकथाम संशोधन विधेयक 2006 जैसी योजनाओं को दी गई प्रचार सहायता विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाए गए। इनमें फ्लैगशिप-पीआईबी, नागरिक चार्टर का प्रचार, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घरेलू नौकर के रूप में रोजगार देने पर पाबंदी, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15-सूत्री कार्यक्रम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों आदि के कल्याण के कार्यक्रम आदि शामिल थे।

2. सूचना अधिकार अधिनियम-2005 लागू होने के बाद से इसका जोरदार प्रचार किया जा रहा है। सभी आकाशवाणी केन्द्रों के कार्यक्रम प्रमुखों से कहा गया है कि वे अपने कार्यक्रमों में इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें।

3. लोगों में दहेज विरोधी कानूनी की जानकारी बढ़ाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया।

4. ध्वनि प्रदूषण, लाउडस्पीकरों और पटाखों आदि के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले कानूनों के कार्यान्वयन आदि के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का आकाशवाणी केंद्रों द्वारा व्यापक रूप में प्रचार किया गया।

5. फरवरी, 2006 में विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित वार्षिक कैलाश-मनासरोवर यात्रा और उसके लिए संभावित यात्रियों से आवेदन आमंत्रित किए जाने को प्रचारित किया गया।

6. विश्व पर्यटन दिवस के सिलसिले में आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रचार किया गया। इसके लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए गए और पर्यटन के बारे में आयोजित विचार गोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों आदि को कवरेज प्रदान की गई।

7. 'उपभोक्ता स्वास्थ्य और सुरक्षा' विषय पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करके राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का प्रचार किया गया।

8. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुरोध पर 18-30 वर्ष की आयु समूह के देश के किशोरों और युवाओं के लिए विशेष प्रचार कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित किए गए।

9. ग्रामीण/शहरी आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कृषि, खाद्य और वितरण मंत्रालय के अनुरोध पर उपभोक्ता मामलों के बारे में अद्यतन जानकारी नियमित रूप से प्रसारित की गई।

10. केंद्र सरकार के अन्य कई कार्यक्रमों, नीतियों आदि को प्रचारित किया गया।

आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार

इस वर्ष आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार-2005 वितरण-संबंधी समारोह का आयोजन 7 जनवरी, 2007 को कोलकाता में हुआ। इस अवसर पर माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मुख्य अतिथि थे।

गांधी दर्शन और लोक सेवा प्रसारण पुरस्कार-2006 घोषित कर दिए गए हैं।

संगीत

इस वर्ष का आकाशवाणी संगीत सम्मेलन (संगीत समारोह) 7 और

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी 7 जनवरी 2007 को नई दिल्ली में, प्रसार भारती के सीईओ श्री बी.एस. लाली और आकाशवाणी के महानिदेशक श्री ब्रिजेश्वर सिंह की उपस्थिति में, आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रदान करते हुए

8 अक्टूबर, 2006 को देश भर के 21 केंद्रों पर आयोजित किया गया। इसमें हिंदुस्तानी और कर्नाटक—दोनों ही शैलियों के कलाकारों ने हिस्सा लिया। इनमें भाग लेने वाले मुख्य कलाकारों की संख्या 44 थी।

इस वर्ष के आकाशवाणी संगीत सम्मेलन (संगीत समारोह) में हिस्सा लेने वाले प्रमुख कलाकारों में पंडित समरेश चौधरी, पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता, पंडित नित्यानंद हालीपुर, पंडित अभय नारायण मलिक, पंडित बलदेवराज वर्मा, श्री दिनकर पाशिकार, पंडित राजेन्द्र प्रसन्ना, विदुषी अफरोज़ बानो, विदुषी वीना सहस्रबुधे, पंडित अरविंद पारिख, डॉ० एन रमानी, एम. चंद्रशेखरन्, कुन्नाकुड़ी आर. वैद्यनाथन, चित्तोड़ जी, वेंकटेशन, एन.रवि किरन, त्रिचूर वी. रामाचंद्रन, टी.वी. संकरनारायण, बोम्बे सिस्टर्स (सी. सरोज और सी. ललिता), आदि शामिल थे। इन संगीत समारोहों की रिकार्डिंग 2 दिसंबर, 2006 से 10 जनवरी 2007 के बीच प्रसारित की गई।

उभरते कलाकारों में निलादरी कुमार, विश्वनाथ, शांति शर्मा, विजया जाधव, भारत भूषण गोस्वामी, अलका देव मारुलकर, नल्शा परानिस, सदीपन समाजपति और सौमित्र लाहिड़ी, विशाख हरि, जयंती कुमारेश, मम्बलम सिस्टर्स (आर. विजयलक्ष्मी और चित्रा), कल्याणी लक्ष्मी नारायण, देसुर डी.एस.डी. सेल्वरतिनम, चेप्पाड ए.ई. वामनन, नम्बूदिरि ने भी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन-2006 के संगीत समारोहों में हिस्सा लिया।

अप्रैल, 2006 से नवंबर 2006 की अवधि में राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम और रविवासरीय अखिल भारतीय सभा के अंतर्गत निम्नांकित वरिष्ठ और उभरते हुए कलाकारों को प्रोत्साहित किया गया। इस प्रसारण के अंतर्गत दिल्ली में विशेष रूप से आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित त्रिमूर्ति संगीत समारोह यानी त्यागराज, स्यामाशास्त्री और मुतुस्वामी दीक्षितार, की संगीत प्रस्तुतियों की रिकार्डिंग भी शामिल की गई।

विनायक चित्तार, याधुप मुदगल, सुधीर फडके, असीम चौधुरी, विराज अमर, प्रवीण गोडखिंडी, निहार रंजन, गुलर सबीर, उस्सान, खान और केशव गिंडे, वेंकटेश कुमार, रफीउद्दीन, सबरी, एस.एफ देसाई, चितरंजन ज्योतिषी, मशकूर अली, देवाशीष भट्टाचार्य, जयतीरथ मेवाडी, अवधेश कुमार द्विवेदी, बृज भूषण गोस्वामी, उस्ताद अली खान, राजेन्द्र नारायण गोस्वामी, पंडित गोकुलोत्सवजी महाराज, साहिल भट्ट, रितेश और रजनीश, डा० निशिन्द्र किंजल्क, नील कमल, उस्ताद अमजद अली खान, रामचंद्र भागवत, अरुण मोरोने, पंडित रघुनाथ सेठ, दीपक चटर्जी, आर पी शास्त्री, विनोद लेले, मंजुषा कुलकर्णी, मोहानी मोहन पटनायक, सुधीष पोटे, अनुराधा पाल, डाक्टर संतोष नाहर, घासी राम निर्मल, के शिवकुमार, ओंकार गुलवाड़ी, कमल कांबले सलीम अल्लाहवले।

दिसंबर 2006 से मार्च 2007 की अवधि में राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम/ रविवारीय अखिल भारतीय संगीत सभा में प्रसारण के लिए निम्नांकित कलाकारों के नाम प्रस्तावित हैं :

पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, पंडित राजशेखर मंसूर, फारूख खान, फैयाज़ खान, उस्ताद अली अहमद हुसैन, पंडित राजन और पंडित साजन मिश्रा, प्रतिमा तिलक, रंजीत सेन गुप्ता, नासिर खान, फायुगी मित्रा, राजेन्द्र कड्गांवकर, आसिफ अली खान, अनिल चौधुरी, विदुषी पूर्णिमा सेन, अराधना डे, नकुल मिश्रा, रफीक खान, विदुषी ज़रीन शर्मा, शांतनु भट्टाचार्य।

एम.एस. शीला (गायन), सिक्किल गुरूचरण (गायन), अनुराधा कृष्णमूर्ति (गायन), ओ.एस. त्यागराजन (गायन), चिन्मय सिस्टर्स (उमा और राधिका (गायन), मधुरई, टी.एल. शेषगोपालन (गायन), मुडिकोंडन एस.एन. रमेश (वीणा), मतांगी सत्यमूर्ति (गायन), सीता नारायणन (गायन), आर वेंकटरामन (वीणा), डा० आर के श्रीकांतन (गायन), गायत्री वेंकट राघवन (गायन), एस. शशाक (बांसुरी), आर एन त्यागराजन और डा० आर एन तारानाथन (गायन), टी. जयराज और जयश्री जयराज (वीणा), रूद्रपटनम के. रमाकांत (गायन), वसंती कृष्ण राव (गायन), कोमांदुरी शेषाद्री (वायलिन)।

क्षेत्रीय और सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में केरल के लोकगीत प्रसारित किए गए। दिसंबर 2006 से मार्च 2007 की अवधि में राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम/रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में निम्नांकित कलाकारों की रचनाएं प्रसारित करने का प्रस्ताव है:

जी. कोदान्दरम् (नादस्वरम्), बी. अरुणा और पी.पदमा (गायन द्वैत), टी.वी. सुंदरवल्ली, (गायन), एस. सुंदर (वीणा), सुब्रमण्य शर्मा, महादेव शर्मा और एस.आर. राजश्री।

तिरुवयारू संत त्यागराज आराधना उत्सव का सीधा प्रसारण 7 जनवरी, 2007 को रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में करने और 8 जनवरी, 2007 को सवेरे दक्षिण भारत के वरिष्ठ कलाकारों की प्रस्तुतियों के कार्यक्रम पंचरत्न कीर्तनम् के अंतर्गत रिले किया गया। तिरुपति से 24 जनवरी, 2007 को 261वें आराधना संत नारायण तीर्थ का प्रसारण राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत रिले किया गया।

निर्धारित कलाकारों में आधे से अधिक ऐसे हैं, जो युवा और उभरते हुए कलाकार हैं तथा पहली बार उनकी प्रस्तुति राष्ट्रीय स्तर के प्रसारण में शामिल की जा रही है।

आकाशवाणी ने आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के समक्ष दर्जा देते हुए क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का उत्सव भी प्रारंभ किया है। इसका प्रसारण 2006-07 के दौरान 23 जनवरी 2006 को वसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। इस क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का प्रयोजन देश की समृद्ध लोक सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित, प्रोत्साहित और प्रचारित करना है।

नई प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए आकाशवाणी अखिल भारतीय रेडियो संगीत प्रतियोगिता का आयोजन करती है। आकाशवाणी का एक नियमित प्रयास है, जिसका उद्देश्य युवाओं में नई प्रतिभाओं की खोज करना है। इस वर्ष संगीत की फाइनल प्रतियोगिता का आयोजन हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के लिए क्रमश: दिल्ली और चेन्नई में अक्टूबर-नवंबर माह के दौरान किया गया। इस वर्ष हिन्दुस्तानी/कर्नाटक संगीत की श्रेणी में कई नई प्रतिभाओं की खोज की गई।

हर महीने के प्रथम सप्ताह में बृहस्पतिवार को क्षेत्रीय, सुगम और लोक संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों के वरिष्ठ कलाकार हिस्सा लेते हैं।

राष्ट्रीय चैनल

आकाशवाणी की प्रसारण प्रणाली तीन स्तरीय है, यानी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय। राष्ट्रीय चैनल प्रथम स्तर के प्रसारण के अंतर्गत आते हैं। आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल की स्थापना 18 मई, 1988 को की गई थी। यह एक रात्रि सेवा के रूप में काम करता है जिसके प्रसारण शाम छह बजकर 50 मिनट से अगले दिन प्रात: 6 बजकर 10 मिनट तक होते हैं। यह सेवा 3 मीडियम वेब ट्रांसमीटरों नागपुर (191.6 एम-1566 किलोहर्त्ज), दिल्ली (246.9 एम-1215 किलोहर्त्ज) और कोलकाता (264.5 एम-1134 किलोहर्त्ज पर 2300 बजे से) के जरिए 64 प्रतिशत क्षेत्र और 76 प्रतिशत आबादी को कवर करती है तथा 31 मीटर बैंड (9425 किलोहर्त्ज और 9470 किलोहर्त्ज) की शार्टवेव सहायता से समूचे देश में कवरेज प्रदान करती है।

समूचा भारत इस सेवा के दायरे में आता है। इसे देखते हुए चैनल के कार्यक्रमों का स्वरूप विविध सांस्कृतिक प्रणालियों और पूरे देश के लोकाचार का प्रतिनिधित्व करता है।

राष्ट्रीय चैनल के विविध विषयों पर कार्यक्रमों का स्वरूप विविध सांस्कृतिक प्रणालियों और पूरे देश के लोकाचार का प्रतिनिधित्व करता है।

राष्ट्रीय चैनल ने विविध विषयों पर कार्यक्रमों की अनेक शृंखलाएं प्रसारित कीं। इनमें भारत रत्न और परमवीर चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वालों से संबंधित वार्ता शृंखला, 1857 के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में वृत्त नाटकों की शृंखला, वेद पुराण और उपनिषद सहित प्राचीन भारतीय साहित्य संबंधी शृंखला, सूचना का अधिकार अधिनियम, वैट, व्यावसायिक मार्गदर्शन, खुदरा प्रबंधन, आतंकवाद-निवारण संबंधी कार्यक्रम, सम-सामयिक घटनाओं से संबंधित रेडियो कार्टून-ढाबा, रवीन्द्रनाथ ठाकुर के उपन्यास, गौरा, बंकिम चंद चट्टोपाध्याय के उपन्यास, देवी चौधरानी और तमिल शिलापद्दिकरम के हिंदी संस्करण 'नुपूर के स्वर' पर शृंखलाएं प्रसारित कीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रसिद्ध नारे 'मैं तुम्हें आजादी दूंगा' पर आधारित रेडियो धारावाहिक 19 जनवरी, 2007 से प्रसारित किया जाएगा।

श्रोताओं को शामिल करने और कार्यक्रम गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए सप्ताह के पांच दिन उनके संदेशों/अनुरोधों के कार्यक्रम प्रसारित किए गए। इनमें सैनिकों के लिए सरहद कार्यक्रम भी शामिल हैं।

हिंदी और अंग्रेजी में हर घंटे समाचार केवल राष्ट्रीय चैनल से पूरी रात प्रसारित किए जाते हैं। संसद के अधिवेशन के समय राष्ट्रीय चैनल श्रोताओं के लाभ के लिए प्रश्नकाल की रिकार्डिंग प्रसारित करता है।

'रमजान' के पवित्र महीने के दौरान 50 मिनट का एक विशेष कार्यक्रम 'शहरगाही' हर रोज (तड़के 4.10 बजे से 5.00 बजे तक) प्रसारित किया गया, जिसमें मानवीय मूल्यों और इस्लामी तहजीब पर बल दिया गया।

राष्ट्रीय चैनल ने रेडियो कार्यक्रमों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम से संबद्ध इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

राष्ट्रीय चैनल ने रेडियो कार्यक्रमों में डिप्लेमा पाठ्यक्रम से संबद्ध इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के विद्यार्थियोंको प्रशिक्षण प्रदान किया।

राष्ट्रीय चैनल ने पहली बार वाणिज्यिक स्पॉट्स/जिंगल्स के प्रसारण और विभागीय कार्यक्रमों के प्रायोजित से करीब 62 लाख रुपये राजस्व के रूप में अर्जित किए।

राष्ट्रीय चैनल ने हमेशा की तरह इस वर्ष भी प्रमुख गरिमापूर्ण घटनाओं का प्रसारण जारी रखा। इनमें विभिन्न व्याख्यानमालाएं, रेल तथा आम बजट, सत्याग्रह शताब्दी कार्यक्रम, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसे अवसरों, खेल पुरस्कार, विभिन्न दिवसों से जुड़े राष्ट्रीय कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण/व्यापक कवरेज की। इस अध्याय में संबद्ध उप-शीर्षकों के अंतर्गत इनका ब्यौरा पहले ही दिया जा चुका है।

आयोजना और विकास

आकाशवाणी अपने विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित कार्यक्रमों के जरिए लोगों को सूचना और शिक्षा प्रदान करता है और उनका मनोरंजन करता है। यह समूचे देश के लोगों को सरकार की नीतियों,

योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारी ध्वनि प्रसारण के माध्यम से देता है। इसके लिए सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। यह देश के सभी हिस्सों के लोगों को समसामयिक रुचि की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी भी प्रदान करता है। आकाशवाणी एक वाणिज्यिक सेवा (विविध भारती) का भी संचालन करता है, जो विज्ञापनों के जरिए वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री को प्रोत्साहित करने में सहायता करती है। यह संगठन विदेशी श्रोताओं के लिए विदेश सेवा के कार्यक्रम भी प्रसारित करता है।

आकाशवाणी से संबद्ध महत्वपूर्ण तथ्य नीचे दिए गए हैं :

क. नेटवर्क और कवरेज में बढ़ोतरी

स्वतंत्रता के बाद से आकाशवाणी विश्व के सबसे बड़े प्रसारण नेटवर्कों में शामिल हो चुका है। आजादी के समय 6 आकाशवाणी केन्द्र और 18 ट्रांसमीटर थे, जो देश के 2.5 प्रतिशत क्षेत्र और 11 प्रतिशत आबादी को कवर करते थे। आज नेटवर्क के अंतर्गत 225 केन्द्र और 361 ट्रांसकीटर हैं, जो 99.14 प्रतिशत आबादी और देश के 91.78 प्रतिशत क्षेत्र को रेडियो कवरेज प्रदान करते हैं।

ख. वर्ष के दौरान शुरू की गई गतिविधियां

1. कानपुर और विजयवाड़ा स्थित मौजूदा केन्द्रों पर एफएम ट्रांसमीटर अस्थायी एवं आंशिक रूप से शुरू किए गए।

2. प्रसार भारती के क्यू बैंड के जरिए डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा :

   विभिन्न राज्यों की राजधानियों से भिन्न-भिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में आकाशवाणी के 20 रेडियो चैनल अब प्रसार भारती (डीडी+) के क्यू बैंड डीटीएच प्लेटफार्म के जरिए देश भर में उपलब्ध हैं। इससे पूरे भारत में कहीं भी क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम सुने जा सकते हैं।

3. कोटा में 20 केडब्ल्यू एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर स्थायी एवं आंशिक रूप से चालू किया गया। हालांकि तत्संबंधी परिचालन एवं रखरखाव गतिविधियों के लिए स्टॉफ की मंजूरी की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

4. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज

भारत के द्वीपीय क्षेत्र, सिक्किम क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य इलाकों में आकाशवाणी सेवाओं में सुधार और विस्तार के लिए सरकार द्वारा मंजूर विशेष पैकेज के प्रथम और द्वितीय चरण के कार्यान्वयन के बारे में वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:

1. प्रथम चरण

प्रथम चरण की मंजूरी जनवरी 2003 में दी गई थी और उसके लिए 24.8 करोड़ रुपये की लगात निर्धारित की गई थी। इस प्रस्ताव के अंतर्गत निम्नांकित 6 परियोजनाएं शामिल थीं : पोर्ट ब्लेयर, ईटानगर और कोहिमा में 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर और ईटानगर, कोहिमा और गुवाहाटी में मौजूदा अपलिंकिंग सुविधाओं का उन्नयन करते हुए उन्हें डिजिटल प्रणाली में बदलना। इनमें से कोहिमा में 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर परियोजना (जिसके लिए अंतरिम व्यवस्था की जा चुकी है) को छोड़कर शेष सभी पूरी हो चुकी हैं। स्थायी ढांचे की संस्थापना का काम भी प्रगति पर है और वर्ष के दौरान पूरा हो जाएगा। ईटानगर और पोर्ट ब्लेयर में 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर अभी पूरी तरह चालू किए जाने हैं। इसके लिए परिचालन एवं रखरखाव स्टॉफ की मंजूरी की प्रतीक्षा है।

2. द्वितीय चरण

पूर्वोत्तर क्षेत्र के पैकेज के दूसरे चरण की मंजूरी 143.32 करोड़ रुपये की लागत के साथ मई 2006 के अंतिम सप्ताह में प्राप्त हुई। दूसरे चरण के अंतर्गत मंजूर की गई आकाशवाणी की परियोजनाएं इस प्रकार हैं :

1. 19 नये एफएम केंद्र।
2. सिल्चर (5 किलोवाट) और गंगटोक (10 किलोवाट) में एफएम ट्रांसमीटरों सहित अतिरिक्त चैनल।
3. डीनएसएनजी/एमएसएस टर्मिनल्स।
4. चिनसुरा-1000 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (स्थानापन्न)।
5. कावारत्ती-10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (1 किलोवाट का स्थानापन्न)।
6. 100 कम शक्ति के एफएम ट्रांसमीटर (100 वाट)।

19 नए एफएम केन्द्रों और कवारत्ती में प्रस्तावित 10 केडब्ल्यू मीडियम वेव ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए राज्य सरकारों की सहायता से नए स्थलों की आवश्यकता है। कुछ स्थानों जैसे बेम्डिला, लम्डिंग, चांगलांग, खोन्सा, गोलपाड़ा, तुइपांग, चेम्फई, उदयपुर और नूतन बाजार में स्थल सर्वेक्षण किए जा रहे हैं और उन्हें लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। इस बारे में राज्य सरकारों से स्थलों की लागत संबंधी टिप्पणियां शीघ्र प्राप्त करने के प्रयास किए

जा रहे हैं। इनमें से कुछ स्थल 2006-07 के दौरान ग्रहण किए जाने और उनकी चहारदीवारी/सुरक्षा संबंधी कार्य पूरे कर लिए जाने की उम्मीद है।

उपकरण खरीदने की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है और ज्यादातर उपकरणों के लिए नमूनों को अंतिम रूप देने का काम जारी है।

100 वाट क्षमता के प्रस्तावित एफएम ट्रांसमीटरों के लिए संबद्ध राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करके 100 से अधिक स्थानों की पहचान की जा चुकी है। इन ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थलों को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है।

6. जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष पैकेज

जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष पैकेज के अंतर्गत परियोजनाओं के परिचालन और रखरखाव के वास्ते स्वीकृत पदों को फरवरी 2007 तक जारी रखने संबंधी मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त हो गई है। परंतु भर्ती के जरिए पद भरने संबंधी मंत्रालय की अनुमति अभी नहीं मिली है।

इस बीच, करगिल में 200 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर ओर द्रास और ताइसरू में 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर 1 सितंबर 2006 से आंशिक और अस्थायी रूप में चालू किए गए। इनक लिए कर्मचारियों की व्यवस्था दौरे और स्थानांतरण के आधार पर की गई। इस तरह जम्मू-कश्मीर विशेष पैकेज में शामिल 12 में से 9 परियोजनाएं अभी तक चालू की जा चुकी हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1.	कठुवा	10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर (6 किलोवाट का स्थानापन्न)
2.	श्रीनगर	300 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (200 किलोवाट का स्थानापन्न)
3.	खाल्सी	1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (रिले)
4.	कुपवाड़ा	20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (रिले)
5.	नौशेरा	20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (रिले)
6.	राजौरी	10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (रिले)
7.	द्रास	1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (रिले)
8.	ताइसरू	1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (रिले)
9.	करगिल	200 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर

तीन परियोजनाएं तकनीकी दृष्टि से तैयार हो चुकी हैं, परंतु परिचालन एवं रखरखाव स्टॉफ के अभाव में उन्हें अभी चालू नहीं किया जा सका है। नये पदों पर भर्ती पर लगी पाबंदी इस दिशा में मुख्य रुकावट है। ये परियोजनाएं हैं : लेह क्षेत्र में दिसकित, न्योमा और करगिल क्षेत्र में पदुम।

7. आकाशवाणी की फोन समाचार सेवा

श्रोता दुनिया के किसी भी समय निर्दिष्ट टेलीफोन नंबर डायल करके हिंदी और अंग्रेजी में आकाशवाणी के मुख्य समाचार सुन सकते हैं। यह सेवा अब दिल्ली, मुंबई, पटना, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, त्रिवेन्द्रम, अहमदाबाद और जयपुर में उपलब्ध है। इस सेवा का विस्तार आकाशवाणी के रायपुर, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी और शिमला स्टेशनों पर भी किए जाने की उम्मीद है।

8. 546 डाइनॉमिक कॉरडिओइड माइक्रोफोन खरीदे गए हैं और उन्हें विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों को भेजा जा रहा है। दिसंबर 2006 तक 95 कन्डेसर कॉरिडिओइड माइक्रोफोन्स और 76 वायरलेस माइक्रोफोन्स प्राप्त किए जाने की उम्मीद है।

9. विभिन्न केन्द्रों को वितरित किए जाने के लिए बीस वाट के 190 स्टीरियो मॉनिटरिंग एम्प्लीफायर जोनल कार्यालयों को भेजे गए हैं। दिसंबर 2006 तक 44 स्टीरियो डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लीफायर मिलने की उम्मीद है।

ग. डिजिटल प्रसारण की दिशा में पहल

प्रभावशाली इंजीनियरी ढांचे का निर्माण करने के बाद आकाशवाणी अब आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी विषयक उन्नयन पर जोर दे रहा है। इसने कार्यक्रम निर्माण और ट्रांसमिशन दोनों ही क्षेत्रों में व्यापक डिजिटलीकरण कार्यक्रम शुरू किए हैं। कई आकाशवाणी केन्द्रों पर एनॉलाग उपकरणों को अत्याधुनिक डिजिटल उपकरणों कसे बदला जा रहा है।

1. आकाशवाणी के 83 केन्द्रों पर कम्प्यूटरीकृत हार्ड डिस्क आधारित रिकॉर्डिंग, संपादन और प्लेबैक प्रणाली पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। 61 और केन्द्रों में ऐसी प्रणाली कायम करने के लिए उपकरण खरीदे जा रहे हैं।

2. अच्छी क्वालिटी की कन्वर्जेन्स-रेडी (समान रूप से काम आने वाली) विषयवस्तु सुनिश्चित करने के लिए अपलिंकिंग केंद्रों और कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं का डिजिटलीकरण शुरू किया गया है। इससे न्यूज ऑन फोन, म्यूजिक ऑन डिमांड जैसी इंटरएक्टिव (परस्पर संपर्क) रेडियो सेवाओं में भी मदद मिलेगी।

3. वाराणसी, रोहतक, लेह, देहरादून, सिल्चर और औरंगाबाद में नए डिजिटल कैप्टिव भू-केन्द्र (अपलिंक्स) बनाये जा रहे हैं।

4. डाउनलिंक सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से डिजिटल बनाया जा रहा है। चालू अवधि में 115 केन्द्रों में ये सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

5. दिल्ली और रायपुर में मौजूदा 100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटरों को चालू योजना के दौरान नये अत्याधुनिक ट्रांसमीटरों में बदला जाएगा।

6. ऑनलाइन जानकारी के आदान-प्रदान और कार्य क्षमता में सुधार के लिए आकाशवाणी केंद्रों और कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण का काम प्रगति पर है।

7. आकाशवाणी के लेह, मैसूर, जयपुर, तवांग आदि केंद्रों के लिए रिकॉर्डिंग, डबिंग, संपादन और प्लेबैक सुविधओं के लिए कम्प्यूटरीकृत हार्ड डिस्क आधारित वर्क स्टेशनों सहित डिजिटल उपकरणों वाले स्टूडियो उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

8. **महानगरों में स्टॉफ क्वाटर्स :** सरकार ने प्रसार भारती कर्मचारियों के लिए चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में स्टॉफ क्वाटरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

9. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आकाशवाणी सुविधाओं की स्थापना के लिए हाल ही में राज्य सरकार से भूमि प्राप्त की गई है। भवन निर्माण के लिए अनुमानित लागत की मंजूरी ली जा रही है और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होने की संभावना है। देहरादून में बनने वाले आकाशवाणी के स्टूडियो कम्प्यूटरीकृत हार्ड डिस्क आधारित रिकॉर्डिंग और संपादन प्रणालियों सहित अद्यतन डिजिटल उपकरणों से सुसज्जित किए जाएंगे।

10. अमरावती, जूनागढ़, ओरस, राइरंगपुर, धर्मनगर, करीमनगर, श्रीकाकुलम में प्रस्तावित एफएम रेडियो केंद्रों के लिए भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

घ. कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी)-एसटीआई(टी)

दिल्ली स्थित कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान इंजीनियरी कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताएं पूरी करता है। प्रशिक्षण सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए भुवनेश्वर, शिलांग और मुंबई में क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसटीआई-टी) स्थापना भी की गई है।

1948 में स्थापित कर्मचारी संस्थान इलेक्ट्रोनिक मीडिया में तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र बनकर उभरा है। संस्थान में एक सुसज्जित पुस्तकालय और उन्नत मल्टी मीडिया उपकरणों से लैस एक कम्प्यूटर केंद्र उपलब्ध है।

संस्थान विभागीय उम्मीदवारों तथा समान सेवा प्रदान करने वाले विदेशी संगठनों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है। विभिन्न फील्ड कार्यालयों में कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं। यह संस्थान सीधे भर्ती किए जाने वाले इंजीनियरी सहायकों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है, और अधीनस्थ इंजीनियरी काडरों में पदोन्नति के लिए विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी करता है। क्षेत्रीय संस्थान कम्प्यूटरीकृत हार्ड डिस्क आधारित रिकार्डिंग, संपादन और प्लेबैक प्रणाली के इस्तेमाल जैसे प्रशिक्षण पाठयक्रमों का संचालन करते हैं।

1 अप्रैल 2006 से 30 नवंबर 2006 की अवधि में आयोजित गतिविधियां

कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) ने इस अवधि के दौरान 48 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया और 723 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवधि में क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), भुवनेश्वर में 393, क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), शिलांग में 51 और क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), मलाड ने 50 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। इस अवधि में निम्नांकित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजित किए गए :

1. आकाशवाणी और दूरदर्शन के सुपरिटेंडिंग इंजीनियरों के लिए एमसीएफ हासन, अंतरिक्ष विभाग, में उपग्रह प्रौद्योगिकी के बारे में एक विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। इस पाठ्यक्रम में 20 इंजीनियरों ने हिस्सा लिया।

2. निदेशकों/उपनिदेशकों के लिए 13 जुलाई 2006 को पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के बारे में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 46 अधिकारियों ने भाग लिया।

3. एसटीआई (टी) में 11 सितंबर, 2006 से 13 सिंतबर 206 की अवधि में एआईआर वर्चुअल साफ्टवेयर के बारे में विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसी तरह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 अक्टूबर, 2006 से 6 अक्टूबर, 2006 के दौरान रेडियो कश्मीर, जम्मू में भी आयोजित किया गया। एसटीआई (टी) और कुछ बाहरी केंद्रों पर भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है।

4. इंजीनियरी में डिग्री और डिप्लोमा के विद्यार्थियों के लिए तीन अलग-अलग ग्रीष्म प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए

गए। ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण के दौरान 100 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

5. डिजिटल अर्थ स्टेशन, डिजिटल उपग्रह समाचार संग्रह प्रणाली, डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सर्विस, और प्रसारण में नई प्रवृत्तियों आदि के बारे में एसटीआई(टी) में विभिन्न पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें मॉरिशस के 8 और भूटान के 9 विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया।

दिसंबर 2006 से मार्च 2007 के बीच प्रस्तावित गतिविधियां :

1. वर्ष की शेष अवधि यानी 31 मार्च, 2007 तक एसटीआई(टी) दिल्ली में आयोजित होने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में करीब 450 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किए जाने की संभावना है। आरएसटीआई(टी) भुवनेश्वर में करीब 150, आरएसटीआई (टी) शिलांग में करीब 100 और आरएसटीआई (टी) मलाड, मुंबई में करीब 100 कार्मिकों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में हिस्सा लेने की संभावना है।

2. रेडियो कंटेन्ट प्रोडॅक्शन एंड डिलिवरी विषय पर एक विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 26 फरवरी से 9 मार्च, 2006 की अवधि में आयोजित किया जाना है। यह पाठ्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, जिसके लिए वित्त व्यवस्था एबीयू-आईएबीएम ने की है।

ड. 'एआईआर रिसोर्सेज' की गतिविधियां

आकाशवाणी के इस वाणिज्यिक एकांश की गतिविधियों की जानकारी इसी अध्याय में पहले दी जा चुकी है।

च. अनुसंधान और विकास

अनुसंधान विभाग रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी शामिल करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्यों में लगा हुआ है। अप्रैल 2006 से अक्टूबर 2006 की अवधि में आकाशवाणी की विभिन्न शाखाओं में शुरू की गई तकनीकी गतिविधियां और नवंबर 2006 से मार्च, 2007 के बीच प्रत्याशित गतिविधियां नीचे दी गई हैं :

अप्रैल 2006 से अक्टूबर, 2006 तक की गतिविधियां

(1) एएम ट्रांसमीटर के लिए टेलीमेट्री प्रणाली : मीडियम वेव ट्रांसमीटरों को दूरवर्ती स्थान से नियंत्रित करने और उन पर निगरानी रखने के लिए टेलीमेट्री प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता होती है। आकाशवाणी रोहतक के 20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर के लिए टेलीमेट्री प्रणाली का हार्डवेयर तैयार कर लिया गया है और सॉफ्टवेयर विकसित करने का काम जारी है। लद्दाख में आकाशवाणी, न्योमा के लिए टेलीमेट्री प्रणाली का हार्डवेयर विकसित करने का कार्य भी प्रगति पर है।

(2) एफएम एंटीना : एक सिंगल वे 3.0 किलोवाट एफएम एंटीना विकसित किया गया और उसे आकाशवाणी पुणे में लगाया गया। इसी प्रकार एक डबल-वे एफएम एंटीना का भी डिजाइन तैयार किया गया है और इसे विकसित किया जा रहा है। इसका परीक्षण आकाशवाणी बंगलौर में किया गया, और यह संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है। ये सिंगल वे और डबल वे एंटीना देश में ही विकसित किए जा रहे हैं, ताकि आपात स्थितियों में आकस्मिक व्यवस्था के रूप में उन्हें तैनात किया जा सके।

(3) समाचार कक्ष का ऑटोमेशन : आकाशवाणी जैसे विस्तृत नेटवर्क में अद्यतन जानकारी का संग्रहण और संप्रेषण करना तथा उसका रिकार्ड रखना अत्यंत कठिन कार्य है। इसके लिए समाचार कर्मियों को निरंतर सजगता आवश्यक होती है। आकाशवाणी के अनुसंधान विभाग हाल ही में समाचार कक्ष ऑटोमेशन प्रणाली विकसित की है, ताकि कार्य तेजी, सरलता और सुचारु रूप से किया जा सके। इस प्रणाली में समाचार आइटमों का पाठ एजेंसियों से सीधे कम्प्यूटर पर प्राप्त किया जाता है, वहीं पर उसे संपादित किया जाता है और टेली प्रोम्प्टर जैसे स्क्रीन पर उसका वाचन किया जाता है। समाचार बुलेटिनों के दौरान ऑडियो क्लिपों यानी श्रव्य सामग्री को इन्सर्ट (शामिल) किया जा सकता है, और प्लेबैक किया जा सकता है। समाचार बुलेटिन में अंतिम क्षणों में संशोधन का प्रावधान भी इस सॉफ्टवेयर भी शामिल किया गया है।

ध्वनि प्रयोगशाला

अनुसंधान विभाग की ध्वनि प्रयोगशाला विभिन्न प्रकार की अध्ययन परियोजनाएं, ध्वनि मापन, परीक्षण और इलेक्ट्रो-अकाउस्टिक्स ट्रांसेंडरों सहित ध्वनि सामग्री के मूल्यांकन की गतिविधियां संचालित करता है। हाल ही में प्रयोगशाला में मापन सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए प्रणाली का आधुनिकीकरण किया गया। इसके लिए नई ध्वनि/शोर विश्लेषक प्रणाली शुरू की गई है। अनुसंधान और विकास विभाग ने करीब 20 तरह की नई ध्वनि सामग्री का ध्वनि मापन शुरू किया है और मानक रिपोर्ट जारी की हैं। इस प्रक्रिया से अनुसंधान और विकास विभाग को स्टूडियो डिजाइन करने के लिए बेहतर डाटा-बेस तैयार करने में भी मदद मिली है।

आकाशवाणी नेटवर्क में इन्टरएक्टिव रेडियो सेवा (आईआरएस) की संस्थापना

इंटरएक्टिव रेडियो सेवा (आईआरएस) सॉफ्टवेयर का डिजाइन और

विकास टेलीफोन लाइन के जरिए स्टूडियो में बैठे प्रस्तुतकर्ता और श्रोताओं के बीच परस्पर संपर्क शुरू करने के लिए किया गया है। यह इस्तेमाल कर्ता के अनुकूल साफ्टवेयर है, और इसका इस्तेमाल देश में आकाशवाणी नेटवर्क के करीब 34 स्थानों के बीच सफलतापूर्वक किया जा रहा है। हाल ही में आकाशवाणी के सिल्चर, खंडवा, कटक, संबलपुर, वारंगल, सवाईमाधोपुर, रत्नगिरि, बिलासपुर, जोधपुर, सूरतगढ़, हैदराबाद और रायपुर केंद्रों को इस सॉफ्टवेयर का लाभ पहुंचाया गया। यह सॉफ्टवेयर अत्यंत लोकप्रिय है और इसे आकाशवाणी की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

टावरों पर वीएचएफ/यूएचएफ ट्रांसमीटिंग एंटीना की समस्तर रेडिऐशन पद्धति का प्रभाव

जालंधर, भटिंडा और बरेली स्थित एफएम केंद्रों के टावरों पर बीएचएफ ट्रांसमीटिंग एंटीनों की समस्तर रेडिऐशन पद्धति के प्रभाव का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन पर आधारित एक अनुसंधान दस्तावेज आईटीयू, जिनेवा को भेजा गया है।

क्षेत्र शक्ति सर्वेक्षण और सम्प्रेक्षण (प्रोपेगेशन) अध्ययन

1. आकाशवाणी भवन में संस्थापित एक प्रायोगिक 100 डब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर की क्षेत्र शक्ति का परीक्षण किया गया। इसका उद्देश्य संतोषजनक संप्रेषण के बारे में इसकी प्राथमिक कवरेज का मूल्यांकन करना था। इसका लक्ष्य यह पता लगना भी था कि उंचे भवनों के बीच संप्रेषण में कितनी क्षति होती है।

2. पीतमपुरा और जामिया मिलिया से प्राप्त एफएम रेडियो सिटी और एफएम कम्युनिटी रेडियो के सिग्नलों के विषयपरक मूल्यांकन के लिए अप्रैल 2006 में सर्वेक्षण किया गया।

नवंबर 2006 से मार्च 2007 के बीच प्रस्तावित गतिविधियां

स्टूडियो डिजाइन और वाणिज्यिक आधार पर विभिन्न ध्वनि सामग्री के नियमित परीक्षण और पूर्व वर्णित अन्य गतिविधियों के अलावा 1 नवंबर, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक वर्ष की शेष अवधि में निम्नांकित कार्य/परियोजनाएं संचालित करने की योजना है:

(i) एएम ट्रांसमीटर के लिए टेलीमेट्री प्रणाली

1. आकाशवाणी रोहतक और आकाशवाणी न्योमा में क्रमश 20 केडब्ल्यू और 1 केडब्ल्यू ट्रांसमीटरों का परीक्षण किया जाएगा।

2. पीतमपुरा दिल्ली स्थित एफएम ट्रांसमीटर नंबर 2 के लिए मौजूदा एफएम टेलीमेट्री को नया रूप दिया जाएगा।

(ii) आयोजना साफ्टवेयर 'ब्रॉड प्लान' का उन्नयन

अनुसंधान विभाग द्वारा पहले विकसित किए गए 'ब्रॉड प्लान' साफ्टवेयर के उन्नयन की आवश्यकता है। इस कार्य के अंतर्गत मुख्य रूप से भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक जिले से संबद्ध आंकड़ों का संशोधन और 'मैपइन्फो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर वी 4.5 से वी 8.5' का उन्नयन शामिल है।

(iii) डीआरएम और मीडियम वेव/शार्ट वेव

डिजिटल रेडियो मोंडियाल (डीआरएम) टेक्नोलॉजी आकाशवाणी नेटवर्क में शामिल की जा रही है। इसके लिए डीआरएम सेवाओं की आयोजना की आवश्यकता है। अनुसंधान विभाग मीडियम वेव/शार्ट वेव बैंडों में डीआरएम सेवा के लिए नेटवर्क आयोजना की शुरूआत करेगा।

(iv) प्रायोगिक शॉर्ट वेव डीआरएम परियोजना

'डिजिटल रेडियो मोंडियाले (डीआरएम) के बारे में प्रयोगात्मक अध्ययन' नाम की अनुसंधान एवं विकास परियोजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत डीआरएम के विभिन्न मानदंडों का अध्ययन शामिल है, जैसे कवरेज एरिया, स्पेक्ट्रल कार्य क्षमता, श्रव्य गुणवत्ता में सुधार, डाटा, टेक्स्ट आदि मूल्य संवर्द्धित सेवाओं की डिलिवरी आदि।

एचपीटी, खामपुर में 250 केडब्ल्यू शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर का उन्नयन किया जा रहा है ताकि शॉर्ट वेव में डीआरएम ट्रांसमिशन शुरू किया जा सके। उन्नयन कार्य पूरा होने के बाद व्यापक क्षेत्र शक्ति सर्वेक्षण किया जायेगा।

(v) आपातकालीन चेतावनी प्रसारण प्रणाली

चक्रवात, सुनामी और अन्य आपदाओं के आने से पहले उनके बारे में चेतावनी जारी करने के लिए रेडियो एक आदर्श माध्यम है। जापान जैसे देशों में पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्लूएस) के लिए ऐनालॉग मोड में रेडियो, ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में जापान ने भू-डिजिटल प्रसारण के साथ इस्तेमाल किए जाने के लिए ईडब्लूएस विकसित की है। अनुसंधान विभाग ने एएम और एफएम ट्रांसमीटरों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली का अध्ययन शुरू किया है। इसके अंतर्गत विशेष प्रकार के रिसीवर सक्रिय हो जाएंगे और उसके बाद चेतावनी की घोषणा की जा सकेगी।

(vi) एफएम एंटीना

रिसर्च विभाग ने सिक्स वे सर्कुलरली पोलराइज्ड 10.0 किलोवाट

एफएम एंटीना विकसित किया है। जल्दी ही आकाशवाणी वडोदरा में पूरी क्षमता के साथ इसका परीक्षण किया जायेगा।

(vii) आकाशवाणी नेटवर्क में इंटरएक्टिव रेडियो सेवा (आईआरएस) का उन्नयन और संस्थापन

इंटरएक्टिव रेडियो सेवा (आईआरएस) सॉफ्टवेयर की संस्थापना से स्टूडियो में बैठे प्रेजेंटर और श्रोताओं के बीच टेलीफोन लाइन के जरिये सीधे संपर्क किया जा सकता है। यह इस्तेमालकर्ता के अनुकूल सॉफ्टवेयर है और इसका इस्तेमाल देश में आकाशवाणी नेटवर्क की 34 से अधिक संस्थापनाओं में किया जा रहा है। इसका लोकप्रियता और नेटवर्क में उपयोगिता को देखते हुए समेकित सॉफ्टवेयर पैकेज विकसित करने का प्रस्ताव है, ताकि मोबाइल फोन के जरिये भी सीधे परस्पर संपर्क कायम किया जा सके।

(viii) क्षेत्र शक्ति सर्वेक्षण और प्रचार अध्ययन

1. दिल्ली में स्थित सभी एफएम ट्रांसमीटरों (आकाशवाणी और निजी प्रसारणकर्ताओं के) का क्षेत्र शक्ति सर्वेक्षण किया जाएगा।

2. खामपुर, दिल्ली में 250 किलोवाट थेल्स ट्रांसमीटर पर डीआरएम चालू होने के बाद से डीआरएम की विभिन्न प्रणालियों में क्षेत्र शक्ति सर्वेक्षण कराये जाएंगे।

श्रोता अनुसंधान

आकाशवाणी कार्यक्रमों की विपणन सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए रेडियो श्रोता सर्वेक्षण कराया जाता है। वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान यह सर्वेक्षण देश भर में प्राइमरी चैनल के 63 स्थानों पर किया गया। इसके आधार पर तय की जाने वाली रेटिंग से अलग-अलग आकाशवाणी केन्द्रों को लोकप्रिय कार्यक्रमों के विपणन में मदद मिलती है। कार्यक्रमों की रेटिंग से कार्यक्रम निर्माताओं को समुचित फीडबैक भी प्राप्त होता है जिससे वे श्रोताओं के विभिन्न वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्यक्रमों के नियत चार्ट में प्रभावकारी संशोधन कर सकते हैं।

इस अध्ययन की रूपरेखा निदेशालय द्वारा शहरों/कस्बों की बाजार संभावनाओं के अनुसार तैयार की जाती है। इसमें लगभग सभी ट्रिपल ए श्रेणी के शहरों, डबल ए श्रेणी के शहरों और ए श्रेणी के शहरों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा बी, सी और डी श्रेणी के शहरों/कस्बों को भी अध्ययन में समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इस अध्ययन में प्रत्येक आकाशवाणी केन्द्र और प्राथमिक चैनल के कार्यक्रमों की लोकप्रियता का पता लगाने, आकाशवाणी और प्राइवेट एफएम कार्यक्रमों (उपलब्धता के अनुसार) की वास्तविक श्रोता संख्या का मूल्यांकन करने, आकाशवाणी कार्यक्रमों की पहुंच और उपयोगिता की पड़ताल करने का प्रयास किया जाता है। इसमें जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमा पार से सम्बद्ध कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी शामिल है।

किसान वाणी चैनल : कृषि और सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किसान वाणी पर प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को अनुसंधान सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने आकाशवाणी महानिदेशालय नई दिल्ली की एआर यूनिट के सहयोग से देश भर में 87 स्थानों पर अध्ययन शुरू किया है। यह महसूस किया जा रहा है कि अनुसंधान अध्ययन के जरिये मिलने वाले फीडबैक से कार्यक्रम निर्माताओं को लक्षित श्रोताओं (यानी कृषक समुदाय) को आसानी से समझ में आने वाले और दिलचस्प कार्यक्रम तैयार करने के लिए बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलेगी।

एफएम रेनबो पर प्रसारित मुख्य समाचारों का सर्वेक्षण : समाचार सेवा प्रभाग ने एफएम रेनबो पर हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में बुलेटिन शुरु किए हैं। मुख्य समाचार बुलेटिनों की गुणवत्ता, उनके प्रभाव, और वास्तविक श्रोता संख्या का पता लगाने के लिए 13 स्थानों पर अध्ययन किया जा रहा है। ये हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, लखनऊ, हैदराबाद, पणजी, तिरुचिरापल्ली, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी और पटना।

आकाशवाणी रायचुर से प्रसारित यूनिसेफ, हैदराबाद के प्रायोजित कार्यक्रम के प्रसारण पूर्व और परवर्ती मूल्यांकन : धारवाड़ स्थित एआर यूनिट ने यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम *बागीना* का प्रसारण पूर्व और प्रसारण परवर्ती मूल्यांकन किया। इस अध्ययन के जरिए प्रसारित शृंखलाओं के प्रभाव और कार्य क्षमताओं का पता लगाया जा सके।

एआईआार कम्पेंडियम (आकाशवाणी सार-संग्रह) 2006-07: यह एक व्यापक वार्षिक संदर्भ पुस्तिका है, जिसमें प्रसारण विषय-वस्तु की आयोजना और प्रसारण समय की बिक्री का ब्योरा दिया गया है। पुस्तिका की रूपरेखा, डिजाइन, संकलन और प्रकाशन निदेशालय द्वारा किया गया। इसमें आकाशवाणी के बारे में उद्देश्यपूर्ण दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं।

कम्पेंडियम के 2006-07 के संस्करण में आकाशवाणी द्वारा मुख्य रूप से सार्वजनिक सेवा प्रसारणकर्ता की भूमिका निभाने अैर प्राइवेट चैनलों की प्रतिस्पर्धा में राजस्व अर्जित करने की गौण प्रक्रिय अपनाये जाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

किसान वाणी के बारे में 7 कार्यशालाएं : कृषक समुदाय को उपयोगी अैर व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एआरयूनिट

ने देश भर में 7 क्षेत्रों में 'किसान वाणी कार्यक्रम निर्माता-अनुसंधाता परस्पर संपर्क' विषय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया। ऐसी कार्यशालाएं कार्यक्रम निर्माताओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय रही हैं और उनमें सार्वजनिक सेवा प्रसारणकर्ता-आकाशवाणी के लिए विकास संचार को गंभीर मुद्दा समझे जाने पर बल दिया गया है।

जीवन है अनमोल : श्रोता अनुसंधान एकक ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजना 'जीवन है अनमोल' का मूल्यांकन किया। इस कार्यक्रम के जरिए आम आदमी को एड्स और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी समुचित और शिक्षाप्रद जानकारी प्रदान करने और समाज में व्यापक जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया गया है। इन कार्यक्रमों का फीडबैक मंत्रालय को भेजा गया।

जुलाई 2006 में विश्व कप फुटबॉल मैच के सीधे प्रसारण का सर्वेक्षण: विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता के सीधे प्रसारण का सर्वेक्षण 2006 में 7 स्थानों-पटना, जालंधर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, पणजी और रांची में किया गया।

प्रायोजित कार्यक्रम-एनड्राइक्कम मल्लातु के बारे में सर्वेक्षण : श्रोता अनुसंधान एकक चेन्नई ने राज्य के राजस्व केन्द्र चेन्नई द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम एनड्राइक्कम मल्लातु (हमेशा के लिए अच्छा) का सर्वेक्षण किया। यह कार्यक्रम एफएम रेनबो, आकाशवाणी चेन्नई और तिरुचिरापल्ली तथा प्राथमिक चैनल तिरुनेलवेली से प्रसारित किया गया है। इस कार्यक्रम के मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया।

खेल

अप्रैल 2006 से दिसंबर 2006 की अवधि में आकाशवाणी ने भारत और विदेश में खेली गई विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को व्यापक कवरेज प्रदान की। इनमें निम्नांकित प्रतियोगिताएं शामिल थीं : भारत में भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट शृंखला, आबूधाबी (संयुक्त अरब अमीरात) में भारत-पाकिस्तान एकदिवसीय मैचों की शृंखला, वेस्टइंडीज में भारत-वेस्टइंडीज क्रिकेट शृंखला (पांच एकदिवसीय और चार टेस्ट मैच), कुवालालंपुर, मलेशिया 2006 में त्रिकोणीय क्रिकेट शृंखला (भारत, आस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज), (पांचवीं आईसीसी चैम्पियन्स ट्रॉफी, भारत, मलेशिया 2006), लंदन में विंबलडन टेनिस चैम्पियनशिप, श्रीलंका में 10वें सैफ खेल, भारत में भारत और सऊदी अरब के बीच एएफसी क्वालिफाइंग फुटबॉल चैम्पियनशिप 2006, भारत में एएफसी यूथ फुटबॉल चैम्पियनशिप (जर्मनी में फीफा विश्व कप फुटबॉल, जर्मनी में 2006 विश्व कप हॉकी)।

देश में खेली गई विभिन्न राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं को आंखों देखा हाल, सारांश, वॉइसकास्ट और साक्षात्कार आदि के जरिए कवरेज प्रदान की गई। इनमें निम्नांकित प्रतियोगिताएं शामिल थीं- गुड़गांव में संतोष ट्राफी फुटबॉल, कोलकाता में अखिल भारतीय बेटन कप हॉकी प्रतियोगिता 2006, मुंबई में अखिल भारतीय बोम्बे स्वर्ण कप प्रतियोगिता 2006, जालंधर में 62वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता, जालंधर में 23वीं सुरजीत सिंह हॉकी प्रतियोगिता, दिल्ली में डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता और दिल्ली में नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता। इसके अतिरिक्त विभिन्न खेलों से संबद्ध अन्य प्रतियोगिताओं को भी कवरेज दी गई।

आकाशवाणी ने पुणे अंतर्राष्ट्रीय मैराथन ओर दोहा, (कतर) में 15वें एशियाई खेलों को कवरेज प्रदान की। गुवाहाटी में 34वें राष्ट्रीय खेलों, वेस्टइंडीज में विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2007 और भारत में त्रिकोणीय (भारत, वेस्टइंडीज और श्रीलंका) क्रिकेट शृंखला भी कवरेज की गई।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

आकाशवाणी देश भर में फैले अपने 215 केंद्रों के नेटवर्क के जरिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के बारे में कार्यक्रम प्रसारित करता है। आकाशवाणी के सभी केन्द्र देश की क्षेत्रीय भाषाओं/बोलियों में परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रसारित करते हैं।

आकाशवाणी केन्द्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के बारे में काफी संख्या में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। ये कार्यक्रम विभिन्न वर्गों के श्रोताओं जैसे ग्रामीण, महिला/बच्चे आदि के लिए विभिन्न रूपों में प्रसारित किए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से वार्ता, चर्चा, फीचर, क्विज जिंगल्स, स्पॉट्स, लघु कथा, नाटक, सफलता की कहानियां, फोन इन प्रोग्राम आदि कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा स्थानीय रेडियो केन्द्रों सहित आकाशवाणी के शेष केन्द्र भी महत्वपूर्ण विषयों पर नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इन विषयों में विवाह की सही आयु, पहला बच्चा देरी से पैदा करने, दो बच्चों के बीच अंतर, मां और शिशु की देखभाल, महिला अधिकारिता, दंपत्तियों के बीच समझ-बूझ/पुरुष दायित्व भावना को बढ़ावा देना, संतान में लड़के को प्राथमिकता देने की धारणा में परिवर्तन, चिकित्सीय पद्धति से गर्भपात, संस्थागत कानूनी प्रावधानों को प्रोत्साहन और यौन संचरित संक्रमण, प्रसव पूर्व निदानात्मक तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग रोकथाम) अधिनियम 1995, एड्स, नशीली दवाओं का सेवन, स्तनपान, बाल अधिकार, बाल मजदूरी, बालिका संतान, विकलांगता, क्षय रोग, कुष्ठ रोग और बाल स्वास्थ्य आदि शामिल थे।

नई संचार नीति को उजागर करने के लिए सभी प्रमुख केंद्रों को इस नीति का ब्योरा भेजा गया। सभी केंद्रों को नए दिशा-निर्देश जारी किए गए कि वे परिवार के छोटे आकार के महत्व, गर्भ रोकने की विधियों, नसबंदी, क्षेत्र आधारित कार्यक्रमों के प्रसारण (परिवार नियोजन के लाभार्थियों के साथ साक्षात्कार) भोजन में पोष्टिक तत्वों की महत्व, बच्चों की देखभाल, रोगों से बचाव के टीकों, स्तनपान और विवाह की आयु बढ़ाने जैसे विषयों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें।

रक्तदान और नेत्रदान के महत्व को व्यापारिक रूप में प्रचारित किया गया। नशीले पदार्थों के सेवन, तम्बाकू, खाने, नशीले पदार्थों की तस्करी, कुष्ठ रोग निवारण और एड्स आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो आकाशवाणी के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखता है और समय-समय पर संदर्भ सामग्री और विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध कराता है। परिवार कल्याण के सर्वोत्तम कार्यक्रम के लिए हर वर्ष आकाशवाणी का वार्षिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

बच्चों के बारे में कार्यक्रमों का प्रसारण

आकाशवाणी के सभी केन्द्र बच्चों के लिए नियमित आधार पर कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। महिलाओं और सामान्य श्रोताओं के कार्यक्रमों में मां और बच्चों के स्वास्थ्य और देखभाल पर बल दिया जाता है। रोगों से बचाव के टीके और प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा आकाशवाणी प्रसारणों का नियमित हिस्सा है।

कार्यक्रमों की योजना बनाने समय निम्नांकित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है।

1) बच्चों के अधिकारों का संरक्षण

2) विकलांग बच्चों की देखभाल और सहायता

3) कठिन परिस्थितियों के अंतर्गत बच्चों की देखभाल और सहायता

4) बालिका को समान दर्जा और महिलाओं को समान अधिकार

5) सभी बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा सुनिश्चित करना और लड़कियों की शिक्षा पर अधिक ध्यान देना

6) सुरक्षित मातृत्व, परिवार के आकार की दायित्वपूर्ण योजना

7) बच्चों को सुरक्षित और मददगार वातावरण प्रदान करना

8) परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार और आत्मनिर्भर समाज

9) बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

10) सुरक्षित पेयजल सुविधा और मल निपटान के स्वच्छ साधन

बालिका संतान के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न रूपों में विशेष कार्यक्रम वर्ष भर नियमित अंतराल के आधार पर निरंतर प्रसारण में शामिल किए गए ताकि लड़की के जन्म का स्वागत भी लड़के के जन्म की तरह ही करने के बारे में सामाजिक जागरूकता पैदा की जा सके। ये कार्यक्रम चर्चाओं, वार्ताओं, लघु कथाओं, जिंगल्स, स्पॉट्स आदि रूपों में प्रसारित किए गए।

आकाशवाणी 3 श्रेणियों के बच्चों के लिए अपने लगभग सभी केंद्रों से कार्यक्रम प्रसारित करता है। इनमें 5 से 7 वर्ष और 8 से 14 वर्ष की आयु समूह के बच्चे शामिल हैं। ग्रामीण बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

कुछ कार्यक्रम साप्ताहिक आधार पर प्रसारित होते हैं। इन प्रसारणों में नाटक, लघु कथाएं, फीचर, समूह गान, साक्षात्कार, महाकाव्यों से कहानियां आदि शामिल होते हैं।

ग्रामीण बच्चों के लिए कार्यक्रम

ग्रामीण बच्चों के लिए आकाशवाणी के उन सभी केन्द्रों से सप्ताह में एक बार कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जिनमें फॉर्म एंड होम एकक हैं। इन कार्यक्रमों में शिक्षा और साक्षरता के किसी भी स्तर से संबद्ध बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। इनके जरिए बच्चों को बेहतर नागरिक बनने के लिए शिक्षित और प्रेरित किया जाता है। सभी कार्यक्रमों में किशोरों के संबद्ध विषय शामिल किए जाते हैं। किशोरों से संबद्ध सभी कार्यक्रमों में सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के संदेश प्रसारित किए जाते हैं।

छोटे बच्चों (5-7 वर्ष) के लिए कार्यक्रम

छोटे बच्चों के लिए साप्ताहिक आधार पर अपेक्षिकृत कम अवधि के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में बच्चों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से नाटक, फीचर, समूह गान, साक्षात्कार, यात्रा वृतांत, महाकाव्यों से कहानियां, विभिन्न देशों की कहानियां आदि रूपों में होते हैं। छोटे बच्चों के अधिकारों को अक्सर समूह गान, कहानियों, कविता पाठ, नाटिकाओं और बच्चों के साथ साक्षात्कार के जरिए उजागर किया जाता है। बच्चों और उनके माता-पिता के साथ मुक्त और स्वस्थ विकास, स्वच्छ वातावरण और राष्ट्र निर्माण तथा परिवार कल्याण में योगदान जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

महिला कार्यक्रमों का प्रसारण

ग्रामीण और शहरी महिलाओं के लिए कार्यक्रमों के प्रसारण में लक्षित समूहों के लिए सुविधाजनक समय का ध्यान रखा जाता है।

महिला श्रोताओं से संबद्ध कार्यक्रमों में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, भोजन और पोषण, वैज्ञानिक तरीके से गृह प्रबंधन, महिला उद्यमशीलता, प्रौढ़ शिक्षा सहित महिलाओं की शिक्षा, और समाज में स्त्री-पुरुष की स्थिति आदि विषयों को शामिल किया जाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य कानूनी साक्षरता के प्रसार के जरिए महिलाओं के अधिकारों और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में व्यापक सामाजिक जागरूकता पैदा करना भी है।

आकशवाणी अपने कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं के प्रति उचित दृष्टिकोण अपनाए जाने के बारे में सामाजिक जागरूकता पैदा करने का प्रयास करता है। विशेष रूप से ग्रामीण श्रोताओं को संदेश देने के लिए विभिन्न परंपरागत लोक रूपों का सहारा लिया जाता है।

महिलाओं के कार्यक्रमों में महिलाओं को मुख्य हिस्सा बनाने के मुद्दे के अलावा महिलाओं की सामान्य समस्याओं और महिलाओं के प्रति सामाजिक नजरिए में बदलाव की जरूरत को भी सामान्य प्रसारण का अभिन्न अंग बनाया जाता है। ये कार्यक्रम वार्ताओं, नाटकों, लघु कथाओं, फीचर चर्चाओं, आदि रूपों में होते हैं और उनमें महिलाओं के खिलाफ अपराध, बालिका संतान को वरीयता देने, दहेज प्रथा की बुराइयों, स्त्री-पुरुष के बीच असमानता और कन्या भ्रूण हत्या रोकने तथा महिलाओं के स्तर में सुधार जैसे विषय निरन्तर शामिल किए जाते हैं।

बच्चों और महिलाओं के लिए घर और बाहर सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए वर्ष भर अभियान चलाया गया। महिलाओं के प्रति सामाजिक नजरिए और व्यवहार पद्धति में परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सामान्य श्रोता कार्यक्रमों के साथ-साथ विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए गए।

आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुखों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं ताकि वे महिलाओं को अधिकारिता के लक्ष्य को ध्यान में रखकर उनके लिए कार्यक्रम बनाएं और महिलाओं के मुद्दों को सिर्फ महिलाओं से संबद्ध नहीं, बल्कि सामाजिक मुद्दों के रूप में पेश करें।

महिला अधिकारिता के प्रति जागरूकता पैदा करना और ऐसे मुद्दों एवं उपायों पर ध्यान केंद्रित करना आकाशवाणी का उद्देश्य रहा है, जिनका उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। लिंग अनुपात में निरन्तर कमी आने से बालिकाओं के खिलाफ भेदभाव का स्पष्ट रूप से पता चलता है। बालिकाओं के स्वास्थ्य और साक्षरता की खराब स्थिति में भी यह भेदभाव प्रकट होता है। बालिकाओं के भोजन में पोष्टिक तत्वों की कमी और कम उम्र में उनकी शादी के कारण किशोरियों/माताओं में खून की कमी और प्रसव के दौरान बड़ी संख्या में मौत की घटनाएं होती हैं। अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी अब भी कम बनी हुई है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा भी चिंता का विषय है। इस संदर्भ में महिलाओं और उनके अधिकारों की स्थिति और परिवर्तन लाने के उपायों के बारे में वर्ष भर गतिविधियां आयोजित की गईं। ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए गए जो महिलाओं और बालिकाओं में आत्मविश्वास और संघर्ष की क्षमता पैदा कर सकें और सामाजिक बदलाव लाने में मदद कर सकें।

आकाशवाणी पर एड्स/एचआईवी कार्यक्रम

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय रति जन्य रोगों/यौन संचरित संक्रमणों और एचआईवी/एड्स संक्रमण की समस्याओं, उनका शीघ्र पता लगाने और तत्काल उपचार करने संबंधी सेवाओं के बारे में जागरूकता अभियान चलाता है।

एचआईवी/एड्स पर नियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका यह है कि यौन संचरित रोगों (एसटीडी) का तुरंत उपचार किया जाये। पुरुष और महिलाओं दोनों में एसटीडी और यौन-संक्रमणों के बारे में अज्ञानता अभी भी बनी हुई है। एसटीडी संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने में पुरुष अक्सर नीम-हकीमों का सहारा लेते हैं। कुछ मामलों में स्वयं उपचार किया जाने लगता है, जिसका नतीजा यह होता है कि औषधि के प्रति ही प्रतिरोध क्षमता विकसित हो जाती है और संक्रमण अधिक विकराल रूप में सामने आता है।

आकाशवाणी ने एड्स से बचाव के उपायों का व्यापक प्रचार किया। इन अभियानों के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का लाभ उठाया गया।

आकाशवाणी देश भर में अपने सभी केंद्रों के विस्तृत नेटवर्क के साथ अनेक भाषाओं और बोलियों में एचआईवी/एड्स के बारे में निरंतर कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। 1 दिसंबर 2006 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सभी आकाशवाणी केंद्रों के कार्यक्रम प्रमुखों को सलाह दी गई कि वे श्रोताओं को एड्स के घातक प्रभाव के बारे में शिक्षित और जागरूक बनाने के लिए पूर्ण प्रचार सहायता उपलब्ध कराएं।

आकाशवाणी केंद्रों ने आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष विचार-गोष्ठियों का आयोजन किया और विशेषज्ञों के साथ सवाल-जवाब, वार्ताओं तथा विचार-विमर्श के रूप में स्टूडियो आधारित कार्यक्रमों का

आयोजन भी किया। कुछ केन्द्रों ने एड्स संक्रमित व्यक्तियों के साथ इंटरव्यू आधारित कार्यक्रम भी आयोजित किए। कुछ केन्द्रों से सामान्य जन, ट्रक ड्राइवरों, श्रमिकों आदि के लिए लोक गीत धुनों पर आधारित संगीत कार्यक्रम भी प्रसारित किए गए। आकाशवाणी ने एचआईवी/एड्स संबंधी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए बहु-भाषी दृष्टिकोण अपनाया।

एड्स के घातक प्रभाव से समुचित जानकारी के आधार पर ही बचा जा सकता है। इसे देखते हुए हर वर्ष एड्स के बारे में अधिकतम कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं।

खेती और घर-परिवार (फार्म एंड होम)

ग्रामीण श्रोताओं के प्रति आकाशवाणी की वचनबद्धता 50 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। आकाशवाणी के सभी केंद्र ग्रामीण श्रोताओं के लिए खेती और घर-परिवार कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। वास्तव में कृषक समुदाय की रोजमर्रा की मौसमी जरूरतों के अनुसार विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। आकाशवाणी के 'फार्म एंड होम' कार्यक्रमों में अद्यतन प्रौद्योगिकी और कृषि उत्पादन संबंधी जानकारी को निरंतर शामिल किया जाता है। ये कार्यक्रम न केवल खेती के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं, बल्कि ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार के तौर-तरीकों के प्रति जागरूकता भी पैदा करते हैं। ये कार्यक्रम हर रोज सुबह, दोपहर और शाम के समय प्रसारित किए जाते हैं। 'फार्म एंड होम' की औसत अवधि हर रोज 60 से 100 मिनट के बीच है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं, बच्चों और युवाओं के लिए कार्यक्रम भी शामिल हैं।

आकाशवाणी की 'फार्म एंड होम' इकाइयां मिले-जुले कार्यक्रम प्रसारित करती हैं, जिनमें ग्रामीण विकास योजनाओं और विशुद्ध खेती संबंधी कार्यक्रम शामिल होते हैं। खेती के कार्यक्रमों में पशुपालन, मछली उद्योग और शुष्क तथा बंजर भूमि में खेती संबंधी गतिविधियां जैसे विषय शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत रोजगार योजनाओं, ऋण और प्रशिक्षण सुविधाओं, स्वच्छता, स्वास्थ्य और पोषाहार आदि विषयों की जानकारी दी जाती है।

आकाशवाणी भूमि और जल संरक्षण, स्थाई खेती, जैव प्रौद्योगिकी, फसलों में समन्वित कीट प्रबंधन, फसल बीमा योजनाएं, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है।

ये सभी कार्यक्रम विशेषज्ञों की सहायता से तैयार किए जाते हैं। आकाशवाणी कृषि और ग्रामीण विकास से संबद्ध केंद्र एवं राज्य सरकारों के मंत्रालयों तथा विभागों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखती है। विभिन्न केन्द्रों से स्थानीय बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। स्थानीय रेडियो केंद्र ग्रामीण विकास के बारे में नियमित रूप से कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। इनमें संवाद, विचार-विमर्श, वार्ताएं, इंटरव्यू, फीचर, धारावाहिक, नाटक, स्लोगन, जिंगल्स, फोन-इन-प्रोग्राम, संगीत रूपक और फॉर्म स्कूल शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल संदेश प्रसारित करने के लिए किया जाता है।

आकाशवाणी ने 15 फरवरी 2004 से कृषि मंत्रालय के सहयोग से किसान वाणी के रूप में कृषि विस्तार के लिए जन संचार माध्यम सहायता परियोजना शुरू करके कृषि प्रसारण के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरूआत की है। इसका उद्देश्य स्थानीय किसानों को रोज के बाजार भावों, मौसम रिपोर्ट और निचले स्तर पर रोजमर्रा की गतिविधियों की जानकारी प्रदान करना है। फिलहाल किसान वाणी का प्रसारण और रिले आकाशवाणी के 96 एफएम स्टेशनों से किया जा रहा है।

पर्यावरण के बारे में कार्यक्रमों का प्रसारण

पर्यावरण के महत्व को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी के सभी केंद्र हर रोज 5 से 7 मिनट की अवधि का कार्यक्रम प्रसारित करते है। इस बारे में बड़ी अवधि का एक साप्ताहिक कार्यक्रम भी प्रसारित किया जाता है। यह प्रसारण एक दशक से भी अधिक समय से किया जा रहा है। स्वास्थ्य/महिलाओं/ग्रामीण महिलाओं/युवाओं और बच्चों से संबंधित अन्य कार्यक्रमों में भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने पर बल दिया जाता है। आकाशवाणी केंद्र इस विषय पर निदेशालय द्वारा जारी अनुदेशों और दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में श्रोताओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक और शिक्षित बनाने और इनमें वनों, वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी आदि के विकास के जरिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदना पैदा करने के प्रयास किए जाते हैं। ये कार्यक्रम रोचक और कलात्मक ढंग से तैयार किए जाते हैं। आकाशवाणी के सभी केंद्रों द्वारा स्थानीय भाषाओं में वार्ताओं, विचार-विमर्श, फीचर, समाचार, स्पॉट्स, धारावाहिक आदि विविध रूपों में कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं। आकाशवाणी केंद्रों को समय-समय पर सलाह दी जाती है कि वे अपनी भावी योजनाओं में पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों को समुचित स्थान दें।

केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा पर्यावरण और वन विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं के बारे में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। आकाशवाणी ने पर्यावरण, वानिकी, वन्य जीवन और पारिस्थितिकी विषयों पर कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए बहु-भाषी दृष्टिकोण अपनाया है। ये कार्यक्रम प्रमुख भाषाओं और विभिन्न छोटे समुदायों द्वारा बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों में प्रसारित

किए जाते हैं।

वन्य जीवन और वन संरक्षण के महत्व को देखते हुए आकाशवाणी ने इन विषयों को चुनौती के रूप में लिया है और संबंधित कार्यक्रमों में विकासात्मक और सामाजिक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। आकाशवाणी वानिकी, वन्य संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन की दिशा में किए गए सरकारी प्रयासों की सफलता को उजागर करती है। वास्तव में आकाशवाणी अपने विशेष श्रोता कार्यक्रमों के जरिए वन्य जीवों और पशुओं की देखभाल का संदेश प्रसारित करता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कुछ विशेष कार्यक्रम तैयार एवं प्रसारित किए गए। कुछ केंद्रों से 'वसुंधरा' नाम का एक दैनिक कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है।

ग्रामीण/महिला/ग्रामीण महिला और युवा स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे कुछ विशेष श्रोता कार्यक्रमों में आकाशवाणी ने श्रोता समूहों को पंजीकृत किया है। ये समूह आमंत्रित श्रोता कार्यक्रमों के दौरान समान्य जागरूकता के प्रसार में योगदान कर सकते हैं।

आकाशवाणी के सभी केंद्र पर्यावरण वानिकी से संबंधित कानूनी पहलुओं का व्यापक विचार करते हैं। सभी केन्द्रों से मासिक जानकारी मांगी जाती है ताकि इन कार्यक्रमों पर निगरानी रखी जा सके।

कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम)

इतिहास

कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान एसटीआई (पी) की स्थापना 1948 में आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली के संबद्ध कार्यालय के रूप में दिल्ली में की गई थी। 1 जनवरी 1990 से अधीनस्थ कार्यालय घोषित किया गया। कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम) दिल्ली और भुवनेश्वर अपने पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों (कार्यक्रम)- अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, शिलांग और तिरुअंनन्तपुरम के साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम एवं प्रशासनिक संवर्गों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देता है।

अप्रैल 2006 से अक्टूबर 2006 के दौरान उपलब्धियां

इस वर्ष विभागीय प्रशिक्षण की संभावना वाले क्षेत्रों में परिवर्तित तकनीकों का प्रबंधन, विपणन प्रबंधन, कॉर्पोरेट कार्य संस्कृति, डिजिटल प्रसारण, प्रस्तुतीकरण की आधुनिक तकनीकें, ध्वनि संस्कृति, प्रसारण प्रबंधन, मौलिक कार्यक्रम, प्रोग्राम पैकेजिंग और प्रोत्साहन, वार्तालाप और भागीदारीपूर्ण कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम और रेडियो जॉकिइंग शामिल थे।

एसटीआई (पी) ने बाहरी एजेंसियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षक के रूप में अपने को स्थापित किया है। यह संस्थान इग्नू और इंडियन एयरलाइन्स को क्रमश: कार्यक्रम निर्माण और साइंस कल्चर प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त प्रसारण, पत्रकारिता की शिक्षा देने वाले मान्यता प्राप्त संस्थानों और विश्वविद्यालयों को भी व्यावसायिक सहायता प्रदान की जा सकती है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के लिए कार्यक्रम प्रारूपों के बारे में विशेष पाठ्यरूप तैयार किए गए।

विभागीय पाठ्यक्रम

एसटीआई (पी), दिल्ली और एसटीआई(पी), भुवनेश्वर ने अपने पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों-अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, शिलांग और तिरुअनंतपुरम के साथ मिलकर 49 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया। इनमें 36 कार्यक्रम पाठ्यक्रम और 13 प्रशासनिक पाठ्यक्रम शामिल थे। कुल मिलाकर 863 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें आकाशवाणी के 625 प्रोग्रामर और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के 238 प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। इन कार्यक्रमों में निम्नांकित गतिविधियां शामिल रहीं:

- दिल्ली, भुवनेश्वर और शिलांग में 'सूचना का अधिकार अधिनियम' के बारे में 4 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें प्रोग्राम और इंजीनियरी से संबद्ध वरिष्ठ ग्रेड के 130 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।
- दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद में वाणी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 'प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण' के लिए 3 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 56 कार्यक्रम कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया।
- आईआईपीए, दिल्ली के सहयोग से 'अनिवार्य व्यावहारिक कौशल' के बारे में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिनमें कार्यक्रम और इंजीनियरी से संबद्ध 19 वरिष्ठ स्तरीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
- केन्द्र निदेशकों और सहायक केन्द्र निदेशकों के लिए 'तनाव प्रबंधन' के बारे में एसटीआई (पी), दिल्ली में एक कार्यशाला आयोजित की गई।
- पहली बार दूरदर्शन के कार्यक्रम कार्मिकों के लिए 2 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया 'प्रोमोज़ एंड प्रोग्राम पैकेजिंग' का एसआईआई (पी), भुवनेश्वर और 'क्रास चैनल पब्लिसिटी एंड प्रोग्राम पैकेजिंग' का आरटीआई (पी), हैदराबाद में आयोजन किया गया। इनमें दूरदर्शन में 21 कार्यक्रम अधिशासियों

और निर्माण सहायकों को प्रशिक्षत किया गया।

- एसटीआई (पी), दिल्ली को यूनेस्को द्वारा एजुकेशनल टीवी एंड रेडियो, काबुल, अफगानिस्तान के कार्यक्रम निर्माताओं को प्रशिक्षण देने के लिए चुना गया। इसके लिए 8 दिन का एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया और 18 से 25 सितंबर 2006 के बीच कार्यान्वित किया गया। इस पाठ्यक्रम का शीर्षक था—शैक्षिक चैनल की आयोजना का प्रबंधन।

प्रशिक्षण संस्थान वर्ष के दौरान आकाशवाणी के कार्यक्रम स्टाफ और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के प्रशासनिक स्टाफ के लिए औसतन 70 से 75 पाठ्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिनमें करीब 1100-1200 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाता है।

समन्वित पाठ्यक्रम

अप्रैल से दिसंबर 2006 की अवधि में एसटीआई (पी), दिल्ली में कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), आकाशवाणी और दूरदर्शन, दिल्ली के समन्वय से हार्ड डिस्क आधारित रिकॉर्ड प्रणाली, कार्यक्रम निर्माण तकनीकों और डिजिटल प्रोग्राम लाइब्रेरी जैसे विषयों पर आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिकारियों के लिए 6 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया। इन विशेषज्ञता क्षेत्रों में आकाशवाणी के 73 कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

वाणी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

नव-नियुक्त सूत्रधारों (एंकर्स) उद्घोषकों और प्रस्तुतकर्ताओं के लिए वाणी (वॉइस आरटिकुलेशन एंड नर्चरिंग इनिशिएटिव) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों द्वारा भुगतान आधार पर संचालित किए जाते हैं। दिसंबर 2006 तक करीब 1179 नव नियुक्त सूत्रधारों, उद्घोषकों और प्रस्तुतकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। इसके लिए आकाशवाणी के 50 केंद्रों पर 65 बैचों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई और वाणी प्रमाणपत्र दिए गए।

इस वर्ष से वाणी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का विस्तार मौजूदा कैजुअल उद्घोषकों और समाचार वाचकों और समाचार वाचक एवं अनुवादकों, संपादकों और रिपोर्टरों के लिए भी रिफ्रेशर कोर्स के रूप में किया गया। समाचार सेवा प्रभाग ने इस वर्ष से अंशकालिक संवाददाताओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शुरू किया है।

'वाणी' नामक पुस्तिका पूरक सामग्री के रूप में वाणी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों के लिए मददगार साबित हुई है। विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों को इसकी बिक्री करके प्रसार भारती के लिए राजस्व अर्जित किया गया।

बाहरी पाठ्यक्रम

- अप्रैल 2006 से दिसंबर 2006 की अवधि में एसटीआई (पी). दिल्ली ने इंडियन एयरलाइन्स के लिए 6 कार्यशालाओं का आयोजन किया और 142 विमान परिचारिकाओं और केबिन कर्मचारियों को आरटीआई (पी), हैदराबाद वॉइस कल्चर का प्रशिक्षण प्रदान किया। इस तरह की कई और कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना है।

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के साथ समझौते के अनुसार प्रसार भारती रेडियो प्रसारण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और श्रव्य कार्यक्रम निर्माण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इसी वर्ष आकाशवाणी के 7 केन्द्रों पर 12 बैंचों में 186 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

- इसके अतिरिक्त, आकाशवाणी के कई केंद्रों ने प्रति प्रशिक्षार्थी 500/- रुपये प्रति सप्ताह शुल्क पर विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया।

- आरटीआई (पी), हैदराबाद ने जन संचार और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से संबद्ध मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के विद्यार्थियों के लिए 1 मई से 9 मई 2006 के दौरान 'रेडियो कार्यक्रम निर्माण' के बारे में 9 दिन के प्रशिक्षण का आयोजन किया।

अर्जित राजस्व

एसटीआई (पी) को अप्रैल से 15 दिसंबर 2006 की अवधि में सभी स्रोतों से 67,55,021 रुपये की आय हुई।

जनवरी-मार्च 2007 के दौरान योजनाबद्ध कार्यक्रम

कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (प्रशिक्षण) की जनवरी, 2007 से मार्च, 2007 की अवधि में योजनाबद्ध गतिविधियों संबंधी रिपोर्ट इस प्रकार है :

विभागीय पाठ्यक्रम

इस अवधि में सभी सात प्रशिक्षण संस्थानों ने 15-20 पाठ्यक्रम आयोजित करने और उनमें 300 से 400 कार्यक्रम तथा प्रशासनिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है।

बाहरी पाठ्यक्रम

1. जनवरी 2007 से मार्च 2007 की अवधि में इंडियन एयरलाइंस की 5-6 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने की योजना है,

एसटीआई (पी) और आरटीआई (पी) संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षार्थियों की संख्या

वर्ष 2005-06 के दौरान और अप्रैल-दिसंबर 2006 की अवधि में

संस्थान	कार्य निष्पादन	2005-06			अप्रैल-दिसंबर 2006 की अवधि में		
		कार्यक्रम	प्रशासनिक	कुल	कार्यक्रम	प्रशासनिक	कुल
एसटीआई(पी) दिल्ली	पाठ्यक्रमों की संख्या	9	2	11	10	1	11
	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	159	45	204	227	15	242
एसटीआई(पी) भुवनेश्वर	पाठ्यक्रमों की संख्या	8	4	12	7	2	9
	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	88	92	180	97	35	132
आरटीआई (पी) अहमदाबाद	पाठ्यक्रमों की संख्या	4	3	7	4	3	7
	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	61	56	117	70	60	130
आरटीआई (पी) हैदराबाद	पाठ्यक्रमों की संख्या	5	2	7	5	2	7
	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	75	54	129	76	42	118
आरटीआई (पी) लखनऊ	पाठ्यक्रमों की संख्या	7	3	10	4	2	6
	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	96	50	146	60	36	96
आरटीआई (पी) शिलांग	पाठ्यक्रमों की संख्या	3	1	4	2	2	4
	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	33	10	43	25	35	60
आरटीआई (पी) त्रिवेंद्रम	पाठ्यक्रमों की संख्या	6	2	8	4	1	5
	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	113	49	162	70	15	85
कुल योग	पाठ्यक्रमों की संख्या	42	17	59	36	13	49
	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	625	356	981	625	238	863

एसटीआई (पी) और आरटीआई (पी) संस्थानों द्वारा आयोजित विभागीय पाठ्यक्रम

		वर्ष 2005-06	वर्ष 2006 अप्रैल-दिसंबर
सभी एसटीआई (पी), और आरटीआई (पी) संस्थानों द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए	पाठ्यक्रमों की संख्या	59	49
	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	981	863
बाहरी एजेंसियों के लिए भुगतान आधारित पाठ्यक्रम			
इंडियन एयरलाईंस	पाठ्यक्रमों की संख्या	3	6
	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	80	142
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)	पाठ्यक्रमों की संख्या	20	12
	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	351	186
वाणी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रमों की संख्या	81	65
	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	1386	1179
अंतराष्ट्रीय पाठ्यक्रम : आकाशवाणी-युनेस्को	पाठ्यक्रमों की संख्या	0	1
	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	0	3
निम्नांकित के साथ समन्वय से : एसटीआई (टी) दिल्ली	पाठ्यक्रमों की संख्या	15	6
	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	135	73

एसटीआई (पी) दिल्ली द्वारा बाहरी एजेंसियों के लिए भुगतान आधारित पाठ्यक्रम

		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (अप्रैल-दिसंबर)
इंडियन एयरलाइंस	पाठ्यक्रमों की संख्या	2	6	10	3	6
	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	33	135	258	80	142
दूरदर्शन	पाठ्यक्रमों की संख्या	0	1	0	0	0
	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	0	12	0	0	0
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	पाठ्यक्रमों की संख्या	0	0	3	0	0
	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	0	0	30	0	0
इग्नू	पाठ्यक्रमों की संख्या	0	0	55	20	12
	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	0	0	996	351	186
वाणी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रमों की संख्या	0	3	66	81	65
	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	0	52	1185	1386	1179

एसटीआई (पी) संस्थानों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम

		दिल्ली	भुवनेश्वर	दिल्ली		
		2002-03	2003-04	2004-05	2005/06	2006...
एआईबीडी/युनेस्को	पाठ्यक्रमों की संख्या	1	1	2	0	1
	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	13	11	34	0	3

एसटीआई (टी) दिल्ली द्वारा समन्वित पाठ्यक्रम

		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006...
एसटीआई (टी) दिल्ली	पाठ्यक्रमों की संख्या	4	4	7	15	6
	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	18	35	43	135	73

जिनमें 150 केबिन कर्मचारियों को वॉइस कल्चर यानी का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस अवधि में आकाशवाणी के कैजुअल उद्घोषकों और मूत्रधारों, समाचार कार्मिकों से संबद्ध वाषी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के अंतर्गत नए चुने हुए कैसुअल उद्घोषकों/सूत्रधारों और कैजुअल समाचार वाचकों तथा अंशकालिक संवाददाताओं को प्रशिक्षत करने की योजना है।

भावी योजनाएं

कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम) अब अन्य सेवा उद्योगों के लिए वॉइस कल्चर में अपनी विशेषज्ञता की संभावनाओं का पता लगा रहा है।

2. इस अवधि में आकाशवाणी के कैजुअल उद्घोषकों और सूत्रधारों, समाचार कार्मिकों से संबद्ध वाणी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के अंतर्गत नये चुने हुए कैजुअल उद्घोषकों/सूत्रधारों और कैजुअल समाचार वाचकों तथा अंशकालिक संवाददाताओं को प्रशिक्षित करने की योजना है।

भावी योजनाएं

कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम) अब अन्य सेवा उद्योगों के लिए वॉइस कल्चर में अपनी विशेषज्ञता के विस्तार की संभावनाओं का पता लगा रहा है।

ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल)

संक्षिप्त परिचय

बीईसीआईएल की स्थापना भारत सरकार ने 1995 में की थी। यह प्रसारण इंजीनियरी के क्षेत्र में प्रमुख परामर्श और सभी प्रकार की खराबियों को दूर करने वाली एजेंसी है।

1989 में खाड़ी युद्ध के बाद प्रसारण क्षेत्र के मुक्त होने के बाद अधिकाधिक उपग्रह चैनलों ने भारत में अपने कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू किया। 1991-92 तक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, कि भारतीय कंपनियां भी उपग्रह के जरिए प्रसारण करने की आवश्यकता महसूस करने लगीं। इन कंपनियों को प्रसारण के क्षेत्र में सलाह लेने के लिए एक एजेंसी की जरूरत महसूस हुई। उस समय सिर्फ आकाशवाणी और दूरदर्शन के पास ऐसी विशेषज्ञता थी। तब भारत सरकार ने ऐसी एक एजेंसी बनाने का निर्णय लिया और इस प्रकार बीईसीआईएल की स्थापना की गई।

बीईसीआईएल उपग्रह प्रसारण, एमएमडीएस, सीएटीवी नेटवर्क, डाटा प्रसारण और एकोस्टिक्स और आडियो-वीडियो प्रणालियों समेत स्टूडियो के विशिष्ट क्षेत्रों में संचालन संबंधी सभी कार्यों सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सलाहकार सेवाएं उपलब्ध कराती है।

बीईसीआईएल सभी प्रकार की प्रसारण प्रणालियों को चलाने और उनके रखरखाव का काम भी करती है। कंपनी के पास विभागीय विशेषज्ञता का भंडार है और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन समेत विशेषज्ञों का एक व्यापक समूह है। बीईसीआईएल अद्यतन प्रौद्योगिकी की जानकारी प्राप्त करते हुए अपने कौशल स्तर में निरंतर सुधार कर रही है।

प्रसारण प्रणालियों की परियोजनाओं को चलाने और रखरखाव करने के अलावा बीईसीआईएल सभी प्रकार के प्रसारण प्रोजेक्ट को विकसित करने और चलाने के लिए भारत और विदेश में ग्राहकों को तकनीकी विशेषज्ञ, इंजीनियर और अन्य विशेषज्ञ भी उपयुक्त शर्तों पर मुहैया कराती है।

बीईसीआईएल प्रत्येक ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीले और ग्राहक की विशेष ज़रूरत के अनुरूप समाधान प्रदान करती है। यह प्रत्येक परियोजना को समय पर, कारगर ढंग से और उचित लागत के साथ पूरा करने के लिए पेशेवर तथा पूर्ण गुणवत्ता-आधारित दृष्टिकोण अपनाने पर बल देती है और उसकी निरंतर समीक्षा और निगरानी करती है।

इसी कार्यशैली की वजह से कंपनी ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सफल रही है। ऐसा करके उसने न केवल विश्वसनीयता को कायम रखा है, अलबत्ता वह सरकार का एक लाभकारी उपक्रम भी बन गयी है। बीईसीआईएल ने इस वर्ष सरकार को 20% लाभांश दिया है।

प्रबंधन और संगठन

दीर्घावधि के लिए निर्णय करने और आयोजना के लिए कंपनी का एक निदेशक मंडल है। रोजमर्रा के कार्यों का संचालन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (संचालन एवं विपणन) द्वारा किया जाता है। निदेशक मंडल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक (संचालन एवं विपणन) और सरकार द्वारा नामित चार से सात अंशकालिक निदेशक होते हैं। फिलहाल इस मंडल में सरकार द्वारा नामित दो निदेशक हैं। निदेशक मंडल से नीचे दो पद संयुक्त महाप्रबंधक और प्रबंधक (विपणन), उप प्रबंधक (वित्त) और कनिष्ठ प्रबंधक (वित्त) के एक-एक पद हैं। कंपनी तकनीकी कार्यों में मदद के लिए अनुबंध के आधार पर सलाहकार तथा परियोजना प्रबंधकों की नियुक्ति करती है। इसके अतिरिक्त बीईसीआईएल के पास स्वयं के विशेषज्ञ और

बी ई सी आई एल की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र.स.	देयताएं	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	शेयर पूंजी	136.50	136.50	136.50	136.50	136.50
2	आरक्षी और अधिशेष	227.89	287.10	364.80	464.02	572.03
3	ऋण कोश	4.00	8.95	268.44	503.48	-
4	चालू देयताएं और प्रावधान	757.54	1187.18	1022.81	1560.04	5513.27
	योग :	**1125.93**	**1619.73**	**1792.55**	**2644.04**	**6221.80**
	परिसंपत्तियां					
5	स्थायी परिसंपत्तियां	38.08	33.40	96.41	122.56	167.76
6	पूंजी कार्य में प्रगति	-	-	-	1.12	13.48
7	चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	1087.53	1585.15	1688.33	2530.44	6014.46
8	विविध खर्च	0.32	1.18	7.81	9.92	26.10
	योग :	**1125.93**	**1619.73**	**1792.56**	**2664.05**	**6221.80**

(लाख रुपये में)

क्र.स.	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	बिक्री	818.76	770.33	808.77	2990.59	2440.00
2	परामर्श एवं अनुबंध आय	397.33	284.55	314.45	584.07	529.70
3	अन्य आय	20.61	54.52	55.55	47.99	39.62
4	जमा कार्य (डिपोजिट वर्क) का मूल्य	128.74	645.71	504.87	150.67	143.07
5	**जमा कार्य सहित कुल योग : आय**	**1,365.44**	**1,755.11**	**1683.64**	**3773.32**	**3152.40**
6	खर्च	1,220.14	1,599.06	1510.45	3572.06	2924.44
7	कर पूर्व लाभ	145.30	156.05	173.19	201.24	227.95
8	आयकर	56.55	59.08	70.50	73.58	93.68
9	कर उपरांत लाभ	88.19	90.00	108.61	130.14	140.67
10	लाभांश कर सहित लाभांश	27.30	30.80	30.86	30.86	31.12
11	अग्रिम प्राप्तियां	60.89	59.20	77.75	99.28	108.00

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुटाए गए विशेषज्ञों का समूह है।

शेयर पूंजी

बीईसीआईएल की स्थापना 250 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ की गई थी। इसकी चुकता पूंजी 1995-96 में 25 लाख रुपये थी जो अब बढ़कर 136.5 लाख रुपये हो गयी है। फिलहाल इक्विटी शेयर पूंजी में भारत सरकार की हिस्सेदारी शत-प्रतिशत है। शुरू में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कंपनी को व्यापार के लिए ऋण प्रदान किया था, जिसे उसने समय पर चुकता कर दिया। बीईसीआईएल को सरकार से कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती। परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था कंपनी स्वयं के संसाधनों या बैंक से प्राप्त अल्पावधि ऋण के जरिए करती है।

वित्तीय स्थिति

बीईसीआईएल ने 24 मार्च 1995 को स्थापना के बाद से सार्वजनिक और निजी प्रसारणकर्ताओं और एजेंसियों के लिए भारत और विदेश में काम करके उल्लेखनीय प्रगति की है। अस्तित्व में आने के समय से ही कंपनी सरकार को लाभांश दे रही है। पिछले पांच वर्षों में कंपनी की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा पिछले पृष्ठ पर दिया गया है।

इस अवधि में कर पूर्व लाभ पिछले वर्ष के 201.24 लाख रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2005-06 में 227.95 लाख रुपये हो गया। इस प्रकार इसमें 13.33 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। जमा कार्य सहित व्यापार कारोबार में कमी के बावजूद लाभ में बढ़ोतरी हुई। इस दौरान कारोबार 3773.61 लाख रुपये से घटकर 3152.39 लाख रुपये का हुआ। परंतु, संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल और परामर्श आय में वृद्धि के कारण मुनाफे में बढ़ोतरी हुई। परामर्श आय पिछले वर्ष की 336.34 लाख रुपये से बढ़कर 523.20 लाख रुपये हो गई। इस प्रकार परामर्श आय में पिछले वर्ष की तुलना में 42.82 प्रतिशत का इजाफा हुआ।

व्यवसाय प्रचालन और गतिविधियां

कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में निरंतर वृद्धि हो रही है, और यह रेडियो प्रसारण इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रमुख परामर्श एवं समाधान-प्रदाता कंपनी के रूप में पहले ही स्थापित हो चुकी है। निजी रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में 91 शहरों में 337 एफ.एम. चैनलों की स्थापना के साथ अपना विस्तार करते हुए कंपनी ने इस योजना के निर्माण और उस पर अमल करने में प्रमुख मददगार की भूमिका अदा की है। इसलिए यह संतोष की बात है कि (91 शहरों में 337 चैनलों के लिए) मूलभूत सुविधाओं का ढांचा कायम करने का काम बीईसीआईएल को सौंपा गया है।

रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में उपलब्धियों के साथ साथ कंपनी टेलीविजन की भी अनेक प्रतिष्ठित परियोजनाओं में संलग्न है। इनमें लोकसभा टीवी चैनल और राष्ट्रपति भवन के लिए मल्टीमीडिया स्टूडियो की स्थापना शामिल है।

क) वर्ष के दौरान संचालित गतिविधियां

i) रेडियो प्रसारण

क) ट्रांसमिशन सुविधाएं

वर्ष के दौरान भारत सरकार ने 91 शहरों में 337 एफएम चैनल निजी प्रसारणकर्ताओं को सौंपे। इन चैनलों में से 87 शहरों में 243 एफएम चैनलों के लिए आशय पत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं। शेष 94 चैनलों के लिए पुन: नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। बीईसीआईएल ने निजी एफ एम प्रसारणकर्ताओं के लिए नीति तय करने और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को तकनीकी जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कंपनी ने साझा एफ एम ट्रांसमिशन ढांचा स्थापित करने का प्रतिष्ठित कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस कार्य में तीन महानगरों, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में बड़ी संख्या में प्रसारणकर्ताओं को शामिल किया गया है। पहले चरण में बीईसीआईएल के कार्य निष्पादन पर विचार करते हुए कंपनी को सभी 91 शहरों में साझा ट्रांसमिशन ढांचा कायम करने का काम सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त कंपनी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पांच शहरों में प्राइवेट एफ एम प्रसारण के लिए एफ एम टॉवर बनाने का ऑर्डर भी मिला है। बीईसीआईएल रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में बड़ी कंपनी के रूप में उभरी है।

ii) टेलीविजन प्रसारण

कंपनी ने टेलीविजन प्रसारण के क्षेत्र में भी अनेक परियोजनाएं शुरू की हैं। वर्ष के दौरान कंपनी को राष्ट्रपति भवन के लिए मल्टीमीडिया टीवी स्टूडियो और लोकसभा सचिवालय के लिए लोकसभा टीवी चैनल की स्थापना के प्रतिष्ठित अनुबंध के लिए ऑर्डर प्राप्त हुआ। बीईसीआईएल ने सरकारी संगठन के लिए टीवी स्टूडियो बनाने का ऑर्डर भी प्राप्त किया है। कंपनी ने मलयालम मनोरमा के लिए तीन चैनल शुरू करने का कार्य भी प्रारंभ किया है।

iii) विदेश व्यापार

कंपनी की प्रबंधन समिति विदेश व्यापार के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। वर्ष के दौरान बीईसीआईएल ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक कंपनी के लिए टेलीविजन स्टूडियो कायम

किया। इसके अतिरिक्त बीईसीआईएल विदेश मंत्रालय के लिए काबुल में तीन परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है। काबुल में सूचना व्यवस्था बहाल/सुदृढ़ करने और अफगानिस्तान के जलालाबाद और नांघर प्रांतों में टेलीविजन हार्डवेयर बहाल/संवर्द्धित करने सम्बन्धी पहली दो परियोजनाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। तीसरी परियोजना पर काम जारी है। यह परियोजना अफगानिस्तान में टीवी कवरेज बढ़ाने से सम्बन्धित है, जो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलाई जा रही है। इसके शीघ्र पूरा हो जाने की संभावना है।

iv) पूर्वोत्तर राज्यों में केबल हेड एंड की स्थापना

कंपनी को देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के दुर्गम भूभाग में 160 केबल हेड एंड्स स्थापित करने का काम सौंपा गया। यह परियोजना पूरी हो चुकी है।

v) प्रसारण उपकरणों की आपूर्ति

वर्ष के दौरान प्रसारण उपकरणों की आपूर्ति प्रमुख व्यापारिक गतिविधि बनी रही। कंपनी ने करोड़ों रुपये मूल्य के ऑर्डर प्राप्त किए और विभिन्न संगठनों तथा सरकारी विभागों को उपकरणों की आपूर्ति की।

vi) अन्य गतिविधियां

परिचालन और रख-रखाव कंपनी के संचालन का प्रमुख क्षेत्र बना रहा। कंपनी दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों को कार्मिक उपलब्ध करा रही है। प्रसारण संगठनों को कार्मिक उपलब्ध कराने के अलावा कंपनी विभिन्न प्रसारण प्रणालियों के परिचालन और रख-रखाव में संलग्न है।

ख) भावी व्यापारिक संचालन और गतिविधियां

बीईएसएल ने अपनी गतिविधियों में कई गुणा बढ़ोतरी की है। अकेले एफ एम रेडियो क्षेत्र में 87 शहरों में 243 चैनलों की स्थापना के लिए साझा ट्रांसमिशन ढांचा कायम करने के लिए कंपनी को 183 करोड़ रुपये के आर्डर मिले हैं। 94 चैनलों की पुनः नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये सभी कार्य पूरे साल कंपनी को व्यस्त रखेंगे।

साझा ट्रांसमिशन ढांचों के अतिरिक्त कंपनी एफएम चैनलों के लिए स्टूडियो प्रणालियों की स्थापना में भी योगदान कर रही है। कंपनी देश के भीतर और बाहर टेलीविजन स्टूडियो कायम करने के लिए समझौतों की प्रक्रिया में है। कंपनी ने मीडियम वेव, शार्ट वेव और एफएम ट्रांसमीटरों और उनके स्टूडियो केंद्रों को शामिल करते हुए अफगानिस्तान में रेडियो कवरेज को दुरूस्त करने के लिए विदेश मंत्रालय के समक्ष 9,772 लाख रुपये का प्रस्ताव पेश किया है। अन्य विदेशी एजेंसियों के साथ भी बातचीत जारी है और उम्मीद है कि प्रस्तावों की मंजूरी के साथ कंपनी को और काम मिलेगा।

i) निजी एफएम प्रसारण

क) ट्रांसमिशन सुविधाएं

कंपनी 91 शहरों में साझा ट्रांसमिशन ढांचा स्थापित करने में जोर-शोर से लगी है। कार्य विशाल है, लेकिन इसकी प्रगति संतोषजनक है। 79 केंद्रों के लिए लंबी डिलिवरी उपकरणों के आर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं। साझा ट्रासंमिशन ढांचे के अतिरिक्त कंपनी 12 केंद्रों पर अंतरिम संस्थापना कार्य को भी अंजाम देगी।

ख) स्टूडियो केंद्र

कंपनी विभिन्न एफएम प्राइवेट प्रसारणकर्ताओं से संपर्क बनाए हुए है, और चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद में प्राइवेट एफएम स्टेशनों के लिए रेडियो सिटी के वास्ते स्टूडियो केंद्रों की स्थापना; जयपुर में सिनर्जी मीडिया और बंगलौर में इंडिगो एफएम की स्थापना के लिए पहले ही आर्डर प्राप्त कर चुकी है। फिलहाल 9 स्टूडियो केंद्रों के लिए बातचीत चल रही है।

ii) टेलीविजन प्रसारण

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कंपनी ने वर्ष के दौरान मलयालम मनोरमा के तीन चैनलों की स्थापना की है। कंपनी 'टाइम्स नाउ' चैनल के लिए परामर्शदाता भी रही है। उपग्रह आधारित टेलीविजन चैनलों की स्थापना का कार्य अब देश में लगभग पूरा हो चुका है। इसलिए कंपनी इस क्षेत्र में विदेशी बाजार की खोज कर रही है।

iii) सामुदायिक रेडियो केंद्र

सामुदायिक रेडियो केंद्रों की योजना ने देश में इसकी संभावनाओं के अनुरूप प्रगति नहीं की है लेकिन इस क्षेत्र में बीईसीआईएल की भागीदारी संतोषजनक रही है। कंपनी फिलहाल कोलकाता में सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में समुदाय रेडियो स्थापित करने के कार्य में संलग्न है।

iv) विदेश व्यापार

जैसा कि टेलीविजन प्रसारण के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, कंपनी इस क्षेत्र में विदेशों में बाजार तलाश रही है। कंपनी इथोपिया में टेली एजुकेशन स्टूडियो की स्थापना कर चुकी है और बंगलादेश में एक टीवी चैनल को परामर्श सेवाएं दे चुकी है। कंपनी अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में बाजार की खोज कर रही है।

कंपनी को उम्मीद है कि नाइजीरिया में टीवी चैनल की स्थापना में उसे सफलता मिलेगी।

कंपनी ने अफगानिस्तान में रेडियो सेवाओं को दुरूस्त करने का एक प्रस्ताव विदेश मंत्रालय के समक्ष पेश किया है। कंपनी को उम्मीद है कि वर्ष के दौरान इस पर काम शुरू हो जाएगा।

v) उपकरणों की आपूर्ति

कंपनी के लिए व्यापार के स्रोत के रूप में विभिन्न सरकारी संगठनों को उपकरणों की आपूर्ति जारी रहेगी।

vi) अन्य व्यापारिक गतिविधियां

कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के अन्य क्षेत्र इस प्रकार रहेंगे –

1) प्रसारण ढांचों का परिचालन और रखरखाव

2) विभिन्न संगठनों के लिए कार्मिकों की नियुक्ति

7. सतर्कता गतिविधियां

क. सतर्कता व्यवस्था का ब्योरा

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का एक छोटा प्रतिष्ठान है, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी। यह माल तैयार करने वाली एजेंसी नहीं है, जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है। इसका कार्य क्षेत्र केवल ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सलाह सेवा, टर्न की, डिपॉजिट वर्क और सेवाओं परियोजनाओं तक सीमित है। कंपनी के नियमित कर्मचारियों की संख्या केवल 13 है और ज्यादातर कर्मचारी अनुबंध आधार पर हैं। इसमें कोई विशिष्ट सतर्कता ढांचा नहीं है, लेकिन बीईसीआईएल के निदेशक (प्रचालन और विपणन) सतर्कता संबंधी कार्यों का भी निरीक्षण करते हैं।

i) बीईसीआईएल के आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा नियमित/सावधिक लेखा-परीक्षा।

ii) सीएजी द्वारा नियुक्त लेखा-परीक्षकों के जरिए कानूनी लेखा-परीक्षा।

iii) सीएजी की टीम के द्वारा पूरक लेखा-परीक्षा।

8. सामान्य

बीईसीआईएल का बजट खुले बाजार में प्रतियोगी टेंडर प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त सलाह सेवा और टर्न-की कामों के ऑर्डर्स के आधार पर आय और खर्च के बारे में उसके स्वयं के आंतरिक अनुमान पर आधारित होता है। बीईसीआईएल को सरकार से कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती और वह स्वयं अपने संसाधन जुटाती है।

बीईसीआईएल को कोई केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित स्कीम नहीं सौंपी गई है। तथापि, दूरदर्शन ने उसे 712 लाख रुपए की अनुमानित लागत का पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित) के 160 गांवों में केबल हेड एंड्स लगाने का काम सौंपा है।

5

फिल्म क्षेत्र

मुख्य सचिवालय

फिल्म क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित दो योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते का होना एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं।

1. योजनाएं

(i) **विदेशी समारोहों/बाजारों में भागीदारी :** इस योजना का उद्देश्य फिल्म उद्योग को तब तक सहारा देना है जब तक यह उद्योग अपने आप निर्यात-संवर्धन कर पायेंगे अथवा यह निर्णय ले पाने में समर्थ हो जाए कि कुछ बाजारों का दोहन करने में कोई लाभ नहीं है।

फिल्म बाजारों में भागीदारी का उद्देश्य भारतीय फिल्म उद्योग की उपस्थिति का एहसास कराना, फिल्मों से जुड़ी सूचना प्रौद्योगिकी से अवगत होना तथा उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाकर वास्तविक व्यापारिक गतिविधियां शुरू करना है। हालांकि केंस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह और बाजार, बर्लिन फिल्म समारोह और बाजार तथा अमेरिकन फिल्म समारोह आदि विशिष्ट संस्थागत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजार हैं, फिर भी सरकार का यह प्रयास रहा कि भारत में फिल्म बाजार आयोजित करने सहित भारतीय फिल्म उद्योग को आगे बढ़ाने के सभी प्रयास किए जाएं। फिल्म उद्योग की निरंतर प्रगति इस प्रयासों का अच्छा प्रमाण है।

(ii) **फिल्मों की गैर कानूनी नकल (पाइरेसी) रोकने में लगे गैर सरकारी संगठनों की मदद और फिल्म समारोहों के आयोजन में सहयोग :** इस योजना के तीन घटक इस प्रकार हैं :

(क) एफ.एफ.एस.आई. को अनुदान सहायता।

(ख) फिल्मों की गैर कानूनी नकल (पाइरेसी) रोकना।

(ग) राज्यों की मदद से आयोजित फिल्म समारोहों को सहायता देना।

एफ.एफ.एस.आई. करीब 250 फिल्म समितियों की शीर्ष संस्था है। देश में फिल्मों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और फिल्मों के क्षेत्र में दर्शकों की रूचि परिष्कृत करने के लिए एफ.एफ.एस.आई. को अनुदान सहायता दी जाती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस संस्था को 20 लाख रुपये मंजूर किए गए। वर्ष 2006-07 की योजना के लिए सारी रकम जारी कर दी गई है। कार्यक्रम के दूसरे घटक 'फिल्मों की गैर कानूनी नकल (पाइरेसी) रोकने में लगे गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता/फिल्म समारोहों का आयोजन' के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में 80 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है। वार्षिक परिव्यय 16 लाख रुपये का है। इस उप घटक की एक गतिविधि फिल्मों की गैर कानूनी नकल (पाइरेसी) रोकने से जुड़ी है। मंत्रालय ने पाइरेसी रोकने वाली एजेंसियों के लिए भारतीय जनसंचार संस्थान की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है।

2. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत सरकार ने 16 फरवरी 207 को फिल्मों के क्षेत्र में भारत-जर्मन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

फिल्म प्रभाग

परिचय

फिल्म प्रभाग का इतिहास स्वतंत्रता उपरांत भारत के घटनापूर्ण वर्षों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है और पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से भारतीय जनमानस को राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए अनुप्रेरित करता रहा है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रभाग के उद्देश्यों में लोगों को राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लागू करने के लिए शिक्षित और प्रेरित करना व देश की परंपरागत विरासत तथा छवि को देश-विदेश के सम्मुख प्रस्तुत करना है। इसके अलावा फिल्म प्रभाग देश में वृत्तचित्र आंदोलन को बढ़ावा देने का काम भी करता है।

यह प्रभाग मुंबई स्थित मुख्यालय से वृत्तचित्र, लघु फिल्में, एनीमेशन फिल्में और न्यूज मैगजीनें तैयार करता है। इसकी दिल्ली इकाई रक्षा और परिवाण कल्याण कार्यक्रम पर फिल्में बनाती हैं, जबकि कोलकाता और बंगलौर स्थित क्षेत्रीय निर्माण केंद्रों पर ग्रामीण दर्शकों के लिए लघु-कथा फिल्में बनाई जाती हैं। फिल्म प्रभाग देश भर के 12000 सिनेमाघरों, देश भर में फैली क्षेत्रीय

प्रचार निदेशालय की इकाइयों, दूरदर्शन, परिवार कल्याण मंत्रालय की क्षेत्रीय इकाइयों, शैक्षिक संस्थानों और स्वैच्छिक संगठनों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। राज्य सरकारों के वृत्तचित्र और न्यूज रीलों को भी प्रभाग प्रदर्शन के लिए जारी करता है। फिल्म प्रभाग वृत्तचित्रों और फीचर फिल्मों के प्रिंट, स्टॉक शाट, वीडियो कैसेट तथा वितरण अधिकार देश-विदेश में बेचता है। फिल्म-निर्माण के अलावा फिल्म प्रभाग निजी फिल्म निर्माताओं को अपने स्टूडियो, रिकॉर्डिंग थियेटर, संपादन कक्ष और अन्य सिनेमा उपकरण किराए पर देता है।

भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वृत्तचित्रों, लघु फिल्मों और ऐनीमेशन फिल्मों का मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (एमआईएफएफ) आयोजित करने का दायित्व फिल्म प्रभाग को सौंप रखा है। प्रभाग को काम-काज की दृष्टि से चार खंडों में बांटा गया है। यह हैं : (1) निर्माण, (2) वितरण, (3) अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु चित्र एवं ऐनीमेशन फिल्मोत्सव और (4) प्रशासन।

निर्माण खंड

निर्माण खंड (1) वृत्तचित्र (2) ग्रामीण दर्शकों के लिए लघु फीचर फिल्मों, (3) एनीमेशन फिल्मों और (4) वीडियो फिल्मों का निर्माण करता है। मुंबई में मुख्यालय के अलावा प्रभाग के तीन निर्माण-केन्द्र बंगलौर, कोलकाता और नई दिल्ली में हैं।

वृत्तचित्रों में विषयवस्तु की दृष्टि से कृषि से लेकर कला और वास्तु शिल्प तक, उद्योग से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तक, खान-पान से त्यौहारों तक, स्वास्थ्य सुविधाओं से आवास तक और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से खेल-कूद तक, व्यापार और वाणिज्य से परिवहन तक तथा आदिवासी कल्याण से लेकर सामुदायिक विकास आदि शामिल हैं।

आमतौर पर प्रभाग द्वारा बनाई जाने वाली फिल्मों में देश भर के स्वतंत्र फिल्मकारों के लिए 40 प्रतिशत फिल्में सुरक्षित रखी जाती हैं, ताकि वृत्तचित्र आंदोलन को बढ़ावा दिया जा सके। अपने सामान्य फिल्म निर्माण कार्य के अलावा फिल्म प्रभाग सरकारी विभागों और मंत्रालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को वृत्तचित्र निर्माण में सहायता देता है।

फिल्म प्रभाग का न्यूजरील खंड राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की राजधानियों सहित प्रमुख शहरों और कस्बों में फैले अपने नेटवर्क के जरिए, प्रमुख घटनाओं, अति विशिष्ट व्यक्तियों के देश-विदेश भ्रमण तथा प्राकृतिक आपदाओं आदि की कवरेज कराता है। इस कवरेज को पाक्षिक न्यूज मैग्जीनों और अभिलेखन सामग्री के संकलन में भी प्रयुक्त किया जाता है।

प्रभाग की कार्टून फिल्म इकाई में उच्च प्रौद्योगिकी अपनाई गई है। सेल अथवा क्लासिकल एनीमेशन की जगह कम्प्यूटर एनीमेशन ने ले ली है।

कमेंट्री अनुभाग अंग्रेजी और हिंदी में बनी फिल्मों और न्यूज मैग्जीनों का 14 भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में रूपांतरण तैयार करता है। प्रभाग की दिल्ली निर्माण इकाई रक्षा मंत्रालय और परिवार कल्याण विभाग और अन्य मंत्रालयों/विभागों के लिए प्रेरक फिल्में तैयार करती हैं। बदलते समय के अनुसार इस इकाई को अब वीडियो फिल्म बनाने की सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया गया है।

प्रभाग के कोलकाता और बंगलूर स्थित क्षेत्रीय केंद्रों ने सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों जैसे परिवार कल्याण, साम्प्रदायिक सद्भाव, दहेज, बंधुवा मजदूर, छुआ-छूत जैसे विषयों पर सामाजिक और शैक्षिक वृत्तचित्रों का निर्माण किया है।

वितरण खंड

फिल्म प्रभाग के वितरण खंड में एक शाखा कार्यालय के अंतर्गत करीब 1200 सिनेमाघर हैं। इस समय इसके दस शाखा कार्यालय बंगलूर, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ, चेन्नई, मदुरई, नागपुर, तिरुअनंतपुरम और विजयवाड़ा में हैं। 2006-07 में 30 नवंबर 2006 तक देश भर में हर सप्ताह 8610 सिनेमाघरों में कुल 5 से 6 करोड़ दर्शकों ने प्रभाग द्वारा जारी फिल्में देखीं।

फिल्म प्रभाग क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की इकाइयों और केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों तथा राज्य सरकारों को फिल्मों के प्रिंट और वीडियो कैसेट उपलब्ध कराता है। इसके वृत्तचित्र दूरदर्शन के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों पर दिखाए जाते हैं। देश भर के शिक्षा संस्थान, फिल्म समितियां और अन्य सामाजिक संगठन भी प्रभाग के वितरण कार्यालयों की लाइब्रेरी से फिल्में लेकर दिखाते हैं। प्रभाग ने 1 अप्रैल 2006 से 30 दिसंबर 2006 की अवधि में 31 वृत्तचित्र और 8 न्यूज मैग्जीन के कुल 9791 प्रिंट सिनेमाघरों के लिए जारी किए। इसके अलावा राज्य सरकारों के लिए 1 न्यूज मैग्जीन के 73 प्रिंट जारी किए गए। इस अवधि में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के लिए 16 फिल्मों के 4048 प्रिंट भी जारी किए गए। दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारण के लिए 33 फिल्में भेजी गईं। मुंबई में 5 संस्थानों और अन्य संगठनों को प्रदर्शन के लिए 14 फिल्मों के प्रिंट उधार दिए गए।

राज्य और आंचलिक फिल्म समारोहों का आयोजन

हालांकि वितरण खंड अपने अंचल में कभी-कभी फिल्म समारोह आयोजित करता रहा है, लेकिन वर्ष के दौरान शाखा कार्यालयों

के लिए महीने में एक आंचलिक फिल्म समारोह और फिल्म प्रभाग मुख्यालय द्वारा राज्य स्तरीय/अंतर्राष्ट्रीय समारोह का आयोजन एक नियमित गतिविधि बनाया गया। इस उपाय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण फिल्म समारोह नगालैंड में मनाया गया। इस उपाय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण फिल्म समारोह नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, गोवा और अन्य राज्यों में भी जल्दी ही ऐसे समारोह आयोजित करने की योजना बनाई जा रहा है। इसके अतिरिक्त फिल्म प्रभाग फिल्म समारोह आयोजित करने में स्वयंसेवी संगठनों, फिल्म समितियों, शिक्षा संस्थानों के साथ भी सहयोग करता है। आगामी वृत्तचित्र समारोह मुंबई विश्वविद्यालय के सहयोग से फरवरी 2007 में आयोजित किया गया है। यह आयोजन विश्वविद्यालय की 150वीं वर्षगांठ मनाने के सिलसिले में किया गया।

1.1.2007 से 31.3.2007 की अवधि में फिल्म प्रिंट जारी करने और लाइब्रेरी प्रिंट तैयार करने के लिए कार्यक्रम

1 जनवरी 2007 से 31 मार्च 2007 की अवधि में 7 वृत्तचित्रों और 6 न्यूज मैग्जीनों के 3290 प्रिंट और लाइब्रेरी फिल्मों के लिए 15 वृत्तचित्रों के 75 प्रिंट, और 10 न्यूज मैग्जीनों के 1600 वीएचएस/वीसीडीज़ जारी किए जाएंगे।

प्रभाग के वीडियो कैसेट रेलवे, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, शैक्षिक संस्थानों और अन्य लोगों को गैर-व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए बेचे जाते हैं। 1 अप्रैल 2006 से 31 दिसंबर 2006 की अवधि में देश में गैर-व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए 184-वीएचएस, 996 वीसीडीज़, 3 बीटा कैम कैसेट की बिक्री 1,45,909/- रुपये में की गई। इसी प्रकार विदेश में 49,549 रुपये के वीसीडी और फिल्मों के बीटा कैम कैसेट की बिक्री की गई। 11,08,656/- रुपये मूल्य के स्टॉक शॉट्स भी बेचे गये। इस अवधि में रॉयल्टी के रूप में 37,500/- रुपये अर्जित किए गए। इसी अवधि में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय को 1283 वीएचएस कैसेट और 1207 वीसीडी बेचे गए। इसके अलावा फिल्म प्रभाग की फिल्मों के, 9 वीसीडी सूचना और प्रसारण मंत्रालय और 8 वीसीडी डीएवीपी को भी भेजे गए।

विदेश मंत्रालय का बाह्य प्रचार प्रभाग फिल्म प्रभाग की चुनी हुई फिल्मों के प्रिंटों का वितरण विदेश स्थित भारतीय मिशनों में करता है। राष्ट्रीय फिल्म विकास लिमिटेड और प्राइवेट एजेंसियां भी प्रभाग की फिल्मों के अंतर्राष्ट्रीय वितरण की व्यवस्था करते हैं। फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित फिल्मों का वाणिज्यिक दोहन भी किया जाता है। इसके लिए विदेश के वीडियो और टीवी नेटवर्कों को रॉयल्टी के आधार पर फिल्में दी जाती हैं। वर्ष के दौरान 33 फिल्में प्रदर्शित किए जाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय दूरदर्शन केंद्रों को भेजी गई।

अंतराष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु और एनीमेशन फिल्म समारोह

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने फिल्म प्रभाग को वृत्तचित्र, लघु और एनीमेशन फिल्मों के मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। एमआईएफएफ प्रतियोगिता का उद्देश्य ज्ञान के बृहत्तर क्षेत्र में योगदान करने वाली फिल्मों का संप्रेषण करना और विश्व के देशों के बीच सुदृढ़ भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। यह समारोह विभिन्न देशों के फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों, वितरकों, प्रदर्शकों और फिल्म समीक्षकों को बेजोड़ अवसर और मंच उपलब्ध कराता है। वर्षों से एमआईएफएफ फिल्म निर्माताओं का पसंदीदा और बहु-प्रतीक्षित आयोजन बन गया है, जहां वे अपने फिल्म-निर्माताओं के पसंदीदा और बहु प्रतीक्षित कार्यक्रम बन गया है, जहां वे अपने कार्य का प्रदर्शन और विचारों का परस्पर आदान-प्रदान करते हैं। एमआईएफएफ का ऐतिहासिक सफर 1990 में शुरू हुआ और उसके बाद से यह आकार और प्रतिष्ठा की दृष्टि से वृत्तचित्र फिल्म आंदोलन के प्रमुख अंतराष्ट्रीय कार्यक्रमों में से एक बन चुका है। इस द्विवार्षिक फिल्मोत्सव में भारत और विश्व के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में प्रमुख वृत्तचित्र और लघु फिल्म निर्माता तथा बुद्धिजीवी और विद्यार्थी हिस्सा लेते हैं। समारोह के प्रत्येक संस्करण में करीब 35-40 देशों की 500 से अधिक प्रविष्टियां शामिल की जाती हैं। नौवां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (एमआईएफएफ) 3-9 फरवरी 2006 की अवधि में आयोजित किया गया। समारोह का आयोजन फिल्म प्रभाग ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया।

व्यापक जन समुदाय, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में समारोह का लाभ पहुंचाने की नीति के अंतर्गत फिल्म प्रभाग ने 2-6 दिसंबर 2006 की अवधि में कोहिमा में वृत्तचित्र, लघु और एनीमेशन फिल्मों के पहले कोहिमा अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन नागालैंड सरकार के सहयोग से किया। इसमें एमाईएफएफ की पुरस्कार विजेता फिल्मों, फिल्म प्रभाग की उत्कृष्ट पुरस्कार विजेता फिल्मों, नागालैंड और पूर्वोत्तर पर बनी फिल्मों सहित एनीमेशन फिल्में प्रदर्शित की गईं।

फिल्म प्रभाग की ऐसे ही फिल्म समारोह इसी वित्त वर्ष में मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश तथा मुंबई में आयोजित करने की योजना है।

प्रशासनिक खंड

प्रशासनिक खंड वित्त, कार्मिक, सामान्य साज-सामान, लेखा,

क्र.सं.	श्रेणी	कार्मिकों की स्वीकृति संख्या	कार्मिकों की वास्तविक संख्या
1.	समूह-क	44	23
2.	समूह-ख (राजपत्रित)	77	68
3.	समूह-ख (अराजपत्रित)	67	61
4.	समूह-ग	496	441
5.	समूह-घ	250	220
	कुल	934	813

सेवा में अजा और अजजा का प्रतिनिधित्व

पद समूह	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति कर्मचारी	अजा कर्मचारियों का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति (अजजा) कर्मचारी	अजजा कर्मचारियों का प्रतिशत	महिला कर्मचारी
समूह-क	23	6	2608%	1	4.34%	1
समूह-ख	129	29	22.48%	8	6.20%	12
समूह-ग	441	106	24.03%	24	5.44%	107
समूह-घ	220	92	41.81%	19	8.63%	25

प्रबंधन और सामान्य प्रशासन की व्यवस्था करता है। यह खंड वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करता है, जिसकी सहायता के लिए निम्नांकित अधिकारी होते हैं -

कार्मिक प्रबंधन, खरीद, सामान्य प्रशासन, सतर्कता और सुरक्षा मामलों की देख-रेख के लिए सहायक प्रशासनिक अधिकारी।

वित्त एवं लेखा संबंधी मामलों के लिए लेखाधिकारी और विभागीय वित्तीय सलाहकार।

31 मार्च 2006 को फिल्म प्रभाग में कार्मिकों की स्वीकृत और वास्तविक संख्या इस प्रकार थी :

सेवा में अजा, अजजा और अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) के उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व के बारे में सरकारी आदेश/निर्देशों का पालन समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाता है। फिल्म प्रभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार रोस्टर बनाए गए हैं।

हिंदी अनुभाग

हिंदी अनुभाग सरकारी पत्राचार में राजभाषा हिंदी के इस्तेमाल की देखरेख करता है।

सतर्कता गतिविधियां

सतर्कता/अनुशासन के मामलों पर निगरानी रखने के लिए एक सतर्कता प्रकोष्ठ कार्यरत है, जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की देखरेख में काम करता है। इसमें एक अधीक्षक, एक अपर श्रेणी लिपिक और एक अवर श्रेणी लिपिक है।

वर्ष 2006-07 के दौरान फिल्म प्रभाग की प्रमुख गतिविधियों की झलक (अप्रैल-नवंबर 2006 के दौरान)

- 24 वृत्तचित्र, लघु एवं ऐनिमेशन फिल्में (22 फिल्में विभागीय तौर पर और 2 फिल्में स्वतंत्र निर्माताओं के जरिए) और 7 न्यूज मैग्जीन बनाईं गयीं।
- 60 फिल्मों के साथ 6 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों, 28 फिल्मों के साथ 4 राष्ट्रीय फिल्म समारोहों और 270 फिल्मों के साथ 21 राज्य स्तरीय फिल्म समारोहों में हिस्सा लिया।
- थियेटरों के लिए 39 फिल्मों के 9791 प्रिंट जारी किए।
- सिनेमा प्रदर्शकों से किराये के रूप में 376.62 लाख रुपये राजस्व अर्जित किया।
- प्रिंट/कैसेट/वीसीडी/डीवीडी/बीटा/स्टॉक शॉट्स की बिक्री और रॉयल्टी आदि के जरिए 13,41,614/ - रु. का राजस्व अर्जित किया गया।
- किराया, प्रिंटों, स्टॉक शाट्स, वीडियो कैसेटों की बिक्री और अन्य साधनों से कुल राजस्व प्राप्ति 398.68 लाख रुपये की हुई।

कार्य निष्पादन

अप्रैल-नवंबर 2006 की अवधि में प्रभाग ने 24 वृत्तचित्र/ शार्ट फिक्सन/वीडियो फिल्में बनाईं। इनमें से 22 फिल्में विभागीय तौर पर और 2 फिल्में स्वतंत्र निर्माताओं के जरिए बनाईं गयीं।

इसके अतिरिक्त फिल्म प्रभाग ने अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की विदेश यात्राओं, महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बारे में सात न्यूज मैग्जीन बनाई और जारी कीं।

महिला अधिकारिता, सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, अस्पृश्यता निवारण, परिवार कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियानों को व्यापक प्रचार एवं संचार सहायता प्रदान की।

इस अवधि में निर्मित महत्वपूर्ण डाक्युमेंटरी फिल्में

1. ऑर्गेनिक फार्मिंग (जैव खेती)
2. मर्धन दा गिद्धा-संगरूर जिले के बारे में परंपरागत लोक नृत्य।
3. सलिल चौधुरी
4. इयर्स ऑफ साहित्य अकेडमी।
5. आदत-सड़क पर थूकने की प्रवृत्ति छोड़ने से संबंधित एनिमेशन फिल्म।
6. स्वयंवर-कन्या भ्रूण हत्या के बारे में कठपुतली फिल्म।
7. पानी-रे-पानी-जल संबंधी मुद्दों के बारे में फिल्म।
8. डागर ब्रदर्स
9. सिक्किम-पैराडाइज ऑन अर्थ
10 वाकिंग डेड फाइट फोर लाइफ
11 उगाडी
12. रसमंजरी-जम्मू कश्मीर के बारे में लघु संस्करण।
13. पार्लियामेंट लाइब्रेरी।
14 मंजिल दूर नहीं-लघु बचत को प्रोत्साहित करने वाली फिल्म।
15. देमाजोंग-ए यूनीक सेक्रेड लैंडस्केप ऑफ सिक्किम

फिल्म प्रभाग ने निम्नांकित व्यक्तियों के जीवन और कार्यों पर जीवनीपरक फिल्में :

1. डॉ. राममनोहर लोहिया
2. स्थपति
3. बी.आर. चोपड़ा

4. डागर ब्रदर्स

5. सलिल चौधुरी

निम्नांकित जीवनीपरक फिल्में निर्माणाधीन हैं :

1. पंडित रामनारायण

2. हुस्नलाल भागात्रम

3. स्वर्गीय श्री के आर नारायण – भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत सरकार

4. शंकरदेब – ए लाइफ लार्जर दैन फिल्म (असम के 15वीं सदी के महान संत शंकर देव पर एक फिल्म)

5. श्री गोपाल स्वरूप पाठक

6. सतगुरु राम सिंह जी और कूका आंदोलन।

7. मुबारक बेगम

8. नौशाद अली

9. राज्यश्री भाग्यचंद्र ऑफ मणिपुर

10. पंडित शिवकुमार शर्मा

वर्ष 2007-08 की अवधि में फिल्म प्रभाग निम्नांकित महत्वपूर्ण विषयों/विषयवस्तुओं पर फिल्मों का निर्माण जारी रखेगा :

1. साम्प्रदायिक सद्भाव

2. राष्ट्रीय एकता

3. नशाबंदी

4. परिवार कल्याण कार्यक्रम

5. पर्यावरण

6. कृषि

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

8. समसामयिक इतिहास

9. ग्रामीण विकास

10. समाज कल्याण

11. उद्योग

12 महिला एवं बाल कल्याण

13. महिला अधिकारिता

14. रक्षा

15. जीवनियों पर आधारित फिल्में

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भागीदारी

प्रभाग विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों पर हिस्सा लेता रहा है। अप्रैल से दिसंबर 2006 की अवधि में प्रभाग ने इन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में हिस्सा लिया।

सलिल चौधुरी, ऋषिकेश मुखर्जी, नौशाद, डागर, हंस अकेला, कटी पतंग, बीआर चोपड़ा, सत्पथी फिल्मों के दो प्रेस शो फिल्म प्रभाग परिसर, मुंबई में आयोजित किए गए।

दो सामान्य शो फिल्म प्रभाग के थियेटर में आयोजित किए गए।

उधार पर फिल्में

मुंबई में शैक्षिक प्रयोजन के लिए पांच संस्थानों और अन्य पार्टियों को 14 फिल्में उधार दी गयीं।

फिल्म प्रभाग में आगंतुक

चार कालेजों, स्कूलों और संस्थानों के 252 से अधिक विद्यार्थियों और उनके प्राध्यापकों ने फिल्म प्रभाग का दौरा किया।

आयोजित समारोह

फिल्म प्रभाग के वृत्तचित्रों के निम्नांकित समारोह आयोजित किए गए :

i) करीम नगर, हैदराबाद में वृत्तचित्र फिल्म समारोह

ii) विजयवाड़ा में नृत्य एवं संगीत समारोह

iii) कला भवन थियेटर, त्रिवेन्द्रम में वृत्तचित्र एवं लघु वीडियो फीचरों का दूसरा समारोह

iv) मदुरई में संगीत और नृत्य का फिल्म समारोह

v) मदुरई में एमआईएफएफ पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र, लघु और ऐनिमेशन फिल्म समारोह

vi) एनएमआरकेवी महिला कालेज, बंगलौर में संगीत और नृत्य फिल्मोत्सव।

vii) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड कल्चर, बंगलौर में संगीत और नृत्य फिल्मोत्सव।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शित फिल्म प्रभाग की चुनी हुई फिल्में :

भारतीय पैनोरमा–2006	डागर
	हंस अकेला
	कटी पतंग
	ऋषिकेश मुखर्जी
	बी.आर. हर दौर में नया दौर
	स्थपति
चौथा कल्पनिर्झर अंतर्राष्ट्रीय लघु कथा	इन द न्यूज
फिल्म समारोह 2006, कोलकाता	
प्रयोगात्मक सिनेमा–भारतीय प्रयोगात्मक फिल्म तथा	चाइल्ड ओन चेस बोर्ड एंड आई फिल्म एवं
वीडियो प्रदर्शनी	मेक शार्ट फिल्म्स
1913 से 2006	ट्रिप
	एक्सप्लोरर
11वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म समारोह	कलामंडलम गोपी
	यक्षगान
	गुरु चेंगन्नूर
	कृष्णाट्टम
	सिद्धेश्वरी
माउंटेन फिल्म समारोह, काठमांडू	एवरेस्ट
	कांगड़ा और कुल्लू
	सोंग्स ऑफ स्नो
	लम्बाता
इमेजेज फेस्टिवल, टोरंटो, कनाडा	चाइल्ड ओन चेसबोर्ड
	एंड आई मेक शार्ट फिल्म्स
	ट्रिप
	एक्सप्लोरर
	आबिद
	क्लेक्स्प्लोजन

प्रतियोगी खंड में चुनी गईं फिल्में :

प्रभाग की फिल्में

11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण फिल्म समारोह, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस	कोंकरिंग द डेजर्ट
11वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म समारोह	हंस अकेला
	सफर. . . भारतीय किसान की यात्रा

विशेष प्रदर्शन/शो

विकास विद्यालय, दादर मुंबई	17 वृत्तचित्र, लघु एवं ऐनिमेशन फिल्में प्रदर्शित की गईं।
राजाराम देव पोद्दार शाला (सेठ आनंदीलाल पोद्दार जूनियर कालेज) आसिफ इंडिया, मुंबई द्वारा अंतराष्ट्रीय ऐनिमेशन दिवस मनाया गया।	6 वृत्तचित्र, लघु एवं ऐनिमेशन फिल्में प्रदर्शित की गईं। मुंबई, बंगलौर, नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद चेन्नई और कोच्चि में 30 ऐनिमेशन फिल्में प्रदर्शित की गईं।
सुचित्रा फिल्म सोसायटी, बंगलौर	15 वृत्तचित्र, लघु और ऐनिमेशन फिल्में दिखायी गईं।
आशय फिल्म क्लब, पुणे (कला फिल्म समारोह)	1 फिल्म प्रदर्शित की गईं।
ग्रैफिटी मल्टी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	11 फिल्में प्रदर्शित (राममोहन की फिल्मों का प्रदर्शन)
जिला महिला और बाल विभाग,	दहेज के बारे में 9 फिल्में नागपुर में दिखायीं गईं।
धम्म प्रवर्तक दिन के बारे में फिल्मों का प्रदर्शन और विपणन, नागपुर	3 फिल्में दिखायीं गईं।
मैसर्स क्रिस्टिना कैरिलो द अल्बोर्नोज, (हाउस आफ इंडिया, स्पेन के सांस्कृतिक परियोजना मैनेजर)	सत्यजित राय फिल्म दिखायी गईं।
एल वी प्रसाद फिल्म और टेलीविजन अकादमी, चेन्नई द्वारा अपने विद्यार्थियों के लिए फिल्म प्रभाग की डाक्यूमेंटरी फिल्मों के प्रदर्शन का आयोजन।	7 फिल्में प्रदर्शित की गईं।

viii) भारतीय विद्या भवन, बंगलौर में संगीत और नृत्य फिल्मोत्सव।

ix) आर्य विद्या मंदिर, बांद्रा, मुंबई में फिल्म समारोह।

x) वस्मत, हिंगोली में फिल्म समारोह।

xi) गोरेगांव, मुंबई में तृतीय फिल्म समारोह।

xii) चेन्नई म्युजिक कालेज, अडियार, चेन्नई के टैगोर आडिटोरियम में प्रथम संगीत एवं नृत्य उत्सव।

xiii) मैसर्स एलवी प्रसाद स्टूडियो, फिल्म और टेलीविजन अकादमी, चेन्नई में द्वितीय संगीत एवं नृत्य उत्सव।

xiv) मैसर्स एलवी प्रसाद स्टूडियो, फिल्म और टेलीविजन अकादमी, चेन्नई में तृतीय संगीत एवं नृत्य उत्सव।

xv) राजकीय संगीत महाविद्यालय, अडियार, चेन्नई में चौथा फिल्म समारोह।

xvi) एमजीआर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, चेन्नई में किनेमा से सिनेमा उत्सव

xvii) यूजीसी और ईएमआरसी द्वारा संयुक्त रूप से भोपाल के यूनिवर्सिटी आडिटोरियम में इंदौर समारोह।

xviii) प्रियदर्शनी इंजीनियरी एवं वास्तुशिल्प महाविद्यालय, नागपुर में फिल्म समारोह।

xix) शहीद स्मारक भवन, नागपुर में फिल्म समारोह।

xx) नागपुर में भोपाल फिल्म समारोह।

xxi) नागपुर और अमरावती डिविजन में फिल्म समारोह

पीआईबी द्वारा आयोजित जन सूचना अभियान :

i) फिल्म प्रभाग, तिरूअनंतपुरम शाखा के सहयोग से दो फिल्में प्रदर्शित की गयीं।

फोटोग्राफरों द्वारा कवर की गयीं घटनाएं :

- गणतंत्र दिवस
- तृतीय संचालन समिति की बैठक
- एमआईएफएफ-2006
- हिंदी कार्यशाला
- डॉ. बी आर अम्बेडकर जयंती
- प्रेस के लिए फिल्म शो
- डॉ. राम मनोहर लोहिया
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव का फिल्म प्रभाग का दौरा
- एवीए पुरस्कार 2006
- सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी का फिल्म प्रभाग का दौरा
- स्वतंत्रता दिवस
- हिंदी दिवस सप्ताह
- फिल्म 'नौशाद', 'सलिल चौधरी', 'ऋषिकेश मुखजी' के प्रेस शो
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह

राजस्व

1. बिक्री

1 अप्रैल, 2006 से 30 नवंबर 2006 की अवधि में फिल्म प्रभाग ने थियेटर क्षेत्र में 39 फिल्मों के 9791 प्रिंट जारी किए। प्रभाग ने भारत में गैर-व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए 1,45,909 रूपये मूल्य के 184-वीएचएस, 996-वीसीडी और तीन बीटा कैम कैसेटों की बिक्री की। विदेश में 49,549 रुपये मूल्य के एक वीसीडी और एक फिल्म बीटा कैम कैसेट की भी बिक्री की गयी। 11,08,656 रुपये मूल्य के स्टॉक शॉट्स भी बेचे गए।

इस अवधि में 37,500 रुपये की रॉयल्टी भी अर्जित की गई।

2. किराया (फिल्में)

1 अप्रैल, 2006 से 30 नवंबर की अवधि में फिल्म प्रभाग ने फिल्मों के किराये से 376.62 लाख रुपये राजस्व के रूप में अर्जित किए।

3. भवनों का किराया

1 अप्रैल 2006 से 12 दिसंबर 2006 की अवधि में फिल्म प्रभाग ने थियेटर, वीडियो थियेटर और मुक्त स्थल किराये पर देकर 22,409 रुपये का राजस्व अर्जित किया।

1 अप्रैल, 2006 से 30 नवंबर 2006 की अवधि में फिल्म प्रभाग

ने कुल 398.68 लाख रुपये का कुल राजस्व अर्जित किया।

फिल्म प्रभाग

वर्ष की उपलब्धियों की एक झलक

फिल्म निर्माण

अप्रैल-नवंबर 2006 की अवधि में फिल्म प्रभाग ने 24 वृत्तचित्र/लघु, फीचर और वीडियो फिल्मों का निर्माण किया। इनमें से 22 फिल्में विभागीय तौर पर बनाई गईं और दो फिल्में स्वतंत्र निर्माताओं से तैयार कराई गई।

1 अप्रैल, 2006 से 30 नवंबर 2006 की अवधि में फिल्म प्रभाग ने 7 न्यूज मैग्जीन भी तैयार कीं, जो महत्वपूर्ण घटनाओं, अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों की यात्राओं आदि से संबद्ध थीं। इनका ब्योरा आगे दिया गया है :

(क) राष्ट्रीय घटनाएं

1. गणतंत्र दिवस
2. स्वतंत्रता दिवस

(ख) अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों की यात्रा

1. राष्ट्रपति द्वारा फ्लीट रिव्यू-2006
2. प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की जर्मनी और उज्बेकिस्तान यात्रा
3. बनवासी, मधुकेशव आस्था बांध
4. नौशाद-ए म्यूजिकल जर्नी
5. सैंटपीटर्स बर्ग में जी-8 सम्मेलन

प्रमुख गतिविधियां : इस वर्ष फिल्म प्रभाग ने 'अंडमान निकोबार' द्वीप समूह में सुनामी के बाद पुनर्वास कार्य' के बारे में वृत्तचित्र फिल्म के निर्माण का काम शुरू किया। इसका उद्देश्य सरकार द्वारा सुनामी से पीड़ितों के पुनर्वास के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी देना था। इसके अलावा फिल्म प्रभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में निम्नांकित विषयों पर वृत्तचित्र बनाने के लिए काम शुरू किया :

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति
3. परंपरागत जड़ी बूटियां
4. मदर्स पीसमेकर्स-रिजोल्विंग कन्फ्लिक्ट
5. मणिपुर के नागा और मैती समुदायों का संयोजन संगीत
6. शंकरदेव-ए लाइफ लार्जर दैन लाइफ (असम के बहुआयामी विद्वान शंकरदेव के बारे में एक फिल्म)
7. राजश्री भाग्यचंद्र ऑफ मणिपुर

फिल्म प्रभाग ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में 'इंदिरा-ग्लिम्पसेस आफ हर लाइफ' नाम की वीडियो फिल्म तैयार की। यह फिल्म श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर प्रदर्शित करने के लिए बनायी गई।

प्रभाग की फिल्मों का डिटिलाइजेशन और वेबकास्टिंग

फिल्म डिवीजन की फिल्मों का ऐतिहासिक महत्व की खराब हो रही फिल्मों को संरक्षित करने के लिए 'फिल्म डिवीजन संग्रहालय के संरक्षण' की योजना शुरू की गई जो 'फिल्म डिवीजन की फिल्मों की वेब कास्टिंग और डिजिटलाइजेशन योजना का संशोधित रूप है। इंटरनेट के तेजी से प्रसार के साथ-साथ टेलीविजन की सूचना प्रसार का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है जिनके जरिए फिल्म डिवीजन की फिल्मों का वितरण जरूरी हो गया है। इस उद्देश्य के लिए इन फिल्मों को डिजिटलाइज करके प्रसारित करने के लिए डिवीजन ने अपनी सेल्युलाइड फिल्मों को उच्च क्षमता के डिजिटल टेप पर परिवर्तित करने की योजना बनाई है। इन सभी 8100 फिल्मों को इस वित्त वर्ष के अंत तक डिजिटाइज़ करने की योजना है। इन सभी 8100 फिल्मों को इस वित्त वर्ष के अंत तक डिजिटाइज करने की योजना है। परियोजना के दूसरे चरण में सेल्युलाइड सामग्री का संरक्षण किया जाएगा क्योंकि ऐसी सामग्री लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकती है। निरंतर बदलती डिजिटल तकनीक को देखते हुए वह और भी ज्यादा जरूरी है।

फिल्म प्रभाग की फिल्मों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार के लिए 220 घंटा अवधि की फिल्मों को नेट पर डालने की योजना है। प्रभाग ने अपनी 330 घंटे की फिल्में पहले ही कोड कर ली है और इन्हें अपनी वेबसाइट www.filmsdivision.org से लोड कर लिया है। इन फिल्मों की वेबकास्टिंग के प्रयास की विश्वभर में डाक्युमेंटरी फिल्म देखने वालों ने सराहना की है। वीडियो फिल्मों और साफ्टवेयर की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए फिल्म प्रभाग की फिल्मों को डीवीडी में भी डाला जा रहा है। वेबसाइट में निरंतर सुधार किए जाते हैं।

डिजिटल 2डी/3डी ऐनीमेशन स्टुडियो

प्रभाग की लोकप्रिय कार्टून फिल्म इकाई का आधुनिकीकरण किया गया है और क्लासिकल ऐनीमेशन का स्थान कम्प्यूटर एनीमेशन ने ले लिया है। उन्नत हार्डवेयर और साफ्टवेयर टेक्नोलाजी की मदद से अब इस इकाई में द्विआयामी और त्रिआयामी (2डी/3डी) एनीमेशन किया जा सकता है।

फिल्मों का वितरण

अप्रैल से नवम्बर 2006 के दौरान प्रभाग ने महत्वपूर्ण विषयों पर डाक्यूमेंटरी फिल्मों और न्यूज मैगज़ीन के 9791 प्रिंट जारी किए। प्रभाग ने एनएसडीसी के लिए 4048 प्रिंट और राज्य सरकारों के लिए एक न्यूज मैगज़ीन के 73 प्रिंट भी जारी किए। प्रभाग ने पूर्वी क्षेत्रीय निर्माण केंद्र/दक्षिणी क्षेत्रीय निर्माण केंद्र और फिल्म प्रभाग आडिटोरियम के लिए 65 लाइब्रेरी प्रिंट भी दिए।

फिल्म लाइब्रेरी

प्रभाग ने संग्रह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक परम्परा और इतिहास को दर्शाने वाली महत्वपूर्ण फिल्में हैं जिनकी दुनिया भर में खासी मांग है। प्रभाग फिल्मों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण फुटेज प्रदान करता है और इसकी बिक्री से राजस्व भी प्राप्त करता है। प्रभाग के पास विभिन्न श्रेणियों के करीब 1.9 लाख नेगेटिव्स तथा प्रिंट्स का संग्रह है।

(क) योजना कार्यक्रमों की उपलब्धियां

वर्ष 2006-07 के लिए फिल्म प्रभाग का योजना व्यय 1010 लाख रुपये रखा गया था। विवरण इस प्रकार है :

(क) वृत्तचित्र, लघु और एनीमेशन फिल्मों का मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

स्वीकृत व्यय 10 लाख रुपये

नवम्बर 2006 तक किया गया व्यय 56 हजार रुपये

फिल्म प्रभाग को इस द्विवार्षिक समारोह के आयोजन का काम सौंपा गया है। समारोह 1990 में शुरू किया गया। समारोह के दो वर्ग हैं—अंतर्राष्ट्रीय फिल्म/वीडियो प्रतियोगिता वर्ग और राष्ट्रीय फिल्म/वीडियो प्रतियोगिता वर्ग। ज्युरी द्वारा दोनों वर्गों में श्रेष्ठ फिल्में चुनी जाती हैं और उन्हें 26 लाख रुपये के नकद पुरस्कारों के साथ स्वर्ण और रजत शंख प्रदान किए जाते हैं।

नौवां समारोह 3 से 9 फरवरी 2006 के दौरान मुम्बई में सम्पन्न हुआ। इसमें राष्ट्रीर वर्ग में 388 और अंतर्राष्ट्रीय वर्ग में भारत सहित 30 देशों की 186 प्रविष्टियां थीं। पुनरावलोकन और विशेष पैकेज वर्ग में 202 फिल्में शामिल की गई। समारोह में भारत सहित 37 देशों ने हिस्सा लिया। श्री राम मोहन को ऐनीमेशन फिल्मों के विविध क्षेत्रों, जैसे पटकथा, डिज़ाइन और निर्देशन में विशिष्ट आजीवन योगदान के लिए 2.5 लाख का पुरस्कार और ट्राफी प्रदान की गई।

प्रभाग ने 2 से 6 दिसम्बर 2006 के दौरान नगालैंड में कोहिमा में वृत्त चित्र, लघु और ऐनीमेशन फिल्मों के लिए पहला कोहिमा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किया। अगला अंतर्राष्ट्रीय समारोह 2008 में आयोजित किया जाएगा।

ख) फिल्म प्रभाग के पुराने उपकरणों का आधुनिकीकरण और बदलाव

स्वीकृत व्यय 1 करोड़ रुपये

नवम्बर 2006 तक व्यय 0.0 रुपये

प्रभाग वृत्त चित्र, न्यूज मैगजीन और लघु कथा चित्र बनाता है। बदलती टेक्नोलाजी को देखते हुए पुराने उपकरण का बदलाव और आधुनिकीकरण जरूरी है ताकि फिल्म निर्माण की गुणवत्ता बनी रहे।

सेल्युलाइड फिल्मों/वृत्त चित्रों के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से वीडियो फिल्मों की मांग बढ़ी है। इसे देखते हुए वीडिये फिल्में बनाने की टेक्नोलाजी अपनाई जा रही है। फिल्हाल कार्टून फिल्म इकाई एनीमेशन फिल्में बना रही है और परम्परागत वृत्त चित्रों में ऐनीमेशन वाले हिस्से जोड़ रही है। ऐनीमेशन में कम्प्यूटर टेक्नोलाजी अपनाने और पुराने उपकरणों को बदलने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है और इस दिशा में काम चल रहा है। वर्ष 2006-07 के लिए प्रस्ताव मंत्रालय भेज दिया गया है। इसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा है और अब तक योजना कार्यों के अंतर्गत इस पद पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

प्रभाग की फिल्मों का डिजिटलीकरण और वेबकास्टिंग

स्वीकृत व्यय : रुपये 200.00 लाख

नवंबर 2006 तक हुआ व्यय : रुपये 185.85 लाख रुपये

फिल्म प्रभाग की फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 220 घंटे की अवधि की फिल्मों को वेबसाइट पर उपलब्ध कराने पर विचार किया गया और वीडियो फिल्म तथा सॉफ्टवेयर की बढ़ती मांग को देखते हुए योजना कार्यक्रम के तहत फिल्म प्रभाग की फिल्मों को डीवीडी में बदलने पर विचार किया

गया। फिल्मों को डीवीडी में बदलने के लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है, वेबसाइट पर दृश्य-श्रव्य सामग्री नियमित अंतराल पर बदली जा रही है। चालू वित्त वर्ष में नवंबर 2006 तक 1102 फिल्में डीवीडी पर हस्तांतरित की गईं और 480 फिल्मों के अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकों का डिजिटलीकरण किया गया। इस पर अभी तक खर्च हुई कुल 182.85 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। योजना कार्यक्रम के अंतर्गत वेबकास्टिंग घटकों के लिए आवंटित 15 लाख रुपये का इस्तेमाल इस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है।

चलचित्रों के लिए संग्रहालय की स्थापना

स्वीकृत व्यय : 7 करोड़ 44 लाख रुपये

खर्च : 000.00 लाख रुपये

निम्नांकित उद्देश्यों के साथ फिल्म प्रभाग ने अपने मुंबई स्थित परिसर में चलचित्रों का संग्रहालय स्थापित करने की व्यवस्था की है :

1. उत्साही उद्यमियों और आगंतुकों के लिए मुंबई में एक केंद्रीय एजेंसी प्रदान करना;
2. समकालीन पीढ़ी को भारतीय सिनेमा के विकास और इतिहास से अवगत कराना;
3. फिल्म निर्माण से संबद्ध बहुमूल्य धरोहर से जुड़ी कलात्मक वस्तुओं के लिए स्थायी संग्रहालय की स्थापना करना; जाने माने निर्देशकों, निर्माताओं, संस्थानों आदि की रचनाओं को आगन्तुकों/फिल्म उत्साहियों के लाभ के लिए प्रदर्शित करना;
4. फिल्म निर्माताओं और फिल्म विद्यार्थियों के लिए विचार गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना ताकि इसे एक सजीव संस्था बनाया जा सके;
5. भावी पीढ़ी में फिल्म आंदोलन के लिए रुचि पैदा करना।

चलचित्रों के लिए संग्रहालय की स्थापना के बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम राष्ट्रीय भवन निर्माण लिमिटेड, नई दिल्ली को सौंपा गया और फिल्म प्रभाग और एनबीसीसी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

एनबीसीसी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित संग्रहालय की वास्तुशिल्पीय रूपरेखा और डिजाइन को मंजूरी दी जा चुकी है। एनबीसीसी को तीन महीने की अवधि में विस्तृत योजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

3. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) को प्रस्तावित संग्रहालय के लिए संग्रहपाल के चयन/नियुक्ति का काम सौंपा गया है। इस प्रयोजन के लिए और साथ ही एनबीसीसी द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए न्यूयार्क के अमेरिकन म्यूजियम आफ मूविंग इमेजेज की संस्थापक निदेशक सुश्री रोचिल स्लोविन को सात दिन के लिए चलचित्र संग्रहालय परियोजना की परामर्शदात्री नियुक्त किया गया।

फिल्म समारोह निदेशालय

फिल्म समारोह निदेशालय की स्थापना 1973 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अच्छे सिनेमा को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए निदेशालय निम्न गतिविधियों का आयोजन करता है।

1. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन
2. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा दादा साहेब फालके पुरस्कार संबंधी आयोजन
3. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और भारतीय फिल्मों का विदेशों में भारतीय मिशनों के माध्यम से प्रदर्शन।
4. भारतीय पैनोरमा का चयन।
5. विदेशों में आयोजित अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह में भागीदारी।
6. भारत सरकार की ओर से विशेष फिल्मों का प्रदर्शन।
7. प्रिंट संग्रहण और प्रलेखन।

ये गतिविधियां भारत और अन्य देशों के बीच सिनेमा के क्षेत्र में विचारों, संस्कृति और अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए बेजोड़ मंच प्रदान करती हैं।

निदेशालय भारतीय सिनेमा को सशक्त मंच भी प्रदान करता है और भारतीय फिल्मों के लिए वाणिज्यिक अवसर पैदा करता है। यह विश्व सिनेमा की नवीनतम प्रवृत्तियों से देश के फिल्म उद्योग, विद्यार्थियों और आम लोगों को अवगत कराता है।

भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

आईएफएफआई-2006

37वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2006 का आयोजन 23 नवंबर से 3 दिसंबर 2006 तक गोवा में राज्य सरकार के सहयोग से किया गया।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2006 में 46 देशों ने भाग लिया। 'विश्व सिनेमा खंड' और विदेशी फिल्मों के अन्य वर्गों

के तहत कुल 94 फिल्में (इनमें 54 फिल्में विश्व सिनेमा, 30 फिल्में कन्ट्री फोकस सहित विदेश सिंहावलोकन, 4 फिल्में सर्वोत्तम श्रेणियों और छह फिल्में तकनीकी सिंहावलोकन से संबद्ध थीं।) दिखाई गईं। समारोह के प्रमुख खंड 'विश्व सिनेमा' की लगभग सभी फिल्में पहले ही अन्य समारोहों में अंतराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुकी थीं। समारोह में प्रदर्शन के दौरान इन फिल्मों का व्यापक स्वागत किया गया। प्रतियोगी खंड में 10 देशों से 11 फिल्में दिखायीं गईं। समारोह में 84 भारतीय फिल्में प्रदर्शित की गईं, जो सिंहावलोकन, श्रद्धांजलि, प्रशस्ति, भारतीय पैनोरमा और मुख्य धारा के भारतीय सिनेमा श्रेणियों से संबद्ध थीं। समारोह में प्रदर्शित सभी 189 फिल्मों का प्रेस और प्रतिनिधियों के लिए प्रदर्शन पांच थिएटरों में किया गया। समारोह के दौरान प्रेस/प्रतिनिधियों, आम लोगों (2 थिएटरों में) तथा जूरी के लिए कुल 326 शो किए गए। दशकों के लिए फिल्मों का प्रदर्शन एक सप्ताह तक किया गया।

उद्घाटन समारोह

समारोह का उद्घाटन 23 नवम्बर, 2006 को शाम 5.30 बजे पणजी में कला अकादमी से सटे ओल्ड फुटबाल स्टेडियम में किया गया। श्री शशि कपूर इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी और गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रतापसिंह राणे ने दर्शकों को संबोधित किया। सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता श्री वेंकटेश, श्री प्रसनजीत और श्री अनिल कपूर इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में शामिल थे। अभिनेत्री सुश्री विद्या बालन ने दीप प्रज्जवलित करने में अतिथियों की सहायता की और श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने समारोह के शुभारम्भ की औपचारिक घोषणा की। इसके बाद प्रतियोगी खंड के जूरी के सदस्यों का दर्शकों से परिचय कराया गया।

इवेंट मैनेजमेंट कम्पनी द्वारा आयोजित संगीत कार्यक्रम ओपन एयर ऑडिटोरियम में फिल्मी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया। फिल्म

जाने-माने फिल्म अभिनेता श्री शशि कपूर पणजी, गोआ में 37वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के उद्घाटन के अवसर पर दीप प्रज्वलित करते हुए

जगत की कई जानी-मानी हस्तियों, गणमान्य व्यक्तियों और अधिकारियों ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया।

स्पेन के पेड्रो अल्मोडोवर द्वारा निर्देशित उद्घाटन फिल्म 'वोल्वर' का प्रदर्शन कला अकादमी में किया गया।

समारोह में निम्नांकित खंड थे :

1. प्रतियोगी खंड

इस खंड में एशियाई, अफ्रीकी और लेटिन अमरीकी निर्देशकों की फीचर फिल्में शामिल थीं।

एक समिति द्वारा प्रतियोगी खंड के लिए 10 देशों का चयन किया गया और इन देशों की 11 फिल्में प्रदर्शित की गईं।

प्रतियोगी खंड की जूरी के अध्यक्ष आस्ट्रेलिया के पुरस्कार विजेता निर्देशक श्री रोल्फ डे हीर थे। जूरी के अन्य सदस्यों में भारत से फिल्म निर्देशक/निर्माता श्री जाह्नू बरुवा, फ्रांस के फिल्म निर्देशक श्री ओलिवर असाइअस, पोलैंड की फिल्म अभिनेत्री सुश्री ग्राज़िना स्ज़ापोलोवस्का और अर्जेंटीना की फिल्म अभिनेत्री सुश्री लेटिका ब्रेडिस शामिल थीं। जूरी ने निम्नांकित पुरस्कारों की अनुशंसा की:

क. सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए स्वर्ण मयूर और दस लाख रुपये का नकद पुरस्कार चीन के फिल्म निर्देशक श्री हासी चाउला को उनकी फिल्म 'द ओल्ड बारबर' के लिए दिया गया।

ख. उदयमान निर्देशक के लिए रजत मयूर और पांच लाख रुपये का पुरस्कार कोरिया की फिल्म 'ए शॉर्ट लाइफ' की निर्देशक सुश्री क्यंग-ली को दिया गया।

ग. विशेष जूरी पुरस्कार बांग्लादेश की फिल्म 'फॉरएवर प्लीज' के निर्देशक श्री अबू सईद को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के रूप में रजत मयूर और पांच लाख रुपये नकद दिए जाते हैं।

2. विश्व सिनेमा खंड :

यह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का प्रमुख औपचारिक पुरस्कार है। इस खंड के अंतर्गत, पिछले लगभग दो वर्षों में बनी 46 देशों की 54 सर्वश्रेष्ठ फिल्में दिखाई गईं। इनमें वे फिल्में शामिल थीं, जिन्हें अपने देश तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में पुरस्कार मिल चुके थे या फिर उन्हें काफी सराहा गया था। अधिकतर देशों की फिल्में इसलिए शामिल की गई थीं, ताकि विभिन्न देशों के सिनेमा में आ रही नवीनतम प्रवृत्तियों की झलक मिल सके। इस खंड की लगभग सभी फिल्मों को काफी सराहना मिली।

3. विदेश सिंहावलोकन, कंट्री फोकस, श्रद्धांजलि, तकनीकी सिंहावलोकन और मास्टर क्लासेस फिल्में

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह-2006 के विदेश सिंहावलोकन खंड में आस्ट्रेलिया के निर्देशक रोल्फ डी हीर द्वारा निर्देशित प्रमुख सिंहावलोकन फिल्में, स्पेन के अभिनेता जेवियर बर्डम की फिल्में, पूर्व-युगोस्लाविया के विभिन्न देशों की फिल्में शामिल थीं। विशेष खंड में फिल्म इंडिया वर्ल्ड वाइड, मास्टर क्लासेस फिल्में और तकनीकी सिंहावलोकन के अंतर्गत डिजिटल संपादन, डिजिटल ऐनीमेशन और फिल्म रिस्टोरेशन तकनीकों को प्रदर्शित करने वाली फिल्में शामिल थीं। इस वर्ष देश-केन्द्रित फिल्मों के अंतर्गत अर्जेंटीना की फिल्में दिखाई गई।

4. भारतीय खंड :

भारतीय खंड में कुल 84 फिल्में प्रदर्शित की गई। इस खंड के निम्न उपखंड थे :

1. भारतीय पेनोरमा
2 भारतीय मुख्य धारा
3. सिंहावलोकन
4. एनएफडीसी की ऐतिहासिक फिल्में
5. श्रद्धांजलि
6. प्रीमियर
7. पुरस्कार प्राप्त फिल्में
8. प्रशस्ति

भारतीय पेनोरमा :

इस खंड का शुभारंभ 24 नवंबर, 2006 को मृदुल तुलसीदास और विनय सुब्रमण्यम द्वारा निर्देशित 'मिस्ड कॉल' (अंग्रेजी और हिंदी-फीचर) और अशोक पंडित द्वारा निर्देशित 'एंड द वर्ल्ड रिमेंड साइलेंट' (अंग्रेजी-गैर फीचर) के प्रदर्शन के साथ हुआ। इस खंड में कुल 20 फीचर और 20 गैर-फीचर फिल्में दिखायी गयीं।

भारतीय मुख्यधारा सिनेमा

इस खंड का शुभारंभ 24 नवंबर, 2006 को कला अकादमी में राकेश ओमप्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म 'रंग दे बसंती' के प्रदर्शन के साथ किया गया। इस खंड के अंतर्गत भारतीय फिल्म परिसंघ द्वारा अनुशंसित 12 फीचर फिल्में दिखाई गईं।

सिंहावलोकन :

इस खंड का आयोजन फिल्म निर्देशक अरविन्दम को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया। इसका शुभारंभ 25 नवंबर 2006 को हुआ। श्री अरविन्दम की पांच फिल्में इस खंड के अंतर्गत दिखाई गई।

एनएफडीसी की ऐतिहासिक फिल्में :

इस खंड के अंतर्गत एनएफडीसी की पुरानी फिल्में प्रदर्शित की गयीं। इसका उद्घाटन 'गांधी' के प्रदर्शन से हुआ और इसमें छह फिल्में प्रदर्शित की गयीं। अन्य फिल्में थीं, 'आगन्तुक', 'मिर्च मसाला', 'मंगम्मा', 'मरूपक्कम' और 'जाने भी दो यारो'।

श्रद्धांजलि :

समारोह के दौरान मशहूर फिल्मी हस्तियों श्रीविद्या, परवीन बाबी, नौशाद अली, ऋषिकेश मुखर्जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ओदुविल उन्नीकृष्णन, पी. भानुमति, पद्मिनी, मनोज पुंज और डॉ. राजकुमार को श्रद्धांजलि दी गयी और इनमें से प्रत्येक से संबद्ध एक एक फिल्म प्रदर्शित की गयी।

प्रीमियर :

समारोह में निम्नलिखित फिल्मों के प्रीमियर आयोजित किए गए, जिनमें इन फिल्मों के सितारों ने भाग लिया :

फिल्म समारोह निदेशालय की गतिविधियां

क्र. सं.	गतिविधियां	2004-05		2005-06		2006-07	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	भारतीय पेनोरमा	1	1	1	1	1	1
2.	सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत विदेश में फिल्म समारोह और अन्य आयोजन						
	1. भारत में	6	4	6	5	6	3
	2. विदेश में	4	8	6	3	6	4
3.	फिल्मों के आदान प्रदान सहित विदेशी फिल्म समारोह में भागीदारी	45	23	45	53	45	35 (दिसं. 06 तक)
4.	राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार	1	1	1	1	1	बाकी है
5.	भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	1	1	1	1	1	1
6.	भारतीय पेनोरमा के सबटाइटल्ड प्रिंटों की तैयारी						
	क. फीचर फिल्म	21	21	21	21	21	20
	ख. गैर फीचर फिल्म	21	20	21	16	21	20

1. गौतम घोष द्वारा निर्देशित यात्रा (मराठी)
2. गजेन्द्र अहिरे द्वारा निर्देशित ग्लास हाउस
3. राजेन्द्र तलक द्वारा निर्देशित अंतर्नाद (कोंकणी)
4. टीएस नागभरण द्वारा निर्देशित अंतर्नाद (कोंकणी)
4. टीएस नागभरण द्वारा निर्देशित कल्लाराली हुवागी (कन्नड़)
5. कवित लंकेश द्वारा निर्देशित थानानम थानानम (कन्नड़)

पुरस्कार-प्राप्त फिल्में :

इस नये खंड के अंतर्गत 50 वर्ष पूर्व राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित और 1956 में केंस फिल्म समारोह में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म 'पाथेर पंचाली', (बांग्ला-1956) प्रदर्शित की गई।

प्रशस्ति :

स्व० पृथ्वीराज कपूर और स्व० सचिनदेव बर्मन की जन्म शताब्दी के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनकी फिल्में (उनके अभिनय और संगीत-निर्देशित वाली) 'मुगले आजम' और 'चुपके चुपके' दिखायीं गयीं।

समारोह के दौरान अन्य गतिविधियां :

समारोह में फिल्मों के प्रदर्शन के अलावा फिल्म बाजार भी लगाया गया, जिसमें 10 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ने समारोह में पोस्टर प्रदर्शनी आयोजित की। समारोह के दौरान मुक्त मंच और विचार गोष्ठियां भी आयोजित की गयीं।

6. समापन समारोह :

37वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का समापन समारोह 3 दिसंबर, 2006 को कला अकादमी में आयोजित किया गया। अध्यक्ष श्री रोल्ड डी हीर ने दर्शकों को संबोधित किया और पुरस्कारों की घोषणा की। गोवा के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और बंगाल की जानी-मानी फिल्म अभिनेत्री सुश्री अपर्णा सेन ने पुरस्कार वितरित किए और इस अवसर पर लोगों को संबोधित किया।

समापन के अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह के बाद तीन दिसंबर को ऐलेजैड्रों गोन्जालेज इन्नार्रितु द्वार निर्देशित 'बाबेल' (अमरीका/मैक्सिको) दिखाई गई।

53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार :

53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत तीन अलग-अलग जूरी बनायीं गई, जिनमें फिल्म उद्योग के विशिष्ट व्यक्तियों को शामिल किया गया। फीचर फिल्मों की 11 सदस्यों की जूरी की अध्यक्ष श्रीमती बी. सरोजा देवी थीं। पांच सदस्यों की गैर-फीचर फिल्मों की जूरी के प्रमुख श्री सिद्धार्थ काक थे। सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए तीन सदस्यों की जूरी का अध्यक्ष श्री खालिद महमूद को बनाया गया था।

भारतीय पेनोरमा 2006 :

भारतीय पेनोरमा के लिए फिल्मों का चयन पांच-पांच सदस्यों की दो जूरी द्वारा किया गया। फीचर फिल्म जूरी के प्रमुख श्री सईद अख्तर मिर्जा और गैर-फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष श्रीराजा मित्र थे। जूरी ने अक्टूबर 2006 में फिल्मों को देखने के बाद 20 फीचर और 20 गैर-फीचर फिल्मों का चयन किया। भारतीय पेनोरमा पैकेज का प्रदर्शन गोवा में आयोजित 37वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किया गया। इन फिल्मों के निर्माता-निर्देशक और कलाकार भी इस अवसर पर मौजूद थे। उन्होंने कला अकादमी, पणजी गोवा स्थित मीडिया सेंटर में अपनी फिल्मों के बारे में संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया।

निदेशालय ने इन फिल्मों का विस्तृत ब्योरा एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया। इस पुस्तिका को समारोह के दौरान भारतीय और विदेशी प्रतिनिधियों को वितरित किया गया।

सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम/भागीदारी तथा विशेष पैकेज/सप्ताहांत फिल्म समारोह :

वर्ष के दौरान असम फिल्म सप्ताह और ओसीटीएवीई-2006 (पूर्वोत्तर फिल्मोत्सव) का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।

सीरी फोर्ट-2 में स्पेनिश फिल्मोत्सव और आल्जीरियाई फिल्म समारोह आयोजित किए गए। इनके अलावा यूरोपीय फिल्म समारोह पहले सीरी फोर्ट-2 (नई दिल्ली) में और बाद में कोलकाता, चेन्नई और तिरूबनंतपुरम में आयोजित किया गया।

भारतीय फिल्मों ने भी भारत में आयोजित विभिन्न अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लिया। इनमें 9वां मुंबई अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह, आईआईटी दिल्ली में स्पिक मैके द्वारा आयोजित वार्षिक समारोह 'विरासत', देहरादून में आयोजित विरासत समारोह, हैदराबाद फिल्मोत्सव, पांडिचेरी में ओरोफिल्म समारोह, ओसियन सिने फैन, भारत अंतराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित आठवां एशियाई सिने उत्सव, कोलकाता फिल्म समारोह और तिरूअनंतपुरम फिल्म समारोह शामिल थे।

सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम/विशेष समारोहों के अंतर्गत कई देशों में, जैसे इजराइल, पेइचिंग, शंघाई, दक्षिण अफ्रीका, ब्रसेल्स और जर्मनी में भारतीय फिल्म समारोह आयोजित किए गए।

भारतीय फिल्मों ने दिसंबर 2006 तक 18 देशों में आयोजित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भी भाग लिया। ये देश हैं: बांग्लादेश, जर्मनी, नीदरलैंड, फिलीपींस, साइप्रस, अमरीका, बहरीन, इटली, स्पेन, ब्रिटेन, इजराइल, केन्या, पौलेंड, जिम्बाब्वे, लातविया, स्लोवाक गणराज्य, इंडोनेशिया और फ्रांस।

प्रथम साइप्रस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में फिल्म 'राम' को दो पुरस्कार मिले - पहला सर्वोत्तम अभिनेता और दूसरा सर्वोत्तम संगीत के लिए।

फिल्म 'मीनाक्षी-3 शहरों की कहानी' को भी दो पुरस्कार मिले। इनमें से एक सर्वोत्कृष्ट सिनेमैटोग्रैफी और दूसरा सर्वोत्तम प्रोडक्शन डिजाइन के लिए मिला।

कार्य अध्ययन

ईआरसी सिफारिशों पर अंतिम फैसला आने तक आंतरिक कार्य अध्ययन एकक की सिफारिशें लागू करना लंबित रखा गया।

फिल्म समारोह निदेशालय में सतर्कता और शिकायत संगठन :

वरिष्ठ उपनिदेशक फिल्म समारोह निदेशालय में सतर्कता अधिकारी हैं। निदेशालय को इस वर्ष के दौरान पदोन्नति के बारे में केवल एक शिकायत/फरियाद मिली जो लंबित है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बारे में रिपोर्ट

इस निदेशालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई पद रिक्त नहीं है। उपनिदेशक (प्रशासन) को निदेशालय के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया है।

वर्ष 2006-07 के लिए हिंदी भाषा में कामकाज के बारे में रिपोर्ट

1. हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म समारोह निदेशालय के कर्मचारी काफी कामकाज मूलरूप से हिंदी भाषा में ही कर रहे हैं। रोजमर्रा के कार्यालयी कामकाज में हिंदी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
2. दिन प्रतिदिन के सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाले अंग्रेजी शब्दों या विचार के समानार्थकों को कार्यालय के बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है।
3 तिमाही आधार पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
4. हिंदी कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन भी तिमाही आधार पर किया गया।
5. हर महीने की पहली तारीख को हिंदी में कामकाज दिवस के रूप में मनाया गया।
6. सितंबर 2006 में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें हिंदी में विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गईं। फिल्म समारोह निदेशालय के कार्यालय में हिंदी के बैनर प्रदर्शित किए गए।
7. सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी से संबद्ध विभिन्न बैठकों में फिल्म समारोह निदेशालय के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया।

कंप्यूटरीकरण :

1. निदेशालय की अपनी वेबसाइट है : http://www.dff.nic.in
2. कार्यालय में लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित किया गया है।
3. सभी अधिकारी तथा कर्मचारी कंप्यूटर पर काम करते हैं और अधिकतर पत्राचार ई-मेल के जरिए किया जाता है।

लेखा :

फिल्म समारोह निदेशालय, सीरी फोर्ट सांस्कृतिक परिसर का रखरखाव करता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के तहत, इस परिसर में फेरबदल तथा संयोजन पर 15 करोड़ रुपये खर्च किए गए। मंत्रालय ने वर्ष 2002-03 और 2003-04 के लिए 3 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपये की राशि को प्रशासनिक मंजूरी दी। इसमें से वर्ष 2002-03 के दौरान डेढ़ करोड़ रुपये और वर्ष 2003-04 के दौरान एक करोड़ 18 लाख रुपये दिए गए। वर्ष 2005-06 के दौरान वित्त मंत्रालय ने एक करोड़ 96 लाख रुपये की राशि को प्रशासनिक मंजूरी दी और धन जारी किया गया। चालू वित्त वर्ष यानी वर्ष 2006-07 के लिए 3 करोड़ 18 लाख रुपये की प्रशासनिक मंजूरी मंत्रालय द्वारा दी गई, जिसमें से योजना के कार्यान्वयन के लिए करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपये जारी किए गए।

निदेशालय सीरी फोर्ट आडिटोरियम को कार्यक्रम आयोजनों के लिए किराये पर भी देता है। किराया राशि और सेवा कर को सरकारी खाते में जमा किया जाता है।

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार

परिचय

कला और ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में फिल्मों के संरक्षण का महत्व पूरे विश्व में माना जाता है। अपनी विविध अभिव्यक्तियों और स्वरूपों में फिल्म संरक्षण का कार्य किसी पर्याप्त संसाधनों,

स्थायी व्यवस्था और स्थानीय फिल्म उद्योग के लिए विश्वसनीय राष्ट्रीय संगठन को दिया जाना जरूरी था। इसीलिए फरवरी 1964 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त मीडिया इकाई के रूप में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना की गई। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. भारतीय सिनेमा की धरोहर की पहचान, इसकी प्राप्ति और इसे चिरस्थायी बनाना और विश्व सिनेमा का प्रतिनिधि संकलन तैयार करना।
2. फिल्मों से जुड़े आंकड़ों को वर्गीकृत और व्यवस्थित करना, सम्बंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना और ऐसी सामग्री को प्रकाशित तथा वितरित करना।
3. भारत में फिल्म संस्कृति के प्रचार-प्रसार के केंद्र के रूप में कार्य करना और विदेशों में भारतीय सिनेमा को परिचित कराना।

पिछले 43 वर्षों में अभिलेखागार ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में निरंतर प्रगति की है।

अप्रैल से दिसंबर 2006 के दौरान अभिलेखागार ने 45 नई फिल्मों, पांच डुप्लीकेट प्रिंट, निशुल्क प्राप्ति के रूपमें 317 फिल्में, 18 वीडियो कैसेट, 249 किताबें, 197 पटकथाएं, 151 डिस्क रिकॉर्ड, 29 स्लाइड्स, 982 अखबारी रिपोर्टें, गानों की 182 पुस्तिकाएं, 178 वॉल पोस्टर, 32 फिल्म फोल्डर, 105 डीवीडी और सीडी में परिवर्तित 868 चित्र छवियां हासिल कीं।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान हासिल की गई कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों/प्रिंटों का विवरण अगले दो पृष्ठों पर बॉक्स में दिया गया है।

रिपोर्ट की अवधि में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम मुंबई, चेन्नई और बंगलौर से परिरक्षण के लिए चित्र और ध्वनि नेगेटिव्स की 1561 रीलें प्राप्त हुईं। बम्बई फिल्म लैब, फिल्म सैंटर, सिने लैब मुंबई, रुतिक मेमोरियल ट्रस्ट कोलकाता और मेरीलैंड स्टूडियो, तिरूअनंतपुरम से भी महत्वपूर्ण फिल्म सामग्री की 1500 रीलें प्राप्त हुईं। भारत की बाल चित्र समिति ने भी इस वर्ष के दौरान अभिलेखागार में परिरक्षण के लिए 684 रीलें दीं।

इन प्राप्तियों का विवरण अनुलग्नक 'क' में दिया गया है।

फिल्म संस्कृति का प्रसार

भारत में फिल्म संस्कृति के प्रसार के लिए अभिलेखागार अनेक कार्य करता है। इसकी वितरण लाइब्रेरी के देश भर में 40 सदस्य हैं। अभिलेखागार साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक आधार पर सात महत्वपूर्ण केंद्रों पर संयुक्त फिल्म-प्रदर्शन आयोजित करता है। इसकी अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि फिल्म माध्यम की समझ सिखाने वाले (फिल्म एप्रिशिएसन) दीर्घ तथा लघु अवधि के कोर्स हैं जो फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान और अन्य शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संस्थानों के सहयोग से चलाए जाते हैं। इस वर्ष पुणे में चार सप्ताह का फिल्म एप्रीशिएसन कोर्स आयोजित किया गया जिसमें सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और पाकिस्तान के एक-एक प्रतिभागी सहित, विभिन्न व्यवसायों से जुड़े 63 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

- 12 से 19 जनवरी 2006 के दौरान चौथा पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किया गया जिसके लिए एनएफआई ने ऑडिटोरियम और अपने अभिलेखागार से फिल्में दीं।
- सिंबिओसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, पुणे द्वारा आयोजित लघु फिल्म प्रीशिएसन कोर्स के लिए एनएफएआई ने फिल्में और प्रीव्यू थिएटर प्रदान किया।
- आशय फिल्म क्लब की पहल पर पुणे में चौथे एशियाई फिल्म समारोह में एनएफएआई ने सहयोग दिया।
- मैक्स मूलर भवन, पुणे के सहयोग से एनएफएआई, पुणे में फिल्म और टेलीविजन में महिलाएं समारोह आयोजित किया गया।

एनएफएआई ने पणजी, गोआ में 24 नवंबर से 3 दिसंबर 2006 के दौरान आयोजित भारत के 37वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान वॉल पोस्टर और स्टिल्स की प्रदर्शनी आयोजित की।

अभिलेखागार ने अलायंस फ्रांसे, मैक्समूलर भवन, ब्रिटिश काउंसिल और मुंबई स्थित रूसी सांस्कृतिक केन्द्र के सहयोग से फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और रूस की फिल्मों के समारोह आयोजित किए।

इसके अलावा एनएफएआई ने निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों के लिए भी विशेष सहयोग दिया -

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद द्वारा 23 से 27 जनवरी 2007 द्वारा आयोजित 'अदूर गोपालकृष्णन पुनरावलोकन' के लिए पांच फिल्में प्रदान कीं।
- फिल्म प्रभाग को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (3-9 फरवरी 2006) के लिए पांच फिल्में प्रदान कीं।
- आशय फिल्म क्लब, मैक्समूलर भवन के सहयोग से पुणे में विकलांग फिल्म समारोह आयोजित किया गया।
- इंदिरा स्कूल ऑफ कम्यूनिकेशन ने पुणे में 26 फरवरी से 3 मार्च 2006 के दौरान 'रौलप्ले-2006' आयोजित किया।
- मुंबई में मार्च में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह-2006 के लिए तीन फिल्में प्रदान कीं।

वर्ष 2006-07 के दौरान हासिल की गई फिल्में

पर्दानशीं	आई ए हफीज़जी/हिंदी/1943
रामप्रसाद	डी. गुप्ता/बांग्ला/1947
गुल बकावली कथा	के. कामेश्वर राव/तेलुगु/1962
जुआरी	सूरज प्रकाश/हिंदी/1965
राजहठ	सोहराब मोदी/हिंदी/1966
लग्न पत्रिके	के.एस.एल. स्वामी/कन्नड/1967
रामराज्य	विजय भट्ट/हिंदी/1967
नम्मा मक्कालु	नागेन्द्र राव/कन्नड़/1969
पुनर्जन्म	पी. शिवराम/कन्नड़/1969
प्रीत तुझी-माझी	दिनेश/मराठी/1975
महाकवि कालीदास	आर. आर. चन्द्रन/तमिल/1977
खूबसूरत	ऋषिकेश मुखर्जी/हिंदी/1980
अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है	अख्तर सईद मिर्जा/हिंदी/1981
मक्काली राळव्वा माने तुम्बा	टी एस नागभर्ना/कन्नड़/1984
आगंतुक	एस. हेब्लीकर/कन्नड़/1987
एक होता विदूषक	जब्बार पटेल/मराठी/1992
लिमिटेड मनुस्की	नचिकेत-जयू/मराठी/1995
दैवानामथिल	जयराज/मलयालम/1995
त्रिशक्ति	मधुर भंडारकर/हिंदी/2000
राजू चाचा	अनिल देवगन/गिंजी/2000
लव के लिए कुछ भी करेगा	ई. निवास/हिंदी/2003
रघु रोमियो	रजत कपूर/हिंदी/2003
साया	अनुराग बसु/हिंदी/2003
फुटपाथ	विक्रम भट्ट/हिंदी/2003
श्वास	एस. सावंत/मराठी/2003
जुए पूरा जून	एस. सभापंडित/असमिया/2003
उन्नी	महेश थुट्टाची/मलयालम/2003

चमेली	सुधीर मिश्रा/हिंदी/2003
ऐथे	सी. येलेती/तेलुगु/2003
हसीना	गिरीश कासरावल्ली/कन्नड़/2004
पेरूमझाकलम डब्ल्यू. आई.	कन्नल/मलयालम/2004
देवराय	एस भावे और एस सुकतंकर/मराठी/2004
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस	श्याम बेनेगल/हिंदी/2004
वीरजारा	यश चोपड़ा/हिंदी/2004
दीनबंधू	मुनीन बरूआ/असमिया/2004
ओरिडम/एन एबोड	प्रदीप नायर/मलयालम/2004
डांसर	योगेश के. आर./तमिल/2004
देस हो या परदेस	मनोज पुंज/पंजाबी/2004
कायान्तरण	शशि कुमार/हिंदी/2004
मुगले आज़म (रंगीन)	के. आसिफ/हिंदी/2004
लाज़	मंजू बोरा/असमिया/2004
कथावशेसन	टी वी चंद्रन/मलयालम/2004
बेरू/द रूट	टी शेषाद्रि/कन्नड़/2005
मिक्स्ड डब्ल्स	रजत कपूर/हिंदी/2005
रेन	अमोल शेतघे/हिंदी/2005
किसना	सुभाष घई/हिंदी/2005
कलामंडलम रमनकुट्टी नायर	अदूर गोपालकृष्णन/मलयालम/2005
सरकार	रामगोपाल वर्मा/हिंदी/2005
पहेली	अमोल पालेकर/हिंदी/2005
मिस्टर प्राइममिनिस्टर	देवानंद/हिंदी/2005
म्युजिक आफ सत्यजित राय	उत्पलेन्दु चक्रवर्ती/बांग्ला/2005
द्वितीय बसंत	केश्टो मंडल/बांग्ला/2005

- विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता के मौके पर मैक्स मूलर भवन, अलायंस फ्रांसे, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी के सहयोग से फुटबॉल पर फिल्मों का उत्सव आयोजित किया गया।
- फिल्म 'झांसी की रानी' आशय फिल्म क्लब को प्रदर्शन के लिए दी गई।
- मराठी में पहला लघु फिल्म एप्रीसिएशन कोर्स आयोजित किया गया जिसमें करीब 100 प्रतिभागी शामिल हुए
- नई दिल्ली में जुलाई 2006 ओसियन सिनेफैन-8 उत्सव के लिए पांच फिल्में दी गईं।
- त्रिशूर में 1-8 अगस्त, 2006 तक संपन्न तीसरे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 35 फिल्में भेजी गईं।
- अगस्त 2006 में महाराष्ट्र की जनजातियों पर एक वृत्तचित्र फिल्म समारोह बहुरंग, पुणे द्वारा आयोजित किया गया।
- आशय फिल्म क्लब, पुणे ने अगस्त 2006 में 'राष्ट्र पुरुष' फिल्म समारोह आयोजन किया, जिसके लिए एनएफएआई ने तीन फिल्में - सरदार, बाबासाहब अंबेडकर तथा सुभाषचंद्र बोस भेजीं।
- इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा नई दिल्ली में आयोजित विश्व सिनेमा क्लासिक्स के लिए अभिलेखागार से चार फिल्में भेजी गईं।
- अलायंस फ्रांसे, पुणे, ब्रिटिश लाइब्रेरी मैक्स मूलर भवन तथा राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ने संयुक्त रूप से पुणे में 21-28 सितंबर, 2006 तक चौथे यूरोपियन फिल्म समारोह का आयोजन किया।
- 27 अक्तूबर से 2 नवंबर, 2006 तक त्रिशूर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए 32 फिल्में भेजीं।
- पणजी, गोवा में 22 नवंबर से 3 दिसंबर, 2006 तक चले 37वें अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए फिल्म समारोह निदेशालय को तीन फिल्में दी गईं।
- तिरुअनंतपुरम, केरल में हुए 11वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (8-15 दिसंबर 2006) के लिए तेरह फिल्में भेजी गईं।
- आशय फिल्म क्लब, ईरानी सांस्कृतिक केंद्र; मुंबई तथा इस्त्रायल दूतावास के सहयोग से पुणे में ईरानी और इस्त्रायली फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों और अन्य विशेष अवसरों पर भेजी गईं फिल्में

- 'लंका दहन' और 'श्री कृष्ण जन्म' मूक फिल्में वीडियो फॉर्मेट में फरवरी 2006 में नेशनल म्यूजियम ऑफ सिंगापुर को भेजी गई।
- 'एलिपथायम' न्यूयार्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट को 'टू सेव एंड प्रोजेक्ट - फिल्म प्रिजर्वेशन एक्जीबिशन' के लिए भेजी गई।
- 'शेजारी' और 'दुनिया न माने' फिल्में अगस्त 2006 में 11वें पुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भेजी गईं।
- राजा हरिश्चन्द्र, लंका दहन और सेतुबंधन अगस्त 2006 में फिल्म प्रयोग कार्यक्रम के लिए भेजी गईं।
- 'कालिय मर्दन', 'शीराज़' और 'दिलेर जिगर' फिल्में फिल्म म्यूजियम, बर्लिन (जर्मनी) को वहां सितंबर 2006 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भेजी गईं।
- 'तरंग', 'फायर इन दे बेली' और 'चार अध्याय' फिल्में त्रिवार्षिक समारोह के लिए आस्ट्रेलियन सिनेमाथेक, क्वींसलैंड आर्ट गैलरी, ब्रिस्बेन (आस्ट्रेलिया) को भेजीं गईं।
- सितंबर 2006 में सिंगापुर नेशनल म्यूजियम के दुबारा खोले जाने के अवसर पर भारत की मूक फिल्मों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 'डी जी फाल्के' और 'कालिय मर्दन' के प्रिंट भेजे गए।

थियेटर सुविधाएं

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के पास दो थियेटर हैं, जिनकी क्षमता क्रमश: 330 और 30 सीटों की हैं। अभिलेखागार तथा फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अलावा इनका लाभ (फिल्म-प्रदर्शन, व्याख्यान संगोष्ठियों आदि के आयोजन के लिए) अन्य संस्थाएं भी उठा सकती हैं।

पुणे स्थित मैक्स मुलर भवन, अलायंस फ्रांसे तथा ब्रिटिश काउंसिल के सदस्यों तथा अभिलेखागार फिल्म सर्किल के सदस्यों के लिए नियमित रूप से फिल्म प्रदर्शन होते हैं। आलोच्य अवधि के दौरान, 511 कार्यक्रमों के लिए मुख्य ऑडिटोरियम तथा प्रीव्यू थियेटर किराए पर दिए गए।

अनुसंधान गतिविधियां

आलोच्य अवधि के दौरान तीन अनुसंधान कार्यक्रम - इंडियन डाक्यूमेंटरी फिल्म्स हिस्ट्री, प्रजेंट एंड मार्केट, 'स्टडी आन वुमेन्स वॉइसेज़ इन टेन इंडियन फिल्म्स डाइरेक्टेड बाई मैन (1959-2003)', 'कंट्रीब्यूशन ऑफ कोल्हापुर स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग टू इंडियन सिनेमा' तथा पी.सी. बरुआ पर एक मोनोग्राफ परियोजना पूरी की गई।

अनुलग्नक-क

31 दिसम्बर, 2006 को समाप्त हुए वर्ष में अभिलेखागार द्वारा प्राप्त सामग्री

सामग्री	31-12-2005	जनवरी-दिसम्बर 2006	31.12.2006
फिल्में	**16,133**	**428**	**16,561**
वीडियो कैसेट्स	**2,264**	**29**	**2,293**
किताबें	**25,500**	**382**	**25,882**
पटकथाएं	**33,180**	**568**	**33,748**
प्रो रिकॉर्डेड ऑडियो कैसेट्स	**1,098**	**—-**	**1,098**
स्टिल्स	**1,24,772**	**2,063**	**1,26,835**
दीवार पोस्टर	**13,671**	**343**	**14,014**
संगीत पुस्तिकाएं	**10,455**	**293**	**10,748**
ऑडियो टेप	**172**	**—-**	**172**
प्रेस कतरनें	**1,59,709**	**39,275**	**1,98,984**
पेंफ्लेट्स/फील्डर्स	**8,002**	**51**	**8,053**
स्लाइड्स	**8,483**	**29**	**8,512**
माइक्रोफिस्च	**42**	**—-**	**42**
माइक्रोफिल्म्स	**1,957**	**—-**	**1,957**
डिस्क रिकॉर्ड्स	**2,973**	**151**	**3,124**
ऑडियो कम्पेक्ट डिस्क्स	**155**	**—-**	**155**
डी वी डी	**287**	**326**	**613**
सीडी पर परिवर्तित इमेज़ेज	**—-**	**868**	**868**

अनुलग्नक-ख

योजना निष्पादन 2006-2007

(लाख रुपये में)

कार्यक्रम/योजना	अनुमोदित योजना परिव्यय **2006-07**	पूर्वानुमानित व्यय **2006-07** के दौरान	नवम्बर 2006 तक का खर्च
चालू योजना			
अभिलेखागार द्वारा फिल्मों का अधिग्रहण और प्रदर्शन	**73.00**	**73.00**	**51.89**
नई योजना			
पुणे में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के लिए भवन निर्माण का द्वितीय चरण	**400.00**	**647.00**	**122.00**
योग	**473.00**	**720.00**	**173.89**

अनुलग्नक-ग

एनएफएआई की मुख्य गतिविधियों से संबंधित आंकड़े

	रीलों की संख्या	
	16 एम.एम.	**35** एम.एम.
1. फिल्मों की विस्तृत जांच	**4**	**89**
2. फिल्मों की नियमित जांच	**607**	**20,594**
फिल्म संस्कृति को प्रोत्साहन		
1. पुस्तकालय सदस्यों में फिल्मों का वितरण		**41**
2. लाइब्रेरी सदस्यों में फिल्मों के वितरण की संख्या		**95**
3. विशेष अवसरों के लिए फिल्मों का वितरण		**3571**
4. संयुक्त प्रदर्शन		**58**
5. फिल्म प्रोत्साहन पा्यक्रमों के लिए फिल्मों का वितरण		**237**
6. प्रोड्यूसर/कॉपीराइट मालिकों को वीडियो बनाने के लिए फिल्मों का वितरण		**21**
7. शोधार्थियों के लिए फिल्म देखने की सुविधाओं में विस्तार		**31**
8. एफ.टी.आई.आई. को शैक्षिक प्रदर्शनों के लिए फिल्मों का वितरण		**166**
9. दिखाई गई फिल्मों की कुल संख्या		**228**
10. लाइब्रेरी सेवा प्राप्त करने वाले पाठकों की संख्या		**1789**
11. प्रलेखन खंड की सेवाएं प्राप्त करने वाले शोधार्थियों की संख्या		**1926**

संरक्षण कार्य

भारत की फिल्म परंपरा की सुरक्षा तभी हो सकती है जब उसके संरक्षण के लिए सतत और विशेष प्रयास किए जाएं। इस कार्य में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार अपने स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आलोच्य अवधि के दौरान अभिलेखागार व सुरक्षा आधार पर 7360 मीटर की नाइट्रेट फिल्म को सुरक्षा बेस में डाला।

निर्माताओं/कॉपीराइट मालिकों को सुविधाएं

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार डिपॉजिट समझौते के तहत निर्माताओं और कॉपीराइट मालिकों को अपनी सेवाएं देने के प्रति वचनबद्ध है। इन सेवाओं के तहत मूल निगेटिव की मरम्मत के लिए फिल्म की आपूर्ति, प्रसारण के लिए डुप्लीकेट कॉपी तथा वीडियो कॉपी तैयार करना शामिल है। अभिलेखागार ने हाल के वर्षों में अपनी पहल पर कई फिल्मों का पुनरुद्धार किया है। अभिलेखागार ने कई सेटेलाइट चैनलों और राष्ट्रीय उपग्रह टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाली फिल्मों को प्रसारण के लिए भी दिया है।

इन गतिविधियों का विवरण अनुलग्नक-ग में दिया गया है।

योजना तथा गैर योजना कार्यक्रम

योजना परिव्यय

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का वर्ष 2006-07 के दौरान दो योजनाओं के लिए 473 लाख रुपये के बजट का प्रावधान था। जनवरी से दिसंबर 2006 के दौरान प्राप्त फिल्मों और अन्य सामग्री का विवरण इसी अध्याय में पहले दे दिया गया है।

जनवरी-मार्च 2007 के दौरान प्रस्तावित कार्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

- इस अवधि में 50 फिल्में, 50 वीडियो कैसेट और डीवीडी हासिल की जानी हैं।
- अभिलेखागार भवन, पुणे के निर्माण के दूसरे चरण का काम पूरा हो जाने की आशा है।

प्रशासन

संगठनात्मक ढांचा

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय पुणे में है। इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर, कोलकाता तथा तिरुअनंतपुरम में स्थित हैं। इन क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रमुख कार्य फिल्म समितियों, शिक्षा संस्थानों तथा सांस्कृतिक संगठनों के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में फिल्म संस्कृति को बढ़ावा देना है। क्षेत्रीय कार्यालयों की देख-रेख निदेशक करते हैं। उप निदेशक-सह-क्यूरेटर इस कार्य में उनकी मदद करते हैं जो मुख्यालय में तकनीकी और प्रशासनिक स्कंधों के भी प्रमुख हैं। अभी उप निदेशक-सह-क्यूरेटर ही निदेशक का काम देख रहे हैं। इस समय भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में 52 कर्मचारी हैं, जिनमें से 25 प्रशासनिक विंग में तथा 27 तकनीकी विंग में कार्य कर रहे हैं।

अंतराष्ट्रीय फिल्म अभिलेखन परिसंघ (एफआईएएफ)

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार मई 1969 से एफआईएएफ का सदस्य है। इसका सदस्य होने की वजह से विशेषज्ञों की सलाह, संरक्षण-तकनीकी, प्रलेखन और ग्रंथ-सूचियां तैयार करने आदि के बारे में सामग्री प्राप्त होती रहती है। परिसंघ के माध्यम से अन्य अभिलेखागारों से दुर्लभ फिल्मों के आदान-प्रदान की सुविधा भी प्राप्त होती है।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

इन सभी वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को नियमानुसार करा गया है।

कार्ययोजना का क्रियान्वयन

पुणे में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार भवन के दूसरे चरण या निर्माण कार्य चल रहा है। यह परियोजना दसवीं योजना के अंत तक पूरी हो जाएगी।

सरकारी काम-काज में हिंदी का प्रयोग

14 से 30 दिसंबर 2006 के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए।

प्रतिनियुक्ति/शिष्टमंडल

एनएफएआई निदेशक ने साओ पाउलो, ब्राजील में 26 अप्रैल, 2006 से 4 मई 2006 तक अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख परिसंघ की 62वीं कांग्रेस में संगोष्ठी तथा आम सभा में भाग लिया।

निदेशक ने म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट, नीस (फ्रांस) द्वारा 3-6 जुलाई 2006 तक आयोजित 'देवी दीवा' पोस्टर प्रदर्शनी में भी हिस्सा लिया। एनएफएआई ने प्रदर्शनी के लिए कुछ मूल पोस्टर भी भेजे।

आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण तथा ई-प्रशासन

अभिलेखागार एक सांस्कृतिक तथा अनुसंधान संगठन है, जिसका प्रमुख कार्य भारतीय सिनेमा की विरासत को संरक्षित करना है। यह देश में फिल्म संस्कृति के प्रसार का काम भी करता है।

देश विदेश के विभिन्न भागों के आम दर्शक, सिनेमा के गंभीर विद्यार्थी तथा शोधकर्ता वेबसाइट के जरिए एनएफएआई के संग्रह तथा सेवाओं तक आसानी से पहुंच सकते हैं। फिल्म सर्किल के लिए आवेदन का फॉर्मेट तथा वितरण लाइब्रेरी सदस्यता वेबसाइट पर उपलब्ध है। ई-मेल (nfai@vsnl.net.) के द्वारा लोगों की शंकाओं का समाधान किया जाता है। संस्थान में इंटरसेट, फैक्स तथा स्कैनिंग की सुविधाएं भी हैं।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 के अंतर्गत हुई थी। यह सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करता है। बोर्ड में एक अध्यक्ष और 25 गैर-सरकारी सदस्य होते हैं। बोर्ड का मुख्यालय मुम्बई में है और इसके नौ क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर, कोलकाता, चेन्नई, कटक, गुवाहाटी, हैदराबाद, मुंबई और तिरुअनंतपुरम में है। फिल्मों की जांच के काम में क्षेत्रीय कार्यालयों की मदद के लिए विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों के सलाहकार पैनल बने हुए हैं। प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर 13 अक्तूबर, 2004 से बोर्ड की अध्यक्ष हैं।

जनवरी से दिसंबर 2006 के दौरान बोर्ड ने 10,551 प्रमाणपत्र जारी किए जबकि 2005 के दौरान 7417 प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। इनमें से 3454 प्रमाणपत्र सेल्युलाइड फिल्मों के लिए और 7097 वीडियो फिल्मों के लिए जारी किए गए। रिपोर्ट की अवधि के दौरान 1091 भारतीय फीचर फिल्में (सेल्युलाइड) और 336 विदेशी फीचर फिल्में प्रमाणित की गईं। प्रमाणपत्र और वर्ग के आधार पर प्रमाणित फिल्मों का विवरण अनुलग्नक - 1 में दिया गया है। भारतीय फीचर फिल्मों का क्षेत्रवार/भाषा और विषयों के आधार पर विवरण संलग्नक - 2 और 3 में दिया गया है।

जनवरी से दिसंबर 2006 के दौरान प्रमाणित 1636 भारतीय फीचर फिल्मों में से 1130 को 'यू', 270 को 'यूए' और 236 को 'ए' प्रमाणपत्र दिए गए। इसी तरह, 1080 विदेशी फीचर फिल्मों में से 460 को 'यू', 269 को 'यूए' और 351 को 'ए' प्रमाणपत्र दिए गए।

बोर्ड ने 7242 भारतीय लघु फिल्मों को जनवरी से दिसंबर 2006 के दौरान प्रमाणपत्र दिए। इनमें 6717 को 'यू', 359 को 'यूए' और 165 को 'ए' प्रमाणत्र दिए गए। एक फिल्म को 'एस' प्रमाणपत्र दिया गया। 513 विदेशी लघु फिल्मों में से 344 को 'यू', 102 को 'यूए' और 67 को 'ए' प्रमाणपत्र दिए गए।

जनवरी से दिसंबर 2006 के दौरान 7097 वीडियो फिल्मों को प्रमाणपत्र जारी किए गए। इनमें से 545 भारतीय फीचर फिल्में, 744 विदेशी फीचर फिल्में, 5494 भारतीय लघु फिल्में और 235 विदेशी लघु फिल्में थीं। 75 भारतीय और 4 विदेशी फिल्मों को 'अन्य' वर्ग के तहत प्रमाणित किया गया। (इन फिल्मों की लंबाई फीचर फिल्मों से ज्यादा थी।)

जनवरी से दिसंबर 2006 के दौरान 48 भारतीय फीचर फिल्मों और 4 विदेशी फीचर फिल्मों को प्रमाणपत्र नहीं दिया गया क्योंकि ऐसा पाया गया कि ये फिल्में सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के अनुच्छेद 5-बी (2) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी वैधानिक निर्देशों में से एक या अधिक निर्देशों का उल्लंघन करती थीं। इनमें से कुछ फिल्मों को बाद में उनके संशोधित रूप में प्रमाणपत्र दिए गए।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की 108वीं बैठक 27 मार्च, 2006 को हुई। 109वीं बैठक 31 जुलाई, 2006 को बंगलौर में और 11वीं बैठक 17 दिसंबर 2006 को पुदुचेरी में हुई।

फिल्म प्रमाणन के बारे में जानकारी देने के लिए सलाहकार पैनल के सदस्यों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं। परीक्षण अधिकारियों और सलाहकार पैनलों के लिए पिछले वर्ष की तरह ये कार्यशालाएं विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों में लगाई गई। दक्षिण क्षेत्र के सलाहकार पैनल के सदस्यों के लिए 303 दिन की कार्यशालाएं मुंबई और बंगलौर में आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं में फिल्मों की जांच के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों पर चर्चा हुई और विभिन्न दिशा-निर्देशों को स्पष्ट करने के लिए कुछ चुनी हुई फिल्मों के हिस्से प्रदर्शित किए गए। आचार संहिता और अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया गया।

सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड और केंद्र सरकार को फिल्मों के प्रदर्शन के दौरान बोर्ड के फैसले लागू करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रशासनों के पास है। बोर्ड ने समय-समय पर फिल्म प्रदर्शन संबंधी फैसले लागू करने वाले अधिकारियों से इस बारे में कारगर कदम उठाने का अनुरोध किया है।

जनवरी से दिसंबर 2006 के दौरान विभिन्न स्थानों पर फिल्मों के अंदर चोरी-छिपे दूसरी सामग्री डालने के 45 मामलों का पता चला और इन मामलों में संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेटों को पुष्टि रिपोर्ट भेजी गईं।

अनुलग्नक - I

प्रमाणित फिल्मों के आंकड़े
(1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2006 तक)

सेल्यूलाइड

	'यू'	'यूए'	'ए'	'एस'	कुल
भारतीय फीचर फिल्में	**624**	**248**	**219**	**-**	**1091**
विदेशी फीचर फिल्में	**85**	**76**	**175**	**-**	**336**
भारतीय लघु फिल्में	**1605**	**102**	**40**	**1**	**1748**
विदेशी लघु फिल्में	**147**	**84**	**47**	**-**	**278**
फीचर फिल्मों के अतिरिक्त लंबी अवधि की भारतीय फिल्में	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
फीचर फिल्मों के अतिरिक्त लंबी अवधि की विदेशी फिल्में	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**
योग	**2462**	**510**	**481**	**1**	**3454**
	वीडियो				
भारतीय फीचर फिल्में	**506**	**22**	**17**	**-**	**545**
विदेशी फीचर फिल्में	**375**	**193**	**176**	**-**	**744**
भारतीय लघु फिल्में	**5112**	**257**	**125**	**-**	**5494**
विदेशी लघु फिल्में	**197**	**18**	**20**	**-**	**235**
फीचर फिल्मों के अतिरिक्त लंबी अवधि की भारतीय फिल्में	**68**	**7**	**-**	**-**	**75**
फीचर फिल्मों के अतिरिक्त लंबी अवधि की विदेशी फिल्में	**4**	**-**	**-**	**-**	**4**
योग	**6262**	**497**	**338**	**-**	**7097**
सर्व योग (सेल्यूलाइड तथा वीडियो)	**8724**	**1007**	**819**	**1**	**10551**

अनुलग्नक - II

1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2006 तक प्रमाणित भारतीय फिल्में

(क्षेत्रानुसार, भाषानुसार सेलूलाइड फिल्में)

क्र. संख्या	भाषा	मुंबई	कोलकाता	चेन्नई	बंगलौर	तिरुअनंतपुरम	हैदराबाद	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
1)	हिंदी	171	2	12	4	4	30	-	-	-	223
2)	तमिल	-	1	140	8	3	10	-	-	-	162
3)	तेलुगु		-	52	6	15	172	-	-	-	245
4)	मलयालम	2	-	1	2	68	4	-	-	-	77
5)	कन्नड़		-	-	75	-	-	-	-	-	75
6)	बांग्ला	2	39	-	-	-	1		-	-	42
7)	गुजराती	16	-	-	-	-	-	-	-	-	16
8)	मराठी	73	-	-	-	-	-	-	-	-	73
9)	अंग्रेजी	7	1	-	-	1	1	—	-	-	10
10)	उड़िया	1	4	-	-	-	-	-	16	-	21
11)	असमिया	1	1	-	-	-	-	-	-	5	7
12)	छत्तीसगढ़ी	3	-	-	-	-	-	-	1	-	4
13)	राजस्थानी	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
14)	भोजपुरी	72		-	-	-	2	-	2	-	76
15)	पंजाबी	12		-	-	-	-	-	-	-	12
16)	हरियाणवी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17)	तमिल (डब की गईं)	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11
18)	कोंकणी	1	-	-		-	-	-	-	-	1
19)	तेलुगु (डब की गईं)	17	-	-	-	-	-	-	-	-	17
20)	मराठी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
21)	संथाली	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
22)	हिंग्लिश	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23)	सद्री	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
24)	फारसी – अंग्रेजी	1	-	-	-	-	-	-	—	-	1
25)	नेपाली	4	-	-	-	-	-		-	-	4
26)	टुलु	-	-	-	2	-	-	-	-	—	2
	योग	**403**	**51**	**205**	**97**	**91**	**220**	**-**	**19**	**5**	**1091**

अनुलग्नक - III

प्रमाणित भारतीय फीचर फिल्मों का विषय-वस्तु के अनुसार वर्गीकरण
(1 जनवरी, 2006 से 31 दिसंबर 2006 तक)
(सेल्यूलॉइड)

क्र. संख्या	विषय-वस्तु	मुंबई	कोलकाता	चेन्नई	बंगलौर	तिरुअनंतपुरम	हैदराबाद	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
1)	सामाजिक	304	51	122	67	63	160	-	19	5	791
2)	आपराधिक	7	-	15	20	13	12	-	-	-	67
3)	हॉरर	9		-	1	2	2	-	-	-	14
4)	धार्मिक	4	-	1	2	-	4	-	-	-	11
5)	एक्शन	4	-	66	-	8	4	-	-	-	82
6)	बाल फिल्में	6	-	-	-	-	5		-	-	11
7)	फैंटेसी	8	-		-	2	-		-	-	10
8)	मिथकीय	16	-	-	-	-	-	-	-	-	16
9)	कॉमेडी	23	-	1	1	1	10	-	-	-	36
10)	शिक्षाप्रद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11)	एक्शन/थ्रिलर	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
12)	व्यंग	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
13)	थ्रिलर	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11
14)	ऐतिहासिक	4	-	-	1	-	1	-	-	-	6
15)	जीवनी	-	-	-		-	-	-	-	-	-
16)	साइंस फिक्शन	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17)	मिस्ट्री/थ्रिलर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18)	अन्य	-	-	-	3	-	17	-	-	-	20
19)	लीजेंड्री	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
20)	रोमांच	1	-	-		-	-	-	—	-	1
21)	सस्पेंस	-		-	-	-	2	-	-	-	2
22)	वृत्तचित्र	-		-	-	1	-	-	-	-	1
23)	रोमांटिक कॉमेडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24)	यौन शिक्षा	-	-	-	-	-	1				1
25)	परा-मनोविज्ञान	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
26)	ट्रेजेडी	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
27)	स्पूफ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	योग	403	51	205	97	91	220	-	19	5	1091

अनुलग्नक - IV

प्रमाणित भारतीय फीचर फिल्में (1 जनवरी, 2006 से 31 दिसंबर 2006 तक)
क्षेत्र तथा देश के अनुसार (सेल्यूलॉइड)

क्र. संख्या	विषय-वस्तु	मुंबई	कोलकाता	चेन्नई	बंगलौर	तिरुअनंतपुरम	हैदराबाद	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
1	सं.रा. अमरीका	**252**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**254**
2	हांगकांग	**31**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35**
3	इटली	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**
4	ब्रिटेन	**6**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**
5	थाइलैंड	**8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**
6	ईरान	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**
7	डेनमार्क	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**
8	कोरिया	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**
9	फ्रांस	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**
10	कनाडा	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**
11	जर्मनी	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**
12	जापान	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**
13	न्यूज़ीलैंड		**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**
14	स्पेन		**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**
	योग	**325**		**11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**336**

अनुलग्नक - V

प्रमाणित भारतीय फीचर फिल्मों का विषय वस्तु के अनुसार वर्गीकरण

(1 जनवरी, 2006 से 31 दिसंबर 2006 तक)

(सेल्यूलॉइड)

क्र. संख्या	विषय-वस्तु	मुंबई	कोलकाता	चेन्नई	बंगलौर	तिरुअनंतपुरम	हैदराबाद	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
1.	बाल फिल्में	**16**	-	-	-	-	-	-	-	-	**16**
2.	फेंटेसी	**32**	-	-	-	-	-	-	-	-	**32**
3.	सामाजिक	**33**	-	**4**	-	-	-	-	-	-	**37**
4.	थ्रिलर	**45**	-	-	-	-	-	-	-	-	**45**
5.	हॉरर	**67**	-	-	-	-	-	-	-	-	**67**
6.	एक्शन/थ्रिलेर	**12**	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**
7.	कॉमेडी	**26**	-	-	-	-	-	-	-	-	**26**
8.	ऐतिहासिक	**2**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**
9.	एक्शन	**37**	-	**5**	-	-	-	-	-	-	**42**
10.	अपराधिक	**16**	-	**1**	-	-	-	-	-	-	**17**
11.	साईंस फिक्शन	**10**	-	-	-	-	-	-	-	-	**10**
12.	रोमांचक	**21**	-	-	-	-	-	-	-	-	**21**
13.	जीवनी	**2**	-	**1**	-	-	-	-	-	-	**3**
14.	ऐनिमेटेड	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
15.	अन्य	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
16.	रोमांटिक	**1**									**1**
17.	वृत्तचित्र	**1**									**1**
18.	स्पूफ	**1**									**1**
19.	रहस्यपूर्ण	**1**									**1**
	कुल	**325**	-	**11**	-	-	-	-	-	-	**336**

बाल फिल्म समिति, भारत (सीएफएसआई)

प्रस्तावना

बाल फिल्म समिति, भारत (सीएफएसआई) की स्थापना मई 1955 में फिल्म जांच समिति (1949) की सिफारिशों और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, की पहल पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में की गई। इसका पंजीकरण समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत किया गया। समिति का मुख्य उद्देश्य बच्चों और युवाओं को फिल्मों के माध्यम से जीवन-मूल्यों पर आधारित मनोरंजन उपलब्ध करना है।

समिति के अध्यक्ष सिने-जगत के कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। वह कार्यकारिणी परिषद और साधारण सभा का प्रमुख होते हैं जिनमें सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। प्रशासन, निर्माण, विपणन संबंधी रोजमर्रा के कामकाज मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा देखे जाते हैं जिसके अधीन सभी विभागाध्यक्ष होते हैं।

वर्ष 2006-07 के दौरान गतिविधियां

(क) निर्माण :

31-12-2006 तक की पूरी हुई फिल्में

	फिल्म	निदेशक
1.	लिलकी (हिन्दी फीचर फिल्म)	बातुल मुख्तियार
2.	नन्दू का राजा (हिन्दी फीचर फिल्म)	शालोन शर्मा
3.	मां. . .आ-आ. (हिन्दी लघु एनिमेसन फिल्म)	चेतन शर्मा
4.	द स्टोरी ऑफ नोकपोकलिबा (लघु एनिमेशन)	मेरेन इम्चेन
5.	मन पसंद (परफैक्ट मैच) (हिन्दी लघु एनीमेशन)	ध्वनि देसाई
6.	एक आदेश - (कमांड फॉर छोटी) (हिन्दी लघु फिल्म)	रमेश आशेर
7.	आंखमिचोली (हाइड एण्ड सीक) (हिन्दी फीचर फिल्म)	विनोद गनात्रा
8.	सुनामी-81 (हिन्दी फीचर फिल्म)	नईम शॉ
9.	सीएफएसआई लोगो	मैसर्स ग्रैफिटी

निर्माणाधीन फिल्म (पिछले वर्ष से जारी और निर्माणाधीन नई फिल्में)

	फिल्म	निदेशन
1.	कठपुतली (हिन्दी लघु एनिमेशन फिल्म)	चार्मी छेदा
2.	पातालेर राजपुत्र (हिन्दी फीचर फिल्म)	गौतम बेनेगल
3.	फोटो द फिल्म मेकर (फोटो) (हिन्दी फीचर फिल्म)	वीरेन्द्र शैती
4.	महक (हिन्दी फीचर फिल्म)	क्रांति कनाडे
5.	सुरभि (हिन्दी फीचर फिल्म)	विशाल चतुर्वेदी
6.	अमूल्यम् (तेलगु फीचर फिल्म)	अक्किनेनी के. राव

(ख) डबिंग : वर्ष 2006-07 के दौरान (31-12-06 तक) निम्नलिखित फिल्मों की डबिंग पूरी की गई:

1. हयात (फारसी से हिन्दी)

वर्ष के दौरान शुरू की गई डबिंग:

1. पिंकी एण्ड मिलियन पग (यंग डिटेक्टिव): जर्मन से अंग्रेजी
2. लाडली (फीचर फिल्म) हिन्दी से तमिल/तेलुगु और कन्नड़

खरीदी जाने वाली और खरीदी गई फिल्में

1. एल्बम (फीचर फिल्म) ईरान
2. द स्टोरी आफ जिआओ जिंग चीन

(ग) विपणन गतिविधियां : अप्रैल, 2006 से दिसंबर 2006 तक सीएफएसआई की विपणन गतिविधियां:

फिल्म प्रदर्शन का तरीका निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

1. स्कूलों और थियेटरों में प्रदर्शन
2. जिला प्रशासनों के सहयोग से फिल्म समारोह
3. जनजातीय इलाकों के नगरपालिका स्कूलों में सुविधाओं से वंचित बच्चों के लिए नि:शुल्क प्रदर्शन
4. वितरकों के माध्यम से 35 मि.मि. और 16 मि.मी. के प्रोजेक्टरों से फिल्म प्रदर्शन
5. राज्य भर के सभी जिलों के सिनेमा घरों को शामिल करते हुए राज्य-स्तरीय फिल्म समारोह आयोजित करना।

बाल फिल्म समिति का मुख्यालय मुंबई में है, जिसके शाखा कार्यालय नई दिल्ली और चेन्नई में है।

बाल फिल्म समिति की विपणन इकाई देशभर में फिल्म-प्रदर्शन गतिविधियों को बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करती है। सीएफएसआई शहरी और ग्रामीण क्षत्रों में स्कूली और गैर-स्कूली बच्चों के लिए भी फिल्म-प्रदर्शन करती है। फिल्म प्रदर्शन का तरीका आगे उल्लिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

सीएफएसआई का विपणन प्रभाग, अपने मुंबई स्थित मुख्यालय और

क्र.सं.	गतिविधि	प्रदर्शनों की संख्या	दर्शक-संख्या
1.	जिला और राज्य स्तरीय फिल्म समारोह नगर पालिका स्कूलों में प्रदर्शन	3387	19,42,113
2.	वितरकों के माध्यम से फिल्मों का प्रदर्शन	933	3,55,400
3.	वैयक्तिक प्रदर्शन	66	30,071
4.	नि:शुल्क प्रदर्शन	972	2,93,177
	योग	**5,358**	**26,20,761**

दिल्ली तथा चेन्नई स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से लक्षित दर्शकों तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है। यह छोटी सी विपणन इकाई 3358 प्रदर्शनों का आयोजन करते हुए 26,20,761 दर्शकों तक पहुंच बना चुकी है।

ऊपर दर्शाई गई श्रेणियों के तहत अलग-अलग प्रदर्शनों के बारे में विवरण इस प्रकार है।

1. **वैयक्तिक फिल्म प्रदर्शन :** कुछ स्कूलों द्वारा या व्यक्तिगत स्तर पर गैर-व्यावसायिक उद्देश्य से सिनेमाघरों या स्कूलों में 35 एम.एम./16 एम.एम. के प्रोजेक्टर से निर्धारित शुल्क देकर फिल्मों का प्रदर्शन कराया जाता है। ऐसे 66 प्रदर्शन आयोजित कर 30,071 बच्चों को दिखाए गए।

2. **जिला स्तरीय फिल्म समारोह :** यह कार्य संबद्ध जिला प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है। विभिन्न राज्यों में ऐसे 6-7 जिले चुने जाते हैं और नाममात्र के प्रवेश शुल्क के साथ फिल्म-प्रदर्शन का कार्यक्रम तैयार किया जाता है। मुख्य रूप से सरकारी/नगरपालिकों स्कूलों के बच्चों को ऐसे फिल्म प्रदर्शनों के लिए प्रेरित किया जाता है। जिला शिक्षा-विभाग टिकट बेचकर सहयोग पहुंचाता है। इस प्रकार की गतिविधियां, सीएफएसआई के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत भी हैं।

राज्यवार/जिलावार समारोह

राज्य/जिला	प्रदर्शनों की संख्या	दर्शक-संख्या
तमिलनाडु		
मदुरै	70	43233
कन्याकुमारी	79	53322
तंजावूर	56	40,000
चेन्नई	21	21,000
नागपट्टनम	65	45,000
नमक्कल	60	40,000
कुड्डालूर	74	50,000
कर्नाटक		
गुलबर्गा	90	60,000
मंड्या	80	50,000
चामराजनगर	70	45,000
आंध्र प्रदेश		
खम्मम	35	18,563
नेल्लोर	40	35,000
विजयानगरम	70	40,000
विशाखापटनम	100	60,000
पंजाब		
मोगा	12	8,000
मुक्तसर	20	10,000
होशियारपुर	20	10,000
उत्तर प्रदेश		
मेरठ	30	15,000
झारखंड		
जमशेदपुर	100	54,360
उड़ीसा		
खुर्दा/भुवनेश्वर	40	16842
बालासोर	70	27206
बारीपदा	50	16935
कटक	45	21147
केन्द्रपाड़ा	15	5625
बिहार		
बेतिया	54	17559
मोतिहारी	65	17580
गोपालगंज	48	7794
छपरा	24	9010
सासाराम	55	1169
आरा	21	9887
सीतामढ़ी	58	15211
महाराष्ट्र		
नासिक	100	90,500
धुले	65	46,870

नंदूरबार	25	18500
जलगांव	125	89600
उत्तराखंड		
अल्मोड़ा	12	5000
राज्य/जिला	**प्रदर्शनों की संख्या**	**दर्शक-संख्या**
नैनीताल	42	20,000
हरियाणा		
पंचकुला	14	8,000
पानीपत	24	12,000
राज्य स्तरीय समारोह		
छत्तीसगढ (16जिले)	500	2,50,000
मध्य प्रदेश (46 जिले)	1343	5,37,200
योग	**3,887**	**19,42,113**

3. निःशुल्क प्रदर्शन - ग्रामीण, जनजातीय और सरकारी स्कूलों में सुविधाओं से वंचित उन बच्चों जिन्हें मनोरंजन के साधन प्रायः उपलब्ध नहीं है, के लिए सीएफएसआई ने निशुल्क फिल्म प्रदर्शन की एक अनोखी योजना शुरू की है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन जैसे गैर-सरकारी संगठनों की सेवाएं ली जाती हैं। ऐसे निशुल्क प्रदर्शनों पर होने वाला खर्च सीएफएसआई की अनुदान राशि के अलावा सरकार द्वारा इसी उद्देश्य के लिए नियत धन से करती है। इस योजना के तहत आश्रयगृहों और सुधार गृहों में रहने वाले बच्चों को भी फिल्में दिखाई जाती हैं।

4. वितरकों के माध्यम से फिल्म प्रदर्शन

सीएफएसआई थिएटरों और स्कूलों में फिल्म प्रदर्शनों के आयोजन के लिए वितरकों/आयोजकों की सेवाएं लेती हैं। ये लोग मासिक दर पर शुल्क अदा कर फिल्में प्राप्त करते हैं और निर्धारित क्षेत्रों में उन्हें दिखाते हैं। करीब 3,55,400 दर्शकों को फिल्मों के 933 प्रदर्शन दिखाए गए।

5. **राज्य स्तरीय फिल्म समारोह**

मध्य प्रदेश राज्य सरकार सीएफएसआई के साथ सहयोग करते हुए राज्य भर में बड़े पैमाने पर फिल्म प्रदर्शन आयोजित करती है। बहुत ही कम समय में सीएफएसआई की ओर से प्राप्त 60-70 फिल्मों का एक पैकेज राज्य के विभिन्न थिएटरों में प्रदर्शित किया गया। मध्य प्रदेश के 46 जिलों में फिल्मों के 1343 प्रदर्शन आयोजित हुए जिससे करीब 537200 बच्चे लाभान्वित हुए। छत्तीसगढ़ में 16 जिलों के करीब 2,50,000 बच्चों के लिए 500 प्रदर्शन आयोजित किए गए।

6. अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भागीदारी

बाल फिल्म समिति, भारत की फिल्मों को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रवेश मिला है।

7. एनिमेशन और फिल्म निर्माण कार्यशालाएं

सीएफएसआई की ओर से फिल्म निर्माण और उसके विभिन्न आंतरिक पहलुओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दो कार्यशालाएं आयोजित की गईं। यह योजना कार्यक्रम का हिस्सा है।

एनिमेशन और फिल्म निर्माण कार्यशालाओं का विवरण

क्र. सं.	राज्य	तिथि	कार्यशाला की संख्या
1	मणिपुर	24 और 25 मई 2006	1
2	मिज़ोरम	16 और 17 मई 2006	1
3.	आजमगढ़ (उ.प्र.)	8 और 9 नवम्बर 2006	1

8. टेलीविजन से फिल्म प्रदर्शन

समिति की पुरस्कृत फिल्म मल्ली (तमिल) बाल दिवस के अवसर पर (14.11.2004 को) मक्कल टी.वी. पर प्रदर्शित की गई।

वीएचएस कैसेट और वीसीडी की बिक्री

सीएफएमआई की फिल्मों के वीएचएस कैसेट और सीडी की बिक्री केवल व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रदर्शनों के लिए की जाती है। कुल 521 वीएचएस और वीसीडी की बिक्री की गई।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में गतिविधियां

सीएफएसआई निर्माण और प्रदर्शन के जरिए पूर्वोत्तर सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी फिल्मों को प्रोत्साहन देती है। सीएफएसआई ने मई 2006 में मणिपुर और मिज़ोरम में फिल्म मूल्यांकन कार्यशाला का आयोजन किया और संगठनों की मदद से जगह-जगह फिल्म प्रदर्शन भी आयोजित किए गए।

स्वर्ण जयंती फिल्म समारोह

सी एफ एस आई ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 14 से 18 नवंबर 2006 को नई दिल्ली के सीरी फोर्ट सभागार में स्वर्ण जयंती फिल्म समारोह का आयोजन किया। तीन वर्गों के अंतर्गत – क्लासिक्स, लोकप्रिय और क्षेत्रीय महत्व की फिल्में प्रदर्शित की गईं। फिल्म निर्माण में उन्नत प्रौद्योगिकी के महत्व को दर्शाने के लिए सीएफएसआई ने बच्चों के लिए डिजिटल फिल्मों का प्रदर्शन शुरू किया। विदेशों के निर्माताओं और निर्देशकों की डिजिटल फिल्मों के पैकेज मंगाए गए और इनकी फिल्में समारोह में प्रदर्शित की गईं।

सीएफएसआई फिल्मों के निदेशक – श्री राजीव मोहन, श्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, श्री सलीम पडियाथ, श्री अरूण खोपकर और डिजिटल फिल्म निर्माता – सुश्री मीना नाइक, श्री राज सिंह, श्रीमती आर. भुवाना को प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया और उन्हें समारोह में सम्मानित किया गया।

दिल्ली सरकार के सहयोग से करीब 27,000 बच्चों को फिल्म देखने के लिए प्रेरित किया गया।

14 नवम्बर 2006 को यू.पी.ए. अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने दीप प्रज्ज्वलित कर इस समारोह का उद्घाटन किया। यह समारोह सीरी फोर्ट के मुख्य सभागार में आयोजित हुआ जिसमें सूचना और प्रसारण मत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी और सीएफएसआई की अध्यक्ष श्रीमती नफीसा अली सोढी भी मौजूद थी। इस मौके पर श्रीमती नफीसा अली सोढी ने सीएफएसआई की गतिविधियों को जारी रखने और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने के लिए और सहायता तथा सहयोग की मांग की।

यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी और बाल फिल्म समिति की अध्यक्ष श्रीमती नफीसा अली सोधी की उपस्थिति में 14 नवंबर 2006 को सी एफ एस आई स्वर्ण जयंती फिल्म समारोह का उद्घाटन करते हुए

अप्रैल से दिसंबर 2006 तक निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में दिखाई गई सी.एफ.एस.आई. की फिल्में

समारोह का नाम	देश	शामिल फिल्म
मेन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	सं.रा. अमरीका	द फ्रेंड
स्प्रोकेटस टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह	कनाडा	द फ्रेंड
ब्रिसबेन अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह	ऑस्ट्रेलिया	घुटकन की महाभारत
लोला केन्या स्क्रीन	केन्या	मल्ली, छुटकन की महाभारत, ये है चक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो
21वां इम्फहान अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह	इरान	छुटकन की महाभारत, रोंग मॉरिशस
34वां रोश्द अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	इरान	छुटकन की महाभारत, रोंग मॉरिशस
शिकागो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह	सं.रा. अमरीका	छुटकन की महाभारत
डाइवर्सीन	उरूग्वे	टोरा'ज लव
लुकास-2006-29वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह	जर्मनी	रांग मॉरिशस
5वां अंतर्राष्ट्रीय बाल एवं युवा फिल्म समारोह	अर्जेंटिना	द फ्रेंड
श्रीलंका बाल फिल्म समारोह	श्रीलंका	मुझसे दोस्ती करोगे, करामाती कोट, बाजा
5वां द्विवार्षिक तेहरान अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह	इरान	अमाची की माची
बाल फिल्म समारोह	सं.रा. अमरीका	गाजा यूकिलर हत्या रहस्य
लास एंजिलस में भारतीय फिल्म समारोह	सं.रा. अमरीका	बन्दु बॉक्सर
बर्लिन का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	जर्मनी	गिल्ली, गिल्ली अट्टा

सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रियरंजन दास मुंशी ने इस मौके पर घोषणा की कि अप्रैल 2007 से देश भर में ये फिल्में प्रवेश शुल्क के बिना ही दिखाई जा सकेंगी। मंत्री महोदय ने सीएफएसआई के बजट को बढ़ाकर तीन गुना करने का भी आश्वासन दिया। अपने उद्घाटन भाषण में श्रीमती सोनिया गांधी ने देश की सांस्कृतिक विविधता की चर्चा की। उद्घाटन समारोह में सीएफएसआई की फिल्म 'नंदू का राजा' दिखाई गई।

समारोह के दौरान फिल्म निर्माण के बारे में तीन कार्यशालाएं भी आयोजित हुईं। प्रत्येक कार्यशाला में विभिन्न स्कूलों के चुनींदा 40 बच्चों ने भाग लिया। समारोह में भारत में बाल फिल्मों पर एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई।

इस समारोह का 18 नवम्बर 2006 को रंगारंग समारोह के आयोजन के साथ समापन हुआ। समापन समारोह में अपने प्रमुख भाषण में राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने बाल फिल्मों के निर्माण में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने बच्चों से अपील की कि वे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साहसी व दृढ़ निश्चयी बनें। इस दौरान राष्ट्रपति ने बच्चों के साथ बातचीत में उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब दिए।

सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रियरंजन दास मुंशी ने घोषणा की कि देश में हर दूसरे वर्ष बच्चों के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगी फिल्म समारोह आयोजित होगा।

देश भर में निःशुल्क प्रदर्शनों का विवरण

राज्य	जिले	प्रदर्शनों की संख्या	दर्शक
केरल	मालापुरम	9	1225
	एर्नाकुलम	24	1465
	कण्णूर	7	925
	कोट्टायम	38	6700
	कावारत्ती	22	6450
तमिलनाडु	चेन्नई	3	445
	रामनाथपुरम	64	22459
महाराष्ट्र	चंद्रपुर	79	23222
उड़ीसा	मुंबई	94	17214
	कोरापुट	25	7266
	कालाहांडी	44	14514
	गंजम	98	30897
	पुरी	100	23954
मध्य प्रदेश	भोपाल	6	3425
मणिपुर	इंफाल	20	13400
पश्चिम बंगाल	बीरभूम	50	14100
झारखंड	जमशेदपुर	45	13060
आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम	14	3925
	कर्नूल	45	9150
	गुंटूर	34	21050
कर्नाटक	बीजापुर	51	17282
	बेलगाम	50	17269
	बेल्लारी	50	23780
	योग	**972**	**2,93,177**

बजट संबंधी प्रावधान :

क. योजना : सीएफएसआई के संदर्भ में 2006-07 का स्वीकृत योजना कार्यक्रम इस प्रकार है :

(लाख रुपयों में)

योजना का नाम	अनुमानित बजट	संशोधित अनुमान
जारी योजनाएं		
योजना I :		
निर्माण, खरीद और डबिंग/उपशीर्षक प्रदान करना	352.00	317.00
योजना II :		
समारोह	15.00	62.00
योजना III :		
आधुनिकीकरण और संवर्धन	1.50	1.50
(अ) वीडियो		
(ब) सूचना प्रौद्योगिकी		
योजना IV :		
एनीमेशन और पांडुलिपि लेखन कार्यशाला	4.80	2.80
योजना V :		
दर्शक अनुसंधान और सीएफएसआई फिल्मों के		
के लिए बाजार सर्वे और विपणन	0.00	0.00
योजना VI :		
सीएफएसआई फिल्मों का डिजिटलीकरण और	0.00	0.00
वेबसाइट पर डालना		
योजना VII :		
नगरपालिका स्कूलों में बाल फिल्मों का प्रदर्शन	58.00	48.00
नई योजनाएं :		
हैदराबाद में बाल फिल्म परिसर	100.00	10.00
योग	**531.30**	**441.30**

ब. गैर-योजना : 2006-07 के दौरान गैर-योजना गतिविधियों के लिए 15 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं।

बाल दिवस (14 नवंबर)

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन देश भर में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। समिति ने 14 नवंबर 2006 को 69 फिल्म-प्रदर्शन किए जिन्हें 27,600 बच्चों ने देखा।

जनवरी से मार्च 2007 के दौरान प्रस्तावित गतिविधियां

जिला फिल्म समारोह/सरकारी स्कूलों में फिल्मों का प्रदर्शन : तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में ग्रामीण/म्यूनिसिपल स्कूलों के बच्चों के लिए जिलों में फिल्म स्मारोह आयोजित किए जाते हैं।

नि:शुल्क प्रदर्शन : नेहरू युवा केन्द्र जैसे स्वयंसेवी संगठनों और क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के सहयोग से तमिलनाडु, कर्नाटक तथा पूर्वोत्तर राज्यों में सरकारी स्कूलों और जनजातीय इलाकों के बच्चों के लिए नि:शुल्क फिल्म प्रदर्शन किए जाते हैं।

कार्यशालाएं : महाराष्ट्र में रत्नागिरि और सिंधुदुर्ग जिलों में फिल्म-निर्माण कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना है।

अन्य गतिविधियां

(क) आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण : बाल फिल्म समिति के मुख्यालय और इसके नई दिल्ली तथा चेन्नई के शाखा कार्यालयों का पूरी तरह कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। फिल्म निर्माण प्रक्रिया का संवर्धन और आधुनिकीकरण किया जाता है। वेबसाइट www.cfindia.org को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

(ख) **अनुसूचित जातियों/जनजातियों और अल्पसंख्यकों का कल्याण**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों की नियुक्ति का कार्य सरकार के निर्देशों के अनुसार ही रहा है। एक छोटा संगठन होने के नाते कल्याण गतिविधियां पूरे कार्यालय के लिए की जाती हैं जिनमें सभी वर्गों के कर्मचारी शामिल हैं।

(ग) **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गतिविधियां**

बाल फिल्म समिति निर्माण और प्रदर्शन के माध्यम से क्षेत्रीय भाषायी फिल्मों को प्रोत्साहन देती हैं इस वर्ष 'दि स्टोरी ऑफ नोकपोकलिबा' शीर्षक से एक लघु एनीमेशन फिल्म (नगा भाषा में) जाने-माने फिल्म निर्देशन मेरेन इंचेन के निर्देशन में पूरी हो गई।

मिज़ोरम और मणिपुर में मई-2006 के दौरान फिल्म निर्माण कार्यशालाओं के साथ-साथ बाल-फिल्म समारोह (राज्य और जिला स्तर पर) आयोजित किए गए। मेघालय में भी 16 फिल्मों प्रदर्शनों के माध्यम से करीब 8000 बच्चे लाभान्वित हुए।

(घ) **हिंदी का प्रयोग :** भारत सरकार के निर्देशों के तहत विभागीय पत्र-व्यवहार में यथासंभव हिंदी का प्रयोग होता है। मुख्य रूप से एक बाल फिल्म निर्माण इकाई होने के नाते फिल्म/टी.वी. धारावाहिक/डबिंग/सबटाइटलिंग आदि में हिंदी का प्राथमिक और उत्तरोत्तर इस्तेमाल होता है।

(ड) **सतर्कता :** सर्तकता जैसी गतिविधियों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नामांकित करने का एक प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया है। सतर्कता संबंधी सभी मामले मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निपटाए जाते हैं।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान फिल्म निर्माण और टेलीविजन प्रोडक्शन की कला और तकनीक में नवीनतम शिक्षा और प्रौद्योगिकी के अनुभव प्रदान करता है। दूरदर्शन और अन्य संस्थानों के सभी वर्ग के अधिकारियों को इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। यह संस्थान नोन-लिनियर, बीटाकैम और ए/बी रोल एडिटिंग सेटअप, जैसे आधुनिक डिजिटल और ब्राडकास्ट ग्रेड प्रोडक्शन सेटअप, सोनी बीवीपी-500 पी जैसे डिजिटल कैमरों, साफ्टक्रोमा कीयर, डिजिटल स्पेशल इफेक्ट जेनरेटर, ऐलियास सॉफ्टवेयर के साथ सिलिकोन ग्राफिक्स 02 वर्क स्टेशन, मॉर्डन मूवी कैमरों, री-रिकार्डिंग उपकरणों आदि से लैस है। जिसमें फिल्म और टेलीविजन के शिक्षकों और छात्रों को बेहतरीन जानकारी मिलती है।

वर्ष 2006 के लिए 1480 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1472 उम्मीदवारों को 21 मई 2006 को 14 परीक्षा केंद्रों - (1) इलाहाबाद, (2) अहमदाबाद, (3) अमृतसर, (4) भोपाल, (5) भुवनेश्वर, (6) कोलकाता, (7) चेन्नई, (8) गुवाहाटी, (9) हैदराबाद, (10) मुंबई, (11) नई दिल्ली, (12) पटना, (13) पुणे, (14) तिरुअनंतपुरम में प्रवेश परीक्षा के लिए बुलाया गया।

395 उम्मीदवारों का चयन ओरिएंटेशन प्रोग्राम/इंटरव्यू/ऑडिशन टेस्ट/वर्कशाप के लिए किया गया।

भारतीय छात्रों के अलावा आईसीसीआर, नई दिल्ली के माध्यम से छात्रवृत्ति के लिए आरक्षित 4 सीटों के लिए अफ्रीकी-एशियाई देशों से 11 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से पात्र समझे गए पांच उम्मीदवारों

को संबद्ध दूतावासों/उच्चायोगों में लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया।

इसी प्रकार एनआरआई/विदेशी सीट के लिए अफ्रीकी-एशिआई देशों के अतिरिक्त अन्य देशों से 15 आवेदन प्राप्त हुए। इन उम्मीदवारों के लिए चयन का आधार टेलीफोन पर इंटरव्यू को बनाया गया। 15 उम्मीदवारों में से आठ को दाखिले के लिए चुना गया।

अंतत: विदेशी उम्मीदवारों सहित 128 उम्मीदवारों को वर्ष 2006 के लिए विभिन्न पाठयक्रमों में दाखिले के लिए चुना गया।

(क) फिल्म और टेलीविजन में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा:

फिल्म और टेलीविजन में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयक्रम के लिए 42 उम्मीदवारों का चयन किया गया। तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए चुने गए उम्मीदवारों का पाठयक्रमवार वर्गीकरण इस प्रकार है :-

1)	निर्देशन (फिल्म और टेलीविजन)	12
2)	सिनेमैटोग्राफी (फिल्म एवं टेलीविजन)	12
3)	संपादन (फिल्म एवं टेलीविजन)	10
4)	ऑडियोग्राफी (फिल्म एवं टेलीविजन)	8

पाठयक्रम 10 अक्टूबर 2006 से प्रारंभ हुआ।

ख) फिल्म एवं टेलीविजन अभिनय में दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा :

फिल्म एवं टेलीविजन अभिनय में दो वर्ष के स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के पहले वर्ष के लिए 20 उम्मीदवारों को दाखिले के लिए चुना गया। यह पाठ्यक्रम 30 अक्टूबर, 2006 से प्रारंभ हुआ।

ग) टेलीविजन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

टेलीविजन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठयक्रम के लिए 30 विद्यार्थियों का चयन किया गया। टेलीविजन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठयक्रम में दाखिले के लिए चुने गए विद्यार्थियों का वर्गीकरण इस प्रकार है :

1)	निर्देशन	10
2)	इलेक्ट्रोनिक सिनेमैटोग्राफी	10
3)	वीडियो संपादन	10
4)	ऑडियोग्राफी और टीवी इंजीनियरिंग	–

पाठयक्रम 9 अक्टूबर 2006 को प्रारंभ हुआ।

(घ) फीचर फिल्म स्क्रीनप्ले लेखन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठयक्रम

फीचर फिल्म स्क्रीनप्ले लेखन के एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठयक्रम में प्रवेश के लिए 12 उम्मीदवारों का चयन किया गया। यह पाठयक्रम 4 अगस्त 2006 से प्रारंभ हुआ।

(ड़) कला निर्देशन में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा

कला निर्देशन में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयक्रम में प्रवेश के लिए 12 उम्मीदवारों का चयन किया गया। यह पाठयक्रम 30 अक्टूबर, 2006 से प्रारंभ हुआ।

(च) ऐनीमेशन और कम्प्यूटर ग्राफिक्स में डेढ साल का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

ऐनीमेशन और कम्प्यूटर ग्राफिक्स में डेढ़ साल के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए 12 उम्मीदवारों का चयन किया गया। यह पाठ्यक्रम 14 अगस्त 2006 से प्रारंभ हुआ।

प्रशिक्षु आदि के रूप में विदेशी छात्र :

फ्रांस की सुश्री नोइली चार्ल्स को अगस्त 2006 से 6 महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षु के रूप में एफटीटीआई में अध्ययन की अनुमति दी गयी।

पोलर मीट्स सोलर ट्राइलेटरल वर्कशाप

'पोलर मीट्स सोलर ट्राइलेटररल वर्कशाप (2006)' नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कार्यशाला एफटीआईआई में 13 नवंबर 2006 से 25 नवंबर, 2006 तक आयोजित की गयी। इसका आयोजन केन्या के मोहम्मद अमीन फाउंडेशन्स फिल्म एंड टेलीविजन सेंटर (एमओएफओ) और स्टाडिया हेलसिंकी पोलिटैक्निक, फिनलैंड द्वारा संयुक्त रूप से विद्यार्थी सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। यह कार्यक्रम 2003 में भारत और केन्या के बीच हुए समझौते के तहत शुरू किया गया था।

'पोलर मीट्स सोलर ट्राइलेटररल वर्कशाप' का समापन एक लघु फिल्म समारोह के रूप में हुआ, जिसमें परिसर के सभी विद्यार्थियों और सामान्य फिल्म प्रेमियों को करीब 5-5 मिनट अवधि की तीन फिल्में दिखायी गईं। ये थीं - द चेस, गोइंग डाउन और स्माइल। फिल्म और सामान्य कला जगत से संबद्ध तीन निर्णायकों - सर्व श्री प्रसाद वानार्से, उमेश कुलकर्णी और अनिल श्रीवास्तव को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने फिल्मों का आलोचनात्मक विश्लेषण किया और सर्वोत्तम फिल्म की घोषणा की।

11 दिसम्बर 2006 को विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार थी :-

फिल्म और टेलीविजन में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम

वर्ष	प्रवेश का वर्ष	विद्यार्थियों की पाठ्यक्रम वार संख्या				विद्यार्थियों की कुल संख्या	अजा/अजजा		विदेशी	
		निदेर्शन	सिने.	संपादन	आडियो		अजा	अजजा	पाठ्यक्रम	देश
प्रथम वर्ष	**2006**	**12**	**12**	**10**	**08**	**42**	**06**	**02**	निर्दे.**-3** सिने.**-3** संपादन–1	फ्रांस**-2** नेपाल**-1** नेपाल इटालिया, रूस कनाडा

वर्ष	प्रवेश का वर्ष	विद्यार्थियों की पाठ्यक्रम वार संख्या				विद्यार्थियों की कुल संख्या	अजा/अजजा		विदेशी	
		निदेर्शन	सिने.	संपादन	आडियो		अजा	अजजा	पाठ्यक्रम	देश
द्वितीय वर्ष	**2005**	**11**	**10**	**11**	**10**	**42**	**06**	**02**	निर्दे.**-2** सिने.**-1** संपादन**-2**	जर्मनी फ्रांस फिलीपीन्स कनाडा आस्ट्रेलिया नेपाल
तृतीय वर्ष	**2004**	**12**	**10**	**11**	**6**	**39**	**05**	**01**	निर्दे.**-3** सिने.**-1** संपादन**-1**	फ्रांस फिलीपीन्स स्वीडन नेपाल अमरीका
		35	**32**	**32**	**24**	**123**	**17**	**05**		

11 दिसम्बर 2006 को पाठ्यक्रमवार विद्यार्थियों की कुल संख्या

तीन वर्षीय डिप्लोमा	अभिनय	कला निर्देशन	ऐनीमेशन और कम्पयूटर ग्राफिक्स	टेलीविजन में प्रमाणपत्र पाठयक्रम	स्क्रीनप्ले लेखन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	कुल
123	**40**	**22**	**24**	**30**	**12**	**251**

अभिनय में दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा

वर्ष	पाठ्यक्रम	विद्यार्थियों की कुल संख्या	अजा	अजजा	विदेशी
2006 (प्रथम वर्ष)	अभिनय	**20**	**3**	-	–
2005 (द्वितीय वर्ष)	अभिनय	**20**	-	-	**1**-दुबई

कला-निर्देशन में दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा

वर्ष	पाठ्यक्रम	विद्यार्थियों की कुल संख्या	अजा	अजजा	विदेशी
2006 (प्रथम वर्ष)	कला-निर्देशन	**12**	**2**	-	**1**-दक्षिण कोरिया
2005 (द्वितीय वर्ष)	कला-निर्देशन	**10**	**2**	-	–

ऐनीमेशन और कम्प्यूटर ग्राफिक्स में डेढ साल का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

वर्ष	पाठ्यक्रम	विद्यार्थियों की कुल संख्या	अजा	अजजा	विदेशी
2005	ऐनिमेशन और कम्प्यूटर ग्राफिक्स	**12**	**1**	-	–
2006	ऐनिमेशन और कम्प्यूटर ग्राफिक्स	**12**	**1**	-	**1**-यमन

टेलीविजन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

प्रवेश का वर्ष	पाठ्यक्रम वार विद्यार्थियों की संख्या			विद्यार्थियों की कुल संख्या		अजा अजजा		विदेशी
	निर्देशन	सिने.	संपादन	आडियो.		अजा	अजजा	
2006	**10**	**10**	**10**	–	**30**	**06**	-	**1**-ईरान **1**-आस्ट्रेलिया

फीचर फिल्म स्क्रीनप्ले लेखन मे एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

वर्ष	पाठ्यक्रम	विद्यार्थियों की कुल संख्या	अजा	अजजा	विदेशी
2006 (प्रथम वर्ष)	स्क्रीनप्ले लेखन	**12**	**1**	-	–

अगले शैक्षिक सत्र 2007-08 के लिए प्रवेश अधिसूचना मार्च 2007 में प्रकाशित की जाएगी।

संस्थान इंटरनेशनल लाइजन सेंटर आफ सिनेमा एंड टीवी स्कूल्स (सीआईएलईसीटी) का सदस्य है, जिससे विश्व के सभी प्रमुख फिल्म एवं टेलीविजन स्कूल संबद्ध हैं। सीआईएलईसीटी की बैठकों में आमतौर पर एक शिक्षक और एक विद्यार्थी हिस्सा लेते हैं। इससे संस्थान फिल्म निर्माण और टेलीविजन प्रोडक्शन तथा फिल्म और टेलीविजन शिक्षण में अद्यतन अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों से अवगत रहता है।

प्रशासन

भारत सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत 1960 में भारतीय फिल्म संस्थान की स्थापना की। 1974 में इसमें टेलीविजन शाखा को जोड़ देने के बाद संस्थान को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान का नाम दिया गया। रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटी एक्ट, 1860 के अंतर्गत अक्टूबर 1974 में संस्थान एक सोसाइटी बन गया। इसमें फिल्म, टेलीविजन, संचार, संस्कृति से जुड़ी प्रमुख हस्तियां, संस्थान के पुराने छात्र और सरकार के पदेन सदस्य शामिल हैं। संस्थान को संचालन परिषद चलाती है, जिसका एक अध्यक्ष होता है। जाने माने लेखक डा. यू. आर. अनंतमूर्ति इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। संस्थान की पाठयक्रम नीतियों और योजनाओं को शिक्षा परिषद तैयार करती है। वित्त से जुड़े मसले स्थायी वित्त समिति द्वारा संचालित किए जाते हैं।

संस्थान की दो शाखाएं हैं :- फिल्म और टेलीविजन, जो फिल्म और टेलीविजन के पाठयक्रमों की पढ़ाई के अवसर प्रदान करती है। फिल्म पाठयक्रम में निर्देशन, सिनेमैटोग्राफी, संपादन और आडियोग्राफी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कराया जाता है। टेलीविजन शाखा निर्देशन, इलेक्ट्रोनिक सिनेमैटोग्राफी, वीडियो संपादन और ऑडियोग्राफी तथा टीवी इंजीनियरिंग में एक वर्ष का स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठयक्रम संचालित करती है। टेलीविजन शाखा दूरदर्शन के सभी श्रेणी के कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसमें टीवी प्रोडक्शन, टेक्नीकल आपरेशन, संपादन, साउंड रिकार्डिंग, कैमरा, ग्राफिक्स और सेट डिजाइन आदि का प्रशिक्षण शामिल है। अन्य संगठनों को भी लघु अवधि के कोर्स कराए जाते हैं। नए पाठयक्रम में संस्थान के विद्यार्थी सैद्धांतिक और तकनीकी क्षमता हासिल करेंगे, जो व्यवसायों के लिए आवश्यक है। दोनों शाखाओं द्वारा तैयार नये पाठयक्रम में फिल्म और टेलीविजन को बराबर महत्व दिया गया है तथा मीडिया में कंप्यूटर की जानकारी के महत्व पर भी ध्यान दिया गया है।

फिल्म मूल्यांकन पाठ्यक्रम

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान तथा भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के संयुक्त तत्वावधान में 15 मई, 2006 से 10 जून 2006 तक 31वां फिल्म मूल्यांकन पाठयक्रम आयोजित किया गया। इस पाठ्यक्रम में 75 पत्रकारों, फिल्म निर्माताओं, कलाकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और मीडिया से जुड़े लोग शामिल हुए।

फिल्म समारोह में भागीदारी

भारत और विदेशों में छात्रों की प्रतिभा को उभारने के लिए डिप्लोमा विद्यार्थियों द्वारा बनायी गयी फिल्में विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में शामिल की जाती हैं। वर्ष के दौरान संस्थान ने निम्नांकित समारोहों/गतिविधियों में हिस्सा लिया :

1. 33वें वार्षिक विद्यार्थी अकादमी पुरस्कार, विलशायर बॉउलेवार्ड, सं.रा. अमरीका, 11 अप्रैल, 2006
2. सेशूट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, बाबेल्सवर्ग, जर्मनी, 25-30 अप्रैल, 2006
3. 52वां अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह, ओबरहोसेन, जर्मनी, 4-9 मई, 2006
4. जूजेंड मीडियेन समारोह, बर्लिन, जर्मनी, 17-21 मई, 2006
5. दूसरा युवा सिनेमा समारोह, ताशकंद, मई 2006
6. 11वां अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी फिल्म समारोह, तेल अवीव, इस्रायल, 3-10 जून, 2006
7. पोर्शे अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी विज्ञापन फिल्म प्रतियोगिता, डेविड, 2006, 7-9 जून 2006
8. नेक्स्ट फ्रेम, यूवीएफए का टूरिंग अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी फिल्म और वीडियो समारोह, फिलाडेल्फिया, जून 2006
9. टेलूराइड फिल्म समारोह, कोलोराडो, 1-4 सितंबर, 2006
10. 25वां एफपीएस समारोह, जग्रेब, क्रोएशिया, 20-24 सितंबर, 2006
11. चौथा बर्लिन एशिया-पेसिफिक फिल्म समारोह, जर्मनी, 4-10 अक्टूबर, 2006
12. चौथा जोरोस्ट्रान और ईरानी संस्कृति फिल्म समारोह, वेंकुवर, कनाडा, 7-8 अक्टूबर, 2006

13. 51वां कोर्क फिल्म समारोह, आयरलैंड, 8-15 अक्टूबर, 2006

14. 13वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टीवी स्कूल समारोह, मीडिया स्कूल-2006, पौलेंड, 17-21 अक्टूबर, 2006

15. द टाइम्स बीएफआई 50वां लंदन फिल्म समारोह, ब्रिटेन, 19-2 नवंबर 2006

16. 25वां उप्पासला अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह, स्वीडन, 17-23 और 29 अक्टूबर, 2006

17. चौथा कल्पनिर्झर अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह, कोलकाता, 27-31 अक्टूबर, 2006

18. 49वां अंतर्राष्ट्रीय लेइप्जिग वृतचित्र एवं ऐनीमेशन फिल्म समारोह, जर्मनी, 30अक्टूबर-5 नवंबर 2006

19. 20वां लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, ब्रिटेन 3-12 नवंबर 2006

20. 5वां विद्यार्थी फिल्म और वीडियो समारोह, पेइचिंग फिल्म अकादमी, चीन, 5-11 नवम्बर, 2006

21. प्रथम राष्ट्रीय बाल डिजिटल फिल्म समारोह, नई दिल्ली में 14-18 नवम्बर, 2006

22. 26वां म्युनिख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म स्कूल समारोह, कोनिग लुडविग ट्रॉफी, जर्मनी में 19-25 नवम्बर, 2006

23. तेहरान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, ईरान, में 21-27 नवम्बर, 2006

24. 18वां अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म समारोह, ऐमस्ट्रडम, नीदरलैंड में 23 नवम्बर-3 दिसम्बर, 2006

25. 14वां अंतर्राष्ट्रीय सिनेमैटोग्राफी कला फिल्म समारोह, कैमेरीमेज, लोज, पोलैंड में 25 नवम्बर-3 दिसम्बर, 2006

26. गोल्डन लॉयन अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी फिल्म समारोह, ताइपेई, ताइवान, में 26-30 नवम्बर

27. 11वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म समारोह, 2006

28. बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, बर्लिन 8-10 फरवरी, 2007

29. 53वां अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह, ओबरहोसेन, 3-8 मई 2007

30. 5वां पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, मार्च 2007 में निर्धारित।

4. लेनसाइट फिल्म समारोह, जनवरी-फरवरी 2007।

कार्यशालाएं/सेमिनार

विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सामग्री की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भारत और विदेश के जाने-माने फिल्म-निर्माताओं द्वारा कार्यशालाओं/सेमिनारों का नियमित रूप से आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान जाने माने फिल्म-निर्माताओं द्वारा निम्नांकित कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन किया गया :

1. श्री रणदीप हूडा ने 'अभिनय' के बारे में 5 अप्रैल, 2006 से 10 अप्रैल 2006 तक कार्यशाला आयोजित की।

2. श्री अतर सिंह ने 'सिनेमेटोग्राफी' के बारे में 7 अप्रैल, 2006 से 08 अप्रैल 2006 तक कार्यशाला आयोजित की।

3. श्री मंजुल सिन्हा ने 'विभिन्न प्रयोजनों के लिए परिवर्द्धित समाचार आइटम' के बारे में 13 अप्रैल, 2006 को व्याख्यान दिया।

4. श्री आदिल अमान ने 'इमेजिनेशन, सेंस मेमोरी' विषय पर 17 अप्रैल, 2006 से 19 अप्रैल, 2006 तक व्याख्यान दिये।

5. श्री हरीश मगन ने 'स्पॉट मेमोरी, वॉइस एण्ड स्पीच' विषय पर 17 अप्रैल, 2006 से 18 अप्रैल, 2006 तक और 27 अप्रैल, 2006 को व्याख्यान दिया।

6. श्री विकास देसाई ने 'प्लेबैक/गीत दृश्यीकरण' के बारे में 18 अप्रैल, 2006 से 22 अप्रैल 2006 तक कार्यशाला का आयोजन किया।

7. श्री प्रकाश झा ने 'स्क्रीनप्ले लेखन' विषय पर 19 अप्रैल, 2006 को व्याख्यान दिया।

8. श्री दिलीप मिस्त्री ने 'प्लेबैक/गीत दृश्यीकरण' के बारे में 20 अप्रैल, 2006 से 22 अप्रैल 2006 तक कार्यशाला का आयोजन किया।

9. श्री विशाल दुबे ने 'आफ्टर इफेक्ट्स' के बारे में 29 अप्रैल, 2006 से 30 अप्रैल 2006 तक कार्यशाला का आयोजन किया।

10. श्री नितिन हडप ने 'कला, वास्तु शिल्प और वेशभूषा' विषय पर 17 अप्रैल, 2006 से 19 अप्रैल, 2006, 21 अप्रैल 2006, 25 अप्रैल 2006 और 26 अप्रैल 2006 तथा 28 अप्रैल 2006 को व्याख्यान दिया।

11. श्री प्रभाकर कुमार सिंह ने 'मोल्डिंग प्रैक्टिकल्स' के बारे में 18 अप्रैल, 2006 से 21 अप्रैल, 2006, 24 अप्रैल 2006 से 28 अप्रैल 2006 और 1 मई 2006 और 4 मई 2006 तक कार्यशालाओं का आयोजन किया।

12. श्री अंजुम राजाबाली ने 'औद्योगिक पहलुओं' विषय पर 21 अप्रैल, 2006 से 22 अप्रैल, 2006 तक व्याख्यान दिया।

13. श्री राजा मुराद ने 'वॉइस एण्ड स्पीच/डिक्शन' विषय पर 28 अप्रैल, 2006 से 29 अप्रैल, 2006, 15 जून 2006 से 17 जून 2006, 10 जुलाई 2006 से 12 जुलाई 2006 और 21 अगस्त 2006 से 23 अगस्त 2006 तक व्याख्यान दिये।

14. श्री सुरेश पई ने 'संपादन' के बारे में 1 मई 2006 से 5 मई 2006 तक कार्यशाला का आयोजन किया।

15. श्री मेघन मांजरेकर ने 'पेंट अप्लीकेशन ऑन वेरियस सर्फेसेज' विषय पर 1 मई 2006 को व्याख्यान दिया।

16. श्री टॉम ऑल्टर ने 'इंप्रोवाइजेशन एण्ड सीन्स' विषय पर 2 मई 2006 को व्याख्यान दिया।

17. श्री पिंटू चौधरी ने 'सिनेमेटोग्राफी-बीएनए' विषय पर 2 मई 2006 को व्याख्यान दिया।

18. श्री अंजुम राजाबाली ने 'स्क्रीनप्ले लेखन के लिए पांच मिनट के वर्णन' विषय पर 5 मई 2006 को व्याख्यान दिया।

19. श्री संजय अग्रवाल ने 'सिनेमेटोग्राफी तकनीकों की परिभाषा' के बारे में 5 मई 2006 से 6 मई 2006 तक व्याख्यान दिए।

20. श्री वाई. के. माथुर ने 'बीएनए अकादमी' विषय पर 5 मई 2006 को व्याख्यान दिया।

21. श्रीमती मृणालिनी खन्ना ने 'स्क्रिप्ट ऑफ एक्टिंग डिप्लोमा फिल्म' के बारे में 5 मई 2006 को व्याख्यान दिया।

22. श्री रवि देशपांडे ने 'विज्ञापन फिल्में और उनकी प्रोडक्शन की तकनीकों' के बारे में 7 मई 2006 से 8 मई 2006 तक कार्यशाला का आयोजन किया।

23. श्रीमती जयश्री कनाल ने 'मल्टी कैमरा प्रोडक्शन टेकनीक फॉर आर्ट' विषय पर 8 मई 2006 को व्याख्यान दिया।

24. श्री भारत नेरकर ने 'टैक्नीकल कंसिडरेशन इन डिजाइन-आर्ट डायरेक्शन' विषय पर 9 मई 2006 से 10 मई 2006 तक व्याख्यान दिए।

25. श्री श्रीराम राघनवन ने 'पटकथा लेखन' विषय पर 22 मई 2006 को व्याख्यान दिया।

26 श्री अंजुम राजाबाली ने 'पटकथा लेखन - एक व्यावसायिक पहलू' विषय पर 27 मई 2006 को व्याख्यान दिया।

27. श्री कमलनाथ ने 'अभिनय के लिए नृत्य' विषय पर 15 जून 2006 से 17 जून 2006 तक व्याख्यान दिए।

28. डाक्टर रोबिन त्रिभुवन ने 'जनजातीय संस्कृति अध्ययन-वास्तु शिल्प और वेशभूषा-कला निर्देशन' विषय पर 16 जून 2006 को व्याख्यान दिया।

29. श्री संजीवन लाल ने टेलीविजन पाठयक्रम के विद्यार्थियों के लिए कोर्स-एण्ड प्रोजेक्ट के बारे में 16 जून 2006 से 5 जुलाई 2006 तक कार्यशाला का आयोजन किया।

30. श्री टॉम आल्टर ने 'अभिनय' के बारे में 20 जून 2006 से 21 जून 2006 तक कार्यशाला का आयोजन किया।

31. श्री अजित पांडे ने 'ड्राफ्टिंग, डिजाइनिंग और कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स के लिए साफ्टवेयर इस्तेमाल का अध्ययन' विषय पर 3 जुलाई 2006 से 29 जुलाई 2006 तक व्याख्यान दिए।

32. श्री योगेश माथुर ने 'प्रोडक्शन डिजाइन एण्ड फेडिंग ऑफ फिल्म' विषय पर 7 जुलाई 2006 को व्याख्यान दिया।

33. श्री इंद्रनील चक्रवर्ती ने 'डिस्कशन फॉर एसपीडब्लू कान्फ्रेंस' विषय पर 10 जुलाई 2006 को व्याख्यान दिया।

34. श्री रूपेश थपलियाल ने 'अभिनय' विषय पर 13 जुलाई 2006 से 15 जुलाई 2006, 3 अगस्त 2006 से 5 अगस्त 2006, 17 अगस्त 2006 से 19 अगस्त 2006 और 25 अगस्त 2006 से 27 अगस्त 2006, 18 सितम्बर 2006 से 20 सितम्बर 2006 तक व्याख्यान दिए।

35. श्री टॉम आल्टर ने 'प्ले परफारमेंस आफ एक्टिंग स्टूडेंट्स' विषय पर 18 जुलाई 2006 से 21 जुलाई 2006 तक व्याख्यान दिए।

36. श्री चंद्रमोहन ने 'प्ले परफारमेंस आफ एक्टिंग स्टूडेंट्स' विषय पर 18 जुलाई 2006 को व्याख्यान दिया।

37. श्री अजित पंधे ने 'डिजाइनिंग और कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स के लिए साफ्टवेयर के इस्तेमाल' विषय पर 1 अगस्त 2006 से 5 अगस्त 2006 और 7 अगस्त 2006 से 11 अगस्त 2006 तक व्याख्यान दिए।

38. श्री सलाम आरिफ ने 'वेशभूषा डिजानिंग' विषय पर 2 अगस्त 2006 और 28 अगस्त 2006 से 3 सितंबर 2006 तक कार्यशालाओं का आयोजन किया।

39. श्री इंद्रनील चक्रवर्ती ने 'पटकथा लेखन सम्मेलन के लिए प्रबंध' विषय पर 3 अगस्त 2006 को व्याख्यान दिया।

40. श्री अंजुम राजाबाली ने 'आरिएन्टेशन इनाग्यूरेशन' विषय पर 4 अगस्त 2006 से 5 अगस्त 2006 तक व्याख्यान दिए।

41. श्री अश्विनी मलिक ने 'ओरिएंटेशन इनाग्यूरेशन' विषय पर 4 अगस्त 2006 से 5 अगस्त 2006 तक व्याख्यान दिए।

42. श्री आनंद कुमार शर्मा ने 'संपादन' विषय पर 4 अगस्त 2006 से 5 अगस्त 2006 तक कार्यशाला का आयोजन किया।

43. श्री वाई. के. माथुर ने 'संपादन के सिद्धांतों' के बारे में 7 अगस्त 2006 और 5 सितंबर 2006 को व्याख्यान दिए।

44. श्री समर सिंह ने 'अभिनय' विषय पर 10 अगस्त 2006 से 12 अगस्त 2006 तक व्याख्यान दिए।

45. श्री अंजुम राजाबाली ने 'पटकथा लेखन' विषय पर 22 अगस्त 2006 से 23 अगस्त 2006 तक व्याख्यान दिए।

46. श्री अंजुम राजाबाली ने 'थीम एण्ड स्टोरी' विषय पर 25 अगस्त 2006 से 26 अगस्त 2006 तक कार्यशाला का आयोजन किया।

47. श्री टॉम आल्टर ने 'अभिनय' विषय पर 28 अगस्त 2006 से 29 अगस्त 2006 तक कार्यशाला का आयोजन किया।

48. श्री प्रशांत नाइक ने 'नोन-लिनियर एडिटिंग' विषय पर 2 सितंबर 2006, 16 सितंबर 2006 और 23 सितंबर 2006 को व्याख्यान दिए।

49. श्री सलीम आरिफ ने 'कस्ट्यूम डिजाइनिंग प्रोजेक्ट डिस्कशन एण्ड एसेसमेंट ऑफ आर्ट डायरेक्शन' विषय पर 8 सितंबर 2006 व्याख्यान दिया।

50. श्री अंजुम राजाबाली ने 'स्टोरी' विषय पर 8 सितंबर 2006 से 9 सितंबर 2006 तक व्याख्यान दिए।

51. श्री विक्रम गायकवाड ने 'कला निर्देशन' विषय पर 9 सितंबर 2006 से 12 सितंबर 2006 तक व्याख्यान दिए।

52. श्री समर सिंह ने 'अभिनय' विषय पर 11 सितंबर 2006 से 13 सितम्बर 2006 तक व्याख्यान दिए।

53. श्री राजेश कौल ने 'टीवी ड्रामा प्रोडक्शन' विषय पर 18 सितंबर 2006 से 23 सितंबर 2006 तक व्याख्यान दिए।

54. श्री समर नाखटे ने 'टीवी ड्रामा प्रोडक्शन' विषय पर 18 सितंबर 2006 से 23 सितंबर 2006 तक व्याख्यान दिए।

55. श्री राजा मुराद ने 'अभिनय' विषय पर 27 सितंबर 2006 को व्याख्यान दिया।

56. श्री अंजुम राजाबाली ने 'स्ट्रक्चर/स्टोरी डिस्कशन' विषय पर 29 सितंबर 2006 से 30 सितंबर 2006 तक व्याख्यान दिए।

57. श्री संदीप सूद ने 'ब्रोडकास्ट मैनेजमेंट' विषय पर 30 सितंबर 2006 को व्याख्यान दिया।

58. श्री दीपक सहगल ने 'प्रजेंट सिनारियो ऑफ टीवी एण्ड ऑपरच्यूनिटिज' विषय पर 9 अक्टूबर 2006 को व्याख्यान दिया।

59. श्री विजय सिंह ने 'स्टोरी' विषय पर 12 अक्टूबर 2006 से 15 अक्टूबर 2006 तक कार्यशाला का आयोजन किया।

60. श्री समर सिंह ने 'अभिनय' विषय पर 16 अक्टूबर 2006 से 18 अक्टूबर 2006 तक व्याख्यान दिये।

61. श्री अंजुम राजाबाली ने 'स्ट्रक्चर' विषय पर 18 अक्टूबर 2006 को व्याख्यान दिया।

62 श्री अश्विनी मलिक ने 'ट्रीटमेंट' विषय पर 27 अक्टूबर 2006 से 28 अक्टूबर 2006 तक कार्यशाला का आयोजन किया।

उपरोक्त कार्यशालाओं और व्याख्यानों के अलावा कई जाने-माने लोगों को एफटीआईआई पुणे में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों और प्रशिक्षार्थियों को उनके साथ परस्पर वार्तालाप का अवसर मिला।

अध्ययन दौरे (स्टडी टूर)

सिनेमेटोग्राफी विशेषज्ञता पाठयक्रम के विद्यार्थियों को अध्ययन दौरे पर दिसंबर 2006 में मुंबई ले जाया गया, जहां उन्होंने रंग विश्लेषण, टेलीसिने और डिजिटल इंटरमीडियेट प्रोसेसिज का अध्ययन करने के लिए विभिन्न फिल्म प्रोसेसिंग प्रयोगशालाओं का दौरा किया।

अन्य अल्पावधि पाठ्यक्रम

संस्थान द्वारा निम्नांकित अल्पावधि पाठयक्रम आयोजित किए गए :

1. 3 अप्रैल 2006 से 15 अप्रैल 2006 तक टीवी रिसर्च मेथड्स कोर्स आयोजित किया गया।

2 17 अप्रैल 2006 से 12 मई 2006 तक मल्टीमीडिया अप्लीकेशन्स फॉर टीवी प्रोडक्शन में आठवां प्रशिक्षण पाठयक्रम आयोजित किया गया।

3. एमजीएएचवी, वर्धा के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए 12 जून 2006 से 16 जून 2006 तक कार्यशाला आयोजित की गयी।

4. मेकअप के बारे में 29 जून 2006 से 13 जुलाई 2006 तक अल्पावधि पाठयक्रम आयोजित किया गया।

5. 10 जुलाई 2006 से 14 जुलाई 2006 तक टेलीविजन पत्रकारिता कार्यशाला आयोजित की गयी।

6. 17 जुलाई 2006 से 29 जुलाई 2006 तक मल्टीकैम प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

7. 31 जुलाई 2006 से 18 अक्टूबर 2006 तक 52वां टीवी प्रोडक्शन और टैक्नीकल ऑपरेशन्स कोर्स आयोजित किया गया।

   इसके अलावा 1.11.2006 से 07.11.2006 तक, 13.11.2006 से 18.11.2006 तक, 27.11.2006 से 02.12.2006 तक और 04.12.2006 से 09.12.2006 तक जी टीवी स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए।

उपकरण

वर्ष के दौरान वीडियो सर्वर खरीदा गया और इसकी संस्थापना और नेटवर्किंग जल्दी ही की जायेगी।

पुस्तकालय

संस्थान के पुस्तकालय में फिल्म और टेलीविजन के विभिन्न पहलुओं के बारे में दुर्लभ पुस्तकों सहित 26,323 से अधिक पुस्तकें हैं।

फिल्म लाइब्रेरी

संस्थान की फिल्म लाइब्रेरी में भारतीय और विदेशी फीचर फिल्मों और लघु फिल्मों, स्टडी एक्स्ट्रक्ट्स और एफटीटीआई फिल्मों सहित 3000 से अधिक फिल्मों का संग्रह है। फिल्म लाइब्रेरी में डिस्क रिकॉर्ड्स, वीडियो कैसेट्स और डीवीडी/वीसीडी आदि श्रव्य-दृश्य सामग्री भी रखी है।

वीडियो टेप लाइब्रेरी

भारतीय और विदेशी फीचर फिल्मों और लघु फिल्मों, डाक्यूमेंटरी और स्टूडेंट्स फिल्मों, विद्यार्थियों और टीवी प्रशिक्षार्थियों द्वारा बनाए गए टीवी प्रोग्रामों, वीडियो डाक्यूमेंटरियों के वीएचएस और यू-मैटिक तथा बीटाकैम कैसेट्स भी संस्थान की वीडियो लाइब्रेरी में रखे गए हैं।

ये टेप संसाधन सामग्री के रूप में विद्यार्थियों के काम आते हैं। इनसे उन्हें विषयवस्तु विकास और निर्माण तकनीकों का गहराई से अध्ययन करने और एडिटिंग टेबलों पर फिल्म देखने के लिए पूरक सामग्री प्राप्त करने में मदद मिलती है।

प्रशासन

नियुक्तियां

वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 6 पदों पर नियुक्तियां की गईं।

महत्वपूर्ण आयोजन

(1) संस्थान ने 1 मई 2006 को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग ट्रस्ट के सहयोग से नई दिल्ली में इंडिया हैबिटाट सेंटर में लेनसाइट फिल्म समारोह आयोजित किया।

(2) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे ने 19 और 20 अगस्त 2006 को प्रथम अखिल भारतीय पटकथा लेखक सम्मेलन आयोजित किया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार एफटीआईआई द्वारा आयोजित सम्मेलन में देश भर से पटकथा लेखक, निर्देशक और विद्वान एकत्र हुए और उन्होंने भारतीय पटकथा लेखन के विभिन्न आयामों पर विचार-विमर्श और बहस में हिस्सा लिया।

(3) संस्थान ने 14 सितंबर 2006 से 20 सितंबर 2006 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया। संस्थान द्वारा आतंकवाद विरोधी दिवस, सद्भावना दिवस और कौमी एकता दिवस भी मनाए गए। इन अवसरों पर सभी कर्मचारियों, विद्यार्थियों और प्रशिक्षार्थियों ने शपथ ली।

महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरे

(1) माननीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य मंत्री श्री

प्रियरंजन दासमुंशी ने 1 सितंबर 2006 को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का दौरा किया।

(2) मालदीव गणराज्य के माननीय कला राज्य मंत्री श्री हुसैन साहब ने 4 सितंबर 2006 को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का दौरा किया।

प्रतिनियुक्तियां और शिष्टमंडल

1. श्री बी सी नारिया, सहायक प्रोफेसर, सिनेमोटोग्राफी को ब्रिटेन में सीआईएलीसीटी द्वारा आयोजित डी-2 सिनेमा कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया।

2. श्री सुरेश छाबरिया, रजिस्ट्रार, श्री एस जी पारले, मुख्य लेखाधिकारी और श्रीमती एस एस म्हाइस्कर, प्रशासनिक अधिकारी को 28 जुलाई 2006 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया।

एफटीआईआई में सतर्कता और निगरानी कार्रवाइयां

1.4.2006 से 31.12.2006 की अवधि में एफटीटीआई में की गई सतर्कता और निगरानी सम्बन्धी कार्रवाइयों का ब्यौरा मंत्रालय को भेजा गया।

सत्यजित राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान

सत्यजित राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त शैक्षिक संस्थान के रूप में 1995 में की गई थी। संस्थान को बाद में पश्चिम बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1961 के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया।

सत्यजित राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत पूर्ण वित्तपोषित स्वायत्तशासी संस्थान है, जिसका संचालन भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति करती है। इस समिति के अध्यक्ष एक कार्यकारी परिषद के माध्यम से संस्थान का संचालन करते है। परिषद में समिति के चुनिंदा सदस्य शामिल होते हैं। कार्यकारी परिषद संस्थान की सभी कार्यकारी गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था है।

सोसाइटी, कार्यकारी परिषद और स्थायी वित्त समिति में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी पदेन सदस्यों के रूप में शामिल किए जाते हैं, जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

संस्थान की एक पृथक शैक्षिक परिषद भी है, जिसे संस्थान से संबद्ध सभी शैक्षिक और कार्यक्रम निर्माण संबंधी नीतिगत निर्णय लेने का काम सौंपा गया है।

फिल्म जगत की मशहूर हस्ती सत्यजित राय की स्मृति में कोलकाता में स्थापित यह संस्थान देश का अपनी तरह का दूसरा संस्थान है। यह फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयक्रम उपलब्ध कराने वाला राष्ट्रीय केंद्र हैं।

संस्थान अद्यतन प्रौद्योगिकी से सुसज्जित है, और इसका उद्देश्य फिल्म और टेलीविजन मीडिया में प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह प्रशिक्षार्थियों को इस क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रचनात्मक एवं मौलिक कार्य करने में सक्षम बनाता है। इस दृष्टि से यह देश में सिनेमा के संवर्द्धन एवं विकास में योगदान करता है।

जाने माने फिल्म निर्माता श्री बासु चटर्जी, सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इस पद के साथ-साथ वे कार्यकारी परिषद, शैक्षिक परिषद और अन्य समितियों के अध्यक्ष भी हैं।

संस्थान के निदेशक इसके प्रमुख होते है, जो मुख्य कार्यकारी, शैक्षिक परिषद आदि के सदस्य सचिव के रूप में काम करते है। शैक्षिक मामलों में उनकी सहायता के लिए डीन और प्रशासनिक मामलों में सहायता के लिए रजिस्ट्रार की व्यवस्था की गई है।

बुनियादी स्वरूप

सत्यजित राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान फिल्म निर्माण और टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण के बारे में व्यापक शिक्षा का प्रमुख स्थान है। इसमें आधुनिक फिल्म/वीडियो निर्माण उपकरण, उत्कृष्ट स्टूडियो, थियेटर और पुस्तकालय हैं।

फिल्म और टेलीविजन स्टूडियो

संस्थान में दो स्टूडियो फ्लोर हैं। इसका फिल्म स्टूडियो देश के पूर्वी क्षेत्र के सर्वोत्तम स्टूडियो में से एक है। स्टूडियो तल का आकार (80'x50') बड़े सेटों के लिए भी उपयुक्त है। इसमें पूर्ण रूप से वातानुकूलित मेकअप रूम, विशिष्ट कैमरों के लिए भूमिगत पिट, प्रकाश व्यवस्था के लिए 3-टीयर प्लेटफार्म, कला सामग्री और एक सुसज्जित काश्तकारी एवं रंगरोगन कक्ष है। इसकी संपत्ति सूची में रंगमंच का सामान्य साज-सामान और वेशभूषा भी शामिल है।

दूसरा स्टूडियो भी पूरी तरह वातानुकूलित है, जो 50'x50' आकार का है। इसमें डिमर पैनल, मोटोराइज्ड टेलीस्कोपिक लाइटिंग ग्रिड, साइक्लोरमा सुविधाएं उपलब्ध है।

फिल्म प्रदर्शन की सुविधाएं

विद्यार्थियों के लिए फिल्म देखने के अवसरों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि संस्थान में मुख्य थियेटर (370 सीटों वाला), प्रीव्यू थियेटर (72 सीटों वाला) और मुक्त आकाश थियेटर है, जिसमें 500 से अधिक दर्शकों के बैठने की क्षमता है। इन थियेटरों में 35 एमएम, 16 एमएम और वीडियो प्रोडक्शन जैसी बहुप्रयोजन सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इनके अतिरिक्त एक क्लासरूम थियेटर भी है, जिसमें व्याख्यान-प्रदर्शन की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

पुस्तकालय

संस्थान का पुस्तकालय दो मंजिले भवन में स्थित है, जो बड़े अध्ययन कक्ष, अनेक दृश्यांकन बूथों और संगीत कक्ष से सुसज्जित है। पुस्तकालय में सिनेमा, टेलीविजन, मीडिया, टेक्नोलॉजी, अभिनय कलाओं और संबद्ध विषयों के बारे में पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। इसमें विभिन्न रूपों जैसे ऑडियो कैसेटों और सीडी में श्रव्य सामग्री का शानदार संग्रह मौजूद है।

पुस्तकालय में सहजता से इस्तेमाल हो सकने वाली कंप्यूटरीकृत कैटलॉग और सर्कुलेशन मैकेनिज्म जैसी इलेक्ट्रॉनिक संसाधन सुविधाएं भी हैं। यह पुस्तकालय व्यापक संदर्भ सेवा प्रदान करता है।

फिल्म लाइब्रेरी

संस्थान में एक लघु फिल्म लाइब्रेरी है, जिसमें भारतीय और विदेशी फिल्मों का संग्रह है। इसका सिने सेंट्रल कलेक्शन अनुभाग सबसे बड़ा है, जिसमें 400 विदेशी फीचर फिल्में और 914 लघु एवं वृत्तचित्र रखे गए हैं। फेडरेशन आफ फिल्म सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया (पूर्वी क्षेत्र) के संग्रह के अंतर्गत 36 फीचर फिल्में और 38 लघु फिल्में तथा एसआरएफटीआई-एनएफडीसी कलेक्शन में 66 फीचर फिल्में रखी गई हैं। ये फिल्म प्रिंट शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं।

एनएफएआई का क्षेत्रीय केंद्र

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का क्षेत्रीय कार्यालय एसआरएफटीआई परिसर में स्थित होने के कारण विद्यार्थियों को दुर्लभ फिल्में देखने में सुविधा रहती है। अभिलेखागार में एक लघु लेकिन महत्वपूर्ण संग्रह है, जिसमें 71 क्लासिक फिल्में शामिल हैं, जो शैक्षिक प्रदर्शन और चर्चा के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं।

सत्यजित राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं।

(i) सिनेमैटोग्राफी

इस विभाग की स्थापना और विकास महान संगीतकार श्री सुब्रत चित्रा की देखरेख में एसआरएफटीआई में की गई। श्री चित्रा ने सिनेमैटोग्राफी में एक नये युग की शुरुआत की थी। उनका अविस्मरणीय योगदान भुलाया नहीं जा जा सकता और विभाग उनके द्वारा स्थापित मानदंडों को बनाये रखने के प्रति वचनबद्ध है।

फोटोग्राफी के सामान्य सिद्धांतों और व्यावहारिक पहलुओं से शुरूआत करते हुए एमपीपी सिनेमैटोग्राफिक सिद्धांत, अवधारणाओं, सौंदर्यपरक पहलुओं, प्रकाश की विभिन्न तकनीकों और प्रयोगशाला चरणों में नियंत्रण की पद्धतियों का प्रशिक्षण देता है।

एमपीपी विभाग में एक पूर्ण स्थिर फोटोग्राफी अनुभाग, अनेक ऐनालोग और डिजिटल कैमरा सैटअप और 16 एमएम तथा 35 एमएम सिने कैमरों से लेकर अरी एसआर 3 और अरी 435 स्तर तक के कैमरे मौजूद हैं। विभाग ने हाल ही में अरी सन-सीरीज एचएमआई लाइट्स हासिल की हैं। विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए अनेक अनुषंगी वस्तुएं भी हैं। विभाग विद्यार्थियों को नियमित रूप से अग्रणी प्रयोगशालाओं में भी ले जाता है।

कोडक और फ्यूजी जैसी कंपनियों के साथ घनिष्ट सहयोग के अलावा विभाग व्यापक कार्यशालाओं का आयोजन करता है। इन कार्यशालाओं में उच्च कोटि के सिनेमैटोग्राफर और वीडियो विशेषज्ञों के साथ वार्तालाप के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। इन विशेषज्ञों में सर्वश्री के के महाजन, वीरेंद्र सैनी, बरूण मुखर्जी, राजन कोठारी, सन्नी जोसेफ, अनिल मेहता, जहांगीर चौधरी, वेणु गोपाल, अभिक मुखोपाध्याय, ए एस कनाल, रंजन पलित, अनूप जोतवानी, रफी महमूद आदि शामिल हैं।

(ii) ऑडियोग्राफी

सत्यजित राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान भारत के उन गिने-चुने फिल्म स्कूलों में से एक है, जो ध्वनि रिकार्डिंग/ऑडियोग्राफी के क्षेत्र में प्रतिभाशाली प्रोफेसनल तैयार कर रहा है। विद्यार्थियों को मौके पर जाकर रिकार्डिंग, स्टूडियो रिकार्डिंग, फिल्म डबिंग और अंततः अत्याधुनिक कंसोलों पर साउंड मिक्सिंग जैसी सभी तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस विभाग में उपलब्ध सुविधाओं में डबिंग स्टूडियो, संगीत/गीत रिकार्डिंग स्टूडियो, जिसमें स्थायी और अस्थायी बूथ हैं, मिक्सिंग (पुनः रिकार्डिंग) स्टूडियो, एक बैक ग्राउंड और फोलि रिकार्डिंग स्टूडियो तथा समर्पित डिजिटल वर्क स्टेशन शामिल हैं। सभी स्टूडियो में अत्याधुनिक और अद्यतन उपकरण लगे हैं।

कलाकार की सुविधा और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए परंपरागत ऑडियो निर्माणोत्तर पद्धति, ऐनालोग रिकार्डिंग का मिश्रण अत्याधुनिक डिजिटल रिकार्डिंग प्रौद्योगिकियों के साथ कराया जाता है। ध्वनि विज्ञान और इलेक्ट्रोनिक जैसी अनुषंगी प्रौद्योगिकियों को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है, ताकि सही अर्थों में पूर्ण साउंड रिकार्डिस्ट तैयार किए जा सकें।

प्रशिक्षकों में फिल्म स्कूलों में प्रशिक्षित जाने-माने व्यवसायी शामिल हैं, जिन्हें फिल्म उद्योग में भी व्यापक अनुभव है। प्रशिक्षण का महत्व इस बात से और भी बढ़ जाता है कि जानी-मानी हस्तियों की कक्षाओं और कार्यशालाओं में नियमित भागीदारी रहती है। इनमें ए एम पद्मनाभन, अविनाश ओक, सतीश कुमार, नकुल कामते, राकेश रंजन, सुमिताभ राय, अनूप मुखर्जी, सोमनाथ मंडल, डॉ. रवीन्द्रनाथ बेरा, अशोक शुक्ला, सुदीप्त मोहन बसू, अरूण बोस, विश्वदीप चटर्जी शामिल हैं।

विद्यार्थियों को जाने माने संगीतकारों और संगीत आचार्यों और अन्य कलाकारों से परस्पर संपर्क का अवसर भी मिलता है, जिन्हें बार-बार संस्थान में बुलाया जाता है।

(iii) विभाग विद्यार्थियों के लिए सीखने में प्रेरक और सहायक वातावरण उपलब्ध कराने के निरंतर प्रयास करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे व्यवसायियों के रूप में खास भूमिका अदा कर सकें और मीडिया संबंधी विभिन्न व्यवसायों में रचनात्मक योगदान करें। इन प्रयासों में व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही स्तरों की जरूरतों पर ध्यान दिया जाता है।

विभाग में फिल्म और वीडियो संपादन के प्रति समर्पित अलग अलग अनुभाग हैं। फिल्म अनुभाग के अंतर्गत अलग-अलग दस स्टीनबीक एडिटिंग सूट्स हैं। डिजिटल नोन-लिनियर संपादन कक्ष में एविड मीडिया कम्पोजर्स, एविड डीवी एक्सप्रेस, फाइनल कटप्रो जैसे उपकरण लगे हैं, वहीं दूसरी ओर नोन-लीनियर संपादन के प्रति समर्पित सिनेमा टूल, अडोब प्रीमियर प्रो सेटअप कायम किया गया है। विभाग में पांच लिनियर वीडियो एडिटिंग सूट्स और वर्क स्टेशन के साथ एक ग्राफिक्स अनुभाग भी है, विभाग के पास नियमित स्क्रीनिंग, विचार विमर्श और विश्लेषण के लिए अवलोकन एवं डिजिटल संपादन डिमोस्ट्रेशन सुविधाओं सहित एक विशेष क्लासरूम-एगिट प्रॉप भी है।

विभाग नियमित रूप से अनुभवी व्यवसायियों को आमंत्रित करता है ताकि विद्यार्थी उनकी विशेषज्ञता से लाभ उठा सकें। वर्ष के दौरान कार्यशालाओं, व्याख्यान पत्रों, मूल्यांकन एवं परस्पर संपर्क कार्यक्रम के दौरान इन विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया :

रीना मोहन, अर्जुन गौरीसारिया, अर्घ्यकमल मित्रा, अमिताभ चक्रवर्ती, सौरव शांरगी, संजीव दत्ता, अब्राहम मजूमदार, असीम सिन्हा आदि।

(iv) निर्देशन और पटकथा-आलेखन

विभाग एक वर्षीय समेकित पाठयक्रम (जो तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयक्रम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम वर्ष है) में समन्वयकर्ता है और दो वर्षीय विशेषज्ञता पाठयक्रम (यानी निर्देशन और पटकथा-आलेखन को दूसरे और तीसरे वर्ष में विकल्प के रूप में अपनाने वाले विद्यार्थियों के लिए) का संचालन करता है।

समेकित पाठ्यक्रम इस बात को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है कि विद्यार्थियों को प्रत्येक विशेषज्ञता विभाग (निर्देशन, कैमरा, संपादन और ध्वनि) के कार्यों की बुनियादी जानकारी दी जा सके और साथ ही फिल्म कला में इन कार्यों की परस्पर निर्भरता और क्रमानुसार उनके विकास का परिचय कराया जा सके।

विशेषज्ञता की शुरूआत अनेक सैद्धांतिक कक्षाओं से होती है और प्रैक्टिकल सत्रों के जरिए पटकथा आलेखन सहित निर्देशात्मक प्रक्रिया की व्यापक जानकारी विद्यार्थियों को दी जाती है। वर्णन कौशल विकसित करने और दृश्य-सज्जा की पुनर्रचना करने की योग्यता पैदा करने के लिए अभ्यास कराये जाते हैं। निर्देशन-कौशल और स्क्रीनप्ले-आलेखन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है और उनमें प्रतिष्ठित व्यवसायियों को बुलाया जाता है।

विभाग में एक प्रदर्शन कक्ष, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला और एक बुनियादी निर्माण परवर्ती सेटअप की भी व्यवस्था की गयी है।

नियमित प्रशिक्षकों के अलावा व्याख्यानों, परिचर्चाओं, कार्यशालाओं और मूल्यांकन के लिए इन विशेषज्ञों को बुलाया गया :

कुमार सहानी, सईद मिर्जा, अडूर गोपाल कृष्णन, के हरिहरन, रीना मोहन, जिरि मेन्ज़ेल, कमल स्वरूप, पॉल कॉक्स, शाजी करुण, आर्टुरो रिएप्स्टेन आदि।

विद्यार्थी आदान-प्रदान कार्यक्रम

विद्यार्थी आदान-प्रदान कार्यक्रम की शुरूआत 2001 में की गयी थी, जिसके तहत एसआरएफटीआई के दो विद्यार्थी कोनडि वोल्फ फिल्म स्कूल, पोत्सदम, जर्मनी भेजे गए थे। उन्होंने वहां 'फोर्थ वर्ल्ड' नाम की लघु फिल्म बनाई थी। जर्मन फिल्म स्कूल से भी दो विद्यार्थी एसआरएफटीआई में आए थे और उन्होंने 'हावर हावर' नाम की डाक्यूमेंटरी फिल्म बनाई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय और

एसआरएफटीआई डिप्लोमाधारकों द्वारा जीते गए पुरस्कार और सम्मान

क्र.स.	फिल्म का नाम	पुरस्कार	विजेता निर्देशक/
1.	मीना झा (हिंदी)	निदेशक की पहली सर्वोत्कृष्ट फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2001	निर्देशक : अंजालिका शर्मा
2.	भोर (बांग्ला)	सर्वोत्तम लघु कथा फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2001	निर्देशक : ऋतुबर्न चडगर
3.	मीना झा (हिंदी)	48वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए सिनेमैटोग्राफी के वास्ते विशेष उल्लेख	सिनेमैटोग्राफर : अमाल नीरद सी आर
4.	खोज (बांग्ला)	कैन्स फिल्म समारोह 2002 (फ्रांस) में सिने फाउंडेशन खंड में प्रदर्शन के लिए चुनी गई।	निर्देशक : त्रिदिव पोद्दार
5.	द ईगोटिक वर्ल्ड (मलयालम)	ओबरहोसेन फिल्म समारोह, 2002 (जर्मनी), मांट्रियल फिल्म समारोह (कनाडा) में प्रदर्शन के लिए चुनी गई।	निर्देशक : विपिन विजय
6.	द ईगोटिक वर्ल्ड (मलयालम)	कोडक विद्यार्थी समारोह, 2001 (भारत) मे सर्वोत्तम विद्यार्थी फिल्म के रूप में चुनी गई	सिनेमैटोग्राफर : मिलिंद नागमूले
7.	खोज (बांग्ला)	बंगाल फिल्म पत्रकार संघ (बीएफऐज) पुरस्कार, 2002 में सर्वोत्तम निर्देशक	निर्देशक : त्रिदिव पोद्दार
8.	अभिमान बैंड पार्टी (बांग्ला)	बंगाल फिल्म पत्रकार संघ (बीएफऐज) पुरस्कार, 2002 में सर्वोत्तम लघु फिल्म	निर्देशक : सिलादित्य सान्याल
9.	सुंदर जीवन (बांग्ला)	सर्वोत्तम लघु कथा फिल्म/राष्ट्रीय पुरस्कार 2003	निर्देशक : संदीप चट्टोपाध्याय
10.	खोज (बांग्ला)	आईडीपीए पुरस्कार (प्रथम सर्वोत्कृष्ट फिल्म)/एमआईएफएफ 2004	निर्देशक : त्रिदिव पोद्दार
11.	टेट्रिस (बांग्ला/इंग्लिश)	केन्स फिल्म समारोह 2006 (फ्रांस) में सिने फाउंडेशन खंड में प्रदर्शन के लिए चुनी गई	निर्देशक : अनिर्बन दत्ता
12.	कुलाई चौला (उड़िया)	केरल फिल्म समारोह 2006 में प्रतियोगिता खंड के लिए चुनी गई	निर्देशक : संजीव मेहरा
13.	बाघेर बच्चा (बांग्ला)	सिंगापुर में प्रथम फिल्मों के एशियाई फिल्म समारोह, फ्रांस में सिनेरेल, पेरिस के वसील फिल्म समारोह के लिए चुनी गई	निर्देशक :क्ष विष्णुदेव हल्दर
14.	एन एक्टर प्रीपेयर्स (बांग्ला/हिंदी)	सिनेमा डू रील, पेरिस	निर्देशक : कालू बेल

अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर अन्य फिल्म स्कूलों के साथ आदान-प्रदान की संभावनाओं की तलाश की जा रही है।

निर्देशन विशेषज्ञता से संबद्ध विद्यार्थियों (2005) ने एचएचएफ, पोत्सदम जर्मनी के साथ फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आदान-प्रदान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एचएफएफ के विद्यार्थी भी एसआरएफटीआई कैम्प्स में आए और कार्यक्रम निर्माण में संस्थान के विद्यार्थियों के साथ मिलकर काम किया।

संपादन विशेषज्ञता से संबद्ध विद्यार्थियों (2006) को 2 हफ्ते की एचडी इन्टर्नशिप के लिए एनएचके जापान भेजा गया, जहां उन्होंने 3 लघु फिल्में बनाईं।

गतिविधियां

संस्थान के परिसर में वर्ष भर ऐसी पाठ्यतर गतिविधियां और कार्यक्रमों का आयोजन जारी रहा, जो संस्थान के प्रमुख लक्ष्य, यानी फिल्म शिक्षा से संबद्ध थीं। विद्यार्थी निम्नांकित गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें अमली जामा पहनाने में सक्रिय रूप से शामिल हुए।

- क्लैपस्टिक : यह विद्यार्थियों की फिल्मों का एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह है। पांच दिन के इस वार्षिक आयोजन का न केवल एसआरएफटीआई के विद्यार्थियों को बल्कि कोलकाता के समूचे फिल्म-प्रेमी समुदाय को उत्सुकता से इंतजार रहता है। इस समारोह में मित्रा मेमोरियल व्याख्यान प्रमुख आकर्षण होता है। पिछले वक्ताओं में के. के. महाजन और वाल्टर मर्च शामिल हैं।
- डोसेडजे : यह एक अंतर्राष्ट्रीय पिचिंग कार्यशाला है। इसमें वृत्तचित्र फिल्म निर्माताओं को अपनी फिल्में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म आयुक्तों के पैनल के सामने रखने का अवसर मिलता है।
- सत्यजित राय मेमोरियल व्याख्यान हर वर्ष 2 मई (सत्यजित राय का जन्मदिन) को आयोजित किया जाता है। अभी तक के वक्ताओं में कुमार शाहानी, मृणाल सेन, अडूर गोपाल कृष्णन, बुद्धदेब दास गुप्ता और शाजी करुण शामिल हैं।
- तृतीय शनिवार सेमिनार : फिल्म कला से संबद्ध विभिन्न विभागों के बीच ताल-मेल कायम करने के लिए हर महीने के तीसरे शनिवार को सेमिनार का आयोजन किया जाता है।
- विद्यार्थियों को जाने मानी फिल्मी हस्तियों से रू-ब-रू कराने के लिए 'गेस्ट इन कैम्प्स', 'मीट द ऐचिवर' जैसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।
- एसआरएफटीआई कैम्प्स मैक्समूलर भवन, एलांयस फ्रांसे, अमरीकन सेंटर और कनाडा उच्चायोग द्वारा आयोजित फिल्म प्रदर्शन और कार्यशालाओं के लिए लोकप्रिय स्थल है।
- वर्ष के दौरान चित्रकारी, संगीत और नृत्य आदि पाठ्यक्रम से इतर विषयों पर भी विचार-गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- एसआरएफटीआई 'टेक वन' नाम से न्यूज लैटर भी प्रकाशित करता है। व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विद्यार्थी होली, नववर्ष, नए विद्यार्थियों के स्वागत जैसे अवसरों पर पार्टी आदि के आयोजन में भी भाग लेते हैं।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

देश में अच्छे सिनेमा आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड - एन एफडीसी की स्थापना की गई थी। एनएफडीसी को भारतीय फिल्म उद्योग के समन्वित तथा सक्षम विकास के लिए योजना बनाने, बढ़ावा देने और संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। एनएफडीसी की गतिविधियों में शामिल कार्य निम्नलिखित हैं -

क. सामाजिक प्रासंगिकता और जीवन मूल्यों वाली सुरुचिपूर्ण फिल्मों का निर्माण और उनके लिए वित्त की व्यवस्था करना।

ख. विभिन्न चैनलों के माध्यम से फिल्मों का आयात और वितरण करना।

ग. विदेशों में भारतीय फिल्मों का निर्यात और संवर्धन तथा स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं को इन फिल्मों का विदेश में विपणन में सहायता करना।

घ. भारतीय फिल्म उद्योग को निर्माण से पहले और निर्माण के बाद तकनीकी परियोजना सेवाएं प्रदान करना

च. सिनेमा के माध्यम से देश और विदेश में संस्कृति और समझबूझ को बढ़ावा देना, इसके लिए फिल्म संस्थानों, राष्ट्रीय फिल्म सर्किल तथा अन्य संगठनों के साथ मिलकर फिल्म समारोहों का आयोजन करना।

छ. भारतीय सिने कलाकार कल्याण कोष - सीएडब्ल्यूएफआई के जरिए पुराने जरूरतमंद फिल्म कलाकारों के लिए कल्याणकारी उपाय करना। सीएडब्ल्यूएफआई निगम द्वारा स्थापित एक परोपकारी न्यास (चैरिटेबल ट्रस्ट) है।

1. फिल्मों का वित्तपोषण और निर्माण

एनएफडीसी कम बजट वाली लेकिन बेहतरीन विषय वस्तु की फिल्मों की अवधारणा को प्रोत्साहन देता है। इसका उद्देश्य युवा फिल्म निर्माताओं को अपने कौशल विकास के लिए मंच प्रदान करना है। निगम द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त/निर्मित फिल्में विगत में कई राष्ट्रीय और अंतरर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी हैं। एनएफडीसी (पहले के फिल्म वित्त निगम एफएफसी सहित) अब तक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत ऐसी लगभग 316 फिल्मों का निर्माण या वित्तीय पोषण कर चुका है।

निगम द्वारा वर्ष के दौरान निर्माणाधीन फिल्म संस्कार (बांग्ला) को पूरा करने का प्रस्ताव है। इसका निर्देशन नब्येन्दु चटर्जी कर रहे हैं।

निगम ने फिल्मों के सह-निर्माण के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत आवेदनकर्त्ता को फिल्म का तीस प्रतिशत बजट जुटाना होगा। निगम प्रत्येक संस्करण में अधिकतम 5 पटकथाएं फिल्म निर्माण का चयन करेगा और पूरी परियोजना की लागत का 30 प्रतिशत निवेश करेगा लेकिन निवेश की अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपये होगी। शेष 30 प्रतिशत की राशि किसी निवेशक या वित्तीय संस्थान से जुटाई जाएगी।

जनजागरूकता अभियान के तौर पर एनएफडीसी फिल्म्स डिवीजन के सहयोग से सभी सिनेमाघरों में एंटी पायरेसी, स्वच्छता और प्रदूषण की रोकथाम इत्यादि जैसे सामाजिक संदेश वाली 60 से 90 सैकंड की लघु फिल्में/एनीमेशन फिल्में प्रदर्शित करेगा।

2. भारतीय पैनोरमा और राष्ट्रीय फिल्म सर्किल

निगम ने देश भर में फिल्म सप्ताह आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों और फिल्म समितियों को सभी मदद देना जारी रखा। निगम के इसी प्रोत्साहन से विभिन्न गैर-सरकारी संगठन, सामाजिक संगठन और महिला संगठन फिल्म समारोह आयोजित करने में रुचि दिखा रहे हैं। देश के कोने-कोने से ये मांग बढ़ रही है कि भारतीय पैनोरमा के लिए चुनी गई फिल्मों को 'फिल्म सप्ताह' और 'फिल्मोत्सवों' के लिए उपलब्ध कराया जाए। वित्त वर्ष 2006-07 (अक्टूबर 2006 तक) के दौरान निगम ने देश भर में केन्द्रों पर पैनोरमा फिल्मों का प्रदर्शन किया।

एनएफडीसी, एनएफएआई और सीएफएसआई के तत्वाधान में राष्ट्रीय फिल्म सर्किल ने नेहरु केन्द्र और एनसीपीए में अच्छे सिनेमा का प्रदर्शन जारी रखा। वित्त वर्ष 2006-07 (अक्टूबर 2006 तक) के दौरान राष्ट्रीय फिल्म सर्किल ने 31 फिल्में दिखाईं। कई अन्य शहरों में भी राष्ट्रीय फिल्म सर्किल को फिर बनाया जा रहा है। दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से फिल्में प्रदर्शित की गईं। चेन्नई में नेशनल फिल्म सर्किल की सदस्यता 205 हो गई है। चेन्नई में हर सप्ताह भारतीय और विदेशी फिल्में दिखाईं गईं।

एनएफडीसी ने देश में प्रमुख क्षेत्रीय फिल्मोत्सम का सह प्रायोजन किया।

3. फिल्मों का निर्यात

(अ) वर्ष 2006-07 के दौरान (अक्टूबर 2006 तक) विभिन्न देशों को 49 फिल्में निर्यात की गईं। इससे 56 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की आमदनी हुई। वर्ष के दौरान निगम की लगभग 77 फिल्में निर्यात करने की योजना है।

निगम अन्तराष्ट्रीय फिल्मोत्सवों और इसी तरह के आयोजनों में नियमित रूप से हिस्सा लेता है। विभिन्न भारतीय कंपनियों को विश्व के प्रमुख फिल्म बाजारों जैसे कान फिल्म समारोह, हांगकांग और अमेरिकन फिल्म आयोजनों में भाग लेने में मार्च 2006 में आयोजित 'फिल्ममार्ट' में भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अपनी फिल्मों के लिए विपणन अवसर बढ़ाने के वास्ते एनएफडीसी ने फ्रांस में अक्टूबर 2006 में आयोजित 'मिपकॉम' तथा नवम्बर 2006 में अमरीका में अमरीकी फिल्म मार्केट में हिस्सा लिया।

(आ) समारोहों में भागीदारी के जरिए भारतीय फिल्मों को विदेशों में प्रोत्साहन

वर्ष 2006-07 के दौरान (अक्टूबर 2006 तक) निगम ने 3 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में शिरकत की और विभिन्न भारतीय भाषाओं की दो फिल्में प्रदर्शित कीं।

4. राजभाषा का कार्यान्वयन

राजभाषा अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बने नियम, राजभाषा विभाग और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के बारे में जारी आदेशों को वर्ष के दौरान निगम के कार्यालयों में लागू किया गया।

निगम के कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं और राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2006-07 के वार्षिक कार्यक्रम को लागू करने के लिए यथोचित कदम उठाए गए। इस वर्ष निगम को हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए मुंबई के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 'आशीर्वाद पुरस्कार' प्राप्त किया।

5. आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण/ई-कामर्स गतिविधियां

वर्ष के दौरान अनेक कंप्यूटर के स्थान पर उनके नए मॉडल लगाए गए। ई-कामर्स के प्रभावी उपयोग तथा ई-मेल के माध्यम से पत्राचार को बढ़ावा दिया गया। निगम की वेबसाइट - www.nfdcindia.com कार्य और विकासात्मक भूमिका के मद्देनजर फिर से डिजाइन की गई।

6. विशेष तकनीकी परियोजनाएं

निगम के पास लेजर के जरिए फिल्मों के उपशीर्षक बनाने (सबटाइटलिंग) अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं तथा हाल में इन्हें उन्नत किया गया है।

सबटाइटलिंग की सुविधा अंग्रेजी, अरबी, चीनी, जापानी और रूसी भाषाओं में उपलब्ध कराई जाती हैं। यूनिट दो अत्याधुनिक स्वचालित मिलेनियम की सॉलिड स्टेट लेजर मशीनों से लैस है। इसमें इंटरपॉज़िटिव लेज़र सबटाइटिलिंग की अत्याधुनिक सुविधाएं भी हैं। यूनिट में वीडियो सबटाइटिलिंग तथा संपादन सुविधाएं भी हैं और यह हाई बैंड बीटाकैम और डिजी बीटाकैम फार्मेट में सभी भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं तथा अंग्रेजी भाषा में सबटाइटलिंग कर सकती है।

निगम ने मुंबई में 2004 से डीवीडी/वीसीडी ऑथरिंग/मास्टरिंग एंड डुप्लीकेशन सुविधाएं शुरू की हैं। निजी कंपनियों के आर्डर के अतिरिक्त भारतीय पैनोरमा 2004, 2005 और 2006 के लिए कई फिल्मों में सबटाइटलिंग की गई। यूनिट सभी भाषाओं में डी वी डी सबटाइटलिंग करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित है।

निगम ने अपनी तथा सहनिर्मित सभी फिल्मों की डीवीडी जारी करने का प्रस्ताव किया है।

निगम की कैमरा यूनिट सभी सहायक उपकरणों से युक्त सुपर 16 मि.मी. एस आर फिल्म कैमरा और वीडियो असिस्ट यूनिट तथा सहायक उपकरणों से युक्त एआरआरबीएल-III फिल्म कैमरा से सुसज्जित है। मुंबई में निगम के अपने वीडियो संपादन कक्ष हैं, जहां गुणवत्ता जांच की सुविधाएं मौजूद हैं। ये संपादन कक्ष प्रोमो कैप्सूल के अलावा प्रमोशनल सामग्री के निर्माण संबंधी जरूरतें पूरी करते हैं।

स्टूडियो में वीडियो फिल्मों इत्यादि की डबिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। नॉन-लीनिअर एडिटिंग सुविधाएं शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। इसमें डी.वी. तथा एच डी फॉरमेट को वरीयता दी जाएगी।

एनएफडीसी के नई दिल्ली स्टूडियो में वीडियो सम्पादन कक्ष हैं जो गुणवत्ता जांच की सुविधाओं से युक्त हैं। ये कक्ष प्रोमो कैप्सूल तथा प्रमोशनल सामग्री के निर्माण संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं।

यूनिट में नोन-लीनियर एडिटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इसमें सम्पादन के लिए नवीनतम ए वी आई डी एक्सप्रेस एच डी ओ मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। यूनिट ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में स्थापित वीडियो सर्वर को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की नई पहल शुरू की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एकलव्य चैनल को भी तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

चेन्नई स्थित वीसीआर यूनिट सारी दक्षिण क्षेत्र के फिल्म उद्योग की जरूरतें पूरी करता है। केंद्र के पास गुणवत्ता जांच के साथ-साथ प्रमोशनल सामग्री के निर्माण के लिए हाई बैंड, बीटा कैम संपादन सुविधाएं मौजूद हैं। यूनिट एफडीएल 60 टेलीसिने मशीनों के जरिए हाइबैण्ड, बीटाकैम और डिजि बीटा कैम फार्मेट में फिल्मों को वीडियो में रूपांतरित करने के उपकरण से युक्त है।

निगम डीवीडी/वीसीडी मास्टरिंग/ऑथरिंग तथा डुप्लीकेशन सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है।

इसके अलावा निगम विभिन्न सरकारी विभागों के लिए वृतचित्रों के निर्माण का भी कार्य करता है। तकनीकी सुविधाओं का इस्तेमाल वीडियो एडिटिंग तथा अन्य कार्यों का सरकार द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए भी किया जाता है।

7. भारतीय सिने कलाकार कल्याण कोष

निगम द्वारा फिल्म उद्योग के अब तक के सबसे बड़े कोष भारतीय सिने कलाकार कल्याण कोष की स्थापना 1992 में की गई थी। इस कोष से बीते जमाने के जरूरतमंद सिने कलाकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। न्यास की राशि अब बढ़ कर 472 करोड़ रुपये हो गई है। अब तक 276 सिने कलाकार इस न्यास से पेंशन और अन्य फायदे ले चुके हैं। इस समय 510 सिने कलाकार न्यास से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष के दौरान अक्टूबर 2006 तक सिने कलाकारों को 26.24 लाख रुपये की राशि पेंशन के रूप में भुगतान की जा चुकी है। अगले वर्ष सिने कलाकारों को पेंशन और अन्य लाभों के रूप में 4600 लाख रुपये की राशि के भुगतान किए जाने की आशा है।

8. सतर्कता संबंधी उपाय

वर्ष के दौरान निर्णय लेने की तथा खरीद आदि की विभिन्न प्रक्रियाओं पर नजर रखने के लिए कई नई व्यवस्थाएं शुरू की गईं।

9. योजना कार्यक्रम तथा कार्य निष्पादन

निगम ने पिछले नौ सालों से अपनी विकासात्मक योजना गतिविधियों को पूरी तरह से अपने आंतरिक संसाधनों से पूरा कर रहा है। इसके लिए सरकार से उसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिल रही है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान निगम के वित्तीय निष्पादन के मुख्य अंश परिशिष्ट में दिए गए हैं।

10. निगम की भविष्य की योजनाएं एवं गतिविधियां

जैसा कि आरंभ में बताया गया है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड कम बजट वाली फिल्मों को प्रोत्साहन देता है लेकिन इस पर भी पूरा जोर दिया जाता है कि फिल्म की गुणवत्ता बनी रहे और ये बेहतरीन कथावस्तु पर आधारित हों।

भारतीय फिल्म उद्योग में हिन्दी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्में बनती हैं। निगम को विभिन्न भाषाओं में फिल्म निर्माण वाली एकमात्र 'प्रोडक्शन हाउस' होने का गौरव प्राप्त है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में निगम ने निम्नलिखित उद्देश्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है :

(क) फिल्मों का निर्माण - अपनी तथा सह-निर्मित फिल्मों स्कीम के अंतर्गत।

(ख) मेट्रो केंद्रों पर फिल्म प्रदर्शन की स्वयं की सुविधाएं स्थापित करना।

(ग) तकनीकी परियोजनाओं का आधुनिकीकरण तथा नई परियोजनाएं शुरू करना।

(घ) विदेशों में भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए बाजार ढांचा तैयार करना।

अपनी स्थापना से ही निगम देश तथा विदेश दोनों स्थानों पर भारतीय फिल्म उद्योग के विकास के उद्देश्य को पूरा करने में जुटा है।

समय के साथ-साथ फिल्म उद्योग ने आकार और आर्थिक रूप में काफी बढ़ोत्तरी की है। इसे देखते हुए जरूरी है कि निगम की गतिविधियों को पुनर्निधारित किया जाए ताकि फिल्म उद्योग को लाभ मिल सके। इसलिए अगले दो-तीन वर्ष के दौरान निगम ने निम्न प्रमुख क्षेत्रों में अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव किया है -

(क) विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में सामाजिक प्रासंगिकता और मूल्यों वाली बेहतरीन फिल्मों का निर्माण करना

(ख) अंतर्राष्ट्रीय सह-निर्माण

(ग) विभिन्न देशों में भारतीय भाषाओं में बनी फिल्मों का निर्यात करना और प्रोत्साहन देना

(घ) पटकथा लेखन विकास

10.1 क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण

सिनेमा भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और भाषाओं को बनाए रखने और इनका संवर्धन करने वाला महत्वपूर्ण साधन है। खास तौर पर यह देखते हुए कि सिनेमा मनोरंजन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है, इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। अनुमान है कि भारत में एक करोड़ लोग प्रतिदिन थिएटरों में फिल्में देखते हैं। भारतीय कला और संस्कृति की किसी ौर विधा का जन-जीवन पर ऐसा व्यापक प्रभाव नहीं है और सिनेमा संस्कृति का जन-माध्यम बनकर उभरा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, 11वीं योजना अवधि में एनएफडीसी को क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण के लिए सरकारी मदद दिए जाने का प्रस्ताव है।

11. अंतराष्ट्रीय/घरेलू-सह निर्माण

एनएफडीसी ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का सह-निर्माण किया है। विश्व बाजार के खुलने से अब विभिन्न देशों मं फिल्म दर्शक अन्य देशों की फिल्मों को देखने में रुचि लेने लगे हैं। फिल्म निर्माण अब देशों की सीमाएं लांघ रहा है और अब फिल्म निर्माता फिल्म बनाने के लिए अन्य देशों के साथ सह-निर्माण के लिए आगे आ रहे हैं। इसके निम्न कारण हैं -

(क) फिल्म के दर्शकों का आधार बढ़ाना

(ख) विभिन्न देशों द्वारा स्थानीय फिल्मों कोमिलने वाले कर छूट तथा अन्य वित्तीय लाभ लेते हुए फिल्म निर्माण की लागत कम से कम करना।

जहां तक भारतीय फिल्मकारों का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय-सह-निर्माण अभी शैशव अवस्था में है। हाल के वर्षों में अन्य देशों द्वारा भारत में फिल्म सह-निर्माण में रुचि दिखाने में वृद्धि हुई और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां विकास की अपार संभावना है। उभरते तथा नए फिल्मकारों की अक्सर अन्य देशों के निर्माताओं तक पहुंच नहीं हो पाती - चाहे संपर्क की बात हो तया फिर अन्य देश के सहनिर्माता से पर्याप्त पूंजी निवेश आकर्षित करने का मुद्दा हो। निगम का इस क्षेत्र में पदार्पण करते हुए संभावित अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू सह-निर्माताओं को आरंभिक पूंजी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

परिशिष्ट क

पिछले पांच वर्षों के दौरान निगम के वित्तीय निष्पादन के मुख्य अंश

(लाख रुपये में)

पूंजीगत ढांचा	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**
प्राधिकृत पूंजी	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
प्रदत्त पूंजी	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
वित्तीय उपलब्धियां					
कारोबार	8,545.52	7,779.54	3,690.65	2,209.28	3,786.71
व्यय	7,980.82	8,442.77	4,616.14	2,596.02	3,538.56
लाभ/(हानि) कर पूर्व	564.70	(663.23)	(925.49)	(386.74)	248.15
लाभ/हानि कर पश्चात	409.70	(663.23)	(925.49)	(386.74)	238.15
विदेशी मुद्रा में आम	119.81	93.36	69.00	100.03	62.88
संचालनात्मक उपलब्धियां					
फिल्म निर्माण तथा फिल्म उपकरणों की खरीद के लिए ऋण वितरण	7.39	15.75	11.86	–	–
स्व निर्माण/सह-निर्माण में निवेश	250.52	277.75	186.73	13.87	9.59
थिएटर निर्माण के लिए ऋण वितरण	–	–	–	–	–
आय					
टीवी के माध्यम से फिल्मों का वितरण	7,355.78	6,388.96	2578.19	1,408.56	658.57
फिल्म साफ्टवेयर का निर्यात	252.17	172.34	141.51	133.21	67.92
विदेशी फिल्मों का वितरण	249.66	469.87	61.50	28.67	5.34
विशेष परियोजनाएं	442.50	406.26	518.02	297.49	296.86

11.1 भारतीय फिल्मों को विश्व बाजार में बढ़ावा देने के लिए एनएफडीसी की निर्यात रणनीति के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैः

(क) विभिन्न चैनलों के लिए भारतीय फिल्मों का निर्यात

(ख) अंतर्राष्ट्रीय सह-निर्माण के लिए निर्माताओं की पहचान

(ग) एनएफडीसी सेवाओं को लाइन प्रोड्यूसर के रूप में प्रोत्साहन

(घ) भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्थल के रूप में प्रचार।

(च) भारतीय बाजार के लिए विदेशी फिल्मों का आयात

पटकथा विकास

ऐसा महसूस किया जा रहा है कि फिल्म उद्योग को पटकथा विकास पर अधिक जोर देने की जरूरत है। एनएफडीसी का लक्ष्य हर वर्ष निश्चित संख्या में मदद करने का है तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के लिए उच्च स्तर की फिल्में बन सकें। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू सह-निर्माण, निर्यात और पटकथा विकास के लिए धन निगम के आंतरिक संसाधनों से जुटाया जाएगा लेकिन विभिन्न भारतीय भाषाओं में अच्छी फिल्में बनाने के लिए सहायता की ज़रूरत है। निगम की वर्तमान अधिकृत पूंजी 14 करोड़ रुपये है जो फिल्म-निर्माण की बढ़ती लागत को देखते हुए अपर्याप्त है। इसीलिए सरकार से योजना सहायता के लिए अनुरोध किया जा रहा है।

6

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

भारत और युनेस्को

भारत संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) का संस्थापक सदस्य है। युनेस्को का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, समाज-विज्ञान, संस्कृति और संचार माध्यमों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। 1981 में युनेस्को की आम बैठक के 21वें अधिवेशन में सदस्य देशों के बीच परस्पर संवाद व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। इसका उद्देश्य विकासशील देशों की संवाद क्षमताओं को उन्नत करना था। इसकी स्थापना में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत युनेस्को की अंतर्शासकीय परिषद के सदस्य के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम का सदस्य भी है।

युनेस्को के साथ सहयोग से संबद्ध भारतीय राष्ट्रीय आयोग की आम सभा की बैठक 30 दिसंबर 2006 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने बैठक में हिस्सा लिया और डब्ल्यूआईपीओ संधि से संबंधित प्रगति की जानकारी दी।

अंतर्राष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम (आईपीडीसी) की अंतर्शासकीय परिषद की 25वीं बैठक 21-23 मार्च 2006 को फ्रांस में पेरिस में आयोजित की गई। इसमें मंत्रालय का प्रतिनिधित्व संयुक्त सचिव (प्रसारण) ने किया।

वर्ष 2007 के लिए युनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम (आईपीडीसी) के लिए भारत का वार्षिक नकद योगदान दे दिया गया है।

गुट निरपेक्ष समाचार नेटवर्क (एन एन एन)

गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल (एनएएनएपी) का औपचारिक गठन 1976 में हुआ। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर सूचना के असंतुलन को दूर करना है। यह गुटनिरपेक्ष देशों की राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के बीच समाचारों और सूचना के आदान-प्रदान का प्रबंध करता है।

गुटनिरपेक्ष देशों के प्रसारण मंत्रियों (सीओएमआईएनएसी) का छठा सम्मेलन 19-22 नवंबर 2005 की अवधि में मलेशिया की राजधानी क्वालालम्पुर में हुआ। इसमें गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल (एनएएनएपी) के स्थान पर जून 2006 से गुटनिरपेक्ष समाचार नेटवर्क स्थापित करने का फैसला किया गया। बैठक में महसूस किया गया कि एनएएनएपी अपना प्रभाव खो चुका है क्योंकि उसे सदस्य देशों का समर्थन घटता जा रहा है। इसलिए ''आगे बढ़ने के लिए एक नई व्यावहारिक व्यवस्था, आवश्यक हो तो नए रूप में इसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।'' बैठक में मलेशिया के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, जिसमें कहा गया था कि एनएएनएपी के स्थान पर इंटरनेट आधारित एनएनएन यानी गुटनिरपेक्ष समाचार नेटवर्क स्थापित किया जाए। एनएनएन की औपचारिक शुरुआत 27 जून 2006 को क्वालालम्पुर में हुई। गुटनिरपेक्ष समाचार नेटवर्क गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों देशों से संबद्ध समाचार एजेंसियों के बीच समाचारों और फोटोग्राफ के आदान-प्रदान की इंटरनेट आधारित नई व्यवस्था है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया सहित गुटनिरपेक्ष देशों की समाचार एजेंसियों से प्राप्त योगदान के रूप में समाचार और फोटो एनएनएन वेबसाइट : http:/www.namnewsnetwork.org पर अपलोड किए जाते हैं ताकि सभी संबंध एजेंसियां ऑनलाइन इन्हें हासिल कर सकें। मलेशिया की समाचार एजेंसी बरनामा फिलहाल क्वालालम्पुर से इस वेबसाइट का संचालन कर रही है।

एनएनएन ने उस गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल (एनएएनएपी) का स्थान ले लिया है, जिसने 30 वर्ष तक गुटनिरपेक्ष देशों के बीच समाचारों के आदान-प्रदान की व्यवस्था के रूप में काम किया। इटरनेट चूंकि सस्ता और भरोसेमंद संचार माध्यम है, इसलिए एनएनएन को गुटनिरपेक्ष जगत के 116 राष्ट्रों के बीच सूचना का स्थायी प्रवाह सुनिश्चित करने की व्यवस्था के रूप में देखा जाने लगा है।

एनएनएन की शुरूआत के सिलसिले में पीटीआई ने अप्रैल 2006 में बरनामा द्वारा क्वालालम्पुर में बुलाई गई बैठक में भाग लिया। इसका प्रयोजन समाचारों के आदान-प्रदान की नई व्यवस्था के लिए संपादकीय नीति और दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देना था। पीटीआई ने एनएनएन के प्रारंभिक कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिए बरनामा ने अक्टूबर 2006 में क्वालालम्पुर में बुलाई गई बैठक में भी भाग लिया। गुटनिरपेक्ष सदस्य देशों की समाचार एजेंसियों के बीच सहयोग

के हिस्से के रूप में बरनामा के मुख्य संपादक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के निदेशक ने अगस्त 2006 में नई दिल्ली में पीटीआई का दौरा किया।

भारत और सार्क

भारत, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सक्रिय सदस्य है। सार्क के सदस्य देशों के सूचना मंत्रियों की बैठक प्रत्येक वर्ष होती है। सार्क देशों की सूचना मंत्रियों की अगली बैठक 2007 की दूसरी तिमाही में भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है।

सार्क सूचना केंद्र (एसआईसी) के कार्यकारी बोर्ड की दूसरी बैठक 19-20 दिसंबर 2006 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई, जिसमें मुख्य रूप से वर्ष 2007 के लिए कार्यक्रमों और 2007 के बजट प्रावधान पर विचार किया गया। इसमें मंत्रालय का नेतृत्व संयुक्त सचिव (कार्मिक और प्रशासन) ने किया।

7

योजना और गैर-योजना कार्यक्रम

योजना परिव्यय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक योजना 2006-07 के लिए 538.00 करोड़ रुपये (प्रत्यक्ष बजट सहयोग) स्वीकृत किए गए हैं। वार्षिक योजना 2006-07 का क्षेत्रवार ब्योरा इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रत्यक्ष बजट सहयोग (जी बी एस)	आंतरिक तथा बजट के बाहर (आई ई बी आर)	योग
1.	सूचना क्षेत्र	**27.28**	**—**	**27.28**
2.	फिल्म क्षेत्र	**40.95**	**—**	**40.95**
3.	प्रसारण क्षेत्र	**469.77**	**—**	**469.77**
	योग	**538.00**	**—**	**538.00**

2. वार्षिक योजना 2006-07 के लिए मीडिया इकाइयों/योजना कायक्रमों का ब्योरा परिशिष्ट में दिया गया है। 538 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष बजट सहयोग में से विभिन्न इकाइयों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 111.93 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जो प्रत्यक्ष बजट सहयोग का 20.80 प्रतिशत है।

3. प्रसार भारती की वार्षिक योजना 2006-07 के कुल परिव्यय में पूर्वोत्तर क्षत्र के रेडियो और टीवी कवरेज के लिए 111.93 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज और जम्मू-कश्मीर के लिए 110.00 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज शामिल है। ब्योरा इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

	आकाशवाणी			दूरदर्शन			कुल प्रसार भारती
	पूंजी	राजस्व	कुल	पूंजी	राजस्व	कुल	
पूर्वोत्तर पैकेज	**12.00**	**1.90**	**13.90**	**53.00**	**43.10**	**96.10**	**110.00**
जम्मू-कश्मीर विशेष पैकेज	**1.20**	**1.50**	**2.70**	**24.50**	**82.80**	**107.30**	**110.00**

अनुलग्नक-I

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
वार्षिक योजना 2006-07

(लाख रुपए में)

(13 फरवरी 2007 तक)

क्र.सं.	मीडिया इकाई	वार्षिक योजना-2006-2007		
		स्वीकृत परिव्यय **2006-2007**	संशोधन अनुमान **2006-2007**	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित राशि **2006-2007**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	**सूचना क्षेत्र**			
1.	पत्र सूचना कार्यालय	**1150.96**	**587.11**	**20.15**
2.	प्रकाशन विभाग	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.	विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय	**259.00**	**2315.00**	**26.00**
4.	भारतीय जन संचार संस्थान	**158.50**	**135.00**	**0.00**
5.	फोटो प्रभाग	**125.00**	**155.00**	**0.00**
6.	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	**110.00**	**113.01**	**12.62**
7.	गीत और नाटक प्रभाग	**850.00**	**737.50**	**100.00**
8.	गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग	**25.00**	**25.00**	**0.00**
9.	भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.	भारतीय प्रेस परिषद	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11.	मुख्य सचिवालय के लिए योजनाएं			**0.00**
	(क) सूचना भवन का निर्माण **(फेज-IV)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	(ख) विदेशों में स्थित संस्थानों में मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण	**50.00**	**40.00**	**0.00**
	योग (I) :	**2728.46**	**4107.62**	**158.77**
II	**फिल्म क्षेत्र**			
1.	फिल्म प्रभाग	**1010.00**	**1183.00**	**0.00**
2.	भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	**473.00**	**720.00**	**0.00**
3.	भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे	**235.11**	**235.11**	**0.00**
4.	सत्यजित राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे	**794.00**	**794.00**	**0.00**

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	मीडिया इकाई	वार्षिक योजना-2006		
		स्वीकृत परिव्यय 2006-2007	संशोधन अनुमान 2006-2007	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित राशि 2006-2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	फिल्म समारोह निदेशालय	671.00	428.00	0.00
6.	भारतीय बाल फिल्म समिति	531.30	356.00	10.00
7.	केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	260.13	241.00	5.00
	मुख्य सचिवालय (फिल्म स्कंध) योजनाएं			
8.	एफएफएसआई/एनजीओ को अनुदान सहायता	20.00	20.00	0.00
9.	भारत और विदेश में फिल्म बाजार में हिस्सेदारी	100.00	100.00	0.00
	योग (II) :	**4094.54**	**4077.11**	**15.00**
III	**प्रसारण क्षेत्र**			
1.	आकाशवाणी	7160.00	7097.00	720.00
2.	दूरदर्शन	38232.00	31603.27	8810.00
	योग प्रसार भारती (1+2)*	**45392.00**	**38700.27**	**9530.00**
3.	इलेक्ट्रानिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)	585.00	200.00	
4.	निजी एफएम रेडियो (फेज-II)	1000.00	415.00	
	कुल प्रसारण क्षेत्र (1+2+3+4)	**46977.00**	**39315.27**	**9530.00**
	कुल सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय (I+II+III)	**53800.00**	**47500.00**	**9703.77**

अनुलग्नक II

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(लाख रुपये में)

(13 फरवरी 2007 तक)

क्र.सं.	योजना कार्यक्रम का विवरण/मीडिया इकाई	वार्षिक योजना-2006-2007	
		स्वीकृत परिव्यय 2006-2007	संशो. अनुमान 2006-2007
[1]	[2]	[3]	[4]
क	**सूचना क्षेत्र**		
I	*पत्र सूचना कार्यालय*		
1	नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केंद्र की स्थापना	1000.00	450.00
2	पीआईबी की आधुनिकीकरण तथा कंप्यूटरीकरण गतिविधियां		
	i) डिजिटल स्टोरेज तथा हाई स्पीड कम्यूनिकेशन	82.55	88.10
	ii) सूचना केंद्र की स्थापना और वहां संचार-सुविधाएं जुटाना	43.41	44.01
3	पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सरकार द्वारा भूमि उपलब्धता वाले स्थानों पर पीआईबी कार्यालय भवनों का निर्माण	25.00	5.00
	योग :	**1150.96**	**587.11**
II	*प्रकाशन विभाग*		
1	प्रकाशन विभाग के कार्यक्रम	0.00	0.00
	योग :	**0.00**	**0.00**
III	*विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय*		
1	विकास प्रचार कार्यक्रम : धारणा और कार्यान्वयन	259.00	2315.00
	योग :	**259.00**	**2315.00**
IV	*भारतीय जन संचार संस्थान*		
	(अनुदान सहायता)		
1	भवन और आवास परियोजना	25.00	25.00
2	अनुसंधान और आकलन अध्ययन	35.00	25.00
3	इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट पत्रकारिता के लिए सुविधाओं का आधुनिकीकरण और विस्तार	83.50	83.50

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजना कार्यक्रम का विवरण/मीडिया इकाई	स्वीकृत परिव्यय 2006-2007	संशो. अनुमान 2006-2007
[1]	[2]	[3]	[4]
4	क्षेत्रीय अध्ययन केंद्रों से सहयोग	15.00	1.50
	योग :	**158.50**	**135.00**
V	*फोटो प्रभाग*		
1	फोटो प्रभाग का आधुनिकीकरण	125.00	155.00
	योग :	**125.00**	**155.00**
VI	*क्षेत्र प्रचार निदेशालय*		
1	फिल्मों/कैसेटों की खरीद	10.00	13.01
2	कैपिटल स्टॉक का आधुनिकीकरण और उन्नयन	100.00	100.00
	योग :	**110.00**	**113.01**
VII	*गीत और नाटक प्रभाग*		
1	पर्वतीय, जनजातीय, रेगिस्तानी, संवेदनशील तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सूचना तथा संचार टैक्नोलॉजी से संबद्ध गतिविधियां	850.00	737.50
	योग :	**850.00**	**737.50**
VIII	*गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग*		
1	आईआईएस अधिकारियों का प्रशिक्षण	25.00	25.00
	योग :	**25.00**	**25.00**
IX	*भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक*		
1	आरएनआई मुख्यालय के मुख्यालय का आधुनिकीकरण	0.00	0.00
	योग :	**0.00**	**0.00**
X	*मुख्य सचिवालय के कार्यक्रम*		
1	सूचना भवन का निर्माण (फेज-IV) *(सतत योजना)*	0.00	0.00
2	मानव संसाधन विकास	50.00	40.00
	योग :	**50.00**	**40.00**

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजना कार्यक्रम का विवरण/मीडिया इकाई	स्वीकृत परिव्यय 2006-2007	संशो. अनुमान 2006-2007
[1]	[2]	[3]	[4]
	सूचना क्षेत्र (कुल योग) :	**2728.46**	**4107.62**
(ख)		फिल्म क्षेत्र	
	फिल्म प्रभाग		
1	अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंटरी, लघु और एनिमेशन फिल्म समारोह	10.00	6.00
2	फिल्म प्रभाग के पुराने उपकरणों का आधुनिकीकरण और उन्हें बदलना	100.00	127.00
3	'म्यूजियम ऑफ मूविंग इमेज' की स्थापना	700.00	250.00
	योग :	**810.00**	**383.00**
II	*राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार*		
1	अभिलेखागार के लिए फिल्मों की प्राप्ति और प्रदर्शन	73.00	73.00
	योग :	**73.00**	**73.00**
III.	**फिल्म समारोह निदेशालय**		
1	फिल्म समारोह परिसर में परिवर्तन और नव-निर्माण	318.00	210.00
	योग :	**318.00**	**210.00**
IV	*बाल फिल्म समिति, भारत*		
	(अनुदान सहायता)		
1	फिल्म निर्माण (अनुदान सहायता)		
	क) फिल्म निर्माण	352.00	260.00
	ख) फिल्म समारोह	15.00	51.00
	ग) आधुनिकीकरण और सुविधाओं को बेहतर बनाना	1.50	1.25
	घ) एनिमेशन और पटकथा लेखन वर्कशॉप	4.80	2.20
2	म्यूनिसिपल स्कूलों में फिल्म प्रदर्शन	58.00	41.55
3	हैदराबाद में सीएफएसआई परिसर (नई योजना)	100.00	0.00
	योग :	**531.30**	**356.00**

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजना कार्यक्रम का विवरण/मीडिया इकाई	स्वीकृत परिव्यय 2006-2007	संशो. अनुमान 2006-2007
[1]	[2]	[3]	[4]
V	*केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड*		
1	सीबीएफसी का कंप्यूटरीकृत प्रबंधन/मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना	50.13	50.00
2	हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में सीबीएफसी के क्षेत्रीय कार्यालय खोलना	24.00	10.00
	योग :	**74.13**	**60.00**
VI	**प्रशिक्षण**		
	क) कैप्टिव टीवी योजनाएं (एफटीआईआई, पुणे)	10.00	10.00
	ख) सामुदायिक रेडियो की स्थापना (एफटीआईआई, पुणे)	10.00	10.00
	ग) कैप्टिव टीवी योजनाएं (एसआरएफटीआई, कोलकाता)	60.00	60.00
	घ) प्रशिक्षण तथा कौशल विकास (एसआरएफटीआई, कोलकाता) (नई योजना)	50.00	50.00
	ड.) प्रशिक्षण तथा कौशल विकास (एसआरएफटीआई, कोलकाता) (नई योजना)	256.00	256.00
	च) 'प्रमाणन प्रक्रिया की निगरानी तथा आधुनिकीकरण' (पहले योजना का नाम 'प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अध्ययन चलाना' था), सीबीएफसी	186.00	181.000
	योग :	**572.00**	**567.00**
VII	**छात्रवृत्ति कार्यक्रम**		
	क) छात्रवृत्ति और आदान-प्रदान कार्यक्रम सहित मानव संसाधन विकास से जुड़े मुद्दे (एफटीआईआई, पुणे)	10.00	10.00
	ख) छात्रवृत्ति और आदान-प्रदान कार्यक्रम सहित मानव संसाधन विकास से जुड़े मुद्दे (एसआरटीआईआई, कोलकाता)	23.00	23.00
	योग :	**33.00**	**33.00**
VIII	**कंप्यूटरीकरण, आधुनिकीकरण और मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रावधान**		
	क) एफटीआईआई की सुविधाओं को बेहतर बनाना और आधुनिकीकरण	205.11	205.11
	ख) वेबकास्टिंग तथा डिजिटलाइजेशन योजनाएं (सीएफएसआई)	0.00	0.00
	ग) एनएफएआई के भवन के फेज-II का निर्माण (एनएफएआई)	400.00	647.00

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजना कार्यक्रम का विवरण/मीडिया इकाई	स्वीकृत परिव्यय 2006-2007	संशो. अनुमान 2006-2007
[1]	[2]	[3]	[4]
	घ) एफडी फिल्मों का डिजिटलाइजेशन और वेबकास्टिंग (फिल्म्स डिवीजन)	200.00	800.00
	ङ) कंप्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण (एसआरएफटीआई) (नई योजना)	405.00	405.00
	योग :	**1210.11**	**2057.11**
IX	**फिल्मों का निर्यात और बिक्री**		
	क) भारत में फिल्म समारोहों के जरिए निर्यात संवर्धन (डीएफएफ)	353.00	218.00
	ख) भारत और विश्व फिल्म बाजार में भागीदारी (मुख्य सचिवालय)	100.00	100.00
	योग :	**453.00**	**318.00**
X	फिल्मों की पाइरेसी रोकने में लगे एनजीओ और एफएफएसआई को अनुदान सहायता (मुख्य सचिवालय)	20.00	20.00
	योग :	**20.00**	**20.00**
	फिल्म क्षेत्र (कुल योग) :	**4094.54**	**4077.11**
ग	**प्रसारण क्षेत्र (प्रसार भारती)**		
	(अनुदान सहायता/ऋण)		
I	**आकाशवाणी**		
1	***जारी योजनाएं***	**1270.00**	**1377.00**
	क) मीडियम वेव सेवाओं का विस्तार	0.00	0.00
	ख) एफ एम सेवाओं का विस्तार	0.00	0.00
	ग) स्टाफ क्वार्टर्स और कार्यालय भवन	1000.00	1000.00
	घ) शार्ट वेव सेवाओं का विस्तार	0.00	0.00
	ङ) अभिलेखागार	0.00	0.00
	च) विविध योजनाएं	0.00	0.00
	छ) एंप्लीफायर, सीडी प्लेयर्स, माइक्रोफोनों को बदलना और ऐसे अन्य उपकरणों को बदलना जिनके बदलाव की ज़रूरत की पहले से जानकारी न हो	0.00	0.00
	ज) जम्मू-कश्मीर विशेष पैकेज	**270.00**	**377.00**

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजना कार्यक्रम का विवरण/मीडिया इकाई		स्वीकृत परिव्यय 2006-2007	संशो. अनुमान 2006-2007
[1]	[2]		[3]	[4]
		(पूंजीगत)	120.00	170.00
		(राजस्व–विविध)	150.00	207.00
		(राजस्व)	0.00	0.00
	झ) संस्थापना व्यय		0.00	0.00
2	***बेहतरी/विस्तार योजनाएं***		**0.00**	0.00
	क) मीडियम वेव सेवाओं का विस्तार		0.00	0.00
	ख) एफएम सेवाओं का विस्तार		0.00	0.00
3	***आधुनिकीकरण योजनाएं***		**0.00**	0.00
	क) कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं का डिटिजटलीकरण		0.00	0.00
	ख) स्टूडियो सुविधाओं का संचालन		0.00	0.00
	ग) प्रसारण सुविधाओं का संचालन		0.00	0.00
4	***उपकरणों में बदलाव की योजनाएं***		**0.00**	0.00
	क) मौजूदा उपकरणों को बदलना		0.00	0.00
	ख) विविध व्यय		0.00	0.00
	ग) एंपलीफायर, सीडी प्लेयर्स, माइक्रोफोनों को बदलना और ऐसे अन्य उपकरणों को बदलना जिनके बदलाव की ज़रूरत की पहले से जानकारी न हो		0.00	0.00
5	***नई योजनाएं***		**3200.00**	**3030.00**
	क) पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष पैकेज		**1390.00**	**720.00**
		पूंजी	1200.00	530.00
		राजस्व–सॉफ्टवेयर	190.00	190.00
		राजस्व (विविध)	0.00	0.00
	ख) इंटरनेट रेडियो प्रसारण, डिजिटल प्रसारण आदि सहित नई टेक्नोलॉजी		0.00	0.00
	ग) स्टॉफ के लिए आवास		0.00	0.00
	घ) संस्थापना व्यय		0.00	0.00
	ड) प्रशिक्षण सेवाओं को मजबूत और बेहतर बनाना		0.00	0.00

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजना कार्यक्रम का विवरण/मीडिया इकाई	स्वीकृत परिव्यय 2006-2007	संशो. अनुमान 2006-2007
[1]	[2]	[3]	[4]
	च) सुरक्षा के उपाय आदि	0.00	0.00
	छ) सुविधाओं में सुधार आदि	0.00	0.00
	ज) सॉफ्टवेयर	1810.00	2310.00
6	राजस्व (विविध)	2690.00	2690.00
	योग (पूंजी)	**2320.00**	1700.00
	योग (राजस्व)	**4840.00**	**5397.00**
	योग (राजस्व-विविध)	2840.00	3237.00]
	योग (राजस्व-साफ्टवेयर)	2000.00	2160.00
	कुल योग : (आकाशवाणी)	**7160.00**	**7097.00**
II	दूरदर्शन		
1	*जारी योजनाएं*	**10730.00**	**4841.00**
	क) टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर्स	0.00	0.00
	ख) कार्यक्रम-निर्माण सुविधाएं (स्टूडियो/ओबी)	0.00	0.00
	ग) उपग्रह प्रसारण उपकरण	0.00	0.00
	घ) संस्थापना व्यय	0.00	0.00
	ड) जम्मू-कश्मीर विशेष योजना	**10730.00**	**4841.00**
	पूंजी	2451.00	1041.00
	राजस्व विविध	2100.00	2100.0
	राजस्व साफ्टवेयर	6179.00	1700.00
	च) राजस्व विविध	0.00	0.00
2	*बेहतरी/विस्तार योजनाएं*	**0.00**	0.00
	क) वर्तमान ट्रांसमीटरों को बेहतर बनाकर और नये ट्रांसमीटर लगाकर डीडी-1 की जमीनी कवरेज बढ़ाना	0.00	0.00
	ख) वर्तमान ट्रांसमीटरों को बेहतर बनाकर और नए ट्रांसमीटर लगाकर	0.00	0.00

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजना कार्यक्रम का विवरण/मीडिया इकाई		स्वीकृत परिव्यय 2006-2007	संशो. अनुमान 2006-2007
[1]	[2]		[3]	[4]
	डीडी-1 की जमीनी कवरेज बढ़ाना			
	ग) क्यू-बैंड में मल्टी-चैनल डिजिटल सैटलाइट डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए अब तक कवरेज से छूटे इलाकों को प्रसारण के दायरे में लाना		0.00	0.00
3	***आधुनिकीकरण योजनाएं***		**0.00**	0.00
	क) कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं का डिजिटलाइजेशन/आधुनिकीकरण (स्टूडियो/ओबी)		0.00	0.00
	ख) उपग्रह प्रसारण उपकरणों का डिजिटलाइजेशन/आधुनिकीकरण		0.00	0.00
	ग) वर्तमान स्टूडियो सुविधाएं बढ़ाना		0.00	0.00
	घ) ट्रांसमीटरों का सवचालतीकरण (एलपीटी और वी एलपीटी)		0.00	0.00
4	***उपकरणों के बदलाव की योजनाएं***		**0.00**	0.00
	क) वर्तमान ट्रांसमीटरों उपकरणों में खराबियों/पुराने पड़ जाने की वजह से बदलाव		0.00	0.00
	ख) वर्तमान कार्यक्रम निर्माण (स्टूडियो/ओबी) उपकरणों की खराबियों/ पुराने पड़ जाने की वजह से बदलाव		0.00	0.00
	ग) वर्तमान प्रसारण उपकरणों में खराबियों/पुराने पड़ जाने की वजह से बदलाव		0.00	0.00
5	***नई योजनाएं***		**27502.00**	**26762.27**
	क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज		**9610.00**	**8810.00**
		पूंजी	5300.00	4500.00
		राजस्व-सॉफ्टवेयर	4000.00	4000.00
		राजस्व विविध	310.00	310.00
				0.00
	ख) नइ कार्यक्रम निर्माण सुविधाएं		0.00	0.00
	ग) नए उपग्रह प्रसारण उपकरण		0.00	0.00
	ग) डीटीटी		0.00	0.00
	घ) डीटीएच		1000.00	1900.00
	ड) एचडीटीवी		0.00	0.00

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजना कार्यक्रम का विवरण/मीडिया इकाई	स्वीकृत परिव्यय 2006-2007	संशो. अनुमान 2006-2007
[1]	[2]	[3]	[4]
	च) आई टी युक्त मल्टीमीडिया	0.00	0.00
	छ) अनुसंधान और विकास/बिक्री	0.00	0.00
	ज) स्टॉफ के लिए आवास, बुनियादी सुविधाओं की बढ़ोतरी और सुरक्षा	0.00	0.00
	झ) प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार	0.00	0.00
	ण) डिजिटल उपकरणों के लिए सेवा केंद्र/वर्कशाप बनाना	0.00	0.00
	ट) डिजिटल उपकरण	0.00	0.00
X	ठ) सॉफ्टवेयर प्राप्ति निर्माण (सामान्य और विविध)	16892.00	16052.27
	योग (पूंजी)	**8751.00**	7441.00
	योग (राजस्व)	**29481.00**	24162.27
	योग (राजस्व-सॉफ्टवेयर)	27071.00	21752.27
	योग (राजस्व-विविध)	2410.00	2410.00
	योग (दूरदर्शन)	**38232.00**	**31603.27**
	योग (प्रसार भारती)	**45392.00**	**38700.27**
	घ. ई एम एम सी	**585.00**	**200.00**
	ड. निजी एफएम स्टडियो (फेज-II) (नई योजना)	**1000.00**	**415.00**
	कुल योग : प्रसारण क्षेत्र (I+II+III)	**46977.00**	**39315.27**
	कुल योग : सूचना और प्रसारण मंत्रालय (क+ख+ग+घ)	**53800.00**	**47500.00**
	योग (क)	**53800.00**	**47500.00**
	ख. केन्द्र-प्रायोजित योजनाएं		
	योग (ख)	0.00	0.00
	योग (क + ख)	**53800.00**	**47500.00**

8

नई पहल

निजी एफएम रेडियो, द्वितीय चरण

आकाशवाणी के प्रयासों को आगे बढ़ाने और पूरा करने के लिए सरकार ने एफएम रेडियो प्रसारण के द्वितीय चरण को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया है। प्रथम चरण के अंतर्गत स्थापित 21 चैनल पहले ही कार्य कर रहे हैं। इनमें से 16 चैनलों ने द्वितीय चरण में अंतरण किया है और समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। द्वितीय चरण में बोली लगाने के लिए प्रस्तावित 337 चैनलों में से 245 के लिए आशय-पत्र जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 243 चैनलों के लिए जीओपीए पर हस्ताक्षर कर दिये गए हैं। कुल मिलाकर भारत में इस समय 48 निजी एफएम चैनल कार्य कर रहे हैं जिनमें से 21 प्रथम चरण के हैं। सरकार ने प्रसारण कर रहे चैनलों से 27.43 करोड़ रुपये वार्षिक लाइसेंस शुल्क के रूप में प्राप्त किए हैं जिसमें 2005-06 से प्रथम चरण से अंतरण कराने वाले एफएम चैनलों से जीओपीए पर हस्ताक्षर करने के बाद लाइसेंस शुल्क के 10.67 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। अन्य कम्पनियों द्वारा चैनल छोड़ने के बाद प्रतीक्षा सूची की कम्पनियों से एक बारी प्रवेश शुल्क के रूप में 87,11,002 रुपये भी प्राप्त हुए हैं। कार्यरत चैनलों से 31 मार्च 2007 तक की शेष अवधि के लिए चौथी तिमाही के शुल्क के रूप में 5 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है।

डीटीएच सेवा

1. डीटीएच सेवा का संबंध उपभोक्ता के घर तक सीधे टीवी सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए उपग्रह प्रणाली के केयू बैंड का उपयोग करके मल्टी-चैनल टीवी कार्यक्रम उपलब्ध कराने से है।

2. सरकार ने 15 मार्च 2001 को भारत में डीटीएच सेवा के संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश आवेदन पत्र तथा लाइसेंस समझौते के प्रारूप के साथ जारी किये थे। डीटीएच संबंधी दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.nic.in) पर उपलब्ध हैं। दिशा-निर्देशों में दी गई पात्रता शर्तों में अन्य बातों के अलावा आवेदक कम्पनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश/प्रवासी भारतीय/ओबीसी/विदेशी संस्थागत निवेशक सहित पूर्ण विदेशी इक्विटी स्वाम्त्वि 49 प्रतिशत से अधिक न होने और विदेशी इक्विटी में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 20 प्रतिशत से ज्यादा न होने की बात कही गई है। इसमें यह भी व्यवस्था है कि आवेदक कंपनी पर भारतीय प्रबंधन नियंत्रण होना चाहिए और उसके बोर्ड में अधिकतर प्रतिनिधि तथा कम्पनी के मुख्य कार्यपालक निवासी भारतीय ही होने चाहिए। डीटीएच सेवा के संचालन के लाइसेंस जारी करने के लिए सभी आवेदनों की जांच पात्रता मानदंडों के अनुसार करना आवश्यक है।

3. डीटीएच सेवा सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती और मैसर्स एएससी एंटरप्राइजेज लिं. तथा मैसर्स टाटा स्काइ लि. द्वारा संचालित की जा रही है। एक अन्य कंपनी मैसर्स सन डायरेक्ट टीवी प्रा.लि. को भी डीटीएच सेवा चलाने के लिए लाइसेंस दिया गया है। मैसर्स रिलायंस ब्लू मैजिक लि. को भी आशय पत्र जारी किया गया है।

4. भारत में डीटीएच सेवा शुरू करने और इसके संचालन के लिए वर्तमान डीटीएच लाइसेंस शर्तों में डीटीएच सेवा के तहत अवांछित सामग्री के प्रसारण को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है। लाइसेंस समझौते के नियमों और शर्तों में अन्य बातों के अलावा डीटीएच लाइसेंसधारी के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए डीटीएच सेवा का उपयोग अपराध माना जाएगा जिसके लिए भारतीय दंड संहिता के अनुसार और वर्तमान कानून के अनुसार दंड दिया जा सकेगा और लाइसेंस को तत्काल रद्द किया जा सकेगा।

प्रसार भारती के बारे में मंत्रियों का समूह

7 मार्च 2006 को मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया। यह प्रसार भारती के कामकाज के निम्नलिखित पहलुओं की जांच करेगा:

(1) प्रसार भारती के लिए पूंजी ढांचा और वित्त पोषण का तरीका;

(2) प्रसार भारती अधिनियम की धारा 22 को बहाल करना;

(3) वर्तमान कर्मचारियों के प्रसार भारती में शामिल होने तक उनके लिए आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं की व्यवस्था;

(4) प्रसार भारती में शामिल होने के लिए कर्मचारियों को दिए जाने वाले वित्तीय लाभ और सेवा शर्तें;

(5) आकाशवाणी और दूरदर्शन में आवश्यक श्रेणी के पदों को भरना;

(6) 1990 के प्रसार भारती अधिनियम में अधिनियम के कार्यकरण को देखते हुए संशोधन;

(7) वाणिज्यिक लेखा परीक्षा को अपनाना;

(8) अन्य संभावित मुद्दे।

ऐच्छिक चैनल चयन प्रणाली (कंडीशनल एक्सेस सिस्टम-सीएएस)

इस प्रणाली के अंतर्गत विशेष उपभोक्ता द्वारा मांगे गए केवल ऐच्छिक चैनलों का प्रसारण उसे उपलब्ध कराया जाता है। इसे आम बोलचाल में सीएएस (कैस) प्रणाली कहा जाता है। यह प्रणाली वर्ष 2002 में केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमत) अधिनियम, 2002 में संशोधित कर पेश की गई। संशोधन के प्रावधान के अंतर्गत केंद्र सरकार को गजट अधिसूचना के ज़रिए देश के किसी क्षेत्र या नगर में 'कैस' लागू करने का अधिकार दिया गया था। यह व्यवस्था 2003 में लागू की जानी थी लेकिन 27 फरवरी 2004 को इसे जनहित में वापस ले लिया गया।

दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 फरवरी 2006 के आदेश के अनुरूप, सरकार ने चार महानगरों के अधिसूचित क्षेत्रों के लिए 31 जुलाई 2006 को संशोधित 'कैस' योजना की अधिसूचना जारी की। इन क्षेत्र में 31 दिसंबर 2006 से 'कैस' प्रणाली लागू हो गई है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 'कैस' लागू करने से संबंधित विस्तृत प्रावधान केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (द्वितीय संशोधन) नियम, 2006 में शामिल किए गए हैं। संशोधित 'कैस' प्रणाली की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं -

(1) 'कैस' लागू किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सुपरिभाषित कार्यान्वयन कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें विभिन्न संबद्ध एजेंसियों के लिए नियम/उनकी जिम्मेदारियां तथा हर कार्य के लिए समयावधि तय कर दी गई है।

(2) भारतीय दूरसंचार नियमन प्राधिकरण ('ट्राई'), बहु-प्रणाली संचालकों (एमएसओ) तथा प्रसारकों को कैस लागू करने के काम के विभिन्न चरणों की जिम्मेदारी दी गई है।

(3) प्राधिकरण (ट्राई) ने मानक इंटरकनेक्सन समझौते अधिसूचित कर दिए हैं जिन्हें सभी प्रसारकों, एमएसओ और केबल ऑपरेटेरों ने परस्पर विचार-विमर्श से अंतिम रूप देना है। 'कैस' क्षेत्र में बुनियादी सेवाओं की शुल्क सीमा के बारे में भी 'ट्राई' ने आदेश अधिसूचित कर दिए हैं।

(4) प्राधिकरण ने शुल्क वाले सभी चैनलों के लिए अधिकतम शुल्क तय करके घोषित कर दिया है। इसी सीमा के अंदर, प्रसारकों को शुल्क वाली चैनलों के लिए उपभोक्ता द्वारा दिए जाने वाला शुल्क तय करना होगा।

(5) प्राधिकरण ने 'सेट टॉप' बॉक्सों के लिए भी मानक शुल्क प्रणाली अधिसूचित कर दी है।

(6) 'कैस' प्रसारण क्षेत्रों में सेवा की गुणवत्ता के मानकों से संबंधित अधिसूचना भी प्राधिकरण ने जारी कर दी है।

(7) इन प्रावधानों के अंतर्गत, उपभोक्ता अपनी पसंद के चैनल चुन कर, उन्हें देखने के लिए भुगतान कर सकेंगे और इसी के अनुरूप अपना बजट तय कर सकेंगे। वे किराये पर भी 'सेट टॉप बाक्स' ले सकेंगे।

(8) चैनल देखने के लिए वसूल किये जाने वाले शुल्क और बिल के ब्यौरे के बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिए भी व्यवस्था है। उपभोक्ताओं की शिकायतों को सेवाओं की गुणवत्ता संबंधी नियमों के आधार पर निपटाया जाएगा। सेवा उपलब्ध कराने वालों को उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली लगानी होगी और वे सेट टॉप बाक्स के लिए किराया योजना की भी घोषणा करेंगे।

(9) सरकार ने मल्टी सिस्टम आपरेटरों को कंडीशनल एक्सेस सिस्टम वाले इलाकों में कार्य करने की अस्थायी अनुमति दे दी है।

(10) योजना में सार्वजनिक जागरूकता अभियान की भी व्यवस्था है।

डाउनलिंकिंग संबंधी दिशा-निर्देश

मंत्रालय ने पहली बार भारत में सार्वजनिक रूप से देखने के लिए डाउनलिंक किये जाने वाले/प्राप्त किए जाने वाले/प्रसारित किए जाने वाले और पुनर्प्रसारित किए जाने वाले समस्त उपग्रह चैनलों को डाउनलिंक करने के लिए नीति संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके परिणामस्वरूप कोई भी व्यक्ति/संस्थान ऐसे किसी चैनल को डाउनलिंक नहीं करेगा जो इन दिशा-निर्देशों के अनुसार मंत्रालय के अंतर्गत पंजीकृत नहीं होगा। भारत के दर्शकों के लिए अन्य देशों के अपलिंक के जरिए टेलीविजन उपग्रह प्रसारण सेवा (टीवी चैनल) उपलब्ध कराने वाले सभी व्यक्तियों/संस्थाओं को इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार मंत्रालय की स्वीकृति लेनी होगी। ये दिशा-निर्देश 11 नवम्बर 2005 को जारी किए गए थे।

इनके अलावा अन्य देशों से अपलिंग हो रही चार उपग्रह चैनलों को, उक्त दिशा-निर्देशों के अंतर्गत भारत में डाउनलिंक करने की अनुमति दी गई। कुल मिलाकर, अन्य देशों से अपलिंक की जा रही 58 चैनलों को भारत में डाउनलिंक करने की अनुमति दी गई। (4 नियमित + 54 अनंतिम अनुमतियां)

अपलिंकिंग दिशा-निर्देश

सरकार ने अपलिंकिंग दिशा-निर्देशों में फिर संशोधन कर इन्हें एक सेट के रूप में संकलित कर दिया है। 'गाइडलाइंस फॉर अपलिंकिंग फ्रॉम इंडिया' नाम से ये दिशा-निर्देश 2 दिसंबर 2005 को अधिसूचित किए गए हैं। ये दिशा-निर्देश इनसे पूर्व जारी सभी दिशा-निर्देशों का स्थान लेंगे। पिछले दिशा-निर्देशों में किए गए कुछ प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं -

(i) सीधे विदेशी निवेश (एफडीआई) के अलावा, विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा प्रवासी भारतीयों (एफआईआई/एनआरआई) द्वारा 26% तक निवेश की अनुमति दी गई है।

(ii) 'सी' बैंड के अलावा, 'क्यू' बैंड में अपलिंकिंग की भी अनुमति दी गई है।

(iii) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की मौके पर कवरेज के लिए, इन घटनाओं के टेलीविजन प्रसारण के लिए प्राधिकृत सभी कंपनियों को, अपनी फीड को, राजस्व के बंटवारे के एक फॉर्मूले के तहत, प्रसार भारती को भी उपलब्ध कराना होगा।

(iv) कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, विदेशी समाचार एजेंसियों/चैनलों को एक साल तक अस्थायी अपलिंकिंग (प्वाइंट-टू-प्वाइंट) की अनुमति दी जा सकती है।

(v) आवेदनों की प्रोसेसिंग और मंजूरी के लिए शुल्क का प्रावधान किया गया है।

इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, मंत्रालय के अब तक 209 उपग्रह टेलीविजन चैनलों को भारत से अपलिंक करने की अनुमति दी है।

फिल्म समारोहों का आयोजन

मंत्रालय का फिल्म प्रभाग 1990 से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु फिल्म और एनीमेशन फिल्म समारोह का आयोजन करता आ रहा है। यह आयोजन मुंबई में हर दो साल बाद किया जाता है। इस समारोह की भारत में वृत्तचित्रों के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे सुव्यवस्थित समारोहों में होती है और इसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। इस द्विवार्षिक महोत्सव में दुनिया भर से फिल्में आती हैं। हर समारोह में करीब 40 देशों की फिल्में आती हैं।

फिल्म प्रभाग अंतराष्ट्रीय वृत्तचित्र समारोह मुंबई में हर दूसरे साल आयोजित करता है। अब उसकी पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसे समारोह आयोजित किए जा रहे है। इसका उद्देश्य बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्रों, फिल्म प्रभाग की बेहतरीन फिल्मों और श्रेष्ठ स्थानीय फिल्मों का प्रदर्शन करना है। पहला कोहिमा अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु और एनीमेशन फिल्म समारोह 2 से 6 दिसम्बर 2006 तक कोहिमा में आयोजित किया गया। इसका आयोजन मंत्रालय ने नागालैंड सरकार के सहयोग से किया। इसका उद्देश्य मीडिया और आम जनता में वृत्त चित्रों के बारे में जागरूकता पैदा करना था।

चालू वित्त वर्ष यानी 2006-07 में इसी तरह के समारोह पूर्वोत्तर क्षेत्र के तीन और राज्यों त्रिपुरा, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश में

आयोजित किए जा रहे है। इसके अलावा मुंबई विश्वविद्यालय के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस विश्वविद्यालय के सहयोग से डेढ़ सौ वर्षीय फिल्म समारोह 5 से 10 फरवरी 2007 तक आयोजित करने का भी प्रस्ताव है।

फिल्म प्रभाग की फिल्मों की वैबकास्टिंग/डिजिटलाइजेशन

फिल्मों के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए समय के लम्बे अंतराल में खराब और नष्ट हो रही फिल्म प्रभाग की फिल्मों को ठीक करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। 'फिल्म प्रभाग के अभिलेखागार के अनुरक्षण और संरक्षण' की योजना के अंतर्गत इसके उपाय किए गए हैं। यह योजना 'फिल्म प्रभाग की फिल्मों की वैबकास्टिंग और डिजिटलाइजेशन' की वर्तमान योजना का ही संशोधित रूप है। टेलीविजन आज सूचनाओं के प्रसारण का बड़ा महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है और इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में भी असाधारण वृद्धि हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए फिल्म प्रभाग ने अपनी सूचनात्मक और शैक्षिक फिल्मों के वितरण के तरीके में बदलाव किया है और इन माध्यमों को अपनाया है। इसके लिए प्रभाग की फिल्मों को डिजिटल रूप में ढालना और स्थानांतरण व प्रसारण की दृष्टि से सुरक्षित रखना जरूरी हो गया है। फिल्म प्रभाग ने अपनी सेल्यूलाइड फिल्मों को हाई डेफिनीशन टेप (करीब 9 एमबीपीएस के उच्च बिड रेट वाले) पर अंतरण करने के साथ-साथ अतिरिक्त डिजिटल ऑडियो अंतरण भी हाई डेफिनीशन टेपों में करने का कार्य प्रारंभ किया है।

अब तक 188 फिल्मों को डिजिटल रूप में ढाला जा चुका है। 480 फिल्मों को हाई डेफिनीशन टेपों में अंतरित किया गया है और 825 को डीवीडी के रूप में बदला गया है।

विशेष अभियान के तहत 6,512 फिल्मों को 31 मार्च 2007 से पहले डिजिटल रूप में बदलने का फैसला किया गया है।

फिल्मों की बिक्री

फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित फिल्मों की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिक्री के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को फिल्म प्रभाग का बाजार एजेंट बनाया गया है जो फिल्मों के हर तरह के अधिकार विदेशों के व्यक्तिगत खरीदारों, संस्थाओं और टेलीविजन चैनलों आदि को बेचता है।

फिल्म प्रभाग की फिल्मों के डीवीडी की बिक्री का प्रस्ताव भी मंत्रालय को भेजा गया है क्योंकि फिलहाल फिल्म प्रभाग डीवीडी नहीं बेचता, जबकि स्थानीय बाजारों में इसकी फिल्मों के डीवीडी की मांग है।

ऑनलाइन प्रतिनिधि पंजीकरण

भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2006 के दौरान समारोह की वेबसाइट को नया रूप दिया गया और महत्वपूर्ण सामग्री शामिल की गई। प्रतिनिधियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को भी अक्तूबर 2006 के पहले सप्ताह से पूरी तरह ऑन लाइन कर दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से ऑन लाइन ई-पेमेंट के विकल्प की भी व्यवस्था की गई। इसके सॉफ्टवेयर का विकास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने किया। इससे भारत तथा विदेशों के 5000 से अधिक प्रतिनिधियों को बिना किसी असुविधा के पंजीकरण सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिली।

तकनीकी सिंहावलोकन

फिल्म विधा के विद्यार्थियों और फिल्म उद्योग के तकनीशियनों के लिए तीन तकनीकी सिंहावलोकनों का आयोजन किया गया।

(क) डिजिटल संपादन :

एविड डिजिटल संपादन कला के जन्मदाता हॉलीवुड के एक संपादन विशेषज्ञ को तकनीकी सिंहावलोकन के संचालन के लिए बुलाया गया। तकनीकी सिंहावलोकन में डिजिटल डेलीज और कैलीब्रेटेड डिस्प्ले सिस्टम, रिमोट कोलैबोरेशन सिस्टम, न्यू हाइब्रिड प्रोडक्शन सिस्टम और डिजिटल इंटरमीडिएट प्रोसेस जैसे विषयों को शामिल किया गया।

(ख) एनीमेशन और डिजिटल इफेक्ट

फिल्म विधा के विद्यार्थियों, विशेष रूप से मल्टीमीडिया विजुअल कम्यूनिकेशन के छात्रों के फायदे के लिए एनीमेशन और डिजिटल इफेक्ट्स पर सिंहावलोकन के आयोजन के लिए विश्व में जाने-माने इटली के एनीमेशन विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया। छात्रों और प्रतिनिधियों ने सिंहावलोकन का बड़ा स्वागत किया और इसकी सराहना की।

(ग) फिल्मों का अनुरक्षण

फिल्म उद्योग के लोगों के कहने पर यह सिंहावलोकन काफी पहले से शुरू किया गया क्योंकि फिल्म प्रयोगशालाओं में विभिन्न कारणों से फिल्मों का उचित तरीके से रखरखाव नहीं हो पाता। इसके अलावा इटली की एक प्रमुख प्रयोगशाला से भी संपर्क किया

गया और फिल्मों के अनुरक्षण पर सिंहावलोकन के आयोजन के लिए किसी तकनीकी विशेषज्ञ की सेवाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। समारोह में शामिल हुए तकनीशियनों ने इस सिंहावलोकन का बड़ा स्वागत किया।

यहां पर यह बताना प्रासंगिक होगा कि सिंहावलोकन खंडों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इनके आयोजन के बारे में सूचना देने वाले पत्र फिल्मों से संबंधित सभी व्यापारिक संगठनों और प्रमुख फिल्म संस्थानों को भेजे गए ताकि वे इसमें शामिल हो सकें।

अखिल भारतीय पटकथा लेखक सम्मेलन

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे ने 19 और 20 अगस्त 2006 को पहला अखिल भारतीय पटकथा लेखक सम्मेलन आयोजित किया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार आयोजित इस सम्मेलन में देश भर से आये पटकथा लेखक, निर्देशक और विद्वानों ने भाग लिया और देश में पटकथा लेखन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इसका आयोजन भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे ने किया। विशेषज्ञों ने अपने अनुभव और पटकथा लेखन शिल्प के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया, एक-दूसरे के अनुभवों को आत्मसात किया और भारतीय पटकथा लेखन के इतिहास में कुछ जोरदार प्रयोगों के बारे में नये सिरे से विचार कर अंतदृष्टि उत्पन्न की।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

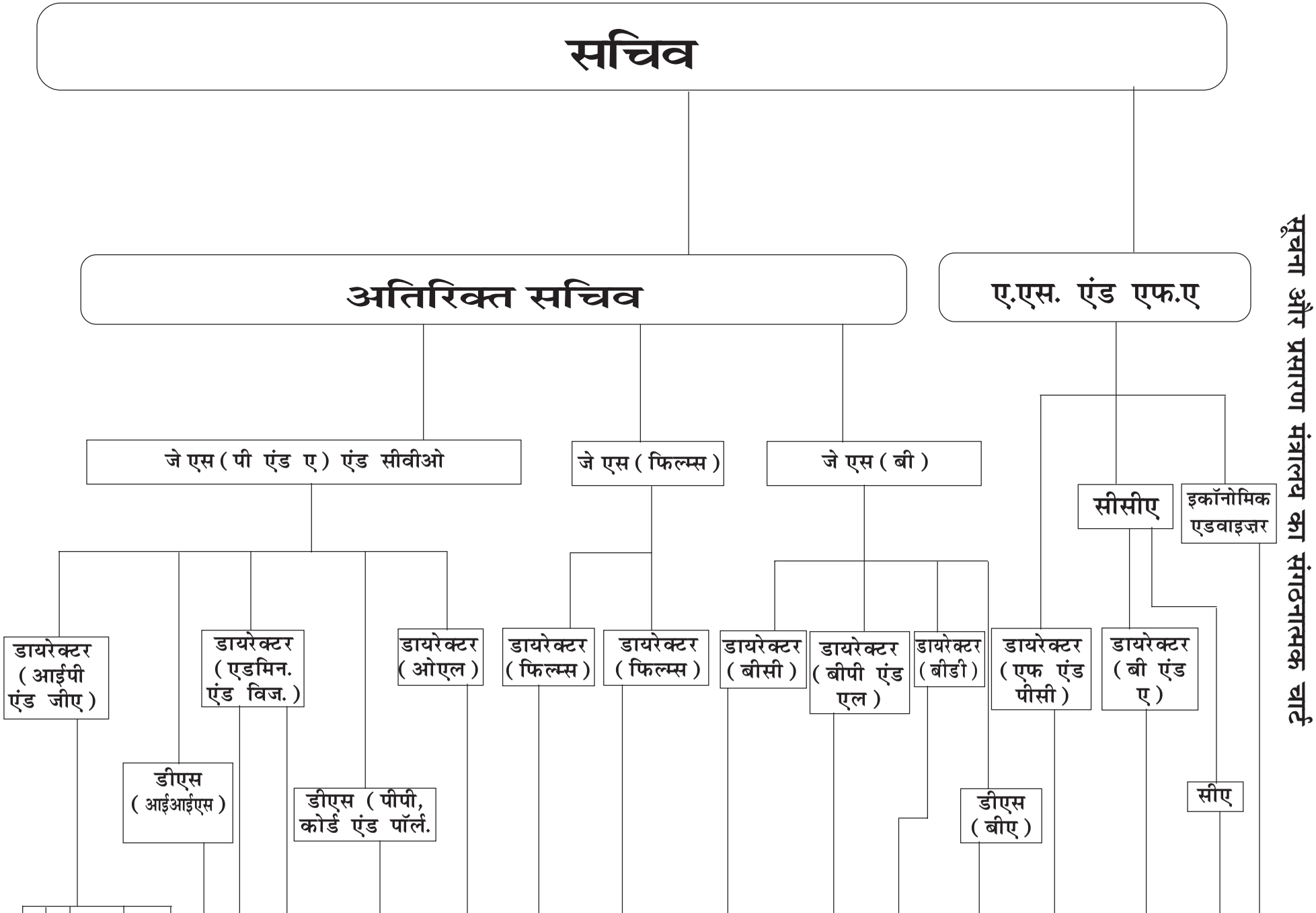

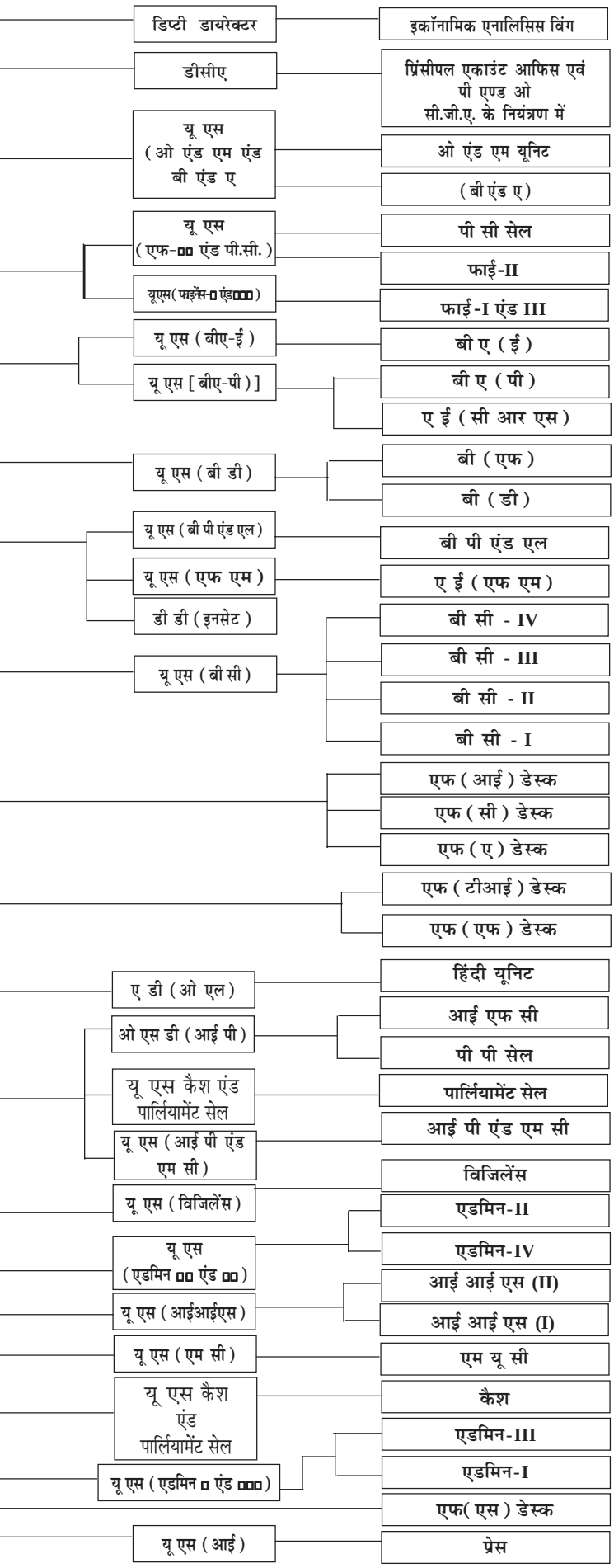

मंत्रालय में पदनाम

सचिव	सचिव
ए एस	अतिरिक्त सचिव
ए एस एंड एफ ए	अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार
जे एस (पी एंड ए) एंड सी वी ओ	संयुक्त सचिव (नीति, मीडिया और प्रशासन) एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी
जे एस (फिल्म्स)	संयुक्त सचिव (फिल्म)
जे एस (बी)	संयुक्त सचिव (प्रसारण)
आर्थिक सलाहकार	आर्थिक सलाहकार
सी सी ए	मुख्य लेखा नियंत्रक
डायरेक्टर (आई पी एंड जे)	निदेशक (सूचना नीति और सामान्य प्रशासन)
निदेशक (ओ एल)	निदेशक राजभाषा
निदेशक (एडमिन एंड विज.)	निदेशक (प्रशासन और सतर्कता)
निदेशक (फिल्म्स)	निदेशक (फिल्म्स)
निदेशक (बी सी)	निदेशक (प्रसारण सामग्री)
निदेशक (एफ एंड पी सी)	निदेशक (वित्त एवं नियोजन समन्वय)
निदेशक (बी पी एंड एल)	निदेशक (प्रसारण नीति एवं विधि)
निदेशक (बी डी)	निदेशक (प्रसारण विकास)
निदेशक (बी एंड ए)	निदेशक (बजट तथा लेखा)
उ.स.(आई.आई.एस.)	उप सचिव (भारतीय सूचना सेवा)
उ.स. (पी पी, कॉर्ड एंड पार्ल)	उप सचिव (नीति नियोजन, समन्वय और संसद)
उ.स. (बी ए)	उप सचिव (प्रसारण प्रशासन)
सी ए	लेखा नियंत्रक
अ.स. (आई)	अवर सचिव (सूचना)
अ.स. (एम सी)	अवर सचिव (मीडिया समन्वय)
अ.स. (एडमिन II एंड IV)	अवर सचिव (प्रशासन II और IV)
अ.स. (आई आई एस)	अवर सचिव (भारतीय सूचना सेवा)
अ.स. (एडमिन I एंड III)	अवर सचिव (प्रशासन एडमिन I और III)
अ.स. (कैश एंड पार्लियामेंट सेल)	अवर सचिव (नकदी और संसदीय सेल)
अ.स. (विजिलेंस)	अवर सचिव (सतर्कता)
अ.स. (आई पी एंड एम सी)	अवर सचिव (सूचना नीति और मीडिया समन्वय)
ओ एस डी (आइ पी)	विशेष कार्याधिकारी (सूचना नीति)
अ.स. (बी सी)	अवर सचिव (सामग्री विषय वस्तु)
अ.स. (बी पी एंड एल)	अवर सचिव (प्रसारण नीति और विधि)
उ.नि. (इनसेट)	उपनिदेशक (इनसेट)
अ.स. (बी डी)	अवर सचिव (प्रसारण विकास)
अ.स. (एफ एम)	अवर सचिव (फ्रीक्वेंसी मोड्यूलेशन्स)
अ.स. (बी ए-पी)	अवर सचिव (प्रसारण प्रशासन-कार्यक्रम)
अ.स. (बी ए-ई)	अवर सचिव (प्रसारण प्रशासन-इंजीनीयरी')
अ.स. (एफ-I एंड III)	अवर सचिव (वित्त-I और वित्त III)
अ.स. (एफ-II एंड पी सी)	अवर सचिव (वित्त-II और योजना समन्वय)
अ.स.(ओ एंड एम एंड बी एंड ए)	अवर सचिव (संगठन एवं प्रविधि तथा बजट एवं लेखा)
डी सी ए	उप लेखा नियंत्रक
उप निदेशक	उप निदेशक
अ.नि. (ओ एल)	सहायक निदेशक राजभाषा
एडमिन. I	प्रशासन I
एडमिन. II	प्रशासन II
एडमिन. III	प्रशासन III
एडमिन. IV	प्रशासन IV
कैश	रोकड़
पार्लियामेंट सेल	संसदीय सेल
एम यू सी	मीडिया यूनिट एक
एफ (एस) डेस्क	फिल्म सोसाइटी डेस्क
हिंदी एकक	हिंदी एकक
सतर्कता	सतर्कता
आईपी एंड एमसी	सूचना नीति तथा मीडिया संभवय
पीपी सेल	नीति नियोजन सेल एकक
प्रेस	प्रेस
आईएसआईएस-I	भारतीय सूचना सेवा - I
आईआईएस-II	भारतीय सूचना सेवा-II
एफ (एफ)डेस्क	फिल्म समारोह डेस्क
एफ (टी आई)	फिल्म और टेलिविजन संस्थान डेस्क
एफ (ए)	फिल्म प्रशासन डेस्क
एफ (सी)	फिल्म प्रमाणन डेस्क
बी सी-I	प्रसारण सामग्री-I
बी सी-II	प्रसारण सामग्री-II
बी सी-III	प्रसारण सामग्री-III
बी सी-IV	प्रसारण सामग्री-IV
बी (डी)	प्रसारण (विकास)
बी (फाईनेंस)	प्रसारण (वित्त)
बी पी एंड एल	प्रसारण नीति और विधायन
बी ए (पी)	प्रसारण प्रशासन (कार्यक्रम)
ए ई (एफ एम)	सहायक इंजीनियर (फ्रीक्वेंसी मोड्यूलेशन)
ए ई (सी आर एस)	सहायक इंजीनियर (सामुदायिक रेडियो स्टेशन)
बी ए (ई)	प्रसारण प्रशासन (इंजीनियरी)
फाइनेंस I एंड III	वित्त I और III
फाइनेंस II	वित्त II
पी सी सेल	योजना समन्वय एकक
बी एंड ए	बजट एवं लेखा
ओ एंड एम यूनिट	संगठन एवं प्रविधि एकक
पी एंड ए ओ	वेतन और लेखा अधिकारी
सी.जी.ए.	मुख्य लेखा नियंत्रक
आई एफ सी	सूचना सुविधा पटल
आर्थिक विश्लेषण शाखा	आर्थिक विश्लेषण शाखा

मीडिया अनुसार बजट

परिशिष्ट - II

मांग संख्या 58 — सूचना और प्रसारण मंत्रालय (हजार रुपये में)

क्र.सं.	मीडिया इकाई/ गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2006-2007		
		योजना	गैर-योजना	योग
1	2	3	4	5
	राजस्व अनुभाग			
	मुख्य शीर्ष-'2251'-सचिवालय सामाजिक सेवाएं			
1.	मुख्य सचिवालय (वेतन और लेखा कार्यालय सहित)	17000	174300	191300
	मुख्य शीर्ष-'2205' — कला और संस्कृति			
	सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सिनेमा फिल्मों का प्रमाणन			
2.	केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	18600	27600	46200
3.	फिल्म प्रमाणन अपील न्यायाधिकरण	0	1200	1200
	मुख्य शीर्ष '2205' का योग	**18600**	**28800**	**47400**
	मुख्य शीर्ष - '2220' सूचना फिल्म और प्रचार			
4.	फिल्म प्रभाग	21000	256400	277400
5.	फिल्म समारोह निदेशालय	35300	47400	82700
6.	भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय	7300	14000	21300
7.	सत्यजित राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता	27900	48500	76400
8.	भारतीय बाल फिल्म समिति को अनुदान सहायता	52130	1500	53630
9.	भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, पुणे को सहायता अनुदान	3000	68200	71200
10.	फिल्म समितियों को अनुदान सहायता	0	0	0
11.	केन्द्रीय अनुश्रवण एकांश	58500	30000	88500
12.	गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग	2500	8900	11400
13.	भारतीय जन संचार संस्थान को अनुदान सहायता	3980	40000	43980
14.	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	23300	592500	615800
15.	पत्र सूचना कार्यालय	7196	216947	224143
16.	भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता	0	23153	23153
17.	पी.टी.आई. को कर्ज पर देय ब्याज के बदले सहायता	0	0	0
18.	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	100	100
19.	पत्रकार कल्याण निधि में हस्तांतरण	0	0	0
20.	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	900	270100	271000
21.	गीत और नाटक प्रभाग	72500	123600	196100
22.	प्रकाशन विभाग	0	130700	130700
23.	रोजगार समाचार	0	291700	291700
24.	भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक	0	24800	24800
25.	फोटो प्रभाग	7500	27100	34600
26.	संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान	0	1400	1400
27.	एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्राडकास्ट डेवेलपमेंट को अंशदान	0	2000	2000
	कुल : मुख्य शीर्ष '2220' का योग	**323006**	**2219000**	**2542006**
	कुल : मुख्य शीर्ष 2251, 2205 और 2220	**358606**	**2422100**	**2780706**

(हजार रुपये में)

संशोधित अनुमान 2006-2007			बजट अनुमान 2007-2008		
योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना	योग
6	7	8	9	10	11
16000	182804	198804	33600	187570	221170
18600	28500	47100	15000	29700	44700
0	908	908	0	1200	1200
18600	**29408**	**48008**	**15000**	**30900**	**45900**
80600	225010	305610	46200	235260	281460
21800	45240	67040	38200	49320	87520
7300	14330	21630	10100	14940	25040
27900	49039	76939	77700	50735	128435
34600	4000	38600	27100	4200	31300
3000	67236	70236	62100	70515	132615
0	0	0	0	0	0
20000	200	20200	29000	30000	59000
2500	10395	12895	200	10395	10595
2800	37600	40400	1000	39500	40500
228900	593175	822075	234100	613925	848025
7196	320198	327394	1210	227015	228225
0	23050	23050	0	23700	23700
0	0	0	0	0	0
0	100	100	0	100	100
0	0	0	0	0	0
1139	262595	263734	100	259910	260010
61250	131915	193165	35600	145415	181015
0	134670	134670	400	134720	135120
0	280220	280220	100	281700	281800
0	22560	22560	200	24770	24970
10500	21875	32375	200	23310	23510
0	1400	1400	0	1400	1400
0	1380	1380	0	2000	2000
509485	**2246188**	**2755673**	**563510**	**2242830**	**2806340**
544085	**2458400**	**3002485**	**612110**	**2461300**	**3073410**

क्र.सं.	मीडिया इकाई/ गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2006-2007		
		योजना	गैर-योजना	योग
1	2	3	4	5
	प्रसारण (मुख्य शीर्ष-2221)			
	ध्वनि प्रसारण (उपमुख्य शीर्ष)			
	निर्देशन व प्रशासन (लघु शीर्ष)			
	वेतन	**100**	**100**	**200**
	टेलीविजन (उप मुख्य शीर्ष)			
	वेतन	**100**	**100**	**200**
	सामान्य (उप मुख्य शीर्ष)			
	प्रसार भारती (लघु शीर्ष)			
	अनुदान सहायता	**2981900**	**9358400**	**12340300**
	कुल - प्रसारण	**2982100**	**9358600**	**12340700**
	पूर्वोत्तर क्षेत्र : पूर्वोत्तर क्षेत्र व सिक्किम के लाभ के लिए अन्य खर्च योजनाएं			
	एकमुश्त प्रावधान **(मुख्य शीर्ष-2552)**	**464600**		**464600**
	कुल - राजस्व खंड	**3805306**	**11780700**	**15586006**

(हजार रुपये में)

संशोधित अनुमान 2006-2007			बजट अनुमान 2007-2008		
योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना	योग
6	7	8	9	10	11
100	**100**	**200**	**100**	**100**	**200**
100	**100**	**200**	**100**	**100**	**200**
2505727	**9392100**	**11897827**	**1031300**	**9607600**	**10638900**
2505927	**9392300**	**11898227**	**1031500**	**9607800**	**10639300**
464777	**0**	**464777**	**205190**	**0**	**205190**
3514789	**11850700**	**15365489**	**1848800**	**12069100**	**13917900**

क्र.सं.	मीडिया इकाई/का नाम	बजट अनुमान 2006-2007		
		योजना	गैर-योजना	योग
1	2	3	4	5
पूंजीगत खंड				
प्रमुख शीर्ष '4220' — सूचना और प्रचार के लिए पूंजी परिव्यय				
अ)	**मशीनें और उपकरण**			
1.	फिल्म प्रभाग के लिए उपकरण की प्राप्ति	**10000**	**0**	**10000**
2.	पत्र सूचना कार्यालय के लिए उपकरण की प्राप्ति	**4500**	**0**	**4500**
3.	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के लिये उपकरण की प्राप्ति	**8300**	**0**	**8300**
4.	गीत एवं नाटक प्रभाग के लिए उपकरण की प्राप्ति	**2500**	**0**	**2500**
5.	फोटो प्रभाग के लिए उपकरणों की प्राप्ति	**5000**	**0**	**5000**
6.	मुख्य सचिवालय के लिए उपकरणों की प्राप्ति	**0**	**0**	**0**
7.	भारतीय जन संचार संस्थान के लिए उपकरण की प्राप्ति	**9370**	**0**	**9370**
8.	सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के लिए उपकरण की प्राप्ति	**51500**	**0**	**51500**
9.	फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, पुणे के लिए उपकरण की प्राप्ति	**20511**	**0**	**20511**
10.	केंद्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के लिए उपकरण की प्राप्ति	**6913**	**0**	**6913**
11.	फिल्म समारोह निदेशालय के लिए मुद्रण इकाई का सुधार	**0**	**0**	**0**
ब)	**भवन**			
12.	फिल्म प्रभाग के लिए बहुमंजिला भवन-प्रमुख कार्य	**0**	**0**	**0**
13.	चलचित्र संग्रहालय (फि.प्र.) का निर्माण मुख्य कार्य	**70000**	**0**	**70000**
14.	एन.एफ.ए.आई. के लिये नाइट्रेट वाल्ट/कर्मचारी आवास निर्माण	**0**	**0**	**0**
15.	एन.एफ.ए.आई. कम्प्लेक्स के लिये द्वितीय फेज का निर्माण	**40000**	**0**	**40000**
16.	फिल्म समारोह भवन-संयोजन एवं परिवर्तन-प्रमुख कार्य	**31800**	**0**	**31800**
17.	कोलकाता में फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की स्थापना-भूमि अधिग्रहण एवं भवन निर्माण	**0**	**0**	**0**
18.	सूचना भवन निर्माण-प्रमुख कार्य	**0**	**0**	**0**
19.	क्षेत्रीय प्रचार के लिये कार्यालय एवं आवासीय भवन निर्माण-प्रमुख कार्य	**0**	**0**	**0**
20.	पी.आई.बी. के लिए राष्ट्रीय प्रेस केंद्र एवं मिनी मीडिया केंद्र की स्थापना	**100000**	**0**	**100000**
21.	भारतीय प्रेस परिषद के भवन का निर्माण	**0**	**0**	**0**
22.	भारतीय जनसंचार संस्थान की भवन तथा आवास परियोजना	**2500**	**0**	**2500**
23.	निजी एफ एम रेडियो स्टेशनों के लिए टॉवर और भवन	**100000**	**0**	**100000**
24.	मास मीडिया (फि.प्र.) संस्थान की स्थापना	**0**	**0**	**0**

(हजार रुपये में)

संशोधित अनुमान 2006-2007			बजट अनुमान 2007-2008		
योजना	गैर–योजना	योग	योजना	गैर–योजना	योग
6	7	8	9	10	11
12700	0	12700	0	0	0
4500	0	4500	0	0	0
8900	0	8900	1100	0	1100
2500	0	2500	400	0	400
5000	0	5000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
8200	0	8200	0	0	0
51500	0	51500	0	0	0
20511	0	20511	0	0	0
5000	0	5000	5100	0	5100
0	0	0	100	0	100
0	0	0	0	0	0
25000	0	25000	50000	0	50000
0	0	0	0	0	0
64700	0	64700	0	0	0
21000	0	21000	34000	0	34000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	20000	0	20000
0	0	0	0	0	0
45000	0	45000	100000	0	100000
0	0	0	0	0	0
2500	0	2500	0	0	0
41500	0	41500	10000	0	10000
0	0	0	100	0	100

क्र.सं.	मीडिया इकाई/ गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2006-2007		
		योजना	गैर-योजना	योग
1	2	3	4	5
	निवेश			
	इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड	**0**	**0**	**0**
	कुल : पूंजी अनुभाग प्रमुख शीर्ष '4220'	**462894**	**0**	**462894**
	सूचना और प्रचार के लिए ऋण (मुख्य शीर्ष 6220)			
	फिल्में : (उप मुख्य शीर्ष)			
	सार्वजनिक क्षेत्र और उपक्रमों के लिए ऋण			
	लघु शीर्ष			
	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम			
	ऋण और अग्रिम	**0**	**0**	**0**
	प्रसारण के लिए ऋण (मुख्य शीर्ष)			
	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण			
	प्रसार भारती : ऋण तथा अग्रिम	**457100**	**0**	**457100**
	उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय व अन्य कार्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजना/योजना (मुख्य शीर्ष 4552)			
	एकमुश्त प्रावधान	**654700**	**0**	**654700**
	कुल पूंजीगत खंड	**1574694**	**0**	**1574694**
	कुल मांग संख्या 58	**5380000**	**11780700**	**17160700**

(हजार रुपये में)

संशोधित अनुमान 2006-2007			बजट अनुमान 2007-2008		
योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना	योग
6	7	8	9	10	11
0	0	0	0	0	0
318511	**0**	**318511**	**220800**	**0**	**220800**
0	0	0	31000	0	31000
411100	0	411100	2174400	0	2174400
505600	**0**	**505600**	**475000**	**0**	**475000**
1235211	**0**	**1235211**	**2901200**	**0**	**2901200**
4750000	**11850700**	**16600700**	**4750000**	**12069100**	**16819100**